जलयात्रा

राजेन्द्र सिंह

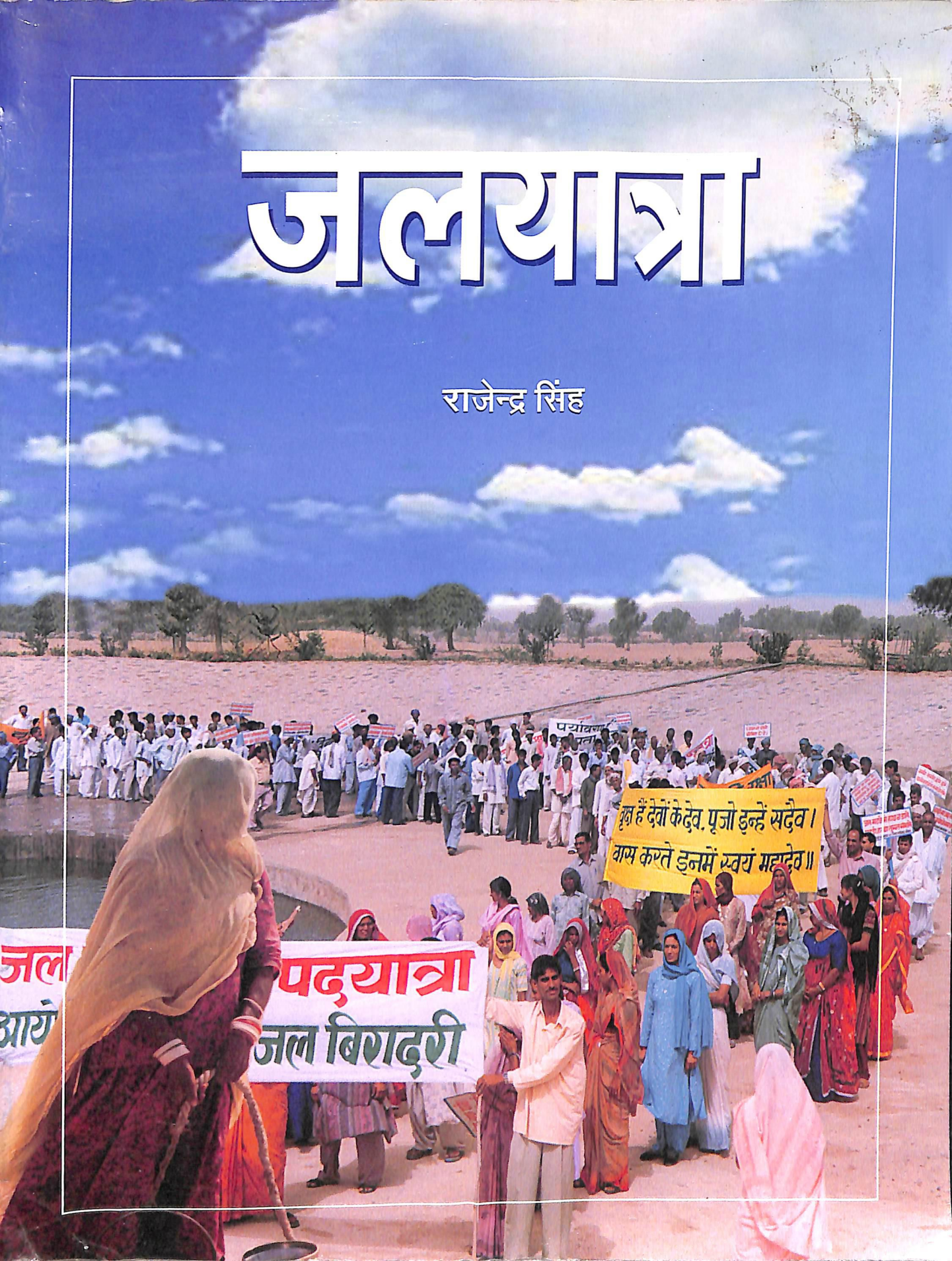

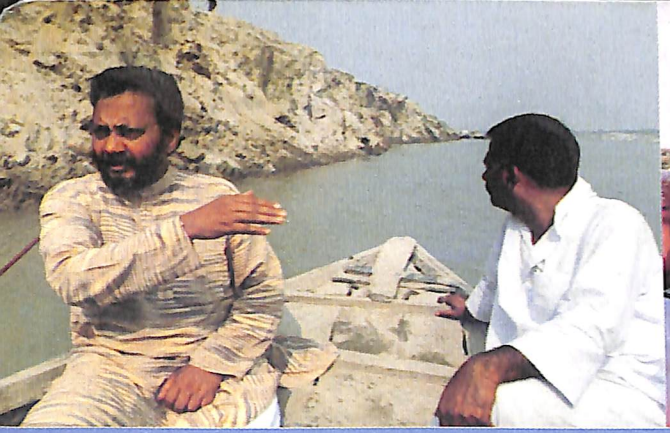

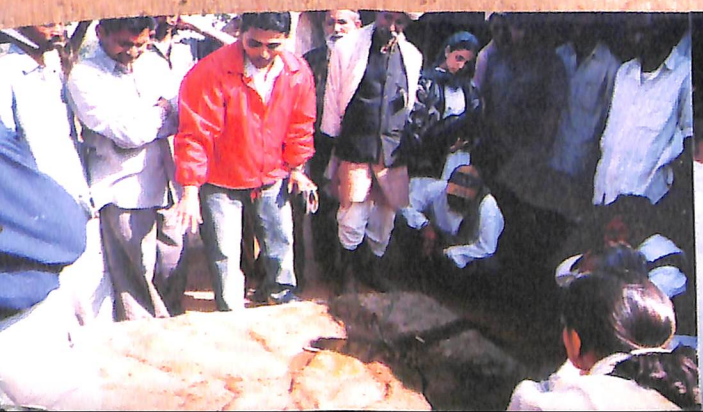

जलयात्रा

राजेन्द्र सिंह

जलयात्रा

प्रथम संस्करण : 2005

मूल्य : 150/-

प्रकाशक
तरुण जल विद्यापीठ
भीकमपुरा किशोरी, वाया - थानागाजी
जिला–अलवर
राजस्थान

वितरक
राष्ट्रीय जलबिरादरी
34/46, किरण पथ
मानसरोवर
जयपुर (राज.)

रूपांकन व मुद्रण
कुमार एण्ड कम्पनी, जयपुर

निवेदन

सारी दुनिया में पानी की कमी हुई है, पर भारत में इसकी जरूरत के मुताबिक पानी अभी भी आसमान से बरसता है। यहां पानी का नहीं, पानीदार सोच का संकट है।

''जो पुरातन है, वह पिछड़ा है... बुरा है...निरर्थक है; जो नया है, वही अच्छा है, स्तरीय है, ग्रहणीय है। जो हासिल हो गया, उसका कोई मोल नहीं, जो नहीं हासिल हुआ, उसी का आकर्षण है। साझा ठीक नहीं; निजी सर्वश्रेष्ठ है। उसी से जुड़ें। परिणामस्वरूप परिवार व समाज दोनों में टूटन बढ़ी है। जहाँ तक प्राकृतिक संसाधनों का सवाल है, लोग सोचते हैं कि हमें पानी पिलाना सरकार का काम है। सरकार ही करे। वन कम हो रहे हैं तो हों, हमें क्या ? क्या हम वनों को काट रहे हैं? जो कुछ होगा, सभी के साथ होगा। मेरे अकेले का क्या ?'' सारे देश में यही हवा चल रही है। साझे और खासकर सरकारी उपक्रमों को लेकर यही सोच बल पा रही है।

जब से जंगल और पानी पर सरकारी मोहर लगी है, इन्हें पराया मानने का चलन कुछ अधिक ही चल पड़ा है, किंतु यह ठीक नहीं है।

हालांकि अलवर के ग्रामीणों ने तरुण भारत संघ को यह बहुत पहले सिखा दिया था कि अपनापन माने बगैर पानी अपना नहीं हो सकता। यह भी कि पानी का पारंपरिक ज्ञान ही टिकाऊ है; वही टिकेगा; उसी से समृद्धि लौटेगी। इसके बाद से हम मानने लगे थे कि जिस काम का प्रबंधन समाज खुद करता है, उसका हकदार भी पूरा समाज ही होता है। भारतीय संविधान का 73-74वां संशोधन भी इसके प्रति आश्वस्त ही करता है, लेकिन वर्ष-2000 में जब नई जलनीति का प्रारूप हमारे हाथ लगा, तो हमारा भ्रम टूट गया। प्रारूप उक्त संशोधन के विपरीत खड़ा था। अब राष्ट्रीय जलनीति भी विपरीत ही बन गयी है। इसमें पानी प्रकृति का उपहार न होकर, व्यापार की वस्तु बना दी गयी है।

सरकार इसे बेचकर धन कमाना चाहती है। अब इसकी बोली लगेगी, फिर चाहे समाज रहे या टूटे। प्रकृति नष्ट हो तो हो, नीति ने ऐलान कर दिया- अब पानी पर प्रकृति और इंसान का कोई हक नहीं। अब सरकार ही इसकी मालकिन है। पर सरकार भूल गयी कि कोई भी सरकार पूरे देश को अकेले दम पर पानी नहीं पिला सकती, तो फिर अकेली मालकिन कैसे हो सकती है ?

हम वैकल्पिक जल नीति को लेकर सभी जन प्रतिनिधियों के पास गये; देशभर के जल प्रेमियों का आह्वान कर राष्ट्रीय जल बिरादरी गठित की, तो सरकार के कान खड़े हो गए। सरकार ने नई जलनीति को लागू करने में बड़ी जल्दबाजी दिखाई। देश को विश्वास में लिए बगैर इसे लागू कर दिया गया। जलबिरादरी ने पुनः इसका विरोध किया, पर तब तक गेंद राज्यों के पाले में जा चुकी थी। अतः समाज का हक बचाने हम राष्ट्रीय जलयात्रा पर निकल पड़े।

जल यात्रियों के लिए यह भारत यात्रा सरीखा था।

बचपन में सुनी 'विविधता में एकता' की उक्ति पानी के मामले में आज भी सच लगी। पानी के संरक्षण के मामले में तकनीकी विविधता भले ही कितनी हों, पर जलदर्शन समूचे भारत में एक जैसा ही है। जरूरत सिर्फ उसे जगाने की है।

तमिलनाडु की उत्साही महिलाएँ, कर्नाटक के स्वयंसेवी प्रयास और उत्तरपूर्व की एकजुटता सभी कुछ आंखें खोलने वाला था। उत्तर प्रदेश अभी भी नींद में ही है। दिल्ली में पानी को लेकर परायापन व कंकरीट के प्रति निजीपन और जगह से कहीं ज्यादा दिखा था। पंजाब का संकट जरूर कुछ भिन्न है। म.प्र. में पानी की चर्चा तो बहुत है, पर काम की गति तदानुरूप नहीं है। गुजरात, बिहार और आंध्र की बदहाली और उड़ीसा में लूट के खतरे चेतना जगाने वाले थे। खयाल रहे कि जलयात्रा कोई अनुदान आधारित परियोजना नहीं थी, अतः लोगों ने जलयात्रियों को जगह-जगह अपने खर्चे पर टिकाया, आवभगत की, सम्मेलन आयोजित किए।

जलयात्रा के इन तमाम अनुभवों के बीच जागृति, एकजुटता और राज्यों में जनोन्मुखी जलनीति बनवाने का लक्ष्य साधना था; नदी जोड़ो योजना की उपयोगिता पर लगे प्रश्न चिह्नों को भी जनमानस के सामने रखना था। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी निभाने में जल बिरादरी कितनी सफल रही, यह तो वक्त ही मापेगा; पर हमें संतोष है कि जलयात्रियों ने अपने अनुभव की पूंजी खोई नहीं, कुछ जनहितकारी लक्ष्य ही साधे।

इसका लाभ उन्हें भी मिले, जो इस यात्रा में शामिल नहीं हो सके। अतः तथ्यों का दस्तावेजीकरण जरूरी था, जो येन-केन-प्रकारेण आपके हाथों में है।

इसमें जो उपयोगी है, उसे सुधी साथी ग्रहण करें, जो कमजोर है, अनुपयोगी है, उसे मुझे लौटा दें। इसी आग्रह के साथ...

राजेन्द्र सिंह,
अध्यक्ष, राष्ट्रीय जल बिरादरी

प्रस्तावना

दुनिया व भारत के सभी राज्यों में पानी एक मुख्य समस्या बनकर उभरा है। पानी की समस्याओं के लिए काफी हद तक सरकार, समाज व बुद्धिजीवी वर्ग की अदूरदर्शिता जिम्मेदार है। यूं पानी की उपलब्धता प्रकृति की देन है, लेकिन पानी का उपभोग व प्रबन्धन तो मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य के विकास की इस लम्बी शृंखला में पानी के प्रबन्धन एवं उपभोग में गंभीर गलतियां हुईं। परिणामस्वरूप आज विश्व के हर भाग व भारतवर्ष के हर राज्य में पानी की अलग-अलग समस्याएँ मुखरित हो उठी हैं। इन समस्याओं के निदान में आज की लोकतांत्रिक सरकारें असफल हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान पानी की आपूर्ति व दोहन पर केन्द्रित है। सरकार की नीतियों में केन्द्रीकृत प्रबन्धन की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया, नतीजतन लोगों की सरकार पर निर्भरता बढ़ी व समाज का पानी से अलगाव हुआ।

राष्ट्रीय जलबिरादरी ने ऐसे समय में पानी की समस्याओं को समझने का राष्ट्रव्यापी और अनूठा प्रयास किया। देश में आजादी से पहले व बाद में अनेक राजनीतिक व सामाजिक यात्राएँ की गईं। ये यात्राएँ गाँधीजी, जयप्रकाश नारायण जी, चन्द्रशेखर सिंह व अनेक साधु-संतों के द्वारा देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हुईं; लेकिन इन यात्राओं का मुद्दा पानी नहीं था। राष्ट्रीय जलबिरादरी ने श्री राजेन्द्र सिंह (तरुण भारत संघ, राजस्थान) के नेतृत्व में एक ऐसी ही यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक व राजस्थान से मणिपुर तक आयोजित की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र व राज्यों की जल समस्याओं को समझना तथा जनमानस में जल के प्रति चेतना जागृत करना था। यह यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा बनी व लाखों लोगों ने इस यात्रा में भाग लिया।

हर राज्य की पानी की समस्याओं में भिन्नता होने के बावजूद कुछ मुद्दे सर्वव्यापी थे, जैसे कि भूजल का गिरता स्तर, सतही व भूजल का प्रदूषण, पारम्परिक स्रोतों की उपेक्षा, नदियों का सूखना या कम बहना, अत्यधिक पानी की खेती, पानी का निजीकरण और पानी के बाजार आदि। इन समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करने, समाधान सुझाने व समाज को जोड़ने में यह यात्रा काफी हद तक सफल रही। इस देशव्यापी जलयात्रा के अनुभवों को इस रिपोर्ट में रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। मैं कामना करता हूँ कि यह रिपोर्ट लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी तथा इस अनुभव से आने वाले वर्षों में अनेक स्वयंसेवी संगठन व समाज पानी की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास करेंगे।

डॉ. मनोहर सिंह राठौड़
आई.डी.एस.

संकल्प

पानी जहाँ दौड़ता है,
वहाँ इसे चलना सिखाना है।
जहाँ रेंगने लगे,
वहाँ इसे ठहराना है।
जहाँ ठहर जाए,
वहाँ धरती पर बैठाना है।
ताकि
नजर न लगे सूरज की
और
जब कभी सूखा और अकाल आए,
तो मर्यादित होकर
इसी जल से
जीवन चलाना है।

अनुक्रमणिका

1.	पहल के पहरुए	9-17
2.	यात्रा का आध्यात्म	18-21
3.	ललक जगाने की कवायद	22-33
4.	दिल्ली : लूट नीति से उबरे बगैर पानीदार बनना असंभव	34-42
5.	हरियाणा : समझ बढ़े, तो बात बने	43-53
6.	राजस्थान : पानी ही प्राथमिकता	54-68
7.	गुजरात: अंधी दौड़ में शामिल प्रदेश	69-78
8.	मध्य प्रदेश : चर्चा खूब, काम कम	79-86
9.	छत्तीसगढ़ : और कितनी सत्यभामा चाहिए ?	87-90
10.	उड़ीसा : जसमा का जस नकारती सरकार	91-99
11.	झारखण्ड : नजर लागी बेईमान की	100-101
13.	महाराष्ट्र : पानी का भोग भी, सूखा भी	102-107
14.	गोवा : पर्यटन ही मारे, पर्यटन ही जिलाये	108-110
15.	कर्नाटक : बहुत कुछ सीखने को है यहां	111-116
16.	आंध्र प्रदेश : परजीवी राज खुद पर जीना सीखे	117-121
17.	तमिलनाडु : एक सपना जगाने की जद्दोजहद	122-126
18.	पॉण्डिचेरी : दर्शन तो है, पर व्यवहार नहीं	127-128
19.	केरल : उलट बहती ज्ञान गंगा	129-135
20.	पंजाब : जल्द टूटेगा पंचनद का दंभ	136-137
21.	बिहार : बाढ़ भी, सुखाड़ भी	138-143
22.	उत्तरांचल – उत्तर प्रदेश : मैली गंगा, सुप्त समाज	144-150
23.	उत्तर-पूर्व : अब बचेगी ब्रह्मपुत्र	151-154
24.	पश्चिम बंगाल : टूटे तटबंध, तो सूखेगा साम्य	155-158
25.	राष्ट्रीय जलयात्रा : विशेषज्ञों की नजर में	159-171
	जलयात्रा कार्यक्रम	172-173
	सहयोगी	174-175

20 वर्षों के दौरान ज़मीनी काम को बढ़ाने की चिंता तो हमें हमेशा रही, लेकिन वर्ष-2000 में जब नई राष्ट्रीय जल नीति का पहला प्रारूप मिला, तो जैसे धारा ही बदल गई। इस प्रारूप ने हमारी नींद हराम कर दी। तब हमने पानी के हक, उपयोग और संरक्षण के दायित्व पर पूरे देश में संवाद स्थापित करना तय किया। इसके लिए जरूरी था कि एक औपचारिक-अनौपचारिक संगठन राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की भूमिका निभाये। इसी पर राष्ट्रीय जल बिरादरी की नींव पड़ी।

पहल के पहरुए

1984 में जब हमने राजस्थान के जिला अलवर, गांव-गोपालपुरा से जल बचाने व संजोने का काम शुरू किया था, तब अपनी परंपराओं और रस्मों में मेरा विश्वास तो था, लेकिन यह नहीं जानता था कि ये सिर्फ रस्म अदायगी के लिए नहीं है, व्यवहार में भी ये ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अब मैं दावा कर सकता हूँ कि हमारी सभी आधुनिक समस्याओं के निदान हमारी परंपराओं में मौजूद हैं। तभी अब यह काम हजारों गांवों में फैला।

जब अलवर में यह काम शुरू हुआ था, तो नौजवान-नवयुवतियां शहरों में काम ढूंढने हेतु पलायन कर चुके थे। कुएँ सूख गये थे। गांव उजाड़ और वीरान-सा हो गया था। पानी की कमी के कारण खेती खत्म होने लगी थी। चारों ओर बेरोजगारी, बीमारी और निराशा थी। चारे की कमी के कारण गायों के माथे पर टीका लगाकर उन्हें घर से बाहर कर दिया जाता था। संवाद व संवेदनहीनता ने अलवर की हथेली से कर्म व भाग्य दोनों ही रेखाओं को मिटा दिया था। सरकार ने इस क्षेत्र को 'डार्क जोन' घोषित कर दिया था। खनन से पहाड़ उजड़ने लगे थे। पेड़ों की अंधाधुन्ध कटाई से हरियाली लगातार नष्ट हो रही थी।

पहले हमने एक गाँव में काम शुरू किया, आगे से आगे कड़ी जुड़ती गई। आज हजारों गाँवों में पानी का काम हो गया है। सरकार ने अपने रिकार्ड बदल कर अब इस क्षेत्र को 'ह्वाइट जोन' (पानी वाला) क्षेत्र घोषित कर दिया है। धरती का पेट पानी से भर गया है। अरवरी, सरसा, जहाजवाली, भगाणी-तिलदेह और

रूपारेल अब सदानीरा नदियाँ बन गई हैं। पलायन रुक गया है। खेती बढ़ी है और हरियाली भी लौट आई है। बाहर के लोग भी इस क्षेत्र में रोजगार हेतु आने लगे हैं। जंगल और जंगली जीव दोनों बढ़े हैं।

जब सरिस्का में जंगल व जंगली जीव बचाने का काम हमने शुरू किया था; सरकारी रिकार्ड के अनुसार खनन आदि के कारण तब वहाँ केवल पाँच बाघ बचे थे, अब वहाँ 27 बाघ हैं। यह सब काम ग्रामीणों के प्रयास एवं अनुशासन से ही हुआ। धरती की हरियाली और इसके सपूतों की चमक ने सदैव हमारा उत्साह बढ़ाया।

आज राजस्थान के दूसरे इलाकों में भी इस काम का प्रताप दिखाई पड़ रहा है।

इन 20 वर्षों के दौरान ज़मीनी काम को बढ़ाने की चिंता तो हमें हमेशा रही, लेकिन वर्ष-2000 में जब नई राष्ट्रीय जलनीति का पहला प्रारूप हमें मिला, तो जैसे धारा ही बदल गई। इस प्रारूप ने हमारी नींद हराम कर दी। यह प्रारूप पानी को बाजारू वस्तु बनाने पर आमादा था। सरकार प्रकृति के पानी पर नियंत्रण कर पैसा कमाना चाहती थी। इससे जोहड़-तालाब के काम में बाधा का यकीन था। यह प्रारूप जनता-जनार्दन नहीं, व्यापारियों और भ्रष्टाचार के अनुकूल था। अत: हम इसे भविष्य व प्रकृति के अनुकूल बनाने को संकल्पित हुए। तब हमने पानी के हक, उपयोग और संरक्षण के दायित्व पर पूरे देश से संवाद स्थापित करना तय किया। इसे ही बाद में राष्ट्रीय जलयात्रा का स्वरूप मिला। इसके लिए जरूरी था कि एक औपचारिक-अनौपचारिक संगठन राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयक की भूमिका निभाए। इसी पर राष्ट्रीय जलबिरादरी की नींव पड़ी। यह जलबिरादरी ही राष्ट्रीय जलयात्रा की पहल का पहरुआ बनी।

इस यात्रा में पानी का काम करने वाले गजधर अर्जुन तथा नीर की नारी-कजोड़ी

जैसे 10-20 व्यक्तियों का दल सदैव साथ रहा। हम तीन दलों में बंट जाते थे। एक समाज के साथ, दूसरा सरकार के साथ, तीसरा शिक्षा संस्थानों व स्वैच्छिक संगठनों से जल संवाद करके जल बचाने, जल हक कायम रखने, परम्परागत जल प्रबन्धन को पुनर्जीवित करने, जल निजीकरण को रोकने, भूजल भण्डार भरने की बात करता था और जहाँ तैयारी हो, वहाँ कुछ काम भी शुरू कराता था। इस प्रकार यह यात्रा 18 माह तक लगातार चली। करोड़ों लोगों के साथ जल संवाद किया । करीब 30 लाख लोगों ने बोतलबंद पानी नहीं खरीदने का संकल्प लिया। 317 स्थानों पर तालाब का काम शुरू करवाया। शिवनाथ नदी को उद्योग व निजी हाथों से मुक्त करने का वातावरण तैयार किया।

जलयात्रा के समापन से पूर्व चुनाव परिणामों ने नदी जोड़ योजना को नकार दिया। अब इस यात्रा के बाद समाज स्वयं क्या करता है ?

तीन नदियों का निजीकरण रुकवाया। 140 नदियों की घाटियों में यात्रा करके 'नदी बचाओ संगठन' बनाने का आह्वान किया। 29 राज्यों में जलबिरादरी का स्वरूप समझाया, जल साथी तैयार किये। कई राज्यों में जल प्रेमियों ने संगठित होकर राज्य जलबिरादरी भी गठित कर ली है।

राष्ट्रीय जल यात्री दल ने देश भर के गाँवों व शहरों में जल संकट की गहराई का अहसास किया और तत्कालीन सरकार की नदियों को जोड़ने जैसी परियोजनाओं के खतरों का आभास कराया। तात्कालिक प्रभाव सभी के सामने हैं। समाज ने पानी का संकट देखकर सरकारों को बदल दिया।

नई सरकार ने जल संकट की नाजुक स्थिति को देखकर अपने बजट में पानी के कुछ छींटे सहेज कर विकेन्द्रित जल प्रबन्धन को महत्व दिया है। केन्द्रीय बजट पहली बार जल सहेजने, ताल, जोहड़, कुण्ड बनाने के लिए कुछ योगदान देता हुआ दिखाई दिया है। तात्कालिक प्रभाव सुखद है, इसे शाश्वत बनाने की जरूरत है।

राष्ट्रीय जलबिरादरी : कब, क्या और क्यूं ?

20 से 22 अप्रैल, 2001 के दौरान तरुण भारत संघ के कार्यक्षेत्र में स्थित ग्राम नीमी में राष्ट्रीय जलबिरादरी का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन से ही जलबिरादरी की स्थापना की प्रक्रिया भी औपचारिक रूप से प्रारम्भ हुई। भारत सरकार की प्रस्तावित जलनीति को केन्द्र में रखते हुए बिरादरी के कार्य को गतिमान किया गया। देशभर से जो हजारों साथी इस प्रक्रिया से जुड़े, उससे विभिन्न भू-साँस्कृतिक क्षेत्रों में स्थानीय जलबिरादरियों का गठन हुआ। इस तरह राष्ट्रीय जलबिरादरी आज कोई औपचारिक संगठन न होकर, एक विशाल परिवार का स्वरूप ले चुकी है।

दृष्टिकोण

भारत के गांवों और शहरों में जल की गम्भीर समस्या है। जन सहभागी जल व्यवस्था के उदाहरणों ने यह दिखाया है कि समस्या का मुख्य कारण जल प्रबन्धन में अव्यवस्था है, न कि जल की कमी। अतः जल समस्या के समाधान का एक ही हल है कि लोगों को वर्षा की एक-एक बूँद का संग्रहण करने हेतु जागरूक किया जाए। जन सहभागी जल संरक्षण व्यवस्था से हम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर अकाल मुक्त हो सकते हैं। यह तभी सम्भव है, जब समुदाय जागृत व संगठित होकर अपने जल की व्यवस्था हेतु केवल सरकार पर निर्भर न रहते हुए खुद भी पहल करे। इसके लिए जरूरी है कि पारम्परिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाए और जल संग्रहण को आगे बढ़ाया जाए। इसी से वर्षा के पानी का अधिकतम संग्रहण व विकेन्द्रित जल प्रबन्धन प्रणाली को पुनः स्थापित किया जा सकता है। जलबिरादरी का सपना एक पानीदार समाज बनाने का है। इस सपने में अपेक्षा की गई है कि कम से कम सरकार पानी को विलासिता की वस्तु न

बनाए। पानी पर आम आदमी का अधिकार रहे और उन परम्पराओं का संरक्षण हो, जिनसे पानी के स्रोत महत्वपूर्ण बने रहते हैं।

अनुभव बताते हैं कि जन सहभागिता के अभाव में समस्याएँ बढ़ती हैं। अभी यह महसूस कर लेना भी जरूरी है कि समुदाय जल संरक्षण के कार्यों में स्वयं पहल करे; स्वयं श्रम संसाधन जुटाए। ऐसा होने पर ही समुदाय उनकी निगरानी और रखरखाव के प्रति संवेदनशील बना रहेगा।

जलनीति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पानी की पहली जरूरत किसे है ?

जलबिरादरी सरकार की नीतियों को ज्यादा मानवीय बनाने और समाज के ज्यादा करीब लाने का प्रयास करेगी। अभी जलबिरादरी यह महसूस करती है कि जलनीति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पानी की पहली जरूरत किसे है ? संभवत: प्रकृति का ही पहला अधिकार बने। इसके बाद समाज के जिन लोगों का जीवन पानी पर निर्भर है, उनके लिये पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो, जैसे-केवट, मल्लाह, मछुआरे, कछारी, खेती करने वाले, धीमर आदि। फिर कृषि के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। बड़े उद्योगों को पानी तभी दिया जाना चाहिए, जबकि उपरोक्त तीनों वर्गों की जरूरत को पूरा किया जा चुका हो।

पानी की कमी के कारण जानवरों और मवेशियों की स्थिति का जो चित्र सामने आ रहा है, वह अत्यन्त ही भयावह है। पानी की कमी के कारण जैव विविधता प्रभावित हो रही है; चारे की कमी हो रही है, जिससे पशुधन के अस्तित्व पर संकट छाने लगा है। स्वाभाविक तौर पर जलबिरादरी का मानवीय दायित्व है कि वह इन्सानों के साथ-साथ जानवरों और पशु-संपदा के संरक्षण पर भी ध्यान केन्द्रित करे।

विकास की मौजूदा पद्धति में विशाल केन्द्रीकृत जल-परियोजनाओं को ही सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। इसके चलते बड़े पैमाने पर विस्थापन और पर्यावरण का भारी नुकसान तो होता ही है, लाभों का बँटवारा भी समतामूलक नहीं होता। आर्थिक दृष्टि से भी ये परियोजनाएँ लाभदायक नहीं सिद्ध हो रहीं।

केन्द्रीकृत परियोजनाओं को तवज्जो देने के चलते विकेन्द्रित जनसहभागी कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता और उनको पर्याप्त संसाधन भी नहीं मिल पाते। यकीनन इससे विषमता भी बढ़ती है। इसे सुधारने की बजाय सरकार ने पानी के संसाधनों को लोगों और समुदायों से छीनकर निजी व विदेशी कम्पनियों के हाथों में देने की नीति अपनायी है, जिससे ये सारी समस्याएँ और गम्भीर हो रही हैं। ये सब विकेन्द्रित जन सहभागी जल प्रबन्धन प्रणाली को खत्म कर देगा। अतः ऐसी विशाल केन्द्रीकृत परियोजनाओं (बड़े बाँध बनाना तथा बड़ी नदियों को जोड़ना) तथा निजीकरण की नीतियों का भी विरोध जरूरी है, ताकि विकेन्द्रित परियोजनाओं को बढ़ावा मिल सके। इन दोनों प्रक्रियाओं पर बराबर जोर देना होगा। ऐसा करने से जल का एक न्यायपूर्ण स्थायी विकास और प्रबन्धन कायम हो सकेगा। साथ ही निर्णय प्रक्रिया और नियन्त्रण जनता के हाथों में ही होगा।

जलबिरादरी के मूल्य

- जलबिरादरी में समाज का आम व्यक्ति, संस्थायें, संगठन, आन्दोलन, सामाजिक कार्यकर्ता, पैरोकार, लेखक, कलाकार, जनप्रतिनिधि, राजनेता, मजदूर, किसान और व्यापारी हर कोई शामिल है।

- यह समूह विश्वास करता है कि पानी एक साझा प्राकृतिक संसाधन है। यह किसी की सम्पत्ति नहीं है; चाहे वह व्यक्तिगत हो, संस्थागत या राष्ट्रीय।

- पानी सबसे पहले उसे मिलना चाहिए, जिसके जीवन का अस्तित्व ही पानी पर टिका है और वह पानी प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष करता रहता है। जीवन के लिए पानी की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है। महिलाओं के जीवन का बड़ा हिस्सा पानी का भार वहन करने में व्यतीत हो रहा है। यह अमानवीय है। इस प्रवृत्ति को स्थायी बनने से रोकना जरूरी है।

- जहां पानी जैव विविधता के लिए सबसे अहम है, वहाँ पर्यावरण का भी

सबसे महत्वपूर्ण घटक पानी ही है। पानी के लिये कोई भी नीति या योजना बनाते समय इस तथ्य को नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिए। व्यवस्था, संगठन और समाज सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह जैव विविधता और पानी के परस्पर सम्बन्ध को नुकसान पहुँचाने वाला कोई कदम न उठायें।

- हमारी संस्कृति, परम्परा, धर्म और सामाजिक जीवन में पानी की परिभाषा को पुनर्स्थापित करना हमारा दायित्व है।

- पानी के उपयोग का सिद्धान्त तय करने की दिशा में समुदाय और सामुदायिक संस्थाओं को पहल करनी होगी।

- अलग-अलग भू-साँस्कृतिक क्षेत्रों की प्रकृति और जरूरतें भिन्न हैं। अत: यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि समस्त भिन्नताओं के आधार पर व्यावहारिक और जनोन्मुखी जलनीति का निर्माण किया जाये।

स्वरूप

जलबिरादरी आपस में मिलकर जनसहभागी जल संरक्षण के लिए काम करेगी, जिसमें मुख्य भूमिका लोगों की होगी। जल के जन आन्दोलनों के विकास के लिए राज्य, अंचल, जिला, ब्लाक और गाँव स्तर पर जलबिरादरी का गठन जारी है। सुचारु ढंग से काम चलाने हेतु अनौपचारिक व्यवस्था बनाई गई है। हर व्यक्ति व संस्था, जो इसके उद्देश्य तथा अवधारणा से सहमत है, वह इसका सदस्य बन सकता है; आगे जरूरत हुई तो संस्थागत ढांचा भी बनाया जा सकता है।

भावी काम

- हाल ही में घोषित नई राष्ट्रीय जलनीति की समीक्षा हेतु देश के विभिन्न अंचलों में जन सुनवाइयों का आयोजन किया जाए; जिनमें राष्ट्रीय जलनीति की कमियों को उजागर करते हुए भारत सरकार से मांग की जाए कि जल

को वस्तु न मानकर, सार्वजनिक संसाधन व जीवन का आधार माना जाये। जल का निजीकरण न करे, बल्कि इसके स्थान पर जल संरक्षण व प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दे; इसका समुदायीकरण करे।

- राष्ट्रीय जलनीति के अनुसार राज्यों को भी अपनी जलनीति बनानी है। राज्यों की जलनीति से स्थानीय समुदाय क्या अपेक्षा रखते हैं – इस पर अपने-अपने राज्यों में समुदायों से चर्चा की जाए। इस बहस के जरिए राज्य सरकार को सुझाया जाये कि राज्य जलनीति का स्वरूप क्या हो ? प्रत्येक राज्य में जनसमुदाय द्वारा संचालित तथा विकेन्द्रित जल-प्रबन्धन को बढ़ावा देने वाली जनोन्मुखी जलनीति बने।

- स्थानीय से लेकर प्रादेशिक व राष्ट्रीय स्तर तक जलबिरादरी से जुड़ी संस्थाओं और लोगों में संवाद की प्रक्रिया को और सक्रिय किया जाये।

- भारत के प्रत्येक भू-सांस्कृतिक क्षेत्र में राज्य और समाज जल का अनुशासित उपयोग करने का प्रयास करे। इसके लिए फसल चक्र बदलने, भूजल भण्डार को भरने वाले कानून-कायदे व दस्तूर बनाने की तैयारी जरूरी है। ऐसा जल आयोग बनाया जाये जो कि प्रत्येक राज्य के जल-संसाधनों पर श्वेत-पत्र जारी करे।

- नदी जोड़ का विचार ही दुष्परिणामों व आशंकाओं से भरा है। अतः जरूरी है कि संबंधित कार्यों की समझ बढ़े। जहां-जहां नदी जोड़ भयानक परिणाम देने वाले हैं, वहां उन्हें शान्तिमय सत्याग्रह करके प्रत्यक्ष रूप से रोकें।

- नदी जोड़ की बजाय समाज को नदियों के साथ जोड़ने का प्रत्यक्ष कार्य करें।

- जल सहेजने का कार्य सब जगह और प्रत्यक्ष रूप से शुरू करायें।

- विकेन्द्रित जल प्रबन्धन योजनाओं को समाज द्वारा संचालित करायें। एक तरफ हमारी सरकार 73-74वां संविधान संशोधन करके ग्राम पंचायतों व

हर व्यक्ति व संस्था, जो जलबिरादरी के उद्देश्य तथा अवधारणा से सहमत है, वह इसका सदस्य बन सकता है।

नगर निकायों को जल का अधिकार दे रही है; दूसरी तरफ संविधान विरोधी जलनीति-2002 बनाई गयी है। अतः हमें ग्राम पंचायतों व नगर निकायों को उनके संवैधानिक हक बचाने हेतु सक्षम बनाना है।

- राष्ट्रीय स्तर पर तो जलकोष बनाया ही जाए, ग्राम तथा ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर भी स्थानीय जलकोष बने।

- नदी-घाटी के छोटे-छोटे संगठन बनाकर समाज को जल प्रबन्धन में लगाना।

पिछले वर्षों में हम जलबिरादरी को प्रदेश, अंचल व जिला स्तर तक ले जा चुके हैं; इस वर्ष हमारी प्राथमिकता बिरादरी को गाँव-गाँव तथा इससे भी नीचे के स्तर तक ले जाने की है। जमीनी स्तर पर जलबिरादरी की भूमिका को और सक्रिय बनाने की दिशा में पहल हो चुकी है, ताकि देशभर में विकेन्द्रित जल प्रबन्धन व जल संरक्षण के कार्य शुरू हो सकें; जल का मर्यादित उपयोग करके भूजल भण्डार भरें; नदियाँ प्रदूषणमुक्त सदानीरा बनें; समाज नदियों से आपस में जुड़ें। जल पर अपना हक कायम रखते हुए समुदाय न सिर्फ अपने जीवन को पानीदार बना सकें, बल्कि एक पानीदार भारत बनाने को भी तत्पर हों।

यात्रा का आध्यात्म

राष्ट्रीय जलयात्रा का मकसद जल नीति-रीति तथा हक व कर्तव्यों के प्रति चेतना जगाना तो था ही, पानी के आध्यात्म को भी व्यवस्था के हर वर्ग तक पहुंचाना था।

"वनेषु व्यन्तरिक्षं ततान वाजमर्त्सु पय उस्रियासु।
हृत्यु क्रतुं वरुणो अप्स्वग्निं दिवि सूर्यमदधात्सोममद्रौ।"

यह आध्यात्म ही जल संरक्षण चक्र की ऊर्जा है, वेग है... प्राण है।

दरअसल आज भारतीय समाज बेपानी बनता जा रहा है। पानी की कमी से धरती का पेट तेजी से खाली हो रहा है। इसका एक कारण तो हमारे वैज्ञानिक व शिक्षकों के मानस में शिक्षा का प्रदूषण तथा साँस्कृतिक गरीबी है, पर भारतीय समाज का मानस, शरीर, आँखें और हृदय क्यों बेपानी बनते जा रहे हैं ? यह बड़ा प्रश्न है। स्पष्ट है कि हमने अपने ज्ञान पर विश्वास और आत्मगौरव दोनों का आभास खोया है। हमारी श्रमनिष्ठा खत्म हुई है। प्रकृति से लेने-देने के रिश्तों में गिरावट आयी है। हमारा समाज पहले अधिक लेने वालों को छोटा मानता था; वह वापस नहीं लौटाये तो उसे चोर तक कहता था। आज अधिक लेने वाला ऐसे नहीं देखा जाता, बल्कि अधिक लेने वाला बड़ा आदमी माना जा रहा है। वह वापस नहीं लौटाये, तो भी उसे चोर कहने को कोई तैयार नहीं है। जो समाज चोर को बड़ा कहने लगा है, वह बेपानी तो ही बनेगा।

यह याद रखने की बात है कि श्रमनिष्ठा ही बेपानी को पानीदार बना सकती है। धरती या प्रकृति से जितना लेते हैं, उतना ही शारीरिक श्रम करके प्रकृति को लौटायें। शारीरिक श्रम से ही धरती का पोषण होगा... प्रकृति बचेगी। हम सोच-समझ कर, अनुशासित बनकर वर्षा की बून्दों को सहेजने हेतु मेहनत करें... पसीना बहायें। इससे हमारी सेहत ठीक होगी, धरती भी उत्पादक बनेगी, सबका पेट भरेगा। सभी के हित में सोचें। तय करें – "बिना सताये सभी का हित करेंगे"। अमीर के लिए गरीब की आँखों में पानी होवे। गरीब के मन में अमीर

के भले की चाह बनी रहे। अमीर के दिल का पानी गरीब के काम आ सके, तभी सभी का साझा पानी, सभी को समान पानीदार बनायेगा।

गुजरात में राष्ट्रीय जल चेतना के दौरान धरती का बेपानी हुआ रूप देखकर दुख हुआ। यहाँ स्वार्थ के वशीभूत समाज ने जिस तरह धरती का पेट पन्द्रह सौ फीट तक खाली कर दिया है, इसके परिणामस्वरूप घर-खेत-उद्योग, सब ही वीरान बने हैं। पानी की कमी से समाज मार-काट पर उतर आया है। बेपानी समाज ही मार-काट पर जिन्दा रहता है। लूट-पाट को ही अपना काम मान कर बड़ा बनना चाहता है। बस ! इसी झूठे बड़प्पन के भ्रम में आज के समाज ने सभी को बेआबरू बना दिया है।

जो
स्वयं मेहनत से काम
करता है,
वही
आगे तक जाता है;
उसी के प्रति
कृतज्ञता बोध भी
जगता है।
जो
केवल लूट कर बड़ा
बनने की कोशिश
करता है,
उसे
बेइज्जत होना ही
पड़ता है।

वह भूल गया कि बेआबरू को आबरूदार तो मेहनत ही बनाती है।

हमारे गाँव भाँवता के लोग बेघर- बेआबरू बनकर दिल्ली में बेलदारी करते थे। अपने गाँव में अपनी ही मेहनत से बरबाद होते पानी को सहेज लिया, अनुशासन बनाकर गाँव का गोचर-जंगल हरा-भरा बना लिया, तो दुनिया भर ने गाँव को सम्मानित किया। महामहिम राष्ट्रपति भी इन्हें सम्मानित करने इनके गाँव पहुंच गये। ब्रिटेन का प्रिंस चार्ल्स इनके गाँव में सीखने आया।

किन्तु पश्चिम की हवा उलट है। आज दुनिया को लूटने वाले बेइज्जत नहीं बन रहे हैं। अमेरिका पूरी दुनिया को लूटकर भी इज्जतदार बन रहा है। हालांकि अब वहाँ भी इस लूट को अन्याय मानकर देश के भीतर से खिलाफ हवा उठने लगी है, पर हमारा देश अपने असल को छोड़कर इस नकल पर चलने लगा है। तभी तो पानी जैसे जीवन के आधार को भी बाजार की वस्तु बना दिया है। कुछ दिनों में पैसे वाले ही पानी खरीद कर पी सकेंगे। यही रहा तो कम पानी में जीने वाले, सबके हित में काम करने वाले भी प्यासे मरेंगे। हमारे पद्मपुराण व ईशोपनिषद् ने सब त्याग कर ग्रहण करने का सन्देश दिया है। जितना धरती से लो, कम से कम उतना तो अवश्य ही अपनी मेहनत से धरती को लौटा दो। इस

बात को मानने वाले हमारे देश में भी कम हैं, पर जो हैं, वे आज भी सुखी, शान्त और समृद्ध हैं।

बाँट कर खाना और कर्म साधना में जीना – हमें इज्जत, आबरू, प्यार, समृद्धि और पानी सभी कुछ देता है, लेकिन हमारी सरकार अब अधिक पाने के नाम पर पानी का बाजार बना रही है। पानी का बाजार बनाने से समाज टूट रहा है। पारंपरिक भारत में पानी हम सबका साझा संसाधन था। पर अब सरकार इसे निजी सम्पत्ति मानती है। वही सभी के हाथों से छीन कर चन्द हाथों में बेच रही है। नदियाँ, नाले, धरती का पेट और ऊपर का पानी सभी को लेकर एक ही व्यापारिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि धरती-नदी हमें केवल पानी दे रही है; हमारी स्वायत्तता, स्वाभिमान सभी कुछ इन्ही से है। हम यह भूल रहे हैं।

जिस बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने हमारे पानी का पट्टा लिया, उसने उस क्षेत्र विशेष में पानी के प्रबन्धन का सारा हक हमारे समाज और सरकार दोनों से ही छीन लिया। समाज जहां कहीं पानी बचाना व सहेजना शुरू करता है, वहाँ बहुराष्ट्रीय कम्पनी उसे वैसा करने से रोक देती है। पानी का मालिकाना हक़ किसी भी दूसरे राष्ट्र की कम्पनी या व्यक्ति को देना, संविधान विरोधी है। हमारे संविधान का 73-74वाँ संशोधन हमारे ग्राम व नगर समाज को पानी का काम व मालिकाना हक़ देता है। अब नई जल नीति संविधान के विपरीत समाज व सरकार के हक को खत्म करके निजी कम्पनियों को दे रही है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने व्यापार कर अपना राज्य अस्सी वर्ष में कायम किया था; बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अब पानी पर नियंत्रण कर अपना राज्य बीस वर्ष में ही कायम करने की नींव डाल रही है। यह कार्य हमारी सरकार ने ही शुरू किया है। यही सरकार नई गुलामी भुगतेगी और फिर पूरा समाज गुलाम बनेगा। यह सरकार पानी पर कब्जा ऐसे हाथों में दे रही है, जिसे आने वाले कल में वापस नहीं ले सकेगी। स्वयं सरकार भी मोहताज बनेगी।

यह सरकार पानी पर कब्जा ऐसे हाथों में दे रही है, जिसे आने वाले कल में वापस नहीं ले सकेगी।

सरकार मोहताज क्यों बनना चाहती है ?

हमारे नेता, अधिकारी, व्यापारी और पुजारी सब बेपानी बन गये हैं। बेपानी समाज व सरकार ऐसा ही करते हैं। पानीदार बनने की चाह हम में जग जाए, तो आज भी हम अपनी आज़ादी को बचा सकते हैं। आज़ादी बचाने की जुम्बिश खड़ी करनी है, तो जन-जन जल सहेजने में जुड़े। किसी भी कम्पनी को पानी का मालिकाना हक नहीं दें। पानी का मालिकाना हक़ समाज को सौंप दें। आज की सरकार निजी कम्पनियों को पानी और पैसा दोनों दे रही है। शिवनाथ नदी का उदाहरण अकेला नहीं है; पालकांड, पेरियार नदी जैसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं, जहाँ के किसान बेहाल, बेघर और बेकाम बन गये हैं। फसलें सूखने के कारण घर में अन्न नहीं है। भूखे मरते लोग, गाँव छोड़कर शहर के नये नरक में मजबूरीवश चले गये हैं। अभी तो गाँव उजड़कर शहर की मलिन बस्तियाँ बन रही हैं, जब शहर में पानी घी के भाव मिलेगा, तो शहर भी उजड़ेंगे।

समय रहते गाँव-शहर सभी का जन-जागरण करके जल जोड़ें... सबको जल दें। जल के लेन-देन का व्यवहार समान बनावें। जल पर सबका हक समान है। सभी को जीने और पानी पीने का मौलिक अधिकार है। इसी तरह धरती को भी पानी रखने का हक है। हम धरती से जितना लें, उतना ही वर्षा का पानी सहेज कर धरती को देने का संस्कार हमारे समाज में बनाएँ, तभी हमारी धरती और भारत राष्ट्र का समाज पानीदार बनेगा।

ललक जगाने की कवायद

पाँच-छः मार्च, 2002 को दिल्ली में राष्ट्रीय जलबिरादरी का सम्मेलन हुआ। इसमें राष्ट्रीय जलनीति को बदलवाने के लिए भारत सरकार के तीन केबिनेट मन्त्री, देशभर के जलयोद्धा व जलकर्मी आये। सभी ने जलनीति बदलवाने का संकल्प लिया। प्रधानमन्त्री जी से मिलकर उन्हें इस नीति के दोषों से अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन दिया। हम इन्तजार करते रहे, परन्तु उन्होंने उसे पूरा नहीं किया। छः माह की प्रतीक्षा के बाद पुनः ज्ञापन दिया गया। अन्त में 16-17 नवम्बर को गुजरात में साबरमती नदी के किनारे कोबा में मिले। जलयात्रा शुरू करने का निर्णय वहीं लिया गया। घोषणा के अनुसार यह जलयात्रा 23 दिसम्बर को बापू की समाधि, नई दिल्ली से सड़कों पर निकल पड़ी। इस तरह समाज ने जलनीति के विरुद्ध शान्तिमय संघर्ष का श्रीगणेश किया।

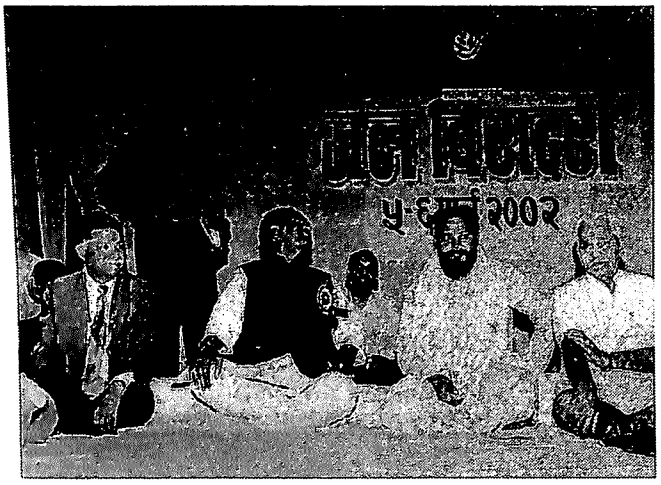

प्रधानमंत्री जी ने नीति को दोषमुक्त बनाने का आश्वासन दिया, किन्तु उन्होंने उसे पूरा नहीं किया।

नई दिल्ली से शुरू होकर यह यात्रा हरियाणा होते हुए राजस्थान पहुँची, वहीं पहला महिला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। यहाँ से होते हुए यात्रा 30 जनवरी, 2003 को गुजरात के साबरमती आश्रम पहुंची। वहां से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल होते हुए 15 मार्च को पुनः दिल्ली पहुंची। तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश होते हुए जब हम वर्धा पहुँचे तो वहाँ दूसरा सम्मेलन हुआ। यात्रा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी गई। 29 मई को कांचीपुरम् में यात्रा के इस दौर का समापन तीसरे राष्ट्रीय जल सम्मेलन के रूप में हुआ। एक जून से राष्ट्रीय

जलयात्रा का तीसरा चरण शुरू हुआ। कन्याकुमारी, त्रिवेन्द्रम से पूरा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा होते हुए पंजाब विश्वविद्यालय में इस दौरे का समापन सम्मेलन आयोजित किया गया।

जलयात्रा के चौथे दौर में अनुपालना व उन्मुखीकरण के छोटे-छोटे कई कार्यक्रम आयोजित हुए। पाँचवें चरण का लक्ष्य उ.प्र., बिहार, बंगाल, झारखण्ड तथा उड़ीसा का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा। इसी तरह छठे चरण के दौरान सूखाग्रस्त महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आन्धप्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में आना-जाना रहा।

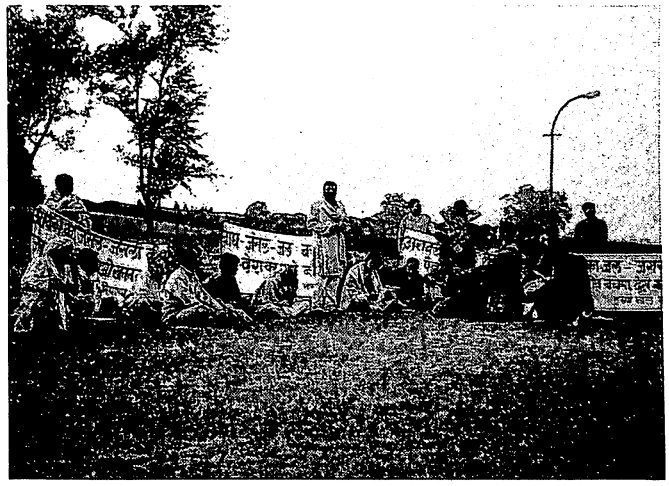

10 जनवरी से अगला चरण शुरू हुआ। इस चरण में केरल से शुरू होकर महाराष्ट्र, उत्तरांचल, यू. पी., बिहार, बंगाल, पूर्वोत्तर; अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा में यात्रा गई। अंततः असम के डिब्रूगढ़ में 10 मई, 2004 को जलयात्रा का सातवाँ दौर सम्पन्न हुआ।

इस यात्रा के पहले चरण में भारत में सक्रिय जल माफिया की घुसपैठ जगह-जगह दिखाई दी।

इस यात्रा के पहले चरण में भारत में सक्रिय जल माफिया की घुसपैठ जगह-जगह दिखाई दी। वर्षा वाले हजारों किलोमीटर लंबे इलाकों में भी छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ जैसे प्यासे गांवों की बड़ी संख्या दिखी। पानी का बाजार भी लूट के बाजार की तरह गर्म दिखाई दिया। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की शिवनाथ, केलो व उड़ीसा की महानदी पर कब्जा करने वालों के हाथ और आँखें दिखाई दिए। इन्हीं क्षेत्रों में कई जगह पर ग्रामीणों द्वारा किए गए जल प्रबन्धन के सफल प्रयोग भी देखने को मिले। उड़ीसा के सिमली पाल बांध परियोजना क्षेत्र में पूर्णापानी और कुन्दबहाली, कर्नाटक के अन्सूडी और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के बहुत से गांव - समाज द्वारा किए गए पानी के कुशल प्रबन्धन के तरीकों से पुष्ट दिखाई दिए।

इस यात्रा के दौरान कई जगह समाज के सफल प्रयासों को देखकर विश्वास होता है कि जो लोग पानी की महाजनी के लिए उस पर नियंत्रण कर पानी का व्यापार कायम करना चाहते हैं, वे सफल नहीं हो पाएंगे। पानी की तिजारत करने में बिवन्डी, स्वेज लिओनेज, डेस ड्योक्स, बैकटेल, कोका कोला और पेप्सी आदि कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियां शामिल हैं। इन्हें भारत छोड़ कर जाना ही पड़ेगा। भारत का पानी इनके व्यापार और मुनाफा कमाने के लिए नहीं है।

बड़े बांधों से लाभ के दिखावटी आँकड़े उत्साहित तो करते हैं, लेकिन इनमें समाज के अनुभव, सर्वहित और अनुभूति की चमक कहीं नहीं दिखाई दी।

इसी तरह हमारे विकास के मंदिर कहलाने वाले बड़े बांध भी देश में बड़ी संख्या में दिखाई दिए। इन बांधों से ऊर्जा उत्पादन, सिंचाई और बाढ़-मुक्ति के दिखाए गए आंकड़े बहुत ही उत्साहित करने वाले थे, लेकिन इन आंकड़ों में कहीं भी समाज के अनुभव, सर्वहित और अनुभूति की चमक दिखाई नहीं दी। हीराकुड बांध के नीचे थोड़ी ही दूरी पर चन्दनकुटी और चन्द्रीमार गांव में सूखा दिखाई दिया। 500 वर्ग मील के जिस कटक डेल्टा को बाढ़-मुक्त करने की प्रस्तावना थी, वह बांध बनने के 45 साल बाद भी बाढ़ से प्रभावित हुआ। छत्तीसगढ़ में भी भयानक सूखा है। खाली हथेली लिए गांव के लोग घर छोड़कर बाहर जा रहे थे। छत्तीसगढ़ पानी का कुछ काम करके नाम कमाने में तो सफल हुआ, लेकिन अभी भी वहां सूखा और अकाल की भयानक चपेट दिखती है। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, झारखंड और बिहार भी पानी की कमी से त्रस्त हैं। कुछ दूसरे इलाकों में पानी के प्रदूषण से उपजी बीमारियां सता रही हैं। बिहार का बांका, झारखंड का हजारीबाग और देवघर जिले का एक बड़ा हिस्सा भी सूखा प्रभावित था। जल ग्रहण क्षेत्र विकास के नाम पर चल रही सरकारी परियोजनाओं में पानी तो नहीं दिखाई दिया, पर परियोजना के दफ्तर सब जगह दिखे।

उत्तरांचल के टिहरी बांध क्षेत्र में एक तरफ महिलाएँ घंटों चल कर पानी लाती हैं, तो दूसरी तरफ हजारों लीटर पानी बहाने वाले नए टिहरी शहर के परिवार

कुछ पुरानी यादें लिए दुःखी होते हैं। जब यात्रा हर की पौढ़ी, हरिद्वार पहुँची, स्वर्गीय श्री मदनमोहन मालवीय द्वारा बनायी गई गंगा सभा के कार्यकर्ताओं का व्यवहार तो उत्साहवर्द्धक था, लेकिन उन सभी को गंगा में अविरल निर्मल जल के बहाव की कमी सता रही थी। शाम को गंगा मां की आरती देखकर हमें लगा कि आज भी हमारे समाज का नदियों के साथ वैसा ही जुड़ाव है। नदियों से भारतीय समाज का जुड़ाव और नदी के साथ समाज के आत्मीय रिश्ते नदियों को जोड़ने की बहस को ठोकर मार रहे हैं। नदियों को जोड़ने की बहस जो भी हो, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो गंगा मां की आरती पर समाज में जो आस्था है, वह मर जाएगी। फिर हमारा समाज इस तरह आत्मिक भाव से बैठकर गंगा का ध्यान नहीं कर सकेगा।

...लेकिन यदि ऐसा हुआ तो गंगा मां की आरती पर समाज में जो आस्था है, वह मर जाएगी। फिर हमारा समाज इस तरह आत्मिक भाव से बैठकर गंगा का ध्यान नहीं कर सकेगा।

कुछ आगे बढ़े, तो आई. आई. टी., रुड़की के विद्यार्थी और शिक्षक पानी की परम्परा के बारे में काफी सवालों के साथ मौजूद थे। इनमें एक भी शिक्षक और विद्यार्थी यह कहने की स्थिति में नहीं था कि उसने अपने हाथ से पानी का काम किया है।

दरअसल आज की शिक्षा पानी के चित्रों से तो हमें जोड़ती है, लेकिन पानी के काम से जोड़ने में असमर्थ है। मेरठ भी बेपानी दिखाई दिया। राजधानी दिल्ली में भी गंगा-जमुना का पर्याप्त पानी आने के बावजूद बेपानी बनते समाज के दर्शन ही यहां हुए। सुबह नालों में पानी तो सड़ता दिखाई दिया, लेकिन सहज तरीके से निर्मल बनता हुआ पानी कहीं नहीं दिखाई दिया। 31 मार्च को सेवाग्राम, वर्धा पहुंचते ही यह संकल्प प्रबल हो उठा कि आज हमारे समाज को पानीदार बनाने के लिये लोगों में पानी के प्रति प्रेम जगाना होगा और पानीदार बनने में सभी को जुटना होगा; लेकिन उस तरह नहीं, जैसा कि महाराष्ट्र में दिखता है।

दरअसल महाराष्ट्र एक विकसित राज्य कहलाता है। यहां गन्ना पैदा करके धरती का पेट खाली कर दिया गया है। भारत के 40 प्रतिशत बड़े बांध इसी राज्य में हैं। इन्हीं बांधों ने पहले तो गन्ना आदि पैदा करके एक तरफ कुछ अर्थ अर्जित किया, पर दूसरी तरफ गरीबी भी बढ़ाई। आज भी गांव में एक तरफ हरियाली, दूसरी तरफ उजाड़ तथा पीने का पानी ढोता हुआ टैंकर मिलता है।

महाराष्ट्र यात्रा में पानी की कमी का रोना ही सुनते रहे; पर ज्यादा पानी पीने वाली अंगूर व गन्ने की फसलों पर इन्होंने कोई लगाम नहीं लगाई। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि यहां अब कुछ किसान सजीव खेती की तरफ देख रहे हैं, बाजारू खेती को गाली दे रहे हैं। अनीतिवश सजीव खेती अपनाने वालों को कोई प्रोत्साहन नहीं है। हमारी सरकार बाजारू खेती को ही प्रोत्साहन देती है, ताकि किसान की मेहनत को बाजार में बेमोल लूटकर कुछ धनी सेठ मजा कर सकें। चूँकि ये सत्ता को पोषित करते हैं, इसलिए पूरी सत्ता बाजारू फसलों के प्रोत्साहन में लगी है। अब कई किसान भुक्तभोगी होकर बाजार की लूट से मुक्त होने के लिए तड़प रहे हैं।

गांववासियों ने मिलकर हिरवे बाजार गांव को हरा-भरा बना दिया है। बेसमझी के बीच इस तरह के कुछ समझदार काम देश में कई जगह देखने को मिले।

शोलापुर में सजीव खेती के बहुत से सफल प्रयोग देखने को मिले। सजीव खेती धरती से लेन-देन का हिसाब संतुलित रखती है। सजीव खेती में कम पानी और कम खर्च लगता है। यह धरती का उपजाऊपन बरकरार रखती है। इसी खेती से हमारा समाज पानीदार बना रह सकता है। विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र आज जहां एक तरफ पानी की कमी से तड़फ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गांववासियों ने मिलकर हिरवे बाजार गांव को हरा-भरा बना दिया है। बेसमझी के बीच इस तरह के कुछ समझदार काम देश में कई जगह देखने को मिले। यहां इस कार्य को शुरू करने वाले युवा श्री पोपट पवार के प्रति ग्रामीणों में कृतज्ञता बोध दिखता है।

महाराष्ट्र के बाद यात्रा ने गोवा में प्रवेश किया। यहाँ पर यात्रा केवल दो दिन रही। जलयात्री पणजी तथा अन्य कई जगहों पर पुराने तालाब देखकर बहुत खुश हुए

और अनुभव पक्का हो गया कि हमारे देश में दिल्ली से गोवा तक सभी जगह एक से तालाब हैं। गोवा जैसे आधुनिक राज्य में आज भी कुछ गांवों में तालाबों से ही खेती और घर के सभी काम पूरे हो रहे हैं। यहां के तालाबों की इंजीनियरिंग राजस्थान के तालाबों से बिल्कुल मिलती-जुलती है, लेकिन गोवा के दो सूखे हुए गांव देखकर आश्चर्य हुआ। इन दोनों गाँवों के कुएँ सूखे हुए थे। इन कुओं को सुखाने का काम यहां के पानी बाजार ने किया है। यहां के कुओं में अच्छा मीठा पानी था। टैंकरों ने उसे खींच-खींच कर गोल्फ के मैदानों की सिंचाई तथा बोतलबंद पानी की बिक्री की। इसी से यहाँ का पानी सूख गया। पानी की कमी के कारण यहां के खेत खाली हैं, यहां के नागरिकों ने कम्पनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और जीत भी गए हैं। अब पंचायत भी नागरिकों के साथ पानी की कम्पनी के खिलाफ लड़ रही है।

हमारे देश में दिल्ली से गोवा तक सभी जगह एक से तालाब हैं।

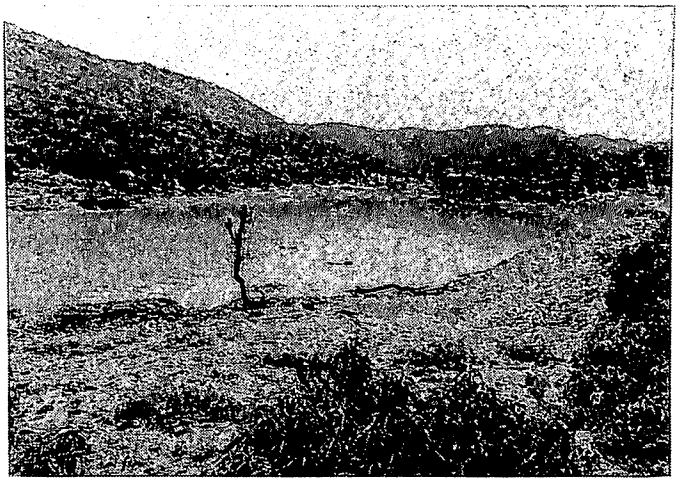

गोवा के शहरी कचरे ने भी एक अन्य गांव का तालाब पूर्णतया नष्ट कर दिया है। फौजी छावनी से भी पानी के स्रोत प्रदूषित हुए हैं। इस प्रदूषण के खिलाफ गांव में आक्रोश खड़ा हो रहा है।

गोवा के बाद कर्नाटक सीमा पर कर्नाटक जलबिरादरी के अध्यक्ष श्री डी. आर. पाटिल ने जलयात्रा का स्वागत किया। धारवाड़ के माधोड़ गांव में तालाब की खुदाई के काम से यात्रा की शुरुआत हुई। कर्नाटक यात्रा में सभी पार्टियों के राजनीतिक नेताओं ने भी हिस्सा लिया। यहां के कई साधु-संन्यासी भी शामिल हुए। यहां के श्रृंगेरी पीठ के जगद्गुरु श्री स्वामी के भक्तों ने उनके जन्मदिन तक छह सौ तालाबों का काम सम्पन्न करने का निर्णय लिया। उनमें से कुछ कार्य चालू हैं, कुछ पूरे हो गए हैं। इस राज्य की जलबिरादरी के अध्यक्ष ने बताया कि यात्रा के दौरान बहुत सारे नए गांवों ने भी तालाबों के पुनःनिर्माण का संकल्प लिया है। कई गावों के लोगों ने मिलकर कई सुन्दर तालाब बनाए हैं । इन तालाबों का काम

समाज ने केवल श्रमदान से किया है। कर्नाटक के काम से हमारे यात्रा दल का बहुत उत्साहवर्द्धन हुआ।

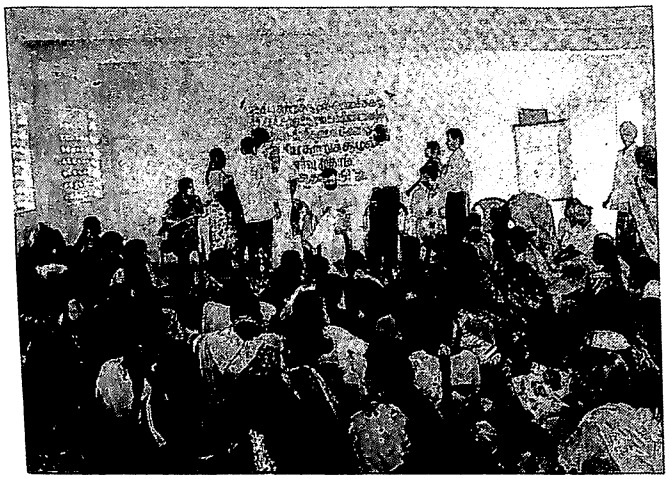

कर्नाटक की यात्रा में प्रतिदिन कम-से-कम चार सभाएँ होती थीं । इन सभाओं में श्रोताओं की संख्या पांच सौ से लेकर पच्चीस हजार तक रही। ज़्यादातर सभाओं में बोतलबंद पानी खरीद कर नहीं पीने एवं बूट एग्रीमेंट के तहत नदियों के निजीकरण को रोकने का संकल्प मजबूती से दोहराया गया। नए तालाबों का निर्माण तथा पुराने तालाबों की गाद की सफाई के कार्य को तेज करने की प्रतिबद्धता भी दिखी । कर्नाटक की यात्रा बहुत ही भव्य एवं विशाल सभाओं वाली रही । यहां पर कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी संख्या में पानी के काम से जुड़ने का उत्साह दिखाया।

कर्नाटक से निकलकर आंध्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री के विधान सभा क्षेत्र कुप्पम में प्रवेश किया। चन्द्रबाबू नायडू की तरह यहाँ की खेती भी हमें हाईटेक और बाजारू ही दिखाई दी। आन्ध्र के सूखाग्रस्त क्षेत्र में भी हम गये। त्रिचूर जिले में गांधी शान्ति केन्द्र के आयोजकों ने कई अच्छी सभाएँ आयोजित कीं। अनन्तपुर जिले के कोदाली गांव में भी हम गए। यह वही गांव है, जहां पर दो दिन पहले ही पानी की कमी के कारण कई लोगों ने आत्महत्याएं की थीं। यूं इस हाईटेक बताये जाने वाले राज्य में पिछले तीन-चार महीनों में लगभग 345 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं।

यहां अकाल राहत के सरकारी काम भी देखे। ज़्यादातर काम मशीनों से चल रहे थे। 'काम के बदले अनाज' योजना में मशीनों से होता पहला कार्य यहीं देखने को मिला। ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देने के सिद्धांत को मशीनें ठेंगा दिखा रही थीं। हम तेलंगाना के प्रसिद्ध क्षेत्र वारंगल भी पहुंचे। यहां के एक ईमानदार जिलाधीश और परियोजना निदेशक ने 'काम के बदले अनाज' योजना में मशीनों

को नहीं लगने दिया है। इस जिले के लोग तालाब की गाद हटाने के कामों में लगे हुए थे।

हैदराबाद के हाईटेक चेहरे पर यहीं की मूसी नदी की मौत का मातम भारी पड़ने लगा है। मूसी नदी को अब नाला कहना ही उचित होगा। इस प्रकार यह यात्रा आगे जाकर खमम में खत्म हुई । खमम एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, लेकिन कोकाकोला कम्पनी ने यहां भी धरती से पानी निकालने की फैक्ट्री लगाकर धरती का पेट खाली कर दिया है। नक्सलवाद प्रभावित इलाका होने के बावजूद खमम सूखे और अकाल की मार झेलते हुए कोकाकोला कम्पनी को कैसे चलने दे रहा है ? यह सब हमारी समझ से अब भी बाहर है।

खमम से चल कर विजयवाड़ा-नेलौर होते हुए यात्रा ने तमिलनाडु में प्रवेश किया। यहां पर ठक्कर बापा विद्यालय में सर्वोदय कार्यकर्ताओं तथा विचारकों ने यात्रा का स्वागत किया। यहां की पूरी व्यवस्था श्री एन. कृष्णास्वामी के नेतृत्व में श्री अन्नामलाई ने की थी। पहले दिन ठक्कर बापा विद्यालय की सभा के बाद कुथाबक्कम में इंलिंगो के नेतृत्व में कुछ पंचायती नेताओं से मिलना हुआ। त्रिवलूर के कलक्टर ने भी यात्रा का स्वागत किया। यहां के महिला मंडल से मिले, तो उन्होंने अपने पानी के संकट की दुःखद कहानी कही।

नक्सलवाद प्रभावित इलाका होने के बावजूद खमम सूखे और अकाल की मार झेलते हुए कोकाकोला कम्पनी को कैसे चलने दे रहा है ? यह सब हमारी समझ से अब भी बाहर है।

इस इलाके में बहने वाली वर्षा नदी बिल्कुल सूखी पड़ी है। इसके बाद हम विनदिवानम जिले में पहुंचे। यहां महिलाओं की एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। यहां से तन्जौर होते हुए मनापराई के ग्रामोदय संस्थान में पहुंचे। यहां भी महिलाओं की तीन बड़ी सभाएं हुईं तथा तमिलनाडु जलापूर्ति विभाग के वैज्ञानिकों के कुछ काम दिखाए गए।

गांधीग्राम के संचालकों ने अपने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत का मौका दिया एवं जल संरक्षण क्षेत्र में अपने काम दिखाए। मदुरई में धान फाउण्डेशन एवं गांधी आश्रम ने मिलकर कुछ कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिनमें हमने तमिलनाडु जैसे राज्य में पानी की कमी को दूर करने के लिए

परम्परागत जल प्रबन्धन पर जोर दिया और कहा कि आज महात्मा गांधी होते, तो पानी के हक को बरकरार रखने के लिए सत्याग्रह करते और तालाब बनाने का रचनात्मक संदेश देते । प्रत्येक गांव में एक तालाब और शहरों के प्रत्येक मोहल्ले में तालाब बनाने की बात भी रखी गई; जिसे सभी ने स्वीकारा । मदुरई के बाद विलाईतीकुलम में सभी धर्मों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सभा हुई । तमिलनाडु की यात्रा अनोखी थी । सभी जगह कुछ नया था । इस राज्य की यात्रा सभी जगह गांधीवादी विचारकों व कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में ही हुई। यहां के यात्रा दल से मिलने को उत्सुक महिला दल अपनी सार्थकता का संदेश दे गए।

कांचीपुरम के राष्ट्रीय जल सम्मेलन में स्थानीय पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य व श्री टी. एन. शेषन के अलावा बहुत से सरकारी इंजीनियर व आन्दोलनकारी शामिल हुए । ये सभी तमिलनाडु सरकार पर अच्छा दबाव बनाने में कामयाब रहे । भूजल भण्डारों को पुनः भरने की माँग वहाँ के मुख्यमन्त्री से की गयी । उन्होंने इसे मानकर भूजल पुनःभरण पर बहुत जोर दिया और अब तो अच्छा नियम बनाकर जल संरक्षण कार्य भी शुरू करा दिया है।

श्री शंकराचार्य जी ने नदी जोड़ के दुष्प्रभाव समझ कर इसे रोकने का आश्वासन दिया।

दोबारा उ.प्र. लौटे तो खयाल आया कि मेरठ का हस्तिनापुर-इन्द्रप्रस्थ कहलाने वाला भूभाग कभी गंगा-यमुना के दोआब की वजह से ही बसा व समृद्ध रहा होगा, लेकिन अब यहाँ हिन्डन, काली, गंगा और यमुना सब केवल जहरीले पानी वाली नदियाँ बन गई हैं । पश्चिम से पूर्व जाते-जाते गंगा का चरित्र बिल्कुल बदल जाता है । कानपुर में गंगा केवल गन्दा नाला बन जाती है । इलाहाबाद प्रपात

में जाने पर गंगा फिर बड़ा रूप बना लेती है। करोड़ों की संख्या में भारतीय श्रद्धालु यहां स्नान करते हैं। इसकी शुद्धता वास्ते हजारों करोड़ खर्च भी हुआ है, लेकिन इसकी गन्दगी बढ़ती गई। गंगा आज कचरा ढोने वाली रेल बन गई है। यहाँ के समाज को भी अभी तक नदियों की पवित्रता और पहाड़ों की हरियाली की चिन्ता नहीं है। यहाँ समाज ने अपनी नदियों को नहीं बचाया, तो समाज टूट जायेगा। उ. प्र. में समाज को नदियों के साथ जोड़ने की बहुत जरूरत है।

बिहार में हम मुख्यमन्त्री एवम् श्री लालू प्रसाद यादव जी से मिले। उनके राज्य के सुखाड़-बाढ़ पर बातचीत की, तो उन्होंने उससे मुक्ति के विषय में चुप्पी साध ली। बाढ़ विस्थापितों की पुनर्वास सहायता के नाम पर रुपए 200 प्रत्येक परिवार सहायता तथा रुपए 200 प्रत्येक पशु के मरने की क्षतिपूर्ति के कानून का जिक्र करते हुए हमने आज की जरूरत अनुसार उसे बदलने की बात कही। उनके द्वारा किए जा रहे नदी जोड़ के विरोध की हमनें उन्हें बधाई दी। हमने जल के निजीकरण को रोकने वाली नीति बनाने की पहल बिहार से ही करने का निवेदन भी किया।

बिहार में हम मुख्यमन्त्री एवम् श्री लालू प्रसाद यादव जी से मिले। उनके राज्य के सुखाड़-बाढ़ पर बातचीत की, तो उन्होंने उससे मुक्ति के विषय में चुप्पी साध ली।

बिहार की जनसभाओं में बाढ़ के साथ जीने वाली आबादी के बीच पारंपरिक बातों पर बहुत जोर दिया गया। यहाँ के समाज ने उसका स्वागत भी किया। बिहार में नदियों के कटाव-जमाव की समस्या बहुत बढ़ गई है। पलायन अब बहुत ज्यादा हो गया है। इसे रोकने की कोशिश अब जल प्रबन्धन बिना सफल होती नहीं दिखती। इस प्रदेश में बाढ़ नेपाल की तरफ से आती है। इससे बचने वास्ते अपने क्षेत्रों में फसल चक्र व बाढ़-सुखाड़ के साथ जीवन जीने वाली जीवन पद्धति ही हमें सुख-समृद्धि के रास्ते पर लेकर जायेगी।

विकसित कहलाने वाला 44 नदियों का राज्य केरल आज सूखा और प्लास्टिक से भरा दिखता है। पर्याप्त पानी की वजह से जहाँ पहले खूब चावल होता था, वहाँ आज केवल सीमेन्ट के नए जंगल दिखाई देते हैं। यहाँ दुकानें भी विदेशी प्लास्टिक के सामान से ही भरी हैं। पहाड़ों का नंगापन तथा नदियों का कटाव-जमाव बढ़ रहा है। जल प्रदूषण की भयानक समस्याएँ भी यहां दिखाई दीं।

पंजाब पानी वाला प्रदेश माना जाता है, लेकिन अफसोस ! अब खजाना खाली हो रहा है।

जम्मू-कश्मीर में जहां एक तरफ सुन्दर वादियां हैं, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती नंगी पहाड़ियां मन को दुखी करती हैं। अच्छी बात यह लगी कि यहां के नौजवान बन्दूक छोड़कर पानी के कार्यों में लगने हेतु लालायित हैं। इस प्रदेश की संस्थायें भी इस दिशा में सक्रिय दिखाई दीं। फौज से लौटे कुछ जवान-अधिकारी इन पहाड़ों को पुनः हरा-भरा बनाकर राज्य को सुख-समृद्धि वाला तथा शान्तिप्रिय बनाना चाहते हैं।

पंजाब पानी वाला प्रदेश माना जाता है, लेकिन अफसोस ! अब खजाना खाली हो रहा है। यहां पानी की बरबादी और प्रदूषण बहुत ज्यादा है। इसके कारण यहां के बहुत बड़े क्षेत्र का भूजल भण्डार खाली हो गया है। कई क्षेत्र 'डार्क जोन' घोषित हो चुके हैं। पंजाब के कई क्षेत्रों में जल संरक्षण के सरकारी कार्यक्रम चालू हैं, लेकिन समाज इनके साथ नहीं जुड़ा है। यहाँ के स्वर्ण मन्दिर में जिस बावड़ी से पहले पानी मिलता था, वह भी अब सूख गई है; दूषित पड़ी है। यहां के मुख्य नेताओं के साथ इसे देखा और इसका जीर्णोद्धार करने का आश्वासन दिया।

हिमाचल के सोलन जिले में पानी की कमी के कारण बिन नहाये रहे। यहां की राजधानी बेपानी हो गई है। निजीकरण के विरुद्ध प्रवाहों में उत्साह है, लेकिन सरकारें पानी को बेचकर धन कमाने को बड़ा काम मानती हैं; पर अच्छा लगा कि सोलन के साथियों ने जल संरक्षण के कई कार्य शुरू किए हैं। यह राज्य भी नदियों की जोड़ परियोजना के पक्ष में नहीं है।

असम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तरांचल देश के पेयजल की 40 प्रतिशत पूर्ति करने वाले राज्य बन सकते हैं। इनके पास बर्फीला व वर्षा का पवित्र जल है, लेकिन यहाँ प्रबन्धन ठीक नहीं है। इसलिए इनकी भी जल समस्याएँ बढ़ रही हैं।

उत्तर-पूर्वी राज्यों के पास आज भी ब्रह्मपुत्र में पर्याप्त जल है और बहुत सी नदियां पानी वाली हैं। पानी की अधिकता होने के बावजूद भी ये राज्य नदियों को जोड़ने के पक्ष में नहीं हैं। बाढ़ यहाँ बहुत कुछ देती है। बाढ़ अपने साथ जहां कुछ तकलीफें लाती है; वहीं मछली, लकड़ी, उपजाऊ मिट्टी-पानी, फसलें और जीवन भी देती है। अब ब्रह्मपुत्र को चीन अपने प्रदेश में मोड़ रहा है। ज्यादातर

पानी ऊपर ही रुकेगा । फिर ब्रह्मपुत्र में भी अधिक पानी नहीं रहेगा । यहां के राजनैतिक दल नदी जोड़ के विरोध में जुटे हैं । उन्होंने यात्रा में बहुत सहयोग दिया ।

उत्तर-पूर्वी राज्य भारत से अलग होना चाहते हैं – ऐसा हमारे राजनेता प्रस्तुत करते हैं । यह ठीक नहीं है । अभी भी यहाँ का समाज अलग देश बनाने के पक्ष में नहीं है । अभी यहाँ पर्याप्त जल उपलब्ध है । अतः यहाँ समाज आज भी पानी बचाने व उसे पवित्र रखने के विषय में बेखबर है । किन्तु चार सौ वर्ष पुराने जयसागर, शिवसागर व गौरीसागर नामक बहुत बड़े टांके यहां देखने को मिले । इन्हें देखकर एक बात साफ हुई कि जहाँ जल है, वहाँ उसका प्रबन्धन करने वाला समाज भी है। तभी तो एशिया का सबसे बड़ा कुण्ड अधिक वर्षा के क्षेत्र असम राज्य में बना। शिवसागर जिला इसी कुण्ड के नाम पर ही बना है। वहां के लोगों ने शहर का नामकरण भी कुण्ड के नाम पर ही किया। यहां एक तरफ वर्षा का आधिक्य है, दूसरी तरफ बड़े-बड़े कुण्ड हैं; जो यह बताते हैं कि पहले पूरा देश पानी सहेजने में एक जैसा ही था । परम्परागत जल प्रबन्धन की विकेन्द्रित व्यवस्था यहां बहुत ही मजबूत थी । अभी वह खत्म हो गई है । इसे पुनः जीवित करने का भाव यहां के समाज में जन्मता दिखाई दिया । जलयात्रा उत्तर-पूर्व में 22 मार्च, 2004 (विश्व जल दिवस) को शुरू होकर 10 मई को डिब्रूगढ़ में ही सम्पन्न हुई ।

जहाँ जल है, वहाँ उसका प्रबन्धन करने वाला समाज भी है। तभी तो एशिया का सबसे बड़ा कुण्ड अधिक वर्षा के क्षेत्र असम राज्य में बना।

राष्ट्रीय जलयात्रा का अगला चरण 18-19 मई को चित्रकूट, बान्दा (उ. प्र.) में सम्पन्न हुआ । सरकार नदी जोड़ परियोजना का शुभारम्भ यहां केन-बेतवा लिंक के कार्य से करेगी। राष्ट्रीय जलबिरादरी ने तय किया कि जब ऐसा होगा, तो जलबिरादरी इसे रोकने हेतु शान्तिमय सत्याग्रह शुरू करेगी। सत्याग्रह की शुरुआत ही राष्ट्रीय जलयात्रा का अगला कदम होगा । चित्रकूट से 20 मई को चलकर यह यात्रा देश के कुछ ऐसे क्षेत्रों में गई, जहाँ पहले नहीं गई थी। समाज की मांग व जरूरत के अनुरूप हमें वहां जाना ही था। 25-26 जून, 2004 को दिल्ली में एक राष्ट्रीय जल सम्मेलन के साथ जलयात्रा सम्पन्न हुई।

लूटनीति से उबरे बगैर पानीदार बनना असंभव

दिल्ली

महात्मा गाँधी जी की समाधि से 23 दिसम्बर, 2002 को श्री सिद्धराज जी भाईसाहब के मार्गदर्शक भाषण से जलयात्रा शुरू हुई । जलयात्रा शुरू करते समय श्री सिद्धराज ढड्ढा ने कहा, ''समाज का पानी पर हक कायम रखने के वास्ते सब मिलकर संघर्ष तो करें, पर साथ ही पानी बचाने के रचनात्मक काम में भी जुड़ें। पानी का मर्यादित उपयोग करें । पानी खरीदकर नहीं पीयें।'' सबसे पहले यात्री दल ने ही बोतलबन्द पानी खरीदकर नहीं पीने का संकल्प लिया । इस तरह देश की नई जल नीति को समाजोन्मुखी और जरूरत पूरी करने वाली बनाने हेतु पूरे समाज को तैयार करने के लिए जल चेतना यात्रा शुरू हो गई।

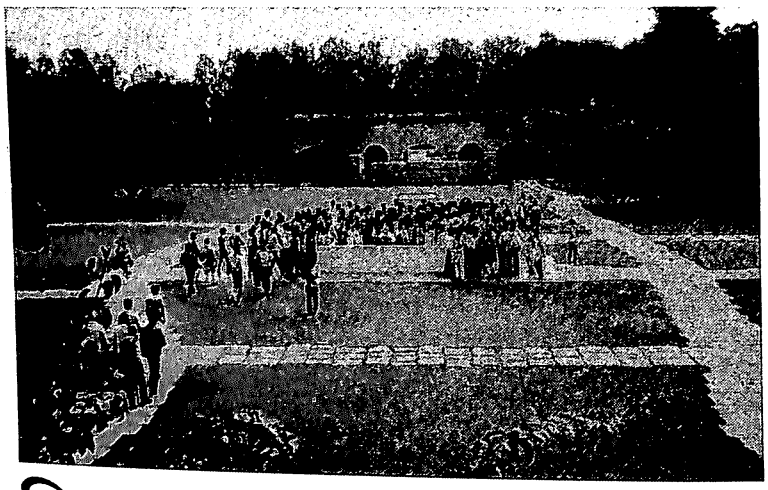

दिल्ली अपने पानी को ही सहेज ले, तो जिंदा रह सकती है। लेकिन दिल्ली के पास सत्ता है, अत: दिल्ली लूट पर निर्भर है।

इस यात्रा के शुभारम्भ के अवसर पर गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान में देश भर की संस्थाओं की एक सभा हुई । सभी ने यात्रा की तैयारी व संचालन में सहयोग का विश्वास दिया। भारत सरकार के वन एवम् पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से जो राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था, उसमें भी जल-जंगल के रिश्ते पर बोलते हुए मैंने कहा ''जल बिना जंगल नहीं हो सकता। इसलिए जल बचाना, जंगल के लिए भी जरूरी है । हम इस यात्रा में जल-जंगल-जमीन को बचाने वाला समाज बनाने का संकल्प लेते हैं।''

दिल्ली में प्राकृतिक जलसंग्रहण क्षेत्रों से नाजायज कब्जा हटाने की जरूरत है।

नई जलनीति में जंगल के सम्बन्ध में एक शब्द तक नहीं है। नदियों के जुड़ने से जंगल व पर्यावरण की बड़ी हानि होगी । इस विषय में कई से सवाल-जवाब हुए। अधिकतर ने नदियों के जोड़ने के भ्रम को तोड़ने का विश्वास दिलाया। जल-जंगल के रिश्तों को जोड़ने की पहल करने पर सरकारी हल्कों में कुछ चर्चा हुई, पर इस मंच पर सरकारी अधिकारियों ने कुछ अधिक रुचि नहीं ली । इस सम्मेलन के आयोजक श्री आशीष कोठारी ने अवश्य बहुत रुचि ली तथा जल, जंगल, जंगलवासी और जमीन के रिश्तों को समझ कर काम करने में रुचि रखने वाली बहुत सी संस्था और संगठनों के मौजूद व्यक्तियों से जुड़ने की अपील की । सभी ने जलयात्रा में साथ देने का वायदा किया।

23 दिसम्बर को दिल्ली में ही जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक अनौपचारिक बैठक रखी । इसमें उनका कहना था कि नदियों के जोड़ने से हम बाढ़-सुखाड़ से मुक्ति दिलायेंगे, नदियाँ जुड़ने से पानी का व्यापार बढ़ेगा और देश की आय भी बढ़ेगी।

मैंने कहा, ''तीन नदियों को जोड़ने का काम बहुत पहले शुरू हुआ था । इन पर जो खर्च हुआ, इसका लाभ कितना हुआ? जिससे अभी तक लाभ नहीं हुआ, आगे सफल होने की क्या गारन्टी है? क्या किसी मुख्यमंत्री ने अब तक अपने राज्य का पानी अधिक बताकर किसी दूसरे राज्य को देने की बात कही या संकल्प जताया है ?'' बस, ये सब सवाल सुनकर सरकारी अधिकारी शान्त हो गये।

इसी दिन दिल्ली में मीडिया के लोगों से मुलाकात हुई । उनकी रुचि भी केवल नदियों के जुड़ने में ही अधिक दिखाई दी । नदियाँ जुड़नी चाहिए या नहीं ? इससे अकाल, सुखाड़-बाढ़ मिट जायेगी ? आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ?

जलयात्रा की तरफ से जवाब था – नदियों को सदानीरा बनाने से ही पानी मिल सकता है, लेकिन नदियों को जोड़ने से ये सदानीरा नहीं बन सकती । नदियों का जुड़ना तो केवल प्रदूषण और भ्रष्टाचार को ही जोड़ना है। नदियों से समाज को

यमुना तटबंध में जल संग्रहण इकाइयों का निर्माण, यमुना जल स्तर सुधार में निर्णायक हो सकता है।

जोड़ना ज्यादा अच्छा है। राजस्थान इसका प्रमाण है। अरवरी और रूपारेल जैसी सूखी नदी को सदानीरा बनाकर यहाँ किसानों ने समाज और प्रकृति दोनों को तृप्त किया है। नदियाँ जोड़ने की बहस मत चलाओ। बहस तो भ्रम है। चुनावी प्रचार जैसा लगता है। इस दुष्प्रचार से सरकारी अधिकारियों को बचना चाहिए। सबको पानी मिले, इस हेतु विकेन्द्रित जल संरक्षण-प्रबन्धन में समाज को लगाने की तैयारी करनी चाहिए। पानी सभी का है; सभी को पानी बचाने में जुटना पड़ेगा, तभी सब को पानी मिलेगा।

दिल्ली के समाज को श्रमनिष्ठ बनाकर पानीदार बनने दो। हर घर की छत से ही पानी बचाना शुरू करें। छत का पानी घर में, घर का पानी परिवार की... घर की जरूरत पूरी करे; धरती का पेट भरे। धरती का पुनर्भरण जरूरी है। हम अपना जीवन चलाने हेतु जितना लेते हैं, उतना ही शुद्ध रूप में धरती को वापस लौटा दें।

पहले हमारा समाज प्रकृतिमय था। वह जितना लेता था, उतना वापस धरती को लौटाता रहा है। आज हम प्रकृति से विमुख हो रहे हैं, इसीलिए यमुना नदी नाला बन गई है। भू-जल भण्डार खाली हो गये हैं। यमुना किनारे पानी का संकट, हमारी जीवन पद्धति में आये बदलाव से पैदा हुआ। अब हम दिल्ली में गंगा का पानी ला रहे हैं। गंगा पर दिल्ली का हक नहीं है। दिल्लीवासी दूसरों के जल अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। दिल्ली अपने पानी को ही सहेज ले, तो जिंदा रह सकती है। लेकिन दिल्ली के पास सत्ता है, अतः दिल्ली लूट पर निर्भर है। अब इस लूट में दिल्लीवासी भी पीछे रह जायेंगे, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस पानी पर कब्जा करके हमारे देश को गुलाम बनाने की तैयारी कर रही हैं।

दिल्लीवासी भारत को गुलाम बनाने का रास्ता बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दे चुके हैं। अभी तो छोटी-सी राह ही बताई है। इस छोटी राह के जरिए दिल्ली ने स्वेज कम्पनी को सोनिया विहार की जलापूर्ति का काम ही नहीं दिया, बल्कि गंगा के बड़े हिस्से पर विदेशी नियंत्रण देकर देश को सन्देश भी दिया है कि पैसे के लिए हम गंगा नदी ही नहीं, देश का सब कुछ बेच सकते हैं। स्वदेशी संस्कृति की रक्षक कहलाने वाली सरकार ने अपने हाथों से हमारे सभी संसाधन दूसरों को दिए हैं। जल जीवन का आधार है। इसका मालिकाना हक दूसरे देश की कम्पनियों को दे दिया, तो फिर हमारे पास क्या बचा? यहाँ पानी की जरूरत पूरी करने का सवाल नहीं है, बल्कि पानी के भोग-विलास का लालच है। दिल्ली में आज भी बड़े-बड़े बंगलों में मात्र 35 पैसे प्रति किलो लीटर में हजारों लीटर पानी मिलता है, जबकि इस पर साढ़े सत्रह रुपये खर्च होते हैं। ग्रामीणों को पानी पर यह छूट नहीं है। ग्रामीणों के लिए किसी तरह की जल सुरक्षा या प्रतिबद्धता सरकार में नहीं दिखती। अमीरों को पानी सब जगह है, गरीब भले तरसते रहें। वर्तमान लोकतंत्र गरीबों का नहीं है, अमीरों का है। गरीबों के हिस्से में केवल पानी बचाने की जिम्मेदारी है, लेकिन जब पेट भरने हेतु अनाज ही नहीं हो, तो पानी भी खरीद कर ही पीना पड़ेगा। दिल्ली के एक सरकारी अधिकारी कहते हैं – ''जब गरीब अनाज खरीद कर खाता है, तो पानी भी खरीद कर पीये।''

दिल्ली में जलयात्रा के अनुभव प्रारम्भ में तो बहुत मीठे नहीं मिले। कहते हैं कि पानी-अनाज-हवा को एक जैसा देखना चाहिए। पानी के व्यापार से दिल्ली को ही सबसे अधिक लाभ बताते हैं। नेता और अधिकारियों की बात एक तरफ तो सच्ची ही लगी; क्योंकि पानी के व्यापार की जड़ें आज दिल्ली में ही हैं। दिल्ली में एक लीटर बोतलबंद पानी के दाम 20 लीटर पानी से बनने वाले एक लीटर दूध के बराबर हैं। एक लीटर दूध गरीब बनाता है, वह 15 रुपये में बिकता है; बड़े पैसे वालों की कम्पनी भी एक प्लास्टिक की बोतल में एक लीटर पानी छानकर 15 रुपये में बेचती है, जबकि इस पानी पर हक इस गरीब का भी है। बड़ी कम्पनी गरीब का पानी बेचकर मुनाफा कमा रही है।

दिल्ली के बंगलों में आज भी मात्र 35 पैसे प्रति लि. में हजारों लि. पानी मिलता है। ग्रामीणों को यह छूट नहीं है।

गरीब के हक का पानी कम्पनी ने बाजार में लाकर बेचा, दूध के भाव। यह

आज बापू होते, तो पानी के व्यापार को रोकने खड़े हो जाते।

'टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, अन्धेर नगरी, चौपट राजा' जैसी बात है। हमारी वस्तु और हम ही पैसा देकर खरीद रहे हैं। गजब मूर्खता है। इसे सरकार पानी का व्यापार बताकर खुश है। हमारे गरीब देश के समृद्ध साधनों पर अमीर कम्पनियों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। इनके कब्जे से अब गुलामी शुरू हो रही है।

आज बापू होते, तो पानी के व्यापार को रोकने खड़े हो जाते। बस ! इसी याद को ताजा करने... बापू की विचारधारा के अनुरूप काम करने हेतु ही उनकी समाधि, नई दिल्ली से राष्ट्रीय जलयात्रा शुरू की। यह जलयात्रा शुरू हुई, पानी की लूट रोकने के लिए। यह जलयात्रा सबका साझा, अपना पानी बनाने की भी यात्रा है। अब चूंकि पानी पर सबसे पहला आक्रमण भी दिल्ली में ही हुआ। याद रहे एक अप्रैल, 2002 के दिन बनी नई जलनीति से यह हमला शुरू हुआ था। इसलिए इसे बदलवाने और रोकने के संकल्प के लिए दिल्ली ही माकूल स्थान लगा।

गंगा जल को हम भले ही अमृत माने, दिल्लीवासी तो इसका उपयोग बाथरूम, शौचालय साफ करने में कर इसके प्रति श्रद्धा का भाव नष्ट करने में जुटे हैं।

दिल्ली को मैंने 33 वर्ष पहले से देखा है। यमुना को तो सात वर्ष की उम्र से देख रहा हूँ। यमुना 40 वर्ष पूर्व जितनी बुरी हालत में थी, आज इसके हालात और भी ज़्यादा खराब हो गये हैं। यमुना की सफाई पर ग्यारह सौ करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी दिल्ली की यमुना और अधिक गन्दी हो रही है। प्रकृति हर वर्ष मानसून में यमुना की सफाई कर देती है, लेकिन हम सब मिलकर वर्ष भर यमुना को केवल गन्दा बनाते रहते हैं। आज यमुना को पवित्र बनाने की बहुत जरूरत है। लेकिन यह रुपयों से नहीं होगा, बल्कि दिल्ली के समाज के प्रयासों से ही होगा।

जिस गंगा जल को हम अमृत मानते थे, यह अमृत जैसा ही था; लेकिन आज दिल्लीवासी गंगा जल को अपने बाथरूम, शौचालय आदि को साफ करने के लिये ही उपयोग करने पर जुटे हैं। इससे गंगा जल के प्रति श्रद्धा नष्ट होगी। दिल्ली सरकार शीघ्र ही यमुना के हैदराबाद की मूसी नदी जैसे नाला बनने की सरकारी घोषणा करने वाली है। आन्ध्र तो नदियों के विषय में अन्धा है, अब दिल्ली भी अन्धी होती जा रही है। दिल्ली ने यमुना को गन्दगी से नहीं बचाया, अब गंगा को भी सुखा कर गन्दा बना देंगे।

यमुना को नदी की जगह नाला बनाने से सरकार को बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। सरकार अब केवल लाभ ही देखती है। अभी तक नदी के नाम से लाभ लिया है; आगे नाले के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करने के लिये मिलेंगे। चूंकि कागज में नाला कहने से सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है।

दिल्ली में राष्ट्रीय जलयात्रा के लिये एक जल सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें निम्न संकल्प लिये। भावी कार्यक्रम भी बने:

1. पानी हमें प्राकृतिक संसाधन के रूप में मिला है। यह हम सबका साझा संसाधन व जीवन का आधार है।

2. समुदाय ही इसका संरक्षण-संवर्धन करे। पानी के सभी अधिकार समाज के हाथ में ही रहें।

3. पानी कोई व्यापार की वस्तु नहीं है।

4. हमारा जीवन... जल धारा यानी नदी के साथ जुड़ा है। जहाँ जैव-विविधता है, वहीं पानी के स्रोत हैं; वहीं जीवन है।

5. वनीकरण हो, इससे दुबारा पानी संरक्षण हो सकता है। जहाँ पानी गिरता है, वहाँ उसका संरक्षण करना चाहिए।

6. पानी की उपलब्धता बढ़ानी है, तो बरबादी में कमी होनी चाहिए। कृषि, उद्योग व शहरों के घरों में बरबादी रोकनी चाहिए। जब जल उपलब्ध ज़्यादा होता है, तो बरबादी ज़्यादा होती है। पानी का पुनर्भरण किया जाना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण तथा पानी के इस्तेमाल की क्षमता दोनों को बढ़ाना होगा। शहरों में पीने के पानी, घरेलू व अन्य उपयोग के लिए जल की अलग-अलग व्यवस्था होनी चाहिए।

सरकार नदियों को जोड़ने की बात कर रही है। यह समाज को मृत्यु के मुख में ले जाने का रास्ता है।

7. पानी की व्यवस्था पुरानी-परम्परागत व शाश्वत है। आवश्यकता अनुरूप ही इस व्यवस्था का नवीनीकरण होना चाहिए। पानी साझा संसाधन होना चाहिए। निजीकरण से बचाने के लिए स्थानीय संसाधन का सामुदायिक प्रबन्धन होना चाहिए।

8. हम पानी के निजीकरण को रद्द करते हैं । इस पर हमारे समुदायों का अधिकार स्थापित करने हेतु हम प्रयत्नशील रहेंगे।

9. पानी ऐसी निजी सम्पत्ति न बने, जो कि बेची या खरीदी जा सके। यह 'वस्तु' नहीं बनाई जाये।

10. जो पानी के निजीकरण की बात करते हैं, हम संस्था व समाज तथा संगठन के माध्यम से उनका विरोध करेंगे।

11. सूखी नदियाँ समाज के द्वारा सदानीरा बनती हैं। पूरे देश में समुदायों ने जो प्रयास किए हैं, वे अच्छे परिणाम ला रहे हैं। पानी के अच्छे उपयोग के बारे में विकल्प आ रहे हैं। इन विकल्पों के माध्यम से सामुदायिक सह-प्रयासों को आगे बढ़ाना है।

12. पानी की गुणवत्ता व उपलब्धता को लेकर प्रस्तुत प्रदूषण व व्यापारीकरण के बाद भी सरकार नदियों को जोड़ने की बात कर रही है। यह समाज को मृत्यु के मुख में ले जाने का रास्ता है। लोगों की आपस में लड़ाइयाँ होंगी। सरकार बिना योजना – बिना अध्ययन के राजनीतिक लाभ के लिए जो काम कर रही है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं।

13. हम यह भी कहते हैं कि यदि ऐसा हो भी, तो लोगों की माँग-सूचना के आधार पर ही नदी जोड़ परियोजना तैयार होनी चाहिए। जहाँ कहीं व्यावहारिक हो, वहीं इस योजना का क्रियान्वयन हो। साथ ही क्रियान्वयन प्रजातांत्रिक हो, स्वतंत्र हो तथा सरकारी एजेन्सी व हमारा समाज ही मिलकर करे। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस योजना में नहीं जुड़ें।

14. जल की बोतलबन्द सप्लाई बन्द की जाय। यह सबसे बड़ा अभिशाप है। पर्यावरण संस्थाओं से अनुरोध है कि बोतल व प्लास्टिकबंद पानी का विरोध करें। इन्हें खरीद कर कोई उपयोग में नहीं लें।

यूं दिल्ली का समाज और सरकार संवेदनहीन सी लगती है, पर दिल्लीवासियों ने भी इस यात्रा में बहुत उत्साह दिखाया। दिल्ली जलबिरादरी के कार्यकर्ताओं ने पांच जून को नई जलनीति को जलाने हेतु जन्तर-मन्तर से रैली शुरू की। संसद् मार्ग पर जलनीति को जलाया। 26 जून को दिल्ली के सभी नौ जिलों में जलनीति बदलवाने हेतु समाज को तैयार किया। नौ स्थानों पर उपवास हुआ। राष्ट्रीय जलयात्रा का अनुसरण व उन्मुखीकरण कार्यक्रम रखा गया। इस जलयात्रा के बाद दिल्ली में जल की मालिकी व जल संरक्षण पर अच्छा संवाद शुरू हो गया है।

दिल्ली में जलयात्रा ने सतत् जल साक्षरता कार्यक्रम बनाया है। दिल्लीवासियों को यह समझाने की जरूरत है कि सोनिया-विहार संयंत्र से उन्हें गंगा का पानी तो मिल जायेगा, लेकिन मोदी नगर-मुरादनगर के किसानों का गला कट जायेगा। हम भी मानते हैं कि पानी पर सबका समान हक है। इसे कायम रखने हेतु सभी को पानी का समान हक तथा समान उपयोग की व्यवस्था बनानी चाहिए। दिल्लीवासी भी भारतीय ग्रामीणों की तरह कम पानी में अपना काम चलायें; एक-एक बूँद जल को प्रदूषित होने से रोकें; बहते, बरबाद होते जल को सहेजने का सत्कर्म शुरू करें, तभी दिल्ली पानीदार बनेगी।

दिल्लीवासियों को तो सोनिया विहार संयंत्र से गंगा-जल मिल जाएगा, पर मुरादनगर-मोदीनगर का गला कट जाएगा।

हमारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की बागडोर सम्भालते ही कहा था – सबको पानी पिलायेंगे, पर इनके काल में बनी जलनीति तो सबका पानी छीन रही है। पानी पर अब विदेशी कम्पनियों का हक कायम हो रहा है। जहाँ राज खुद समाज का पानी छीन कर दूसरों को दे, वहाँ समाज और राज दोनों बेपानी बन जाते हैं।

दिल्ली में माननीय श्री अटल जी का राज कायम होते ही नई जलनीति बनाने की चर्चा शुरू हुई थी। तभी से हम इसे समाजोन्मुखी बनवाने की कोशिश करने लगे थे। 29-30 मई, 2000 तथा 5-6 मार्च, 2002 को दिल्ली में राष्ट्रीय जल सम्मेलन किये। देशभर की सभी पार्टियों को लिखा, लेकिन किसी ने न ही सुना और न ही जवाब दिया। कई सभा-सम्मेलन करके निकल गये।

दिल्ली में माननीय श्री अटल जी का राज कायम होते ही नई जलनीति बनाने की चर्चा शुरू हुई थी। तभी से हम इसे समाजोन्मुखी बनवाने की कोशिश करने लगे थे। जल सम्मेलन किये; देशभर की सभी पार्टियों को लिखा, लेकिन किसी ने न सुना, न ही जवाब दिया।

जलनीति की होली जलाई। इस सबका बहुत असर सरकार पर नहीं हुआ। जलनीति अभी तक वैसी ही है।

फिर पाँच जून को दुबारा पहुँच कर प्रधानमन्त्री जी को ज्ञापन दिया। जलनीति की होली जलाई। इस सबका बहुत असर सरकार पर नहीं हुआ। जलनीति अभी तक वैसी ही है।

अब दिल्ली में नई लोकसभा... नई सरकार बनी है। शायद अब कुछ असर होवे। सब धीरज से सीखते हैं। दिल्ली में अब गंगा-यमुना को माँ की तरह देखना शुरू होवे।

यहाँ का राज और समाज दोनों पानी से सीखें और अपने पानी पर जीयें। यदि महानगर अपने पानी पर जीने लगेगा, तो देशभर का समाज पानीदार बन जायेगा। गंगा और यमुना भी पवित्र माँ बनी रहेंगी।

समझ बढ़े, तो बात बने

हरियाणा

यमुना-सतलुज लिंक नहर का पानी हरियाणा को मिलेगा, ऐसा नहीं लगता; पर तालाब-झालरों का पुनरोद्धार हमें हमारा गौरव दिला सकते हैं।

हरियाणा को जल साक्षरता की बहुत जरूरत है।

19 जून, 2003 से ही हरियाणा में अच्छी वर्षा हुई। इस वर्षा की हरियाली तो सभी जगह देखी, पर यहाँ के तालाबों में प्लास्टिक आदि की गन्दगी भी सभी जगह से अधिक दिखाई देती है। इस राज्य में जलयात्रा ने 23 से 29 दिसम्बर तक, अप्रैल माह में 5 दिन, 8 से 12 जून तक और फिर 28 से 31 जुलाई तक विभिन्न क्षेत्रों में यात्रायें की हैं। यहाँ पानी के दुःख का राज्य है। वर्षा का पूरा पानी यहाँ बरबाद हो रहा है।

23 दिसम्बर, 2002 को दिल्ली के शहरी समाज से निकलते ही गुड़गाँव के ग्रामीण क्षेत्र सोहना, नूंह, फिरोजपुर-झिरका की धरती के नीचे खारा पानी और ऊपर सूखा और वीरान भूगोल दिखाई दिया। इस क्षेत्र में खनन, उद्योगों तथा बाजारू खेती से पानी की कमी आई है। इस वर्ष तो खेत भी खाली और उद्योग भी कम ही चलते दिखाई दिये।

यात्रा महात्मा गाँधी की समाधि राजघाट से शुरू होकर शाम को करीब 8 बजे मेवात के प्रमुख कस्बा नूँह पहुँची। स्थानीय बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की, जिनमें मेवात विकास सभा के श्री दीन मोहम्मद एवम् मेवात विकास मंच के श्री आसिफ प्रमुख थे। बुद्धिजीवियों एवम् पत्रकारों से वार्ता के दौरान 'पानी बचाओ और अरावली बचाओ' पर विशेष जोर दिया। यह सम्मेलन श्री पी. के. खरे द्वारा संचालित स्वयंसेवी संस्था 'नेचुरल केयर' के कार्यालय में हुआ। इस सम्मेलन में देशज प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री महन्त तिवारी एवम् मेवात क्षेत्र के संयोजक श्री इब्राहिम खाँ भी मौजूद थे। यहां जलयात्रा दो दलों में बँट गयी। एक दल मेरे साथ राजस्थान के लिए रवाना हुआ तथा दूसरा दल मेवात क्षेत्र में कार्य के लिए रुक गया।

लोगों में अरावली खनन पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाने से नाराजगी थी, जब उन्हें खनन के सम्भावित भयंकर संकट के बारे में अवगत कराया, तो वे मान गये कि रोक उचित है।

24 दिसम्बर को प्रातः सामूहिक प्रार्थना के बाद अल्पाहार लेकर यात्रा ग्रामीण क्षेत्र के लिए रवाना हो गई। यात्रा फिरोजपुर नमक, चन्देनी, बड़का अलीमुद्दीनपुर, कौराली, बसई खोड़ – (नूँह विकास खण्ड) तथा जुलावट, तावडू, सेवका – (तावडू विकास खण्ड) आदि गाँवों से होकर शाम को नेचुरल केयर के कार्यालय नूँह पहुँची। जिन गाँवों में यात्रा गई, उन गाँवों की ग्राम सभा एवम् महिला समूहों की बैठक में 'पानी बचाओ एवम् अरावली बचाओ' पर चर्चा की गई। हालांकि यहाँ के लोगों में अरावली खनन कार्य पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाने से नाराजगी थी, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग खनन कार्य से आजीविका चलाते थे। जब उन्हें खनन जारी रहते हुए सम्भावित भयंकर संकट के बारे में अवगत कराया, तो वे मान गये कि खनन कार्य पर रोक उचित है। सभी गाँवों के लोगों ने पानी बचाने का संकल्प लिया। जिस गाँव में यात्रा जाती थी, वहाँ पहले से मौजूद नेचुरल केयर एवम् देशज प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं ने गाँव के लोगों से संपर्क कराया। आज की सभाओं में मुख्य वक्ता श्री राज नारायण, श्री छोटेलाल, श्री छाजूराम, श्री इब्राहीम खाँ, श्री पी. के. खरे एवम् श्री महन्त तिवारी थे।

25 की सुबह से ही काफी उत्साह का वातावरण था। यात्रा गाँव मालब – आयस होती हुई गाँव असायसी के नजदीक बड़कली चौक पहुँची। वहां काफी बड़ी सभा जुटी हुई थी। यहाँ रशीद खाँ नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता ने खुशी-खुशी सभी यात्रियों के जलपान का इंतजाम कर रखा था। यात्रा गाँव मरोड़ा – बसई खंजदा में छोटी-छोटी सभाएँ करती हुई खेड़ली कलाँ पहुँची। खेड़ली कलाँ गाँव में काफी बड़ा जुलूस निकला और पानी-पर्यावरण के हक में बुलन्द आवाज में नारे लगे, जिनमें एक नारा यह भी था – 'कहती गीता और कुरान, पेड़ लगाओ हज़ समान'।

इस्लाम ने पानी बचाने के बारे में क्या कहा है ? उसकी चर्चा जरूरी थी। जैसे कि वज़ू में कितना पानी खर्च करना चाहिए?

इसके बाद काली बाड़ी सभा गाँव की चौपाल पर बैठक की गई, जिसमें पानी बचाने के संबंध में इस्लाम के सिद्धान्तों पर रोशनी डाली गई। मेवात के प्रत्येक गाँव में इस्लाम के मानने वालों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए इस्लाम ने पानी बचाने के बारे में क्या कहा है ? उसकी चर्चा जरूरी थी। जैसे कि वज़ू में कितना पानी खर्च करना चाहिए? नमाज़ अदा करने से पहले हाथ, मुँह एवम् पैर धोने की क्रिया को वज़ू कहा जाता है। यहाँ के लोगों ने पानी बचाने के बारे में संकल्प लिया। गाँव की तरफ से श्री जान मोहम्मद ने यात्रियों की आवभगत की। गाँव पापड़ा के निवासी बेसब्री से यात्रा का इंतजार कर रहे थे। यात्रा पापड़ा गाँव में पहुँची। पिनगवा ने गाँव के पुरुष एवम् महिलाओं को एक जगह इकट्ठा कर रखा था। अतः अधिक संख्या में लोगों से संपर्क हो सका। गाँव की तरफ से श्री शौकत खाँ (पूर्व पटवारी) एवम् श्री खलील अहमद ने जल यात्रियों का स्वागत किया। उन्होंने गाँव की तरफ से विश्वास दिलाया कि गाँव का प्रत्येक व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री; पानी का उपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। सभी पानी संरक्षण हेतु हरसंभव प्रयास करेंगे।

यहाँ पर समाज सेवक श्री मो. शाकीर ने सभी यात्रियों को भोजन कराया। यात्रियों ने भोजन और सहयोग के लिए धन्यवाद किया और आगे चल दिए। गाँव तिगाँव, महूँ, सचाला, रवा बफौला, मदापुरा छोटी-छोटी नुक्कड़ सभाओं को सम्बोधित करते हुए गाँव फाटा, शमसरबाद पहुँचे। वहाँ पर तरुण भारत संघ की प्रेरणा से देशज प्रतिष्ठान द्वारा बनाया गया सेवता वाला बाँध देखा। वहाँ देशज प्रतिष्ठान के क्षेत्रीय

सोमेश्वर तालाब चारों तरफ से मन्दिरों से घिरा है। पाँच सौ वर्ष पुराना यह तालाब आज भी आधे शहर को पानी पिला सकता है, लेकिन आज यह कचरे का घर बन गया है।

संयोजक श्री इब्राहिम खाँ ने बाँध की उपयोगिता के बारे में विस्तार से सभी यात्रियों को बताया। रास्ते में पड़े हुए एक कछुए को देख वह अधीर हो उठे। उसे पानी में छोड़ने के लिए गये, ताकि उसके प्राण बच सकें। फिर स्थानीय कस्बा फिरोजपुर-झिरका में शाम को अम्बेडकर चौक पर एक बड़ी सभा की गई। लोगों ने गौर से सुना। तत्पश्चात् यात्रा ने राजस्थान के तिजारा क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया।

तिजारा के पत्रकार खनन दुष्प्रभावों के कारण चिन्तित थे। कम पानी वाली औषधीय खेती के बारे में भी कुछ किसान बात करते नजर आये। यहाँ से चरखी-दादरी तक एक जैसा ही दृश्य था। बीच में कहीं भी पानी नहीं था। यहाँ सिर्फ नहरें ही बेपानी हुई हों, ऐसा नहीं है; हरियाणा का तो पूरा समाज ही बेपानी बन रहा है। चरखी-दादरी के विद्यालय में विद्यार्थी-शिक्षक पानी के लिए बात तो करते हैं, परन्तु पानी के उपयोग हेतु गम्भीर, अनुशासित व संस्कारित नजर नहीं आते। साधु-संन्यासी भी पानी के लिए खुद कुछ करते हुए नजर नहीं आये।

पुराने समय में सभी मन्दिर तालाब के किनारे बनते थे। चरखी-दादरी भी सोमेश्वर तालाब के किनारे ही बना, बसा व बड़ा हुआ। सोमेश्वर तालाब चारों तरफ से मन्दिरों से घिरा है। पाँच सौ वर्ष पुराना यह तालाब आज भी आधे शहर को पानी पिला सकता है, लेकिन आज यह कचरे का घर बन गया है। इसके सूखे रहने से इसके आसपास के मन्दिर व मकान सब सूने-सूने दिखाई दिए। कभी यह पुराने व्यापारियों का केंद्र था। जब ऊँटों से व्यापार होता था, तब सारे ऊँट यहीं आकर ठहरते थे, क्योंकि तब यह एक तरह से पानी का तीर्थ था। व्यापारी और ऊँट इसी तालाब के पानी पर जिन्दा थे। फिर इसके चारों तरफ व्यापारियों ने कुएँ बना लिये। व्यापारी कुएं का और ऊँट तालाब का पानी पीकर अपनी जिन्दगी चलाते रहे। आज कुएं-तालाब सबको बेकार करके लोग ट्यूबवैल, बोरवैल की सप्लाई से टोंटी का पानी पीते हैं। अब यहाँ टोंटी भी सूखने लगी है। भविष्य में चरखी-दादरी का पेट भरने हेतु तालाब बनाने पर फिर जोर देना होगा। यह सब प्रक्रिया श्रम से जुड़ी हुई है। जब यहाँ के लोग मेहनत से तालाब साफ करके इसमें पानी लायेंगे, यह फिर भर जाएगा। इससे धरती का पेट भरेगा; तभी धरती हम सब का पेट भरेगी।

हरियाणा में सतलुज-यमुना का विवाद पुराना बन गया है। इनका पानी हरियाणा को मिलने की सम्भावना कमजोर लगती है, लेकिन हरियाणा का समाज चाहे तो वर्षा जल से धरती और अपना दोनों का पेट भर सकता है।

जब नहर में पानी आता है, तो किसानों में इस पानी को लूटने की होड़ लगती है। पानी की लड़ाई ने यहाँ कई लोगों की जान ले ली।

चरखी-दादरी से भिवानी की तरफ रास्ते में नन्दगाँव में रुके तो यहाँ के संन्यास आश्रम में एक बहुत अच्छा कुण्ड देखा। आज भी खरा है यह कुण्ड। कई सौ साल पुराना यह कुण्ड ओंकारगिरि स्वामी या संन्यासियों को तो पानी पिला ही रहा है, पूरे गाँव के लोगों को भी पानी पिलाता है। मई का महीना भी इस कुण्ड के लिए पानीदार रहता है।

हरियाणा में धरती के पानी की लूट का सही जवाब ऐसे टांके (कुण्ड) ही हैं। तालाब, झालरों से ही यहाँ का जीवन टिका रह सकता है। झालरों की नकल पर बने सरकारी जलघर जगह-जगह दिखाई दिये, लेकिन ये खाली थे। नहर के पानी के इन्तजार में ये जलघर प्यासे ही रहते हैं। जब नहर में पानी आता है, तो किसानों में इस पानी को लूटने की होड़ लगती है। कोई किसान सब्जियाँ और फसलों के सूखते खेतों के लिए नजर गड़ाये बैठा है, तो कोई गन्ने, कपास के लिए। पानी की लड़ाई यहाँ साफ दिखाई दी। यहाँ पानी की लड़ाई में कई लोग मरे भी हैं।

हम नन्दगाँव में एक विद्यालय की छत पर गहरी नींद में सोये, तो रात में हवा के साथ अच्छी बारीक रेत उड़कर आ रही थी। यह गाँव भी जैसलमेर के गाँवों जैसा रेतीली हवाओं वाला है। यहाँ के महिला व पुरुष समूहों के साथ बहुत अच्छी बातें हुईं। इस गांव में परम्परागत जल प्रबन्धन का सफल उदाहरण तथा सरकारी योजनाओं की असफलता के नमूने... दोनों विद्यमान हैं।

यहाँ के परम्परागत तालाब को पाइप लाइन द्वारा जोड़कर नहर के पानी से भरने की कोशिश में लाखों रुपया खर्च कर दिया गया। पाइप में जहाँ से पानी आना है, वह नीचा है। पानी की लाइन उँचे पर डाल दी गई है। इसलिए पानी आज तक तालाब में नहीं पहुँचा। लाखों रुपया खर्च होने के बाद भी नहर का पानी तालाब में नहीं गया। अच्छा हुआ, यहाँ का तालाब आज भी खरा बना रहा... कोई मिलावट नहीं।

नन्दगाँव का तालाब भी मन्दिर के किनारे ही बना है। मन्दिर तालाब के किनारे तालाब की पवित्रता बनाये रखने तथा मरम्मत व देखभाल करने वास्ते बनाया जाता था। मन्दिर में रहने वाले तालाब को भी मन्दिर की तरह तीर्थ मानते थे। जब से हमारे तीर्थ गन्दे होने लगे, तभी से हमारे तालाब भी गन्दे बनते जा रहे हैं। गन्दगी तो बेपानी होती है। नन्दगाँव भी अब तालाब के जलग्रहण क्षेत्र में कूड़ा-कचरा डालने लगा है। वर्षा में यही कचरा तालाब में जाता है। यात्रा के बाद उम्मीद जगी कि अब शायद गांव वाले ऐसा न होने दें। यहां तालाब में नहर का पानी भी मौजूद नहीं है। लोग आरामतलब बन गये हैं। स्वयं कोई मेहनत नहीं करना चाहता। समाज की बेशर्मी बहुत बढ़ी है। बेशर्मी कम होगी, तो ही पानी बढ़ेगा। बेशर्म समाज पानीदार नहीं बन सकता। श्रम और पानी का रिश्ता गहरा होता है। लोग भूल गए कि हरियाणा में कभी बिना नहर के भी पानी था, अब नहर में भी पानी नहीं है।

नांगल-चौधरी के आस-पास 39 गाँवों के कुएं सूख गये हैं। इन सब गाँवों में बदहाली है। इस क्षेत्र में यहाँ के किसानों ने गायों के माथे पर टीका लगाकर खोल दिया। यह दृश्य दुखदायी है।

यहाँ एक स्कूल में जल सम्मेलन हुआ। इसमें नांगल-चौधरी के बहुत से प्यासे किसान आये थे। इनके यहाँ पानी की कमी के कारण पिछले तीन वर्षों से फसल नहीं हुई। उनकी आँखों में पानी तो था, पर अनाज से पेट खाली था। नांगल-चौधरी के आस-पास 39 गाँवों के कुएं सूख गये हैं। इन सब गाँवों में बदहाली है। मैंने सुना था कि राजस्थान-गुजरात में गाय को टीका लगाकर छोड़ देते हैं। गाय के लिए चारा-पानी नहीं होता है, तो इसे अपने घर से खोल देते हैं। अब तो हरियाणा के इस क्षेत्र में गाय भी नहीं रही। यहाँ के किसानों ने भी गायों के माथे पर टीका लगाकर खोल दिया। हरियाणा में मेरे लिए यह दृश्य दुखदायी है। 'हरियाणा' हरियाली का प्रतीक है, लेकिन यहाँ तो सूखा और वीरानगी ही दिखाई दी। हरियाणा का दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान से भी अधिक बदतर स्थिति वाला है। वर्षा जल सहेजकर इसे अवश्य बेहतर बना सकते हैं।

हरियाणा को तत्काल जल बचाने एवम् पुराने तालाबों के पुनरुद्धार में लगना होगा, तभी हरियाणा पानीदार बन सकता है। सतलुज-यमुना विवाद तथा नदियों को जोड़ने की बहस को बढ़ाने से सबको पानी नहीं मिलेगा। हरियाणा-पंजाब जल विवाद निबटायें; नदियों के जुड़ने के सपने देखना बन्द करें। जल संभाल कर सबको पानी पिलायें; तभी हरियाणवी कहलायें।

हरियाणा में एक बड़ा हिस्सा सीलन व रिसाव को सहता है। कुरुक्षेत्र-करनाल तक में यह समस्या है। जल का संकट गहरा है। यहाँ नहरों का रिसाव पानी को नहर के अन्तिम छोर तक पहुँचने नहीं देता। नहरों में एक तरफ जल अधिकता का संकट है, तो दूसरी तरफ सूखा है। ऐसी ही विषमता मानव समाज में भी है। कहीं-कहीं किसान पानी का अति दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे आधा हरियाणा नहरों के जल के बावजूद प्यासा है। ज़्यादा पानी मिलने से आधे से अधिक जमीन खराब हो गई है। आधुनिक जल प्रबन्धन में ऐसी ही कुव्यवस्था है। पुराना जल प्रबन्धन विकेन्द्रित था, इसलिए जल वितरण में बहुत कम विषमता थी। केन्द्रीकृत जल वितरण विषमता ही पैदा करता है। हरियाणा इसका सबसे बुरा उदाहरण है। जल संरक्षण सभी जगह करना पड़ेगा। जो जल उपयोग करेगा, वही वर्षा जल को पकड़ेगा, बचायेगा। फिर सभी को पानी मिलेगा। सभी को पानी चाहिए, तो सभी को बचाना पड़ेगा; तभी पूरा हरियाणा पानीदार बनेगा।

आज के विकसित कहलाने वालों की सोच है कि तालाबों का पानी पीने योग्य नहीं होता है। सौ साल पहले तक बड़े तालाब वाला गाँव ही बड़ा माना जाता था।

जुलाई, 2003 को फिर दिल्ली से निकलते ही सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला का क्षेत्र जलमग्न दिखाई दिया। यहाँ बहुत अच्छी वर्षा हुई थी, पर सब पानी धान-गन्ने के खेतों में रासायनिक खाद की भरमार से सड़ता दिखाई दिया। पानीपत का शहरी व औद्योगिक प्रदूषण भी पानी की सड़न को बढ़ा रहा है। इस राज्य में पर्यावरण का संकट पानी के प्रदूषण से पैदा हो रहा है। यहाँ का पानी प्रदूषण कई राज्यों में बीमारियाँ पैदा कर रहा है। ये बीमारियाँ हरियाणा को पानीदार नहीं बनने देंगी। पानीदार बनने का प्रमाण होता है – पानी सब जगह स्वच्छ, पेय व निर्मल होवे। देश की धरती के ऊपर जहाँ भी जल हो, वह पीने योग्य हो... नहाने लायक हो। ऐसा हरियाणा में दिखाई नहीं दिया, जबकि राजस्थान में आज भी बहुत से तालाबों का पानी सीधे ही पी सकते हैं।

आज के विकसित कहलाने वालों की सोच है कि तालाबों का पानी पीने योग्य नहीं होता है। आज विकास के मापक बदल गये हैं। सौ साल पहले तक बड़े तालाब वाला गाँव ही बड़ा माना जाता था। पिता अपनी बेटी के लिए वैसा गाँव या शहर देखता था, जहाँ पीने के पानी वाला पवित्र तालाब होवे। आज बेटा-बेटी की शादी में तालाब मुख्य नहीं रहा, पैसा और पूँजी मुख्य बन गई है। पानी

और प्रकृति का संकट पैदा करने वाली यही मुख्य समस्या हरियाणा में नजर आयी। नाम हरियाणा है, पर हरा-भरा जंगल कहीं नहीं दिखता। पेड़ भी कम होते जा रहे हैं।

बारह सौ लाख हैक्टर कृषि क्षेत्र में फसलें नहीं पैदा कर सकते। ये सरकारी आंकड़े हैं। हालात तो इससे भी अधिक भयानक और खराब हैं। हरियाणा के गाँवों में भी यही आंकड़ा लागू होता है।

मैं हरियाणा को बचपन से देख रहा हूँ। 39 वर्षों से हरियाणा के करनाल स्थित घरोंडा-ददलाना आदि स्थानों पर बहुत जाता रहा हूँ। मैंने हरियाणा को बहुत करीब से देखा है। अब हरियाणा बहुत बदला है। नये हरियाणा में पानी और पर्यावरण की चुनौती बहुत ही भयानक है। इनका सामना करने हेतु हरियाणा राज्य को बहुत कुछ चुकाना पड़ेगा। अभी समय है। आज से ही इस राज्य की बूँद-बूँद को सहेजें व अनुशासित होकर बूँद-बूँद का उपयोग करें। खेती को उद्योग बनने से रोकें। प्रकृति प्रेमी व मानवीय जरूरत पूरी करने वाली संस्कृति ही हमारी खेती बने। उद्योग-व्यापार के नाम पर केवल लाभ कमाने का धन्धा नहीं, बल्कि सुखी जीवन की जरूरतें पूरी करने में मददगार उद्योग ही पनपें, तभी हरियाणा पानीदार व समृद्ध बनेगा। ऐसा भाव हरियाणा जलयात्रा में बना है।

जलयात्रा की शुरुआत में हरियाणा गये थे, अन्त में अब फिर गये। पहले चरण की शुरुआत और समापन भी हरियाणा में हुआ। पहले चरण के समापन तक 17 राज्यों के 210 जिलों के 1200 ब्लॉकों में स्थित लगभग पाँच हजार गाँवों में गये। हमने घूमते-घूमते 62000 कि. मी. लम्बी यात्रा तय की। इस यात्रा के दौरान हर तीसरा गाँव बेपानी दिखाई दिया। इस वर्ष सरकार ने 52,310 पंचायतों एवम् 1,53,701 गाँवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। बारह सौ लाख हैक्टर कृषि क्षेत्र में फसलें नहीं पैदा कर सकते। ये सरकारी आंकड़े हैं। हालात तो इससे भी अधिक भयानक और खराब हैं। हरियाणा के गाँवों में भी यही आंकड़ा लागू होता है। ये आँकड़े देश में पानी का दृश्य भयावह बनाते हैं।

दूसरा दौर

राष्ट्रीय जलयात्रा के दक्षिण-पश्चिम राज्यों की यात्रा के दो चरण पूरे होने के उपरान्त 19 मई को देश के उत्तरी क्षेत्र की यात्रा का श्रीगणेश हरियाणा के नारनौल शहर से हुआ। नारनौल एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ दोहन पच्चीसी के नाम से जाने

जाने वाले यहाँ के पच्चीस गाँवों ने पानी के संकट के विरोध में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर अपना रोष प्रकट किया था। राजस्थान की सीमा से सटे दक्षिणी हरियाणा में जब जलयात्रा ने प्रवेश किया, तो पहला पड़ाव नीरपुर गाँव में था। यहाँ नागरिक चेतना मंच की अगुवाई में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने यात्रा दल का स्वागत किया। राष्ट्रीय जलयात्रा के पिछले अनुभव और स्थानीय आयोजकों की सलाह पर इस बार यात्रा दल अपेक्षाकृत छोटा रखा गया था। हमारे साथ वर्षों से जुड़े जलकर्मी अर्जुन गुर्जर व कजोड़ी देवी हरियाणा की यात्रा टीम के सदस्य थे। इस टीम ने नीरपुर चौक स्थित बी. एम. हाई स्कूल के प्रांगण में आयोजित जल सम्मेलन में राष्ट्रीय जलयात्रा का मकसद बताया। हरियाणा... विशेषतः दक्षिणी हरियाणा में भूजल स्थिति का आकलन, भावी जल प्रबन्धन एवं रणनीति पर व्यापक चर्चा हुई। जल सम्मेलन में दक्षिणी हरियाणा में उत्पन्न पानी के संकट पर सभी वक्ताओं की चिन्ता स्पष्ट तौर पर उजागर हुई। यात्रा के प्रथम आयोजन में नारनौल के सामाजिक संगठनों द्वारा शहर के दो तालाबों की छँटाई का काम देखकर बेहद प्रसन्नता भी हुई।

दोहन पच्चीसी के पच्चीस गांवों ने पानी के नाम पर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया था।

गौरतलब है कि मुझे गत वर्ष 25 अप्रैल को इन तालाबों की सफाई अभियान का श्रीगणेश करने का मौका मिला था; आज भी हमने एक अन्य ऐतिहासिक बावड़ी की सफाई का शुभारम्भ किया। नारनौल के पड़ाव में स्थानीय विश्रामगृह में पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए यात्रा ने हरियाणा में जल संरक्षण के काम की उज्ज्वल सम्भावनाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की।

नारनौल से जलयात्रा महेन्द्रगढ़ के गाँव सेहलंग पहुँची, जहाँ ग्रामीणों के साथ एक बैठक में अर्जुन गुर्जर ने राजस्थान में पानी को बचाने के लिए किये गये काम का विस्तार से जिक्र किया। 20 मई को प्रातः नौ बजे आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की एक सभा थी। इसमें जलयात्रियों ने नई पीढ़ी से पानी के साथ भावनात्मक रिश्ते कायम करने की अपील की। दो हजार छात्रों की सभा में स्थानीय सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा डॉ. आर. एन. यादव, श्री प्रतापचन्द शास्त्री तथा हरियाणा जलयात्रा के संयोजक व हरियाणा जलबिरादरी के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र यादव ने भी आयोजित पत्रकार वार्ता में विभिन्न राष्ट्रीय व

स्थानीय मुद्दों पर व्यापक बातचीत की। सायंकालीन सत्र में जिला भिवानी के नन्दगांव संन्यास आश्रम में पानी से आध्यात्मिक रिश्ता कायम करते हुए सन्त ओंकार गिरि ने देश में पानी के परम्परागत स्रोतों को बचाने में समाज की भूमिका को रेखांकित किया। यहाँ ग्रामीणों ने वर्षा-जल संचयन पद्धति पर अनेक शंका व प्रश्न किये। देर रात तक भिवानी के विश्रामगृह में आयोजित प्रेस कान्फ्रेन्स में श्री राजेन्द्र यादव के साथ-साथ युवा शक्ति के अध्यक्ष श्री सुरेश राठी भी उपस्थित थे।

21 मई की सुबह शहर के प्रतिष्ठित हलवासिया विद्या विहार में तीन हजार छात्रों के साथ जल संरक्षण पर सार्थक चर्चा हुई। यहाँ कुछ शिक्षकों ने भी पानी के निजीकरण सम्बन्धी अनेक शंकाओं का निराकरण किया। अम्बेडकर युवा क्लब द्वारा ढाण लाडनपुर में नौजवानों के साथ बातचीत की गई। आज की यात्रा का अगला पड़ाव जिला हिसार का एक गाँव था, जहाँ नेहरू युवा केन्द्र और नौजवानों के संगठन द्वारा आयोजित विशाल जनसभा में पानी के काम को लेकर युवाओं में विशेष उत्साह था। सभी ने हरियाणा में पानी का काम करने का संकल्प लिया। यहाँ गाँव के लोगों द्वारा एक बड़ा तालाब बनाया गया है, जो नहर के पानी से भरा गया है। यह तालाब पशुओं को पीने का पानी मुहैया कराता है।

यहाँ गाँव के लोगों द्वारा एक बड़ा तालाब बनाया गया है, जो नहर के पानी से भरा गया है। यह तालाब पशुओं को पीने का पानी मुहैया कराता है।

जलयात्रा के हिसार पहुँचने पर जिला प्रशासन द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। यद्यपि आज हिसार दूरदर्शन टीम सुबह से यात्रा के साथ थी, फिर भी हिसार स्थित दूरदर्शन केन्द्र ने आधे घण्टे का साक्षात्कार रिकार्ड किया। हिसार में राष्ट्रीय जलयात्रा का कार्यक्रम नेहरू युवा केन्द्र तथा जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। प्रथम चरण में जिला हिसार के एक हजार पंच-सरपंच तथा युवा क्लबों के प्रतिनिधियों के साथ जलयात्री श्री अर्जुन गुर्जर ने अपने अनुभव बाँटे। जिला प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों ने हरियाणा में पानी के बदलते समीकरणों की चर्चा करते हुए भविष्य में जल चेतना की आवश्यकता जताई।

यहाँ उपस्थित लोगों को मैंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते हरियाणा के लोगों ने पानी की बर्बादी नहीं रोकी, तो इस खुशहाल कहे जाने वाले प्रदेश के लोगों को भी पानी के संकट से दो-चार होना पड़ेगा। देश भर में जल संकट की स्थिति का चित्रण प्रस्तुत करते हुए मैंने यह भी बताया कि किस प्रकार आन्ध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में किसान आत्महत्या करने को विवश हुए।

हरियाणा की जलयात्रा के दौरान अच्छी बात यह रही कि मीडिया और किसान वर्ग पानी के मुद्दे पर जानने और काम करने के लिए लालायित नजर आया। नारनौल के क्षेत्र में 1600 फुट तक भूमिगत जल समाप्त होने के कारण जमीन में अचानक आई बड़ी दरार भविष्य के अशुभ संकेत दे रही है। हिसार, करनाल और अम्बाला क्षेत्र में सेम के कारण कृषि भूमि बेकार हो रही है। आज हरियाणा का किसान खेती को घाटे का सौदा मान रहा है, जो हम सबके लिए चिन्ता का कारण है। यात्रा के दौरान चार हजार लोगों ने बोतलबन्द पानी न पीने का संकल्प लिया। हरियाणा में जलकर्मियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई।

निश्चय यही बना कि हरियाणा में किसानों तथा उद्यमियों को मिलकर जल बचाने में जुटना पड़ेगा। इस दिशा में जलयात्रा ने एक दृष्टि दी है। जलदर्शन अभी पूरी तरह यहाँ के मानस में बसा नहीं है। इस समाज के मुँह से जलतीर्थ जैसे शब्द कहीं सुनने को नहीं मिले, जलधर आदि शब्द हैं। जब तक शब्दों में जल का भाव नहीं भरेगा, तब तक समाज जल बचाने हेतु खड़ा नहीं होगा।

हरियाणा में जल साक्षरता की बहुत जरूरत है। जल साक्षरता बढ़ेगी, तो यहाँ के किसान अपना फसल-चक्र बदलेंगे। जल का अनुशासित उपयोग होना शुरू होगा। यहाँ जल सहेजने का भाव जगेगा और तभी हरियाणा पानीदार, हरा-भरा बनेगा। अभी तो देखकर लगा कि हरियाणा रेगिस्तान बन रहा है। यहाँ रेत और नंगापन बढ़ता दीख रहा है। हरियाणा जलबिरादरी इसे नंगा होने से रोकने की तैयारी तो कर रही है, लेकिन पूरे समाज की तैयारी से ही सफलता मिलेगी।

आज हरियाणा का किसान खेती को घाटे का सौदा मान रहा है, जो हम सबके लिए चिन्ता का कारण है।

पानी ही प्राथमिकता

राजस्थान

कम साधनों में भी समृद्ध, सन्तोषी और सुखी रहने वाला ठेठ राजस्थानी भी आज कहीं-कहीं पर्यटन और दिखावटीपन की चपेट में है, बावजूद इसके इस राज्य में और जगह की तुलना में गहरा और ज्यादा पानीदार समाज है। विश्वास है कि यह राज्य आगे और पानीदार बनेगा।

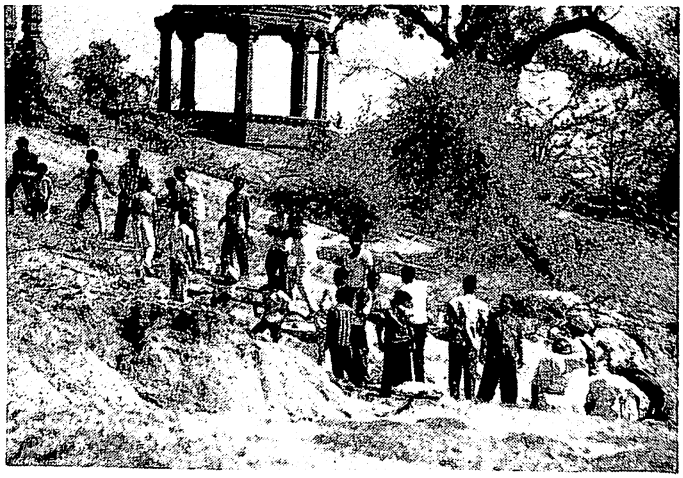

अन्तर्राष्ट्रीय जलवर्ष-2003 के पहले दिन ही जलयात्रा लावा का बास (अलवर) में पहुँची । यहाँ दिनभर एक जल-सम्मेलन चला। देश-प्रदेश के बहुत से सहभागी इसमें आये । सुश्री वन्दना शिवा ने यहाँ एक लम्बी रैली को सम्बोधित कर रवाना किया । इसमें हजारों की संख्या में महिलाओं की उपस्थिति जल के प्रति नारी संकल्प की कथा कह रही थी । यह रैली लावा के बास से चलकर थानागाजी, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, सपोटरा तक गई । वहाँ से गंगापुर होते हुए लालसोट से हम तरुण आश्रम, भीकमपुरा पहुँचे । यहाँ पर 20-23 जनवरी तक राष्ट्रीय महिला जल-सम्मेलन आयोजित हुआ । इस सम्मेलन में कई सक्रिय महिला सम्भागी देशभर से आयीं। उन्होंने मिट्टी के सात मटके पानी से भरकर धरती का पेट पानी से भरने का निर्णय लिया ।

पानी की कमी से महिलाओं का कष्ट बढ़ता है । मीलों दूरी से सिर पर पानी ढोकर जीवन चलाना बहुत ही दूभर काम है । गाँव सभा से लेकर संसद् तक जहाँ भी देखें, पानी की नीति व निर्णय प्रक्रिया से महिलाओं को दूर रखा गया है । पानी के निर्णय महिलाओं के हाथ में आवें; महिलाएँ जल संरक्षण व प्रबन्धन में सक्षम बनकर जुटें; इसीलिए राष्ट्रीय जल बिरादरी द्वारा राष्ट्रीय महिला जल-सम्मेलन का आयोजन किया गया । यह आयोजन तरुण भारत संघ के भीकमपुरा, थानागाजी स्थित तरुण आश्रम में हुआ । यहाँ ग्रामीण और शहरी महिलाओं ने महिला सबलीकरण, पानी का महत्व और समाज व जल के रिश्तों के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इस काम में महिलाएँ गम्भीरता से जुटें तथा जल निर्णय ले सकें, ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश हुई ।

पानी की कमी से महिलाओं का कष्ट बढ़ता है । मीलों दूरी से सिर पर पानी ढोकर जीवन चलाना बहुत ही दूभर काम है । गाँव सभा से लेकर संसद् तक जहाँ भी देखें, पानी की नीति व निर्णय प्रक्रिया से महिलाओं को दूर रखा गया है ।

इस अवसर पर मैंने खुद इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह अति आवश्यक है कि जल से सम्बन्धित हर मामले में महिलाओं की अग्रणी भूमिका रहे, क्योंकि महिलाओं के साथ पानी का अधिक गहरा रिश्ता है । मैंने यह भी कहा कि भारतवर्ष की नदियों को जोड़ने के स्थान पर समाज को नदियों से जोड़ें । धरती के ऊपर की नदियों के स्थान पर यदि धरती के अन्दर की नदियों (भू-जल भण्डारों) को जल संवर्धन के द्वारा भर दिया जाये तो नदियाँ स्वतः जुड़ जायेंगी ।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यू. एन. डी. पी. के भारत प्रमुख श्री मोरीस डवेलफ ने इस मौके पर कहा कि समुदाय द्वारा वर्षा के जल को रोकना आज की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जैसे तरुण भारत संघ ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कार्य किया है, उससे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए।

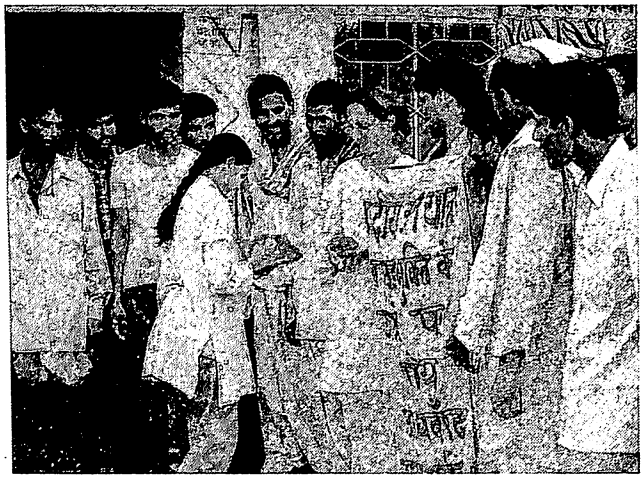

इस सम्मेलन में विभिन्न प्रदेशों से आई अधिकतर ग्रामीण महिलाओं ने अपने-अपने विचार रखे। उन्होंने इस बात पर सहमति जतायी कि महिलाओं का जो बहुमूल्य समय पानी लाने में व्यतीत होता है, पानी की समस्या के सुलझाये जाने पर वही समय अन्य अर्थपूर्ण कार्यों में लगाया जा सकेगा।

समाज, सरकार तथा स्वैच्छिक जन-जल अभिक्रम में समन्वय की कमी में सुधार जरूरी है।

इस अवसर पर सुश्री सुरेखा शाह व सुश्री मधु झुनझुनवाला द्वारा लिखित पुस्तक- ''जोहड़ व महिला की सबलता के मापदंड'' का विमोचन भी किया गया।

सम्मेलन के दौरान पानी से सम्बधित प्रश्नों और राष्ट्रीय जल नीति के निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं पर व्यापक चर्चा एवं सहमति हुई :

1. जल ही जीवन का आधार है और इस नाते जल किसी एक की सम्पत्ति नहीं है, बल्कि समाज का साझा संसाधन है।
2. नदियों के निजीकरण व जोड़ने का विरोध किया गया; नदियों को समाज से जोड़ने का संकल्प लिया।
3. अलग-अलग भू-सांस्कृतिक क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार जनोन्मुखी जलनीति बनाए जाने की मांग की।
4. धरती में पानी का पुनर्भरण किया जाये।
5. जलनीति में महिलाओं को भी अधिकार मिले।

6. पानी के स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखा जाये ।

7. पानी पर समाज का हक कायम रखने हेतु राष्ट्रीय जलयात्रा जारी रहे ।

सम्मेलन के समापन समारोह के दौरान महिलाओं ने अपने-अपने राज्यों में जल बिरादरी के गठन और पानी की समस्या को सुलझाने के कार्यों को जी-जान से पूरा करने का संकल्प लिया। सम्मेलन में आयी महिलाओं का विचार था कि यह सम्मेलन महिला और जल के सम्बन्धों को समझने और सुधारने के सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण शुरुआत है । इन्हीं विचारों के साथ सम्मेलन का समापन हुआ । तरुण भारत संघ द्वारा किये गये कार्यों के अवलोकन के बाद मुख्य अतिथियों को राजस्थानी परम्परा के अनुसार चुनरी ओढ़ाई गई ।

इस सम्मेलन के निर्णयों को जलयात्रा से जोड़ते हुए हम 24 जनवरी को प्रातः भीकमपुरा से चलकर हमीरपुर, समरा, कालेड़, आन्धी, जमवारामगढ़, आमेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर होते हुए अहमदाबाद पहुँचे । राजस्थान की यात्रा में अरावली क्षेत्र और रेगिस्तान क्षेत्र दोनों में भू-सांस्कृतिक विविधता है । अरावली में खनन बन्द होने के कारण हमारी यात्रा के विरुद्ध वातावरण था। पानी की कमी व त्रासदी को रोकने हेतु इस क्षेत्र में खनन को बन्द रखना जरूरी है ।

जहाँ खदानें कुओं से भी अधिक गहरे पहुँच जाती हैं, वहाँ सारा पानी खनन के गड्ढों में इकट्ठा होता है । इस पानी को खनन मालिक बाहर निकाल कर व्यर्थ ही बहा देता है, पर इससे कुएं सूख जाते हैं । तिलवाड़ी, तिलवाड़, पालपुर गाँव के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, इसलिए जगह-जगह सभी सभाओं में ये बातें आती ही रहीं। ठीक दस वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में तरुण भारत संघ ने 'अरावली बचाओ पदयात्रा' की थी । अतः बहुत सारी बातें यहाँ के लोगों को याद थीं। यात्रा के दौरान भी अरावली अधिसूचना को लागू कराने को लेकर बड़ा गहरा तनाव था। अब उच्चतम न्यायालय ने पुनः इसी अधिसूचना को लागू करने का आदेश दिया है। इस कारण पूरे क्षेत्र में हड़कम्प मचा है । राष्ट्रीय जलयात्रा में हमें कई जगह मारामारी के कड़वे अनुभव भी मिले, लेकिन हम तो ऐसे वाकयों के भुक्तभोगी व अनुभवी रहे हैं; अतः धीरज से सब सहन करते हुए आगे बढ़ चले ।

ठीक दस वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में तरुण भारत संघ ने 'अरावली बचाओ पदयात्रा' की थी, इसलिए बहुत सारी बातें यहाँ के लोगों को याद थीं।

अतः राष्ट्रीय जलयात्रा में हमें कई जगह मारामारी के कड़वे अनुभव भी हुए।

इस क्षेत्र में खनन से पूर्व कोई जल संकट नहीं था, राजसमन्द झील कभी सूखती नहीं थी; लेकिन अब यही सबसे पहले सूखती है ।

राहत की बात सिर्फ इतनी दिखी कि अकाल राहत कार्यक्रम के तहत किए गए जल संरक्षण कार्य में पहली बार कोई भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिला।

राजसमन्द में काफी तनाव था । एक तरफ पानी की कमी का संकट, दूसरी तरफ खनन का दबाव। इस क्षेत्र में खनन से पूर्व कोई जल संकट नहीं था, राजसमन्द झील कभी सूखती नहीं थी; लेकिन अब यही सबसे पहले सूखती है । इसका रिचार्ज खनन में चला जाता है। अतः झील खाली होकर सूख जाती है। कुएं सूख जाते हैं। बाहर से पानी लाना पड़ता है ।

इस क्षेत्र में अकाल राहत के लिए अच्छी तरह किए गए जल संरक्षण कार्य पहली बार देखे । इस पूरे काम में कहीं भी कोई भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिला। मस्ट्रोल में फर्जी नाम नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम का अवसर दिया गया। पूरे काम की माप ली जा रही है । सभी काम जल संरक्षण हेतु चल रहे हैं । इन कार्यों से भू-जल पुनर्भरण जरूर होगा। ये बात पूरे राजस्थान में देखने को मिली... जोधपुर में भी और बाड़मेर में भी । सभी जगह इन्हें चलते देखकर अच्छा लगा, पर जैसलमेर के रास्ते में जहाँ-तहाँ हरियाली को सूखते देखकर आश्चर्य भी हुआ। ''पहले तो बोरवैल, ट्यूबवैल में पानी मिल गया, अब सूख गया'' – सब जगह यही सुनने को मिला। जब पानी मिला, तो बेहिसाब दोहन कर लिया; पर जब धरती का पेट खाली हो गया, तो कुएं तो सूखने ही थे... सूख गये ।

यहां पालीवाल समाज ने पानी बचाने के कुछ अच्छे काम किये थे । इनका अच्छा प्रभाव अभी भी दिखता है । भू-संरचना को ठीक से देखकर ही जल संरक्षण के कार्य किये होंगे। ऊपर ताल-तलाई, नीचे पानी देने वाली कुँइयां – यह यहाँ के जल-विज्ञान की अद्भुत समझ है, लेकिन

यह समझ अब व्यवहार में इतनी नहीं दिखाई दे रही है । इस जल ज्ञान-विज्ञान को बचाना जरूरी है ।

बाड़मेर जिले के कई गाँवों में रेत के टीबों को देखने कई पर्यटक आए हुए थे । वे भी हमारी यात्रा में शामिल हुए । यहाँ पर अब गाँव-गाँव पर्यटन केन्द्र बन गए हैं। पर्यटक बोतलबन्द पानी पीते हैं। इनका असर यहाँ के कुछ युवाओं में भी दिखाई दिया। मैंने जब उनसे पूछा, तो कुछ ने बताया – ''यह पानी ताकतवर है; कुछ ने कहा, इससे बीमारी नहीं होती।'' जब उन्हें बताया गया कि यह तुम्हारे गाँव के हैण्डपम्प से भी खराब है और कुछ बोतलों में तो औद्योगिक क्षेत्रों का प्रदूषित पानी है, जिसमें रसायन डाल कर इसके कीड़े मार दिये गये हैं, तो सभी ने इस बोतल के पानी को खरीदकर नहीं पीने का संकल्प ले लिया । खुहड़ी गाँव का जन-जन अब अपने पानी को अच्छा बताने लगा है । अब अपने घर के कुण्डों की बड़ाई करने लगा है । स्वाभिमान बढ़ रहा है ।

जब उन्हें बताया गया कि बोतलबन्द पानी गाँव के हैण्डपम्प से भी खराब है और कुछ में तो औद्योगिक क्षेत्रों का प्रदूषित पानी है, जिसमें रसायन डाल कर इसके कीड़े मार दिये गये हैं, तो सभी ने इस बोतल के पानी को खरीदकर नहीं पीने का संकल्प ले लिया।

यात्रा सेपीथला गाँव भी पहुंची। यहाँ जल संरक्षण की काफी सम्भावनाएँ हैं । मैंने इस गाँव में कहा – ''जब हमें आज़ादी मिली तो देश में 232 गाँव बेपानी थे। वर्ष-2002, मार्च में 90 हजार गाँव और वर्ष-2003 आते-आते बेपानी गांवों की संख्या अब 1,53,701 तक पहुँच गई है।

अब केवल हमारे जैसलमेर, बाड़मेर ही सूखे नहीं हैं; देश के 210 जिले, 1200 ब्लॉक, 1200 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल, 52,310 पंचायतें आज सूखे की चपेट में आ गई हैं। समझ में नहीं आता, कि आज़ादी के बाद हमने करोड़ों रुपया पानी पर खर्च किया पर तस्वीर उलट क्यूं हुई ? लगता है, सब पैसा पानी की तरह ही बह गया । न पानी

बचा और न ही पैसा । सब कुछ ही बहकर समुद्र में चला गया । आज जरूरत है कि पूरे समाज को मिलकर खड़ा होने तथा स्वयं पानी बचाने में जुटने की । हम सभी पानी बचाने में जुटेंगे, तभी पानीदार बनेंगे ।

जैसलमेर के रामदेवरा में तरुण भारत संघ की मदद से सुश्री सुनीता भाटी ने एक तालाब पूरा किया है । यह एक अच्छा तालाब है । इस तालाब के किनारे पंच, सरपंच, प्रधान और ग्रामीणों ने मिलकर यात्रा का भव्य स्वागत किया। कई लोगों ने भविष्य में ऐसा ही काम करने का संकल्प लिया । तत्काल काम शुरू करने की बातें भी कहीं। यहाँ से आगे चलकर रात्रि में कुछ पुरानी खेत तलाई व चिंकारे देखकर प्रसन्नता हुई ।

सोड़ावास गाँव के लोगों का कहना था कि धरती के नीचे यहाँ सरस्वती बहती है। पहले नीचे से पानी निकाल कर खेती करनी शुरू की थी, लेकिन कुओं को अब हर साल 10 मीटर नीचे करना पड़ता है ।

सोड़ावास गाँव में सभा हुई। यहाँ सड़क के दोनों तरफ अच्छी सेवण घास दिखाई दी । रात्रि में जहाँ-तहाँ जीरे के खेत दिखाई दिये । यहाँ के लोगों का कहना था कि धरती के नीचे यहाँ सरस्वती बहती है । पहले नीचे से पानी निकाल कर खेती करनी शुरू की थी, लेकिन अब तो ऐसे कुएँ भी सूख रहे हैं । कुओं को अब हर साल 10 मीटर नीचे करना पड़ता है । कुछ जगह तो नीचे बिल्कुल ही पानी नहीं है। इसका अर्थ है कि सरस्वती नदी में बहने वाले पानी की मात्रा बहुत कम है । इस पूरे पानी को अब नदी से ट्यूबवैल-बोरवैल द्वारा उलीच रहे हैं । इस पर कुछ रोक लगनी चाहिए । इस बात पर सर्वसम्मति तो नहीं हुई, लेकिन कुछ गरीब लोगों का कहना था, बड़े लोग सारा पानी निकाल कर हमें प्यासा मारने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात पर कुछ बहस हुई, इस पर जलयात्रियों ने कहा कि पानी पर सबका समान हक है। इस बात पर सब शान्त हुए । पानी का दुरुपयोग रोकने पर सर्वसम्मति बन गई ।

जैसलमेर खादी परिषद् में बड़ी सभा हुई। इसमें पूरे रेगिस्तान के प्रतिनिधि मौजूद थे। श्री भगवान दास माहेश्वरी जी ने यात्रा का स्वागत किया। इस सभा में पानी और आध्यात्म के रिश्तों पर गहरी बातें हुईं। सभी धर्मों में कम पानी के उपयोग करने के निर्देश हैं। हमें इनकी ठीक से पालना करनी चाहिए।

कुरान में लिखा है- जो इन्सान पानी बचाता है, वह कुदरत की हिफाजत करता है। जो कुदरत की हिफाजत करता है, वह पैगम्बर जैसा है। पानी बचाने की बात केवल शास्त्र में नहीं लिखी, व्यवहार में भी लागू है। नमाज अदा करने में बावन तौले से अधिक पानी खर्च नहीं करते। जो वजू में ज़्यादा पानी खर्च करते हैं, उनकी नमाज अदा नहीं होती। यह बात जैसलमेरवासियों की तरफ से कही गई। यहाँ पुराने मौलवी इस बात का मुस्तैदी से पालन कर रहे हैं।

जो इन्सान पानी बचाता है, वह कुदरत की हिफाजत करता है। जो कुदरत की हिफाजत करता है, वह पैगम्बर जैसा है। पानी बचाने की बात केवल शास्त्र में नहीं लिखी, व्यवहार में भी लागू है।

श्री दीनदयाल ओझा ने कहा, हिन्दू धर्म शास्त्रों में भी जल उपयोग व जल मर्यादा का गहरा वर्णन है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि पानी में हर इन्सान का हिस्सा तय है। वह ज़्यादा जीना चाहता है, तो नित्य जीवन में कम खर्च करे। ज़्यादा खर्च करने वाला, जल्दी मरता है। पहले हमारी यह मर्यादा थी, हम इसका पालन भी करते थे। हमें त्याग कर, ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। हम सृष्टि से जितना लेते थे, अपने श्रम से कम से कम उतना वापस देने की कोशिश भी करते थे। हमारे यहाँ जो लेकर वापस नहीं लौटाये, उसे चोर कहते हैं। जो लेता कम, देता ज़्यादा है, वह महाजन-दाता कहलाता है। आज हम धरती से पानी केवल लेते हैं, देते नहीं; तो हम सभी चोर हैं। सज्जन और महाजन बनने हेतु हमें धरती से लेन-देन सन्तुलित करना होगा।

यहाँ के शिक्षाविद् श्री शोभागमल जी ने कहा - हमारी शिक्षा और व्यवहार बदल गया है। प्रकृति और धरती के प्रति प्रेम समाप्त हो गया है। इसे पुनः बनाना है। इसी से हम अपनी सनातन परम्परा को पुनर्जीवित कर धरती को टिका सकते हैं... सबको पानी पिला सकते हैं। यहाँ पानी की कमी है,

लेकिन अच्छा पर्यटन केन्द्र बनता जा रहा है, पर पानी ही न रहा तो कब तक ...? इस तरह की आकर्षक बातों से ही जैसलमेर शहर सभा में कुछ अच्छे निर्णय हुए।

यहाँ से अगले दिन प्रातः चलकर सुनवड़ा गाँव पहुँचे । यहाँ अच्छी सभा हुई। कई लोग पानी बचाने के इच्छुक दिखाई दिये । हमारे जलयात्री लुकखुर्द गाँव भी पहुँचे। जल बिरादरी, बाड़मेर के सदस्य मास्टर श्री सांगा सिंह जी ने सरकार के साथ मिलकर यहाँ जल संरक्षण का कुछ अच्छा कार्य कराया है। इनकी पहल से बना एक अच्छा एनिकट यहाँ देखा। इसमें गाँव ने मिलकर काम किया था। इसी एनिकट पर बड़ी सभा हुई ।

...तो गाँव वालों ने तुरन्त 70 गाँवों का एक संगठन बनाया और कम्पनी को नदी में बोर नहीं करने दिया। संघर्ष तीन दिन तक चला, लेकिन नदी बच गई।

दोपहर का भोजन कर यहाँ से बाड़मेर शहर होते हुए सांचोर में प्रेस वार्ता की। फिर डीसा, पालमपुर होते हुए हम अहमदाबाद निकल पड़े। 30 जनवरी को प्रातः एक बजे अहमदाबाद, साबरमती आश्रम पहुँच गये। वहाँ स्नानादि करके आठ बजे बापू-कुटी में पहुँच गये ।

राष्ट्रीय जलयात्रा का एक दल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखण्ड, बिहार, उत्तरांचल और दिल्ली होता हुआ फिर राजस्थान पहुँचा । श्री छाजू गुर्जर के साथ जिला दौसा में बड़खेड़ा... बाणगंगा के पास के गाँवों से होते हुए जलयात्रा सिकन्दरा पहुँची । एक कंपनी ने 18.03.2003 को सिकन्दरा के पास बाणगंगा पर 27 बोर करने का तय किया था और बाणगंगा में बोर करने के लिए पाँच मशीनें भी पहुँच गई थीं, लेकिन जब वहाँ के गाँव वालों के साथ जलयात्रा दल ने बात शुरू की, तो गाँव वालों ने तुरन्त 70 गाँवों का एक संगठन बनाया और कम्पनी को नदी में बोर नहीं करने दिया। संघर्ष तीन दिन

तक चला, लेकिन नदी बच गई। श्री अमरसिंह सिकन्दरा, श्री रामफूल कालेड़ और जलबिरादरी के सदस्य श्री छाजूराम जी इस आन्दोलन में मौजूद रहे। उन्होंने वहाँ का भू-जल भण्डार खाली करने वालों से नदी भी बचाई और पानी पर गाँव का हक भी बचाया। भू-जल भण्डार बचाने का यह सफल आन्दोलन जलयात्रा की पहल से ही सम्भव हुआ।

शेखावाटी जलयात्रा में श्री निरंजन सिंह, कर्नल श्री बक्स सिंह, बिग्रेडियर पी.के. भटनागर, बहन अमला रुइया और रघुहरि डालमिया के साझे संयोजन से मीठे अनुभव हुए। हम पूरा शेखावाटी घूमे। शेखावाटी में जल प्रबंधन की समृद्ध परम्परा को देखकर मैं अभिभूत हो गया। विशालकाय तालाब, जोहड़, बावड़ी, चार-मीनार कुएं और सुन्दर टांके... जल मन्दिर के रूप में युग-युग से यहां के लोगों की प्यास बुझाते आ रहे हैं। इस तरीके के जल प्रबंधन के कार्य देश के अन्य हिस्सों में देखने को नहीं मिलते। गत कुछ वर्षों में इन ढांचों के प्रति शेखावाटी समाज में भी उदासीनता आई है। यह बदलाव यहां के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। शेखावाटी के लोगों को जागरूक होकर अपने जल संरक्षण कार्यों को आगे बढ़ाना होगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है।

शेखावाटी में जल प्रबंधन की समृद्ध परम्परा को देखकर मैं अभिभूत हो गया। विशालकाय तालाब, जोहड़, बावड़ी, चार मीनार कुएं और सुन्दर टांके... जल मन्दिर के रूप में युग-युग से यहां के लोगों की प्यास बुझाते आ रहे हैं।

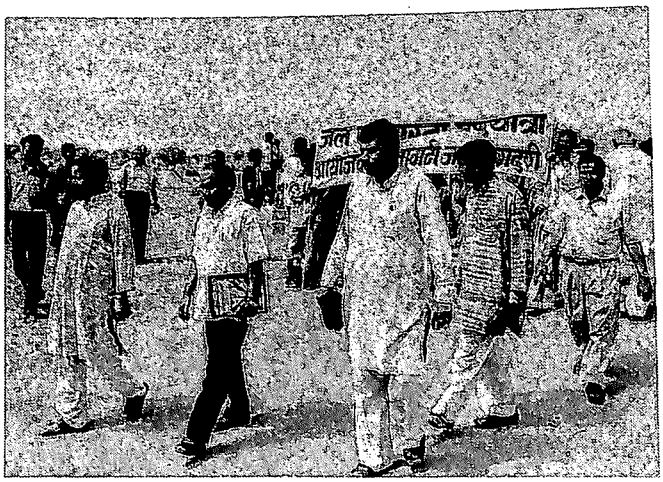

बहन अमला रुइया (रामगढ़-शेखावाटी) और रघुहरि डालमिया (चिड़ावा) जैसे महाजनों ने खुद पहल कर पानी के काम को आगे बढ़ाया है। इस यात्रा के दौरान बदनगढ़ गांव में एक तरफ गांव की बसावट में भरते हुए पानी के रंग हैं, तो दूसरी तरफ घरती का पेट पानी से खाली है; जिसके कारण फसलों की बुवाई और सिंचाई तक नहीं हुई। ऐसे उदाहरण

जगह-जगह मिले, लेकिन राहत की बात है कि शेखावाटी जलबिरादरी ने इस इलाके में जल साक्षरता बढ़ाकर गरीब बेसहारा किसानों के लिए पीने के पानी हेतु कई नए टांके बनाए हैं ।

इस यात्रा में झटावां खुर्द, मीणों की ढाणी, कैकड़ेऊ कलां, मुखा का बास, पालास, नेठवा खोटिंया, देवाब, बुटिया, रामगढ़ शेखावाटी, झुंझुनूं, मण्डावा और चूरू आदि में पानी के सवाल पर समझ बढ़ाने वाली अच्छी सभाएं हुईं तथा यहां पर हुए नये जल संरक्षण के कार्यों को भी देखा । ये कार्य पानी की वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करने में सक्षम साबित हो सकते हैं ।

बामनवास में पिपलाई के पास नदी में भी एक बोर लग रहा था । इसे भी जलयात्रियों ने रोका।

जल साक्षरता यात्रा

पदयात्री आबुसर के कृषि विज्ञान केन्द्र के तालाब से पैदल चलकर झुंझुनूं शहर के सामुदायिक विकास भवन में आयोजित शेखावाटी जल सम्मेलन में पहुंचे । पदयात्रा में शेखावाटी की महिलाओं सहित करीब 1500 लोग साथ थे। लादूसर, ढांढण व चिड़ावा में भी जल सम्मेलनों का आयोजन किया गया । इस दौरान बहुत से लोगों के साथ सीधे बात करने का मौका मिला ।

बामनवास में पिपलाई के पास नदी में भी एक बोर लग रहा था । इसे भी जलयात्रियों ने रोका। जिस कम्पनी के कार्यकर्ता ने यहाँ आकर मशीन लगाई थी, गाँववासियों ने उसका पूरा विरोध किया। चालाक कंपनी ने मीणा समाज के एक किसान के युवा लड़के को नौकरी लगाने का लालच दे दिया और फिर उसी किसान के खेत में बोर लगाई। इस तरह राजस्थान में जगह-जगह पर पानी की लूट के बहुराष्ट्रीय प्रयास दिखाई दिए। इन्हें रोकने की कुछ कोशिश तो हो रही है, किन्तु इन्हें असफल करने में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भी पीछे नहीं ।

राजस्थान में इस वर्ष पंचकालिया सूखे के बाद वर्षा आयी है। अतः बूँदों को सहेजने का काम करना बहुत जरूरी है । जहाँ समाज ने काम किया है, वहीं पर कुछ पानी रुका है ; जहाँ नहीं हुआ, वहाँ बह गया। इस वर्ष राजस्थान सरकार ने भी अकाल राहत में पानी के बहुत काम किए, लेकिन अधिकतर बह गये।

सिंचाई विभाग के बनाये गये बहुत से बाँध टूट गये । अलवर स्थित लावा का बास जोहड़ के ऊपर सिंचाई, वन तथा पंचायत विभागों ने सात बाँध, एनिकट, जोहड़ बनाये थे। वे सब टूट गये। इनके टूटने से इनकी मिट्टी, पानी बहकर लावा का बास जोहड़ में एक साथ आ गई। इससे लावा का बास का जोहड़ भी टूट गया।

इसी तरह सरकार का समरा सागर लाखों या करोड़ों रुपयों का बना था। यह भी 19 जून को पहली वर्षा में ही टूट गया। इससे नीचे अरवरी नदी पर बने हमीरपुर, समरा और कालेड गाँव के एनिकटों को भी बहुत नुकसान पहुँचा। सिंचाई विभाग का दायित्व है कि वह इन्हें दुबारा बनवाए। शायद सिंचाई विभाग इन्तजार कर रहा है कि ग्रामीण संगठित होकर पुनःनिर्माण हेतु मांग करें... जन आन्दोलन करें, तब वह काम शुरू होगा । थानागाजी के लोग तो अपने पसीने से जोहड़ बनाते रहे हैं। इनके जोहड़ को सरकारी जोहड़ों के दबाव ने ही तोड़ा है, किन्तु अब इनके पुनःनिर्माण हेतु आन्दोलन तो समाज को ही करना पड़ेगा।

आज राजस्थान सरकार पानी के नाम पर अच्छा करने का संकल्प तो ले रही है, पर धरती पर इसके विपरीत ही काम दिखाई दे रहा है । सरकार को समाज के कार्यों में सहयोग करना ही चाहिए।

लावा का बास के लोगों ने 28 जुलाई, 2003 को तरुण आश्रम, भीकमपुरा में आकर सरकार से अपना जोहड़ बनवाने की मांग उठाई। सरकार को देवउठनी ग्यारस तक का समय दिया । सरकार ने यदि देवउठनी ग्यारस तक काम शुरू कर दिया, तो ठीक है, अन्यथा थानागाजी के सब लोग जनान्दोलन करेंगे। ऐसा तय हुआ है। 31 जुलाई को थानागाजी के मन्दिर में लावा का बास व थानागाजी के समाज ने एक सम्मेलन बुलाया । इसमें 7-8 गाँवों के लोग आये। जलयात्रा भी यहाँ पहुँची। सभी ने मिलकर लावा का बास का जोहड़ पुनः बनाने हेतु सरकार पर दबाव डालने का निर्णय लिया ।

आज राजस्थान सरकार पानी के नाम पर अच्छा करने का संकल्प तो ले रही है, पर धरती पर इसके विपरीत ही काम दिखाई दे रहा है । सरकार को समाज के कार्यों में सहयोग करना ही चाहिए। समाज के द्वारा किये कामों को प्रोत्साहित करना जरूरी है । इसी से समाज की जल संरक्षण में वास्तविक भागीदारी सम्भव है । सरकार का नारा 'खेत का पानी खेत में - गाँव का पानी गाँव में' तभी सफल

होगा। सिंचाई विभाग की प्रतिबद्धता राजस्थान सरकार के साथ होनी चाहिए, किन्तु आज सिंचाई विभाग और सरकार अलग-अलग राग अलाप रहे हैं। सरकारी विभागों के परस्पर विरोधी अलाप ही हमारे पानी बचाने की चेतना को कम करते हैं; लोगों की हिम्मत को तोड़ते हैं।

घग्घर में बाढ़ – रिसाव आदि समस्या पैदा करने वाले जल को धरती के पेट में डाल कर हम राजस्थान के भूजल भण्डार भर सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर के कारण खारी बन रहे रेगिस्तान को भी रोक सकते हैं; पर सरकार सजग नहीं है ।

राजस्थान में विकेन्द्रित जल प्रबन्धन व जल की जरूरत पूरी करने वाली जनोन्मुखी जल नीति राजस्थान में बननी चाहिए। साथ ही हमारे प्रदेश का बहुत सारा पानी व्यर्थ बहकर पाकिस्तान में बाढ़ पैदा करता है, इसे रोकना चाहिए। घग्घर में बाढ़ – रिसाव आदि समस्या पैदा करने वाले जल को धरती के पेट में डाल कर हम राजस्थान के भूजल भण्डार भर सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर के कारण खारी बन रहे रेगिस्तान को भी रोक सकते हैं; पर सरकार सजग नहीं है । राजस्थान के भविष्य को सुरक्षित व पानीदार बनाने हेतु इसे प्रथम काम मान कर सरकार को करना चाहिए, तभी राजस्थान का समाज... सरकार से जुड़ेगा। आज पूरे प्रदेश में समाज की प्राथमिकता पानी है । ऐसा तो दिखाई देता है, पर पानी सरकार व राजनीतिक दलों की प्राथमिकता बने, तो बात है।

राजस्थान जलयात्रा अरावली और रेगिस्तान में दो भिन्न दलों में चली। दोनों क्षेत्रों में जल निधि की भिन्नता तो है, लेकिन जल दर्शन समान ही मिला। हमारा राजस्थान आज भी देशभर में पानी प्रेम में अग्रणी है। यहाँ वर्षा जल सहेजने का भाव आज के जल संकट का जवाब दिखाई देता है; जबकि दूसरे राज्यों में धरती से पानी निकालना, पाइप लाइन, नहर, बड़े बाँध और नदियों से पानी उलीचना आदि बातें अधिक सुनने को मिलती हैं।

राजस्थान को देखकर एक विश्वास जन्मता है कि हमारे प्रदेशवासियों का जल-प्रेम दुनिया के जल संकट के समाधान का रास्ता बन सकता है । हम जितना जल प्रकृति से लेते हैं, कम से कम उतना पानी अवश्य धरती को दें । ऐसा भाव-बोध यहाँ बना हुआ है । इसे बनाए रखने में सरकार अपनी भूमिका समझे । सिंचाई विभाग वर्षा की बूँद-बूँद का मालिक बनने का विचार छोड़ दे। हमारा समाज,

पेड़-पौधों तथा नदी-नालों को पानी का अधिकार दे। नदी-नालों पर इस प्रकार की जल संरचनाओं का निर्माण करे, जिनसे नदी-नाले सदानीरा बने रहें। जोहड़, तालाब, चैक डेम, एनिकट, नाला-बन्ध, खेत-तलाई, मेढ़बन्दी जैसी छोटी-छोटी जल संरचनाओं से नदी-नाले सदानीरा बनते हैं; कुओं का जल स्तर ऊपर आता है; खेती में रोजगार बढ़ता है; लड़कियों को भी शिक्षा का समान अवसर प्राप्त होता है। ऐसा इन सभी जगह देखने को मिला। जहाँ कहीं समाज ने स्वयं जल बचाने का काम किया है... वहाँ राजस्थान के अकाल में भी पानी है। शेष जगह सूखा और पलायन है। आज़ादी के बाद हजारों करोड़ खर्च करके भी आज तक अकाल मुक्ति नहीं हो पायी। यह एक नीतिगत समस्या है।

राजस्थान जलयात्रा बहुत उत्साहजनक रही। अरावली, विन्ध्य (हाड़ौती), थार-रेगिस्तान के सभी क्षेत्रों में जाकर हम पानी बचाने के काम में सभी को जोड़ सके। यहाँ के जल संरक्षण की विविध समस्याएँ हैं। सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र में नये बोरवैल अस्थाई व दिखावटी हरियाली पैदा कर रहे हैं, किन्तु इनसे इस नदी का अधो-भूजल सूख रहा है। शुरू में पानी मिलता है, फिर सूख जाता है, इस बदलाव से सेठों-कम्पनियों को जरूर फायदा हो रहा है, लेकिन इस क्षेत्र के किसान लुट रहे हैं। इस लूट को रोकना जरूरी है, अन्यथा देश, धरती का पानी और पैसा बड़ी कम्पनियां ही लूट लेंगी।

इस क्षेत्र में अब तेल मिलने से बड़ी कम्पनियां सब तरह की लूट में लग गई हैं। तेल की खोज तो हमारी सरकारी कम्पनियों ने की थी, पर अब इसका लाभ विदेशी कम्पनियाँ उठायेंगी। इसे रोकना जरूरी लगता है। रेगिस्तान में तेल मिलना शुभ है, पर इसका लाभ राजस्थान के समाज को मिले। आज जिस तरह से काम चालू है, इससे तो राजस्थान लुटता ही नजर आता है। तेल कीमती है;

रेगिस्तान में तेल मिलना शुभ है, पर इसका लाभ राजस्थान के समाज को मिले। आज जिस तरह से काम चालू है, इससे तो राजस्थान लुटता ही नजर आता है।

इन्दिरा गान्धी नहर और खनन... दोनों ने ही उल्टे काम किये हैं। खनन ने कुएं सुखाये; खेती बन्द कराई। इन्दिरा गान्धी नहर से जल जमाव बढ़ा; खेती बदली; जीवन बदला, लेकिन अशान्ति बढ़ी और सतत् आय घटी।

लेकिन पानी को अधिक कीमती मानकर संरक्षण हो और हमारे समाज को इसका लाभ मिले। ऐसी व्यवस्था बनाना हमारी सरकार का दायित्व है।

नदी-जोड़ से पानी मिलेगा... इसका इन्तजार न करें। राजस्थान का समाज पूरे प्रदेश में ऐसे जल सहेजे, जैसा कि भांवता गाँव ने सहेजा है। इस तरह के सामुदायिक कार्यों को बढ़ावा देने वाली जलनीति बने। जल कानून बने। यहाँ सभी किसान भूजल भण्डार को अपना निजी व भूतल जल को साझा मानते हैं, जबकि दोनों ही जल साझे हैं। साझे काम मिलकर करने पड़ते हैं। साझे काम के संस्कार इस प्रदेश में कहीं-कहीं और बढ़ाने की जरूरत है। कहीं-कहीं इसका अभाव दिखा, जैसे अरावली क्षेत्र में खनन ने जल-जंगल-जमीन को वीरान बनाया। जहाँ भी गये, खदानें चलती मिलीं। इनके कारण कुओं का जल सूखा मिला।

इस प्रदेश में आज़ादी के बाद विकास के नाम पर इन्दिरा गान्धी नहर और खनन ही मुख्य हैं। इन दोनों ने ही उल्टे काम किये हैं। खनन ने कुएं सुखाये; खेती बन्द कराई। इन्दिरा गान्धी नहर से जल जमाव बढ़ा; खेती बदली; जीवन बदला, लेकिन अशान्ति बढ़ी और सतत् आय घटी। दोनों विकास योजनाएँ विनाश के रास्ते पर चल पड़ी हैं।

शहरों व गांवों में पानी के असमान वितरण, प्रदूषण तथा व्यापार पर नियंत्रण जरूरी है।

राजस्थान हमेशा से ही पशुपालन और हस्त-उद्योग का केन्द्र रहा है। यह कभी कम साधनों में सुखी, समृद्ध, सन्तोषी और सम्मानित... कुशल इन्सानों का राज्य था; आज यह सब बदल कर पर्यटन और दिखावटी दिल वाला राज्य दिखाई दिया। पुराना पानीदार परम्परा वाले राजस्थान को हमने अपनी यात्रा की सभी सभाओं में पानीदार बनाने की कोशिश की। इस पूरे राज्य की आँखों और दिल में सब जगह पानी दिखता है। आशा है, यह राज्य पानीदार बनेगा। ऊपरी पानी वालों से तो इसमें गहरा और ज़्यादा पानी है।

अंधी दौड़ में शामिल प्रदेश

गुजरात

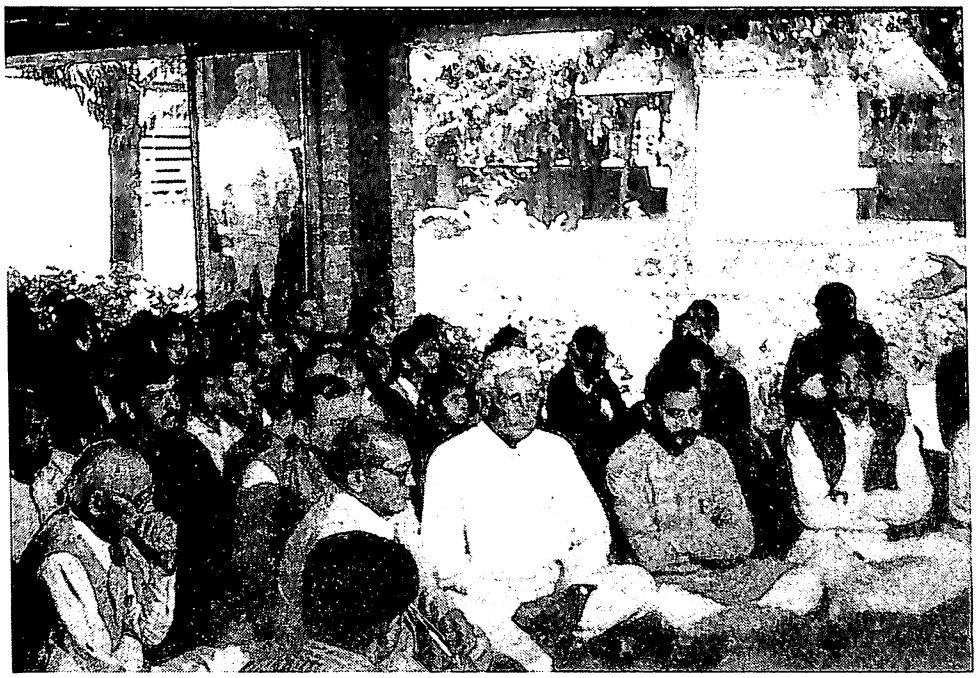

बापू के इस प्रदेश में प्रकृति प्रेम, अहिंसा और सद्भाव की जगह समाज, सम्प्रदाय और पानी का व्यापारीकरण हावी है।

यूं तो गांधी का दर्शन अब भौगोलिक सीमाओं में बंधा नहीं है, पर गुजरात उनका मूल प्रदेश तो है ही । सोचा था कि प्रकृति से प्रेम के अनुपम उदाहरण यहां अवश्य देखने को मिलेंगे, पर जब साबरमती, बनास और हरणाव नदी के स्थानीय किसानों ने कहा कि हम ने पानी और चारे का ऐसा संकट पहले कभी नहीं देखा, तो हम निराश हुए । उन्होंने कहा कि उनके जीवन में यह पहला मौका है कि न खेत में पानी है और न ही कहीं चारा । उनके पशु भूख और प्यास से मर रहे हैं। सरकार मदद के नाम पर जो कुछ भी कर रही है, वह तो बस दिखावा है । वे पानी बचाने के लिए जो जगह सरकार को बताते हैं, उसे सरकार के इंजीनियर उचित नहीं मानते; क्योंकि जगह को लेकर अपनी मर्जी के अनुसार भ्रष्टाचार करने व अपनी जेब भरने का लालच उनके मन में होता है ।

सरकार के अधिकारियों ने बाजारू फसलें और अनाज पैदा करने के लिए किसानों को उत्प्रेरित किया था। किसान मानते हैं कि उन्होंने बहकावे में आकर रासायनिक खाद, संकर बीज व कीटनाशक दवाइयों से अपनी लूट खुद करवाई और इसके साथ-साथ धरती के पानी को खींचकर भू-जल भण्डार भी खाली कर दिए। पानी का सोच-समझकर उपयोग करने की अपनी पुरानी परम्परा को वे भूल गये। सरकारी अफसरों व नेताओं के जाल में फँस कर आज गुजरात भी बेपानी बन गया है, पर अच्छा यह रहा कि कुछ गंवा कर अब गुजराती किसान सीखने लगे हैं। जल यात्रियों से हुई लंबी चर्चा ने असर डाला है। किसान कम खपत वाली फसलें उगाकर सजीव खेती तथा जल संरक्षण को संकल्पित हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं ने भी अपने क्षेत्रों में जल बचाव के कार्य की मुहिम खड़ी करने व जन-जागरण का संकल्प लिया। कहा कि जिन गाँवों में समाज ने पानी के अच्छे काम किये, उन कार्यों को समाज को दिखाकर हम उन्हें प्रेरित करेंगे। हम गुजरात राज्य सरकार की जल-नीति बनवाने में अधिक से अधिक लोक सहभागिता एवं जल लोकाधिकार की बात करेंगे, जिससे जन आवश्यकताओं के अनुसार जल संरक्षण की पुरानी पद्धतियां पुनः खड़ी हों और राज्य में पानी का संकट न रहे।

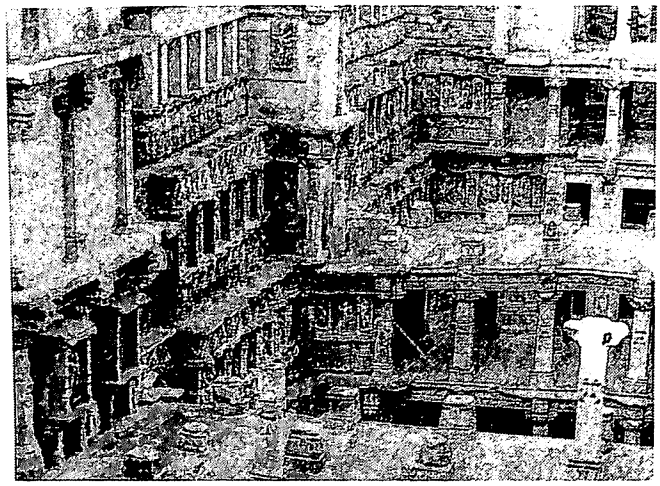

...लेकिन अच्छा यह रहा कि कुछ गंवा कर अब गुजराती किसान सीखने लगे हैं।

गुजरात में जल संरक्षण हेतु तत्काल एक जनान्दोलन खड़ा करना जरूरी है। गुजरात राज्य की स्वैच्छिक संस्थाओं को साथ लेकर जल, जंगल, जमीन के संरक्षण को पहली प्राथमिकता बनाना हमारा निश्चय है। अब हम अगले 10 वर्ष केवल प्रकृति के संरक्षण-संवर्धन में लगायेंगे। समाज के हक को बनाये रखते हुए समाज व सरकार को जोड़कर काम करेंगे।

पानी सबका साझा है और साझे से ही इसका बचाव व प्रबंधन सम्भव है। सरकार

हमें बाँटती रहती है और अधिकारी लोगों के बीच फूट डालकर अपनी मनमानी करते रहते हैं। अब हम भी स्वार्थी बन गए हैं। अपने स्वार्थ में हम साझे भविष्य को भूल जाते हैं। इस यात्रा से हम यह सीख ले रहे हैं कि सबके साझे भविष्य को सुधारने का काम साझा मिलकर कैसे हो सकता है और इसे कैसे करेंगे? इसके लिए हम सभी को पानी बचाने का काम तुरंत ही शुरू करना होगा।

विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने कहा कि हम अपने विद्यार्थियों को पानी व जंगल बचाने के कार्य में लगायेंगे। विश्वविद्यालय में चलने वाली राष्ट्रीय संचय योजना के अंतर्गत तालाबों का निर्माण एवं मरम्मत के नये कार्य शुरू करेंगे। अपने विद्यार्थियों को अपने घर की छत से पानी रोकने का कार्य शुरू करने का भी निर्देश देंगे।

इस यात्रा से हम सीख रहे हैं कि साझे भविष्य को सुधारने का काम साझा मिलकर कैसे हो सकता है ?

पत्रकारों ने यात्रा दल से कहा कि हम पानी के सम्बंध में सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने और समाज को पानी बचाने के कार्य हेतु उत्साहित करेंगे। नागरिकों द्वारा जल बचाने के लिए किये गये कार्यों को समाज व सरकार के सामने अधिक से अधिक उदाहरण देकर लिखेंगे। विद्यार्थियों ने संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में जितना पानी उपयोग करेंगे, कम से कम उतना तो अपनी मेहनत और कमाई से वर्षा की बूंदों को इकट्ठा करके धरती माता का पेट भरेंगे। गुजरात के विभिन्न किसान संगठनों ने कहा कि कुएँ, बोर वैल और ट्यूब वैल के लिए जो लाइसेन्स व्यवस्था बनाई जा रही है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हम गुजरात राज्य की जलनीति को किसानों के हित में बनवाने के लिए कोशिश करेंगे। इस तरह सभी ने आश्वस्त किया।

उन्होंने यह भी कहा कि अब हम बाजारू खेती के बजाय सजीव व स्वावलम्बी

खेती को बढ़ावा देंगे और पानी बचाने के लिए सरकार से मदद लेकर किसान संगठनों को मजबूत बनायेंगे। हमारा मानना है कि नीति ऐसी हो, जो किसान जितना पानी खेती में उपयोग करता है, उतना ही पानी बचाये और जो पानी बचाने से ज़्यादा खर्च करता है, उससे अतिरिक्त जल खर्च वसूला जाये। जो लोग पानी बचाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाये। पानी के लेन-देन की समान व्यवस्था बनाने की कोशिश जरूरी है।

पशुपालन के बारे में मालधारियों से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि परम्परागत तरीके न अपनाने से पानी संकट बढ़ गया है और इस संकट के कारण हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जिसे सुधारने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे क्षेत्र में तालाब व पशुओं के लिए चरागाह की व्यवस्था करवाये। यदि यह काम सरकार ने समय रहते न किया, तो पानी के साथ दूध का भी संकट हो जायेगा। पानी के संकट के कारण हमारी गाय-भैंसें प्यासी मर रही हैं। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी पशुओं को पीने का पानी उपलब्ध कराए।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने बोतलबन्द पानी को दस रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने की इजाजत दी है, तो दूध सौ रुपये प्रति लीटर की दर से बिकना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हम सरकार पर दबाव डालेंगे कि दूध की कीमत पानी से दस गुना अधिक होनी चाहिए। यदि सरकार ने बोतलबन्द पानी को दस रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने की इजाजत दी है, तो दूध सौ रुपये प्रति लीटर की दर से बिकना चाहिए। पानी के भाव दूध खरीदने वाली सरकार अन्याय कर रही है। एक गाय दिन भर में पचास लीटर पानी पीकर पाँच लीटर दूध देती है। इसके साथ-साथ इसके रख-रखाव पर भी कई गुना अधिक पानी खर्च होता है। मैंने समझाया कि दूध महंगा हो न हो, पर पानी महंगा क्यों हो ? यह तो प्रकृति का है, यदि हम इसका प्रबंधन करें, तो इस पर हक भी तो हमारा ही होना चाहिए।

व्यापारी संघ का यह मानना था कि पानी की कमी के कारण उनका व्यापार ठप्प हो रहा है । पिछले दो वर्षों से खरीद-फरोख्त बहुत घट गई है । पानी के हालात अगर ऐसे ही रहे, तो व्यापार खत्म हो जायेगा । जगह-जगह पानी का व्यापार होने के कारण नदियाँ सूख गई हैं। वे सभी चाहते हैं कि इन सूखी नदियों को जीवित करने के लिए जल बचाने का काम जल्दी शुरू हो।

जब सरकारी वन अधिकारियों ने बड़े उत्साह से जलयात्रियों का स्वागत किया, तो हमें सन्तोष हुआ कि चलो, इनका मानस भी पानीदार रास्ते पर चल पड़ा है।

जंगलात के अधिकारियों ने हमें बताया कि सूखे और अकाल के कारण जंगल में आग लगने के खतरे बढ़ गये हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जंगल घटते जा रहे हैं। जंगलों के घटने के कारण पानी के पुनर्भरण का गंभीर सवाल खड़ा हो गया है । कुछ जगह तो जंगल के पेड़ भी सूखने लगे हैं। पशुपालकों ने चारे की कमी के कारण पेड़ों की कटाई करके, जंगल के लिए एक और नया संकट पैदा कर दिया है । जब सरकारी वन अधिकारियों ने बड़े उत्साह से जलयात्रियों का स्वागत किया, तो हमें सन्तोष हुआ कि चलो, इनका मानस भी पानीदार रास्ते पर चल पड़ा है। उन्होंने यह भी कहा – "इस यात्रा में जल, जंगल व जमीन बचाने की जो बातें हो रही हैं, इससे हमारे प्रदेश में जंगल बचाने का एक अनुकूल वातावरण बनेगा एवं हमारे विभाग के साथियों को भी समझ में आएगा कि यह पानी बचाने का काम जंगलों के लिए बहुत जरूरी है । पानी के बिना जंगल का बच पाना मुश्किल है।"

अमेरिकन और इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी ने कहा कि इस जलबिरादरी की यात्रा से जल की शुद्धि व व्यवस्था संबंधी मार्गदर्शन मिलेगा । डॉक्टर मरियन मानते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी को बचाने और रोगमुक्त रखने के लिए जल की शुद्धता का कार्य अत्यन्त आवश्यक है । इस यात्रा में भागीदार रहकर उन्हें भी जल का दर्शन और सामाजिक तकनीक समझ में आई, जो कि पानी बचाने के कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

दरअसल पर्याप्त शुद्ध जल की व्यवस्था होने पर ही हमारे भविष्य को उज्ज्वल रखा जा सकता है। शुद्ध जल की कमी के कारण ही अधिकतर बीमारियाँ होती हैं, इसलिए पीने योग्य शुद्ध जल की व्यवस्था करने में इस जलयात्रा द्वारा पैदा की जा रही चेतना का कुछ अंश उन्हें भी प्रभावित कर गया। ज़्यादातर डॉक्टरों का मानना था कि साफ पानी के नाम पर अभी तक हम बिना सोचे-समझे धरती से पानी निकालते रहते थे। यूनिसेफ भी बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण के नाम पर बोरवैल, ट्यूबवैल लगाने का कार्य कर रही है। इसका परिणाम क्या होगा ?... शायद अब वे इस पर पुनर्विचार करें।

यहां इस यात्रा से जुड़े सदस्यों के सुझाव निम्न प्रकार से हैं:

1. इब्राहिम भाई (हरियाणा)

इब्राहिम भाई का सुझाव था कि उत्तरी गुजरात के भारत-पाक सीमा के निकट गाँव में जल की समस्या विकट है। वहाँ पर जंगल के नाम पर सिर्फ बबूल था। वहाँ पर जन जागरूकता की भी कमी है तथा अब तक पानी के जो कार्य हुए हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं।

2. राजा गोपालसिंह

(पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान)

आपके अनुसार गुजरात के किसान पानी के मामले में मेहनती व जागरूक हैं। किसानों को भूमि व जल संरक्षण के बारे में पता तो है, पर उन्हें एक मार्गदर्शक की जरूरत है। यह यात्रा एक उत्प्रेरक के

रूप में ऐसे लोगों के लिए सहायक होगी।

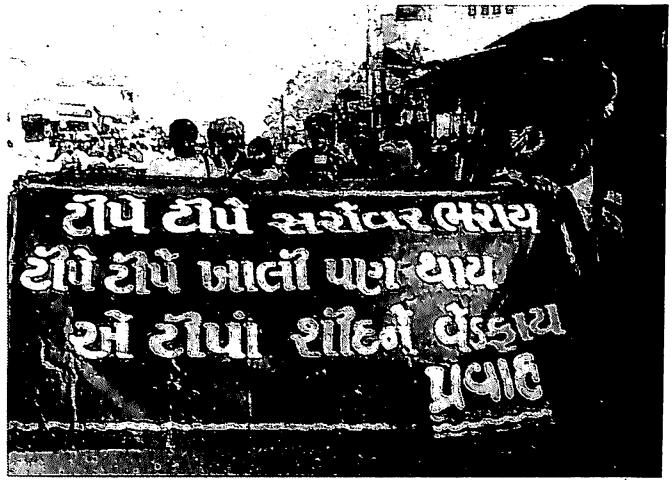

3. अर्जुन गुर्जर (अलवर)

गुजरात में जल के कार्यों में पैसे का खूब दुरुपयोग दिखाई दिया। इसकी वजह शायद इन कार्यों में समाज की पूरी भागीदारी न होना है और इसीलिए पानी के इन कार्यों के प्रति उनमें अपनापन नहीं है।

गुजरात की महिलाओं का मानना था – हमें ही पानी बचाने के लिए काम तुरन्त शुरू करना चाहिए क्योंकि पानी की कमी के कारण हमारा ही कष्ट बढ़ता है। जब घर पर पानी नहीं होता, तब हमारे बच्चे भी ढंग से पढ़ नहीं पाते। पानी की कमी के कारण हम लोग भी घरेलू कार्यों में पूरी तरह से समय नहीं दे पातीं, जिससे कि मुख्य रूप से हमारी लड़कियाँ और महिलाएँ पीछे रह जाती हैं । इसलिए अगर पानी का काम होगा, तो निश्चित तौर पर महिलाएँ आगे बढ़ेंगी। यह जलयात्रा महिलाओं के सबलीकरण और आगे बढ़ने का भी एक माध्यम है।

राष्ट्रीय जलयात्रा गुजरात के जिन क्षेत्रों में गई, उनमें से अधिकतर जगह खाली खेत, सूखे कुएँ व नवयुवकों का पलायन देखने को मिला। कहीं-कहीं पर अकाल राहत के कार्य गलत तरीके से होते देखे गये । इन कार्यों में पानी की बेसमझी और राहत कार्यों के नाम पर उलटा विनाश ही देखने को मिला। एक जगह तालाब बनाने के कार्य में पहाड़ से मिट्टी खोदी जा रही थी, जबकि तालाब की मिट्टी हमेशा उसके अंदर से खोदी जाती है। यह कार्य विपरीत

बुद्धि वाला है। इसी विपरीत बुद्धि के चलते गुजरात के किसान काफी चिन्तित और दुखी नजर आए।

गुजरात में जलयात्रा का आयोजन 'प्रवाह' नामक संस्था ने अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर किया। यहाँ सुश्री नफीसा बहन, श्री राजू-दीप्ति, श्री श्याम जी भाई अंटाला, श्री लल्लू भाई, श्री मनुभाई मेहता, श्री हंसमुख पटेल तथा श्री प्रेमजी भाई की अगुवाई में जलयात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। इसमें कई युवा साथियों का बहुत ही सक्रिय योगदान रहा। यहाँ की एक बहन नम्रता ने नौ राज्यों में इस यात्रा को सफल बनाने में सहयोग दिया । उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार में एक दल की अगुवाई भी की।

यहाँ पानी की निरक्षरता नहीं है, लेकिन समझकर उपयोग करने की कुशलता और साक्षरता भी नहीं है ।

इस राज्य के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में अब पानी के कई काम और ढेरों बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ का समाज हर काम को व्यापार ही बना देता है। अब यहाँ जल भी व्यापार ही बन रहा है। यहाँ कई संस्थाओं ने जल प्रबन्धन, जल संरक्षण के अच्छे काम किये हैं। कुण्डला तालुका में अच्छे व देखने लायक कई छोटे काम हैं। इसी प्रकार उत्थान आदि के काम भी सुन्दर हैं। यहाँ समाज मिलकर अच्छे बड़े काम करने की कुशलता और क्षमता रखता है । इसे अब ठीक से उभारना जरूरी है।

यहाँ पानी की निरक्षरता नहीं है, लेकिन समझकर उपयोग करने की कुशलता और साक्षरता भी नहीं है । इस राज्य में भूजल भण्डारों का बहुत क्रूरता से शोषण हुआ है । यहां के लोग केवल धरती से जल लेते रहे; इन्होंने धरती को जल देने का कार्य नहीं किया । इसीलिए यहाँ की साबरमती जैसी बड़ी नदी भी सूख गई ।

यहाँ बड़े बाँध बनाने व नदी जोड़ने को लेकर सबसे अधिक उत्साह दिखाई दिया। इन दोनों विषयों पर सच्चाई बोलने वालों पर कई बार हमले की तैयारी भी देखने

को मिली। महासभा में तो हमारे यात्रा दल पर ही हमला कर दिया। रात्रि में सभा पर हुआ हमला पहले से नियोजित भले ही न रहा हो, लेकिन युवाओं में बड़े बाँध और नदी जोड़ का बहुत भ्रम है। वे बार-बार नर्मदा-साबरमती जोड़ की बातें करते रहे।

इस प्रदेश में जल प्रभात फेरी व विद्यालय जल रैली अच्छी हुई। शिक्षक-विद्यार्थी बहुत रुचि लेकर इस कार्य में जुटे रहे। इस राज्य की यात्रा में कर्नाटक राज्य के जल संसाधन मन्त्री श्री एच. के. पाटिल, नेहरू युवा केन्द्र के महानिदेशक, सुश्री वन्दना शिवा, श्री सिद्धराज ढड्ढा आदि सर्वोदय के बड़े लोगों ने भागीदारी निभाई। हमारे पुराने साथी श्री महादेव भाई भी शामिल हुए। इस राज्य का वातावरण अलग है, फिर भी हमारी यात्रा अच्छी तरह सम्पन्न हुई। छह फरवरी, 2003 को गुजरात से विदा होने से पूर्व सभी वर्गों से बातचीत करना आंखें खोलने वाला था। निष्कर्ष पूछो, तो इस राज्य की जल समस्याएँ कम नहीं हैं। पानी का प्रबन्धन दोषपूर्ण है। यहाँ पानी का बाजार दूसरे राज्यों से अलग है। भूजल शोषण पर कोई नियन्त्रण नहीं है। फसल चक्र में कोई अनुशासन नहीं है। आधुनिक बाजारू खेती ने यहाँ धरती का पेट खाली कर दिया है। इस पर रोक जरूरी है। जंगलों की कटाई इस राज्य में बहुत है। उद्योगों में जल खपत बढ़ गई है। यहाँ की बसावट, जीवन-चक्र और जीवन पद्धति में तेजी से बदलाव आया है। यहाँ अधिक जल खपत वाला किसान... उद्यमी सभी का बड़ा सम्मान है, क्योंकि इनमें से अधिकतर के पास पैसा है। अफसोस है कि लौहपुरुष वल्लभभाई पटेल और बापू के इस प्रदेश में लूट के विरुद्ध कोई मजबूत आवाज नहीं सुनाई दी।

रात्रि में हमारी सभा पर हुआ हमला पहले से नियोजित भले ही न रहा हो, लेकिन युवाओं में बड़े बाँध और नदी जोड़ का बहुत भ्रम है।

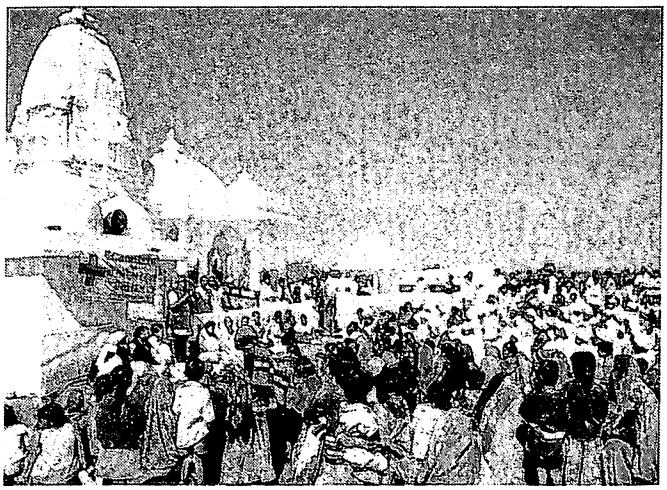

सम्प्रदायवाद की छाप यहाँ बहुत अलग तरह से दिखाई देती है। पानी प्रबन्धन के आधुनिक तरीके और उनके क्रियान्वयन में भी साम्प्रदायिक

भेदभाव साफ दिखता है। इस राज्य में सेवा, कल्याण... उत्थान आदि शब्दों की परिभाषा ही दूसरी है। गरीबों के प्रति करुणा व धर्मभाव तो दिखता है, लेकिन यहां बराबरी की बात करना ही अपराध है। सादगी और समता की बातों को इस राज्य में कोरा आदर्शवाद कहकर नकार दिया गया है। गांधी के प्रदेश का ऐसा हश्र दुःखदायी है ।

छोटे-छोटे साधु-संन्यासियों की महानता को नापने का पैमाना यह है कि उस संन्यासी से भक्तजनों का कितना कल्याण हुआ?... किस संत के कारण कितने भक्तों के व्यापार, खेती या उद्योग बढ़े?... ये सब देखकर ही यहाँ के लोग साधुओं के शिष्य बनते हैं। जलयात्रा में भी जल की बातें सुनने आते थे, तो कुओं में जल बढ़ाने का गुरुमन्त्र ही जानना चाहते थे, जबकि दूसरे राज्यों में ऐसा अनुभव नहीं हुआ।

किस संत के कारण कितने भक्तों के व्यापार, खेती या उद्योग बढ़े?... ये सब देखकर ही यहाँ के लोग साधुओं के शिष्य बनते हैं।

गुजरात को विकसित राज्य बनाने वाला आधुनिक विकास मापक यन्त्र इनके हाथ में ही दिखाई दिया। अजीब बात है कि जल कम हो रहा है... जल दूषित बन रहा है... लोग प्यास से मर रहे हैं, फिर भी गुजरात अपने को विकास के रास्ते पर बता रहा है।

गुजरात में जल-जंगल-जमीन की कीमत पर विकास के आंकड़े बढ़ रहे हैं। यहाँ तथाकथित विकास के विरुद्ध बात करना राष्ट्रद्रोह है । यह तो समझ में आता है लेकिन जल-जंगल-जमीन का क्षरण रोकना, तो विनाश को रोकना है; यहाँ का राज्य संचालक वर्ग इसे भी विकास में रुकावट मानता है। इसी कारण गुजरात जलयात्रा में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमें उम्मीद है, गुजरात के युवा अपने स्थायी भावी विकास और विनाश के अन्तर को समझकर ठीक दिशा में अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। मिलकर जल बचाएंगे और सबको समान पानी पिलाएंगे ।

खूब हो जल और हक भी समान।
तभी बनेगा गुजरात महान् ॥

चर्चा खूब, काम कम

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में स्वैच्छिक संस्थाओं व जन-संगठनों के स्वागत-सत्कार ने जलयात्रियों को अभिभूत कर दिया। झाबुआ के नंगे-सूखे पहाड़ों और वीरान क्षेत्रों में गुजरते, जगह-जगह स्वैच्छिक संस्थाओं के पानी के काम देखते और विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए हम मेयई पहुँचे। गाँव से आये आदिवासियों ने अपने द्वारा किये गये पानी के प्रयासों की चर्चा की। उन्होंने सूखे और उजड़े हुए बेपानी गाँवों के पशुओं और वीरान खेतों की दुःखद गाथाएँ भी सुनाईं।

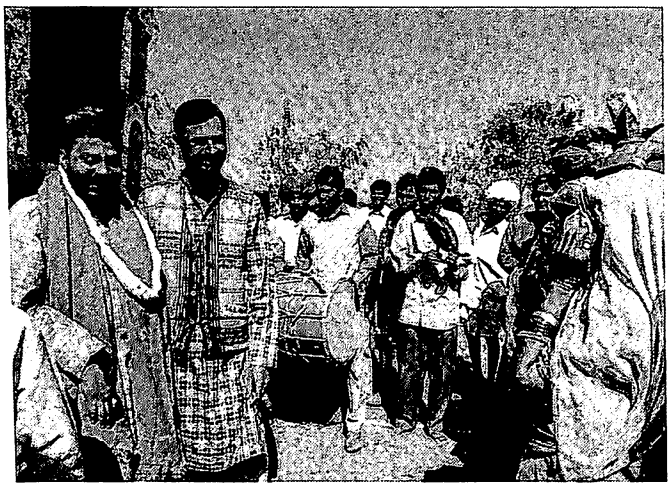

मध्य प्रदेश जलबिरादरी के समन्वयक श्री नीलेश देसाई ने यात्रा के स्वागत अवसर पर कहा – हम सरकार और समाज को जोड़कर पानी का काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र को इस दिशा में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। यदि समाज खड़ा हो जाये, तो यह काम आसानी से होगा। हम मध्य प्रदेश के समाज को पानी बचाने हेतु खड़ा करना चाहते हैं। हमारे प्रदेश में जलबिरादरी का मुख्य उद्देश्य यही है। तत्पश्चात् जलयात्रियों ने भी राष्ट्रीय जल बिरादरी के विस्तृत उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और मध्य प्रदेश में कौन क्या करेगा - इसकी जिम्मेदारी तय की। श्री नीलेश देसाई के नेतृत्व में जल जन आयोग बनाया, जो कि मध्य प्रदेश की जलस्थिति पर श्वेत-पत्र तैयार कर अगले राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करेगा।

मध्य प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा अलग तरह का अनुभव रहा। यहाँ के जल संगठनों में पानी की गहरी समझ है। आपसी संवाद बहुत अच्छा है। इस प्रदेश के आदिवासी भी उद्यमी हैं। पाटी, सेंधवा, रूपखेड़ा ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ समाज ने स्वयं अपने तरीके से पानी बचाने का काम शुरू किया है। यात्रा के दौरान आदिवासियों ने अपनी मेहनत से किये कामों को बहुत ही अपनेपन की भावना के साथ प्रस्तुत किया।

एक स्थानीय समाज ने पहाड़ को पेड़ों की हरी-भरी पगड़ी बाँधकर और धरती माँ को हरी साड़ी पहनाने का संकल्प लिया। रूपखेड़ा के किसानों ने अपनी मेहनत व स्वाभिमान से जल संरक्षण के कार्यों को

आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। सेंधवा की सभा में आदिवासियों ने बहुत ही गर्व के साथ कहा – ''अब हमने भी सेंधवा में पानी का काम शुरू कर दिया है। सरकार को भी इस काम में हमारी मदद करनी चाहिए, किन्तु यदि सरकार मदद नहीं करेगी, तो भी हम सरकार को सिखायेंगे कि कम पैसे में भी कैसे बड़े और टिकाऊ काम होते हैं। यहाँ के आदिवासी नौजवानों में पानी के काम के प्रति बहुत लगन दिखाई दी। इन्होंने जल्दी ही कुछ पानी के अच्छे काम करने का फैसला किया। इसी तरह मध्य प्रदेश के पत्रकार भी पानी की बातचीत में किसी से पीछे नहीं दिखे। खण्डवा के श्री जय नागदा ने चार घंटे के अन्दर दो जनसभाओं और एक पत्रकार सभा का आयोजन किया। इन सभाओं में सरकार, समाज और सामाजिक संस्थाओं ने भागीदारी निभाई। सभी ने खण्डवा को पानीदार बनाने का संकल्प किया।

सेंधवा आदिवासियों में पानी का काम खुद शुरू करने का गर्व है।

इस सभा में मैंने बोतलबन्द पानी नहीं पीने का पुराना संकल्प दोहराया।

तत्पश्चात् सरकार द्वारा किये गये जल संरक्षण कार्यों में तोरणी गाँव के जलग्रहण क्षेत्र को देखा। डेरागाँव के काम भी देखे। डेरागाँव में वहाँ के समाज ने पानी के जो काम किये हैं, उसे देखकर प्रसन्नता हुई। सरकार और समाज के कार्य में स्पष्ट फर्क दिखाई दिया। समाज जो काम करता है, उसका मालिक वह स्वयं बना रहता है; सरकार जो काम करती है, उसका मालिक सिर्फ कागज होता है। समाज का कोई काम व्यर्थ या उपेक्षित नहीं रहता, जबकि सरकार के जलग्रहण के कार्य में टूट-फूट होने के बाद कागज इसे दुरुस्त नहीं कर पाता है। इसीलिए तोरणी गाँव के नये सरकारी काम देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। इन्हें मशीनों से पूरा किया गया है। ये अच्छे सुन्दर दिखने वाले काम भी निष्प्राण दिखाई दिये। क्यों ?... क्योंकि इनका मालिकाना कागज के पास है। वहीं सुखलेवा गाँव के किए हुए काम देखने में सूखे-सूखे थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति और साझेदारी के चलते वे भी प्राणवान् लग रहे थे। इसी तरह सामाजिक स्वाभिमान के बिना मध्य प्रदेश में हुए राजीव गाँधी वॉटर मिशन के काम, जितने सुन्दर और आकार में विशाल थे, इतने ही बेपानी और निष्प्रभावी दिखाई दिये। दरअसल यह समझना जरूरी है कि जब समाज मालिकाना भाव से जल बचाने

समाज जो काम करता है, उसका मालिक वह स्वयं बना रहता है; सरकार जो काम करती है, उसका मालिक सिर्फ कागज होता है।

का काम करेगा, तो ही मध्य प्रदेश का भविष्य पानीदार बना रह सकता है। सरकारी योजनाएँ तो केवल पानी के ढाँचे बना सकती हैं। ये ढाँचे पानीदार बनते रहें... ऐसा सरकारी प्रचार-प्रसार के बावजूद भी सुनिश्चित नहीं होता।

मध्य प्रदेश में पानी की बातचीत करने की रुचि केवल ग्रामीणों में ही नहीं, शहरी बुद्धिजीवियों में भी बहुत दिखाई दी। बहुत से लोगों ने पानी बचाने के मॉडल बनाकर, इसमें निजी पूंजी भी लगाई है, परन्तु इनमें सामुदायिक आधार कहीं नहीं दिखा। इस प्रदेश में बातचीत में बहुत समय गया। बातचीत के तत्काल बाद कुछ शारीरिक श्रम करने की मानसिकता सामान्यत: कम ही नजर आई। हाँ ! आदिवासी किसानों में शारीरिक श्रम करने की ललक अवश्य दिखाई पड़ी। किसानों ने अपने खेतों पर कुछ खेत तलाई, इबरी... कुण्ड आदि स्वयं अपनी मेहनत से बनाए हैं।

सोयाबीन ने बहुत सारे तालाबों को तुड़वा दिया, क्योंकि सोयाबीन की फसल न तो अधिक पानी बर्दाश्त कर सकती है और न ही सूखा।

पुराने के साथ नया चलन भी यहाँ मौजूद दिखा। यहाँ के किसानों ने पिछले 20-22 वर्षों में अपने फसल चक्र को वैज्ञानिकों की दखल से बहुत बदला है। सोयाबीन ने बहुत सारे तालाबों को तुड़वा दिया, क्योंकि सोयाबीन की फसल न तो अधिक पानी बर्दाश्त कर सकती है और न ही सूखा। मध्य प्रदेश में पानी का संकट पैदा करने में सोयाबीन की फसल सबसे ज़्यादा जिम्मेदार दिखाई दी। बाजारू खेती के साथ-साथ जल आधारित उद्योगों से उपजी त्रासदी भी मध्य प्रदेश को भुगतनी पड़ रही है। ऐसे में जल के बाजारीकरण और निजीकरण के विषय में मध्य प्रदेश के जन संगठनों की सही समझ से ही कुछ उम्मीद जगती है। इन्हीं पर बड़ा दायित्व है। कई सामाजिक कार्यकर्ता और जन संगठन निजीकरण के खिलाफ आन्दोलन के लिए तैयार भी नजर आये। इन सभी संगठनों ने जलबिरादरी से भी पूरी ताकत के साथ जल निजीकरण आन्दोलन में जुड़ने का

आग्रह किया। मालवा, निमाड़, मध्य क्षेत्र, बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड और मदा के टोले से गुज़रते हुए हमने अनुभव किया कि ये क्षेत्र भी झाबुआ की तरह अति सूखे और वीरान हैं। इनका लगभग एक-तिहाई से अधिक भू-भाग जलविहीन है और भू-जल भण्डार तो दो-तिहाई से अधिक खाली हो चुके हैं। मुश्किल से आधी कृषि भूमि पर खेती दिखाई दी। एक-तिहाई गाँवों में रौनक नजर नहीं आई। पलायन के कारण गाँव उजाड़ और वीरान थे। हम जहाँ भी गए, वहाँ गाँवों में कुछ बूढ़े पुरुष और बच्चे ही अधिक दिखे। अक्सर निराशा का आलम नजर आया। इन हालात से त्रस्त बुजुर्गों से हम जब भी पानी की बात करते, तब वे अतीत की याद कर भरआँसू सिसकने लगते थे। ऐसे में जब इनके साथ श्री अर्जुन गुर्जर और श्री छाजू मीणा ने राजस्थान के अनुभव की बात की, तो उनके चेहरे पर रौनक लौट आई और फिर उन्होंने भी इसी तरह से काम करने का संकल्प लिया। ऐसा कई गाँवों में हुआ।

'भागीदारी' शब्द की मध्य प्रदेश के सरकारी हलकों में बहुत चर्चा सुनने को मिली, लेकिन जन भागीदारी का सच्चा नमूना हम कहीं नहीं देख पाये।

'भागीदारी' शब्द की मध्य प्रदेश के सरकारी हलकों में बहुत चर्चा सुनने को मिली, लेकिन जन भागीदारी का सच्चा नमूना हम कहीं नहीं देख पाये। कई सरकारी सफल प्रयास भी देखे। इन प्रयासों में सरकारी अधिकारियों की भूमिका प्रखर रूप से देखने को मिली। यह प्रखरता संतोषजनक है, लेकिन यदि यही प्रखरता समाज से जोड़ दी जाती, तो यही काम स्थायी रूप से टिक जाते और प्रदेश भर में इनकी पुनरावृत्ति होती; लेकिन ऐसी पुनरावृत्ति और टिकाऊपन का दृश्य किसी भी सरकारी अधिकारी ने यात्रा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। मैंने पूछा– ''क्या किसी एक गाँव के काम को देखकर, दूसरे गाँव में भी ऐसा ही कोई काम हुआ है?'' इस पर सरकारी अधिकारियों में मौन ही दिखाई दिया।

बुन्देलखण्ड स्थित टीकमगढ़ जिले के तरीचरकला में सर्वोदय मण्डल द्वारा कुछ

अच्छा जल संरक्षण का कार्य हुआ है, लेकिन ऐसे उदाहरणों से भी सरकारी अधिकारियों ने कुछ नहीं सीखा। शेष स्थानीय ग्रामीण समाज भी वैसा काम नहीं कर पाया है ।

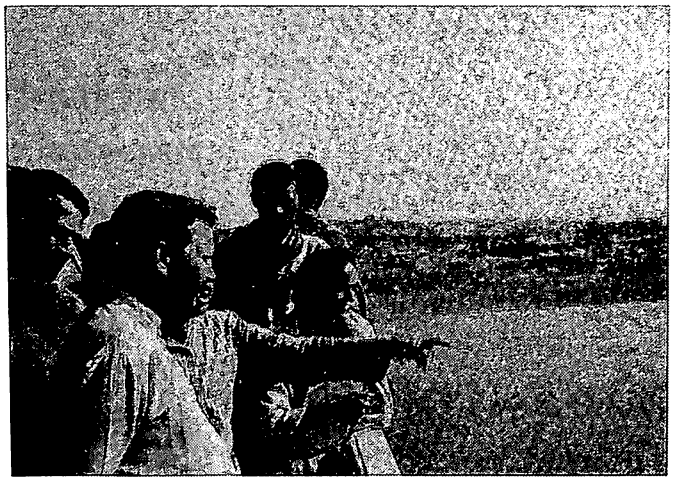

इसकी एक वजह यहाँ पानी की बातचीत में सामाजिक संवेदना और सजगता का नहीं होना है। कई जगह पर 'पानी रोको अभियान' के पक्ष-विपक्ष में पंचायत प्रतिनिधियों की बहुत सारी टिप्पणियाँ सुनने को मिलीं, लेकिन इनमें से कोई भी पंच-सरपंच 'पानी रोको अभियान' के टिकाऊ लाभ की पुनरावृत्ति नहीं कर सका। कई जगह यात्री दल के श्री छाजू मीणा ने चंबल में पानी के संरक्षण के अपने काम का वर्णन करते हुए पूछा – चंबल में हुए पानी के काम से ही अब लोगों ने डकैती छोड़कर खेती शुरू कर दी है, किन्तु ऐसा सिर्फ राजस्थान में ही क्यों हुआ ? मध्य प्रदेश में भी तो चंबल के बीहड़ बढ़ते ही जा रहे हैं, पर मध्य प्रदेश में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। क्यों ? मुरैना जिले में तो गांधीवादियों का पुराना काम है। कभी यहाँ भी बहुत सारे डकैतों ने डकैती छोड़ी थी, लेकिन खेती के लायक जमीन और पानी उन्होंने भी नहीं तैयार की। क्यों ? चंबल के इस क्षेत्र में आज बीहड़ सुधार की जरूरत है । इसी से पानी का सुधार होगा।

मुरैना जिले के कई क्षेत्रों में यात्रा दल गया। कुनो वन क्षेत्र में तरुण भारत संघ की मदद से कुछ जल संरक्षण के कार्य भी हुए हैं, वहाँ भी यात्री दल पहुँचा । यहाँ पर जो पानी का काम दिखा, वह हरियाणा से आये किसानों, खासकर हरियाणा जल बिरादरी

के पूर्व अध्यक्ष श्री देवव्रत आचार्य ने तरुण भारत संघ की मदद से किया है । इसे देखकर अब अन्य लोग भी पानी का ऐसा काम करने लगे हैं, लेकिन इनमें हरियाणा व राजस्थान के किसान ही अधिक हैं । हम यात्रा के अंत तक नहीं समझ पाये कि चंबल के किसान स्वयं क्यों नहीं पानी और पेड़ बचाने में रुचि ले रहे? इस चिंता भरे सवाल को मन में लिए हम मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से विदा हुए।

चंबल क्षेत्र में युवा राजनेता श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पानी के प्रबन्धन में काफी रुचि दिखाई है । इनके कार्यकर्ता पानी का काम देखने बड़ी संख्या में राजस्थान गये थे। इन्होंने वापस लौटकर पानी के काम के कुछ अच्छे प्रयास भी किए, लेकिन यहाँ की संस्थाओं के काम हम यात्रा के दौरान नहीं देख पाये। यहाँ भी पानी पर काम से अधिक उसकी चर्चा ही दिखी । जलयात्रियों ने सभी संस्थाओं से निवेदन किया कि पानी के काम के लिए समाज को खड़ा करना बहुत जरूरी है । हमारी उपस्थिति में चंबल क्षेत्र की सभी संस्थाओं ने निर्णय लिया कि वे जल बचाने के व्यावहारिक काम तत्काल शुरू करेंगे ।

आगे बढ़े तो बघेलखण्ड में पानी की गहरी और व्यावहारिक समझ वाले डॉ. जी. डी. अग्रवाल की मौजूदगी स्मरण हो गई। इन्होंने कई संस्थाओं और विद्यार्थियों को जल बचाने के काम हेतु प्रेरित किया है । यहाँ पर दीनदयाल शोध संस्थान के श्री भारत पाठक ने चित्रकूट और मझगाँव में कुछ सभाएँ आयोजित कीं । यहाँ खासकर तकनीक और इंजीनियरिंग की ही बातें

सुनने-देखने को मिलीं। गायों की देशी नस्ल को सुधारने तथा सजीव खेती को बढ़ाने के प्रयोग दिखाई दिए। रींवा में गोविन्दगढ़ तालाब पर श्रमदान से सफाई का काम सम्पन्न हुआ। पत्रकारों तथा विश्वविद्यालय के कुलपति एवं शिक्षक पानी के काम में गहरी रुचि वाले दिखाई दिये। अब यहाँ परम्परागत जल संसाधनों के संरक्षण की एक अच्छी शुरुआत हुई है।

मध्य प्रदेश की जलयात्रा के अनुभव बहुत ही मिश्रित रहे। एक तरफ ढोल-धमाकों से स्वागत और कई अच्छी रैलियां, प्रभात फेरी, विद्यालय-महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की सभा-संगोष्ठियाँ, श्रमदान, जल के जन स्वाभिमान को जगाने में पत्रकारों की रुचि, चन्द राजनेताओं व बड़े अधिकारियों द्वारा स्वागत तथा मौका मुआयना; वहीं दूसरी तरफ सरकारी तंत्र की बेरुखी और राजनेताओं का बेपानीपन !... फिर भी राष्ट्रीय जलयात्री दल का अत्यंत उत्साह इसलिए बना रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश में स्वैच्छिक संस्थाओं, जन संगठनों और जन साधारण ने मिलकर बहुत ही समझदारी से जलयात्रा का संयोजन किया था। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की यात्रा व्यस्ततम और एक-एक मिनट का सदुपयोग करने की चाह वाली सफल यात्रा रही।

मध्य प्रदेश से यात्रा की विदाई के वक्त यहाँ की संस्थाओं ने मध्य प्रदेश की जल स्थिति पर श्वेत-पत्र तैयार करने का संकल्प दोहराया तथा समय से पूर्व ही इसे अंतिम रूप देने का सर्वसम्मत निर्णय सुनाया। मध्य प्रदेश जलबिरादरी ने अपने काम और जिम्मेदारियों का बँटवारा ठीक से समय पूर्व ही कर लिया। जलयात्रा में मध्य प्रदेश जलबिरादरी का कुशल प्रबन्धन देखकर जलयात्री दल का अन्त तक उत्साह बना रहा। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र शेष था, इसे एक अन्य दल ने पूरा करने का निश्चय किया।

...और कितनी सत्यभामा चाहिए ?

छत्तीसगढ़

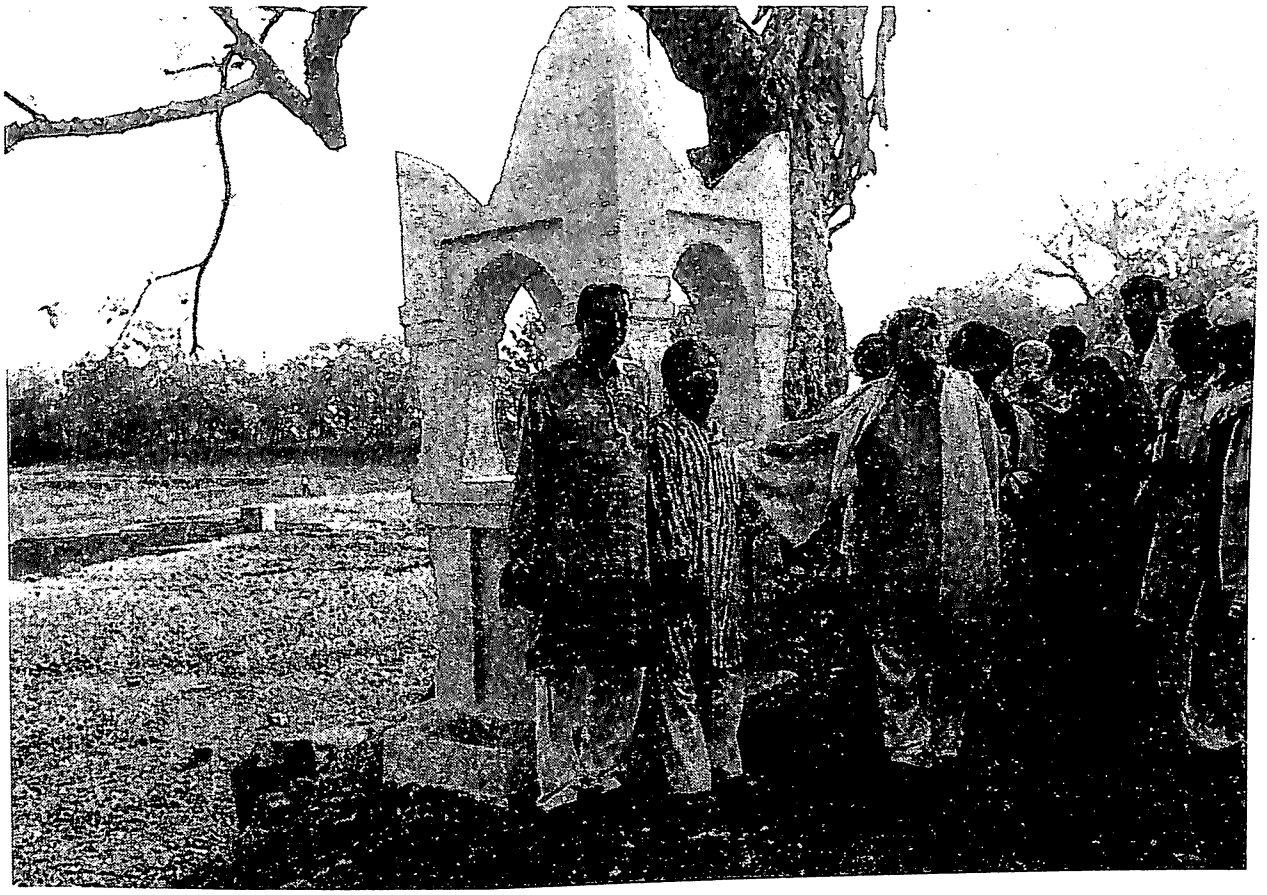

शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ के समाज के लिए जीवन धारा सरीखी है, फिर भी सरकार ने कम्पनी क्यों बेच दी ? इसका कोई जायज कारण हमें समझ नहीं आता। यह नदी मछुआरों को मछली, किसानों को खेती और गरीबों को पानी देती है । अतः इन सब की रोजी-रोटी छीनकर इस नदी को कम्पनी को दे देने को अवैध मानकर वापस समाज के हाथों में दिलाना हमारे यात्रा दल के लिए एक चुनौती बन गया। इसीलिए हमने ज्यादातर समय नदी किनारे के लोगों का आन्दोलन खड़ा करने पर ही लगा दिया। इसका परिणाम बहुत ही उत्साहजनक

रहा। लोगों ने नदी किनारे के गांवों में रैलियां निकाली... सभाएं कीं। आखिर में सरकार द्वारा यह नदी रेडियस कम्पनी से छीनकर वापस समाज को सौंप दी गयी।

ध्यान रहे कि छत्तीसगढ़ ऐसा सबसे पहला राज्य है, जिसने किसी एक प्राइवेट कंपनी को एक नदी की मालकिन ही बना दिया। यह इस मायने में भी पहला राज्य है, जिसमें नदियों के अतिक्रमण के खिलाफ **सत्यभामा** नाम की एक महिला ने आन्दोलन किया और अपने को नदी बचाने में शहीद कर दिया।

छत्तीसगढ़ में दूसरा मुख्य मुद्दा है – ''जल संरक्षण की परम्परागत संरचनाओं को पुनर्जीवित करना तथा बहते वर्षा जल को सहेजना।'' इस काम की शुरुआत छुरियाँ गाँव से हुई। इस क्षेत्र में श्री रवि मानव ने 'वरदान' संस्था के माध्यम से पानी सहेजने का संकल्प किया। छुरियाँ में ही छत्तीसगढ़ की

अधिकतर संस्थाएँ इकट्ठी हुई थीं। छत्तीसगढ़ जलबिरादरी के संयोजक श्री गौतम बन्दोपाध्याय और अध्यक्ष श्री ललित सुर्जन आदि ने छत्तीसगढ़ में जलयात्रा के

कामों को लेकर कुछ खास निर्णय लिए। इनमें सबसे मुख्य था– राज्य में जल आयोग का गठन करना और राज्य की जलस्थिति पर श्वेत-पत्र जारी करना।

अगले दिन जलयात्रा राजनन्दगाँव के अधिकारियों को जल संरक्षण हेतु प्रशिक्षित करते हुए दुर्ग जिले में प्रवेश कर गयी। यहाँ पर शिवनाथ नदी के निजीकरण के खिलाफ लोगों को तैयार किया। उसके बाद रायपुर होते हुए हमने बिलासपुर विश्वविद्यालय में सभा की। वहां से रायगढ़ पहुँचे। रायगढ़ में केलो नदी पर कब्जे को देखकर बहुत दुख हुआ। यहाँ सत्यभामा नगर होते हुए पूरी नदी का भ्रमण किया तथा लोगों को लक्ष्य के लिए तैयार करते हुए आगे बढ़ चले। जहांगीर चापा से होकर डबरा, रायगढ़ और पिहीरा होते हुए सारंगगढ़ के केराड़ गाँव में पहुंचे, तो श्री रवि नेतराम व डॉ. प्रवेश मिश्रा ने महानदी के दोनों तरफ के गाँवों को दिखाया। महानदी के एक किनारे जंगल में बसे गाँव पानी की कमी के कारण काफी दुखी और त्रस्त दिखे तथा दूसरी तरफ के गाँवों में महानदी की बाढ़ के कारण बहुत तबाही हुई है।

देखभाल और मरम्मत के कारण तालाब की पाल पर बने हुए मंदिरों की स्थिति तो बहुत अच्छी है; पर तालाबों पर बड़ी संख्या में हुए अतिक्रमण और गाद के कारण तालाब बरबाद हो गये हैं।

ध्यान देने की बात यह है कि इस राज्य में आज भी हजारों साल पुराने कई तालाब हैं। देखभाल और मरम्मत के कारण तालाब की पाल पर बने हुए मंदिरों की स्थिति तो बहुत अच्छी है; पर तालाबों पर बड़ी संख्या में हुए अतिक्रमण और गाद के कारण तालाब बरबाद हो गये हैं। हमें लगा कि इस राज्य में यदि केवल पुराने तालाबों की मरम्मत का काम ही ठीक से हो जाये, तो ही स्थानीय जल संकट से निपटा जा सकता है, लेकिन यहाँ की सरकार का ध्यान पुराने तालाबों की मरम्मत पर नहीं है, बल्कि नई डबरियाँ बनाने के नाम पर पानी का खेल खेला जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस राज्य में जल सहेजने के परम्परागत तरीकों को पुनर्जीवित किया जाये। वन क्षेत्र को ठीक से बचाकर भी पानी संकट से उबरने में बड़ी मदद

...किन्तु यहाँ के वनवासी अभी इससे बेफिक्र हैं। राजनेताओं ने इनका स्वाभिमान समाप्त कर दिया है।

मिल सकती है। इसी से जमीन के अंदर-बाहर का संतुलन बना रहेगा।

छत्तीसगढ़ में अधिकतर नदियों पर किसी न किसी रूप में उद्योगपतियों का कब्जा बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ जल बिरादरी का सबसे पहला काम नदियों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कब्जे से बचाना, पानी का निजीकरण रोकना व केन्द्र की नई जल नीति का विरोध कर अपने राज्य के अनुकूल जनोन्मुखी जल नीति बनाना है, ताकि समाजोपयोगी विकेन्द्रित जल प्रबन्धन को बढ़ावा मिले और पूरा समाज संगठित होकर जल बचाने में लग जाये। छत्तीसगढ़ राज्य की जल नीति राज्य की महिलाओं, बच्चों व गरीबों के अनुकूल बने, इस हेतु भी प्रयास चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जल संसाधनों पर श्वेतपत्र जारी करने की सभी तैयारियाँ कर ली गई थीं और छत्तीसगढ़ जलबिरादरी ने नदियों से कब्जा हटवाने में सफलता भी पा ली थी। यहाँ के साथियों ने नदियों के अतिक्रमण हटवाने हेतु सत्याग्रह का संकल्प भी किया है।

इस राज्य की जल बिरादरी के कई क्रान्तिकारी साथियों ने दूसरे राज्यों की जलयात्रा को भी पर्याप्त समय दिया। इस राज्य का पानी लुटे नहीं, इस हेतु यहाँ के साथियों को और अधिक ध्यान देना होगा। छत्तीसगढ़ के पानी पर बाहर की कम्पनियों का अधिक ध्यान है, किन्तु यहाँ के वनवासी अभी इससे बेफिक्र हैं। राजनेताओं ने इनका स्वाभिमान समाप्त कर दिया है।

यहाँ के साथियों को एक तरफ अनुकूलता है, तो दूसरी तरफ बहुत कड़ा संघर्ष है। नदियों को जोड़ने की बहस में छत्तीसगढ़ को क्या मिलेगा और क्या जायेगा? यह संवाद चलाना है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बाढ़-सुखाड़ का संकट; तीसरी तरफ नदियों का बदलता रूप; चौथा राज्य जलनीति की दिशा से बिगड़ने वाले भावी जल हालात सुधारने हेतु जलसंरक्षण की मुहिम खड़ी करनी है। जल-संरक्षण कर्मियों की कुशलता-क्षमता बढ़ाने हेतु कुछ सतत् प्रशिक्षण चलाने होंगे। इस कार्य में केन्द्रीय व राज्य की जल बिरादरी को तुरन्त प्रयास शुरू करने चाहिए। छत्तीसगढ़ जल बिरादरी का एक दल तरुण आश्रम, भीकमपुरा में प्रशिक्षण हेतु भेजकर यहीं इनको प्रशिक्षित करके भावी जिम्मेदारी प्रदान की जावे।

जसमा का जस नकारती सरकार

उड़ीसा

जलयात्रा में शामिल लोग ऐसे हैं, जिन्होंने लुटते हुए पानी को या तो खुद अपने हाथों से बचाया है या फिर समाज की शक्ति जगाकर उसे पानी बचाने के काम में लगाया है। उड़ीसा में पहले ऐसे लोग बहुत थे। वे सभी पानीदार थे। उन्हें ओड कहते थे। वे पानी प्रबन्धन की सब विधियों के जानकार थे। उनसे ही इस क्षेत्र की पहचान बनी। उन्हीं के कारण इस प्रदेश का नाम उड़ीसा पड़ा।

यहाँ की महिलायें पुरुषों से भी आगे थीं। जसमा ओडन इसका बड़ा उदाहरण है, जिसने जोहड़ बनाने से ही जस पाया। इसी ने जल और जोहड़ का महत्व रेखांकित किया। जलयात्रा भी चाहती है कि ऐसे ही समाज में विश्वास जगे।

यह यात्रा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होती हुई उड़ीसा के एक बेपानी गाँव बिलाईगढ़ में प्रवेश कर गयी। यहां से आदिवासी अंचल चदैनीमाल, चंदनखूंटी, दाजिंग, पूर्णापानी, कुंदबहाली और शरद गाँव से होते हुए आज हम भुवनेश्वर पहुँचे हैं। उड़ीसा के बारे में मेरी जो मान्यता थी, वह काफी बदली है। बिलाईगढ़ प्यासा है। यहाँ की महिलाएं घंटों मेहनत कर नदी में कुएं खोदती हैं और पानी भर कर लाती हैं। इनका आधा से ज़्यादा समय

जसमा ओडन ने जोहड़ बनाने से ही जस पाया।

पानी लाने में चला जाता है । ये सभी पानी बचाने के काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शासन की सीमा और सरकारों की बेरुखी के कारण यहाँ पानी का काम नहीं हो पा रहा है ।

देवगढ़ जिले में ब्राह्मणी नदी पर बने रेंगाली बान्ध से विस्थापित हुए चंदनखूंटी गाँववासी आज बेघर हैं । पहले पानी की अधिकता से उजड़े और अब पानी की कमी के कारण तरस रहे हैं । इस तरफ सिमली पाल बांध परियोजना में बसे पूर्णापानी और कुन्दबहाली आदिवासी गाँवों ने स्वयं श्रमदान करके अपने चार बांधों का काम पूरा कर लिया है । इस तरह के काम यदि उड़ीसा का समाज सब जगह शुरू करे, तो सरकार का एक नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसे कार्यों में बाधक बनने के बजाय स्वैच्छिक संस्थाओं और समाज को प्रोत्साहित करे ।

बड़े बांधों के ठीक नीचे 30 किलोमीटर दूर तक के गाँव बेपानी हैं।

उड़ीसा राज्य में एक तरफ अत्यंत वर्षा है... और हीराकुड, इंद्रावती, रेंगाली जैसे बड़े-बड़े बाँध हैं, तो वहीं इनके ठीक नीचे 30 कि. मी. दूर तक बेपानी और सूखे की लाचारी से तरसते ग्रामीण रहते हैं। यहाँ के वनवासी जीवन चलाने के लिए जिस वन पर आश्रित हैं, उस पर जंगलात विभाग के डँडे की मार या जेब भरने का रुआब बहुत भयंकर दिखता है । इसी के कारण उड़ीसा के वन, वनवासी और वन्य जीव एक-दूसरे से अलग-थलग हो रहे हैं। चन्द चाँदी के लिए जंगल जल रहे हैं । प्रकृति से केवल लूटने का भाव उड़ीसा में अधिक नजर आया। इसी के कारण यहाँ का भूजल स्तर घट रहा है । पर्याप्त वर्षा के बावजूद धरती का बड़ा भू-भाग खेती के बिना खाली है ।

उड़ीसा का खालीपन दूर करने के लिए प्रकृति से जोड़ने वाली विकास की नीति बनानी पड़ेगी । उड़ीसा राज्य को प्रकृति ने जो कुछ दिया है, वही सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन है । जंगल इनकी समृद्धि

का रास्ता है । पानी के व्यापारीकरण और निजीकरण से उड़ीसा समृद्ध नहीं हो सकता । सामुदायिक भागीदारी से ही जल और जंगल के विकास के रास्ते पर उड़ीसा आगे बढ़ सकता है । इसलिये यहाँ पर एक जल-जन आयोग गठित करने की अत्यंत आवश्यकता है । पूरी यात्रा के दौरान हमें इसकी जरूरत महसूस हुई।

जानना जरूरी है कि आज़ादी के बाद उड़ीसा के जल व वन्य संसाधनों को सम्भालने के उद्देश्य से यहाँ के पानी का कितना और कैसे उपयोग हुआ?

आज़ादी के बाद उड़ीसा के जल व वन्य संसाधनों को सम्भालने के उद्देश्य से यहाँ के पानी का कितना और कैसे उपयोग हुआ? पानी के नाम पर आज जो खर्च किया गया, इससे किसे और कितना लाभ या हानि हुई ? यहाँ के नदी और नालों के जल बहाव की अब क्या स्थिति है? इनमें कितना बदलाव आया है? उड़ीसा के पानी के प्रबन्धन के परम्परागत तौर-तरीके आज कितने सार्थक हैं? उड़ीसा की भावी जलनीति कैसी होनी चाहिए?... जल जन आयोग को इस पर सतत् और एक गहरा अध्ययन करके उड़ीसा के जल संसाधन पर श्वेत-पत्र तैयार करना चाहिए ।

हमने यात्रा के दौरान राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज्य जल जन आयोग का गठन किया था। अब उड़ीसा में भी एक जल जन आयोग का गठन हो गया । इस आयोग में पाँच सदस्य हैं; श्री आदित्य पटनायक, लिंगराज, कुलपति, एक न्यायाधीश और एक सिविल इंजीनियर । यह आयोग अगले छः माह में अपने राज्य की जल-स्थिति पर अध्ययन करके राज्य की भावी जल नीति एवं भावी कार्यक्रम सुझाएगा ।

राष्ट्रीय जलयात्रा ने समाज को जल संरक्षण कार्यों के लिये तैयार किया। पानी के निजीकरण व व्यापारीकरण को रोकने के लिए प्रदेश भर के विद्यालयों-महाविद्यालयों में जाकर बोतलबन्द पानी को नहीं खरीदकर पीने का संकल्प दिलाया । नदियों तथा प्राकृतिक नालों को संरक्षित करने हेतु जगह-जगह ग्रामीणों के बीच स्थानीय जल बिरादरी का गठन भी किया ।

अब जल बिरादरी ग्राम स्तर से लेकर नदी बेसिन स्तर तक गठित की जाएगी। फिर किसी भी नदी को किसी भी कम्पनी या व्यक्ति को नहीं दिया जा सकेगा। बिरादरी इसकी निगरानी रखेगी। जल बिरादरी संगठन पानी के रास्ते से आने वाली गुलामी को रोकने के लिए संघर्ष जारी रखेगा, लेकिन यह तभी संभव होगा, जब इस देश के जागरूक नागरिक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, सांस्कृतिक कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, छात्र, शिक्षक, महिला... बच्चे सभी एकजुट होकर पानी के निजीकरण और व्यापारीकरण को रोकें तथा पानी को बचाने के कार्य में संगठित होकर जुटें।

श्री आदित्य पटनायक ने आगामी उड़ीसा के जल की कल्पना की है और इसी नाम पर काम भी शुरू किया है।

हमने प्रदेश की उन सब नदियों की स्थिति पर श्वेत-पत्र जारी करना तय किया, जिन ग्यारह नदियों को सरकार ने नदी सुधार के नाम पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देने की बात स्वीकार की है। इस तरह की मंशा इसी राज्य में सबसे प्रबल दिखाई दी। यह मंशा बहुत घातक है।

उड़ीसा में जलयात्रा की पूरी व्यवस्था प्रसिद्ध गान्धीवादी कार्यकर्ता श्री आदित्य पटनायक ने की थी। श्री पटनायक बहुत ही उत्साही, जुझारू और अहिंसक सत्याग्रह में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने आगामी उड़ीसा के जल की कल्पना की है। इसी नाम पर काम शुरू किया है। यही उड़ीसा जल बिरादरी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने जन संगठनों और सरकारी-स्वैच्छिक... सभी संस्थाओं को जोड़कर जल प्रबन्धन की विकेन्द्रित जनोन्मुखी व्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास शुरू किया है। इस राज्य में सांस्कृतिक दल बहुत ही अच्छा है। चम्पा नामक महिला बहुत अच्छी जन गायिका है। इन्होंने बहुत सारे जलगीत तैयार किये हैं। समाज को गाकर सुनाये भी। उड़ीसा को पानीदार बनाने की प्रेरणा पैदा करने वाले गीत सुनकर हमें भी अच्छा लगा।

श्री मुकुन्द कण्ठ, श्री सुरेश भाई, श्री ए. बी. स्वामी आदि साथियों ने इस यात्रा में बहुत सहयोग दिया । श्री अच्युतदास, श्री जगदानन्द आदि साथियों ने भी उड़ीसा जलयात्रा में पूरा हाथ बँटाया।

'समाज' अखबार के प्रबन्ध निदेशक, श्री ब्रजभाई ने पूरी यात्रा के साथ अपने संवाददाताओं को जोड़कर रंखा । इनके कारण व आदित्य भाई की सक्रियता से प्रतिदिन यात्रा के विषय में कुछ न कुछ नया पढ़ने को मिल जाता था ।

यहाँ लगभग सभी पार्टियों के कार्यकर्ता, नेता व मन्त्री भी इस यात्रा में शामिल हुए। उप कुलपति श्री भुवनेश्वर का बहुत उत्साह यहाँ देखने को मिला । इस राज्य में सब कार्यक्रम समय पर शुरू व सम्पन्न हुए । ये सभी गांधीवादी तरीकों से चले। कहीं भी कोई दिखावा नहीं; सादगीपूर्ण, सप्रेम, संवेदनशील संवाद बना रहा । सभी सभाओं में संकल्प हुए । बोतलबन्द पानी खरीद कर नहीं पीने का संकल्प करने वालों की अधिक संख्या इसी राज्य में रही। वैतरणी नदी को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में जाने से रोकने का कार्य यह यात्रा सफलतापूर्वक कर सकी है ।

वैतरणी नदी को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में जाने से रोकने का कार्य यह यात्रा सफलतापूर्वक कर सकी है ।

श्री आदित्य पटनायक की अगुवाई में जल संरक्षण के कई नये काम स्वैच्छिक तौर पर जंगल में शुरू हुए । कुछ अधूरे काम भी पूरे किए । कई संस्थाओं ने मिलकर इस दिशा में काम करने का निर्णय भी लिया। यहाँ की जल बिरादरी भविष्य में बराबर सबको पानी पिलाने के लिये कटिबद्ध दिखाई दी। इस राज्य के जन संगठन, जल आन्दोलनों ने स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ मिलकर सामुदायिक जल संरक्षण की कार्ययोजना बनाई है । आशा है, जल्द ही कार्य शुरू होगा । श्री आदित्य पटनायक के नेतृत्व में बिरादरी... कटक डेल्टा की बाढ़ से मुक्ति व बाढ़ के साथ जीने का स्वभाव तैयार करने का काम करेगी। आपदा निवारण प्रकोष्ठ

बनाने का निर्णय भी उड़ीसा जल बिरादरी ने किया । उड़ीसा बाढ़-सुखाड़ से त्रस्त राज्य है । यहाँ पानी का व्यवहार बदलने की दिशा में भी काम करना होगा । यहाँ की जल बिरादरी ने निम्न सिद्धान्त अपनाने का निर्णय लिया है:

पानी जहाँ दौड़ता है, वहाँ इसे चलना सिखाना है।
जहाँ रेंगने लगे, वहाँ इसे ठहराना है।
जहाँ ठहर जाए, वहाँ धरती पर बैठाना है।
ताकि नजर न लगे सूरज की और
जब कभी सूखा और अकाल आए,
तो मर्यादित होकर इसी जल से
जीवन चलाना है।

उड़ीसा में भूमि संरक्षण, नमी बनाए रखने, वनीकरण, भूजल संरक्षण आदि काम ढालू टीलों से लेकर घाटी तक सतत-क्रमबद्ध ढंग से किए जाने हैं। इस हेतु राज्य जल बिरादरी ने प्रत्येक जिला जल बिरादरी को यह जिम्मेदारी दी है और वह उक्त दिशा में काम शुरू कर रही है । ये जिला जल बिरादरी क्रमशः राज्य जल बिरादरी व राज्य सरकार पर दबाव बरकरार रखते हुए काम जारी रखेंगी।

विदेशी आजकल हमारे अच्छे शब्दों को चुरा कर अपना स्वार्थ साधने हेतु इनका उपयोग कर रहे हैं। इस भ्रम से भी हमें बचना होगा ।

उड़ीसावासियों को 'पानी पंचायत' के प्रति सावधान करना जरूरी है, क्योंकि यात्रा के दौरान इस 'पानी पंचायत' की चर्चा काफी सुनी । 'पानी पंचायत' शब्द तो उड़ीसा का लगता है, लेकिन इस शब्द की पालना के लिए परिस्थिति और पात्र बिल्कुल अलग है। उड़ीसा का समाज 'पानी पंचायत' के मानदण्डों पर निश्चित ही अयोग्य साबित होगा। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पानी के काम के लिए हमने जो कर्ज लिया है, उसे यह समाज ठीक से चुका नहीं पा रहा है । संसाधनों को समाज से छीनकर विदेशों के हाथ में देने का यह एक सोचा – समझा तरीका है । इस विषय में उड़ीसा के पत्रकार मुझे ज़्यादा जागरूक नजर आए ।

यात्रा के दौरान उन्होंने यह सवाल जरूर पूछा और मैंने कहा, पानी का मालिकाना हक समाज के हाथों से निकाल कर विदेशों को देना ही 'पानी पंचायत' है । विदेशी आजकल हमारे अच्छे शब्दों को चुरा कर अपना स्वार्थ साधने हेतु इनका

उपयोग कर रहे हैं। इस भ्रम से भी हमें बचना होगा।

उड़ीसा के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच पानी का मामला बहुत गर्माया। महात्मा गांधी कालेज, भुक्ता एवं अन्य कालेजों तथा उड़ीसा की शहरी जन सभाओं में विद्यालयों के शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में पानी नहीं खरीदकर पीने का संकल्प लिया गया। इससे एक बात तो समझ में आई कि उड़ीसा की अत्यंत गरीबी और अमीरी के बीच जो बहुत दूरी है, इसके कारण ही सबसे बड़ा तबका पानी के क्रय-विक्रय के विरोध में है। मुझे लगा कि उड़ीसा में पानी के निजीकरण... व्यापारीकरण के विरुद्ध जो सिंहनाद गूँज रहा है, उसे यहाँ के जन संगठन और स्वैच्छिक संस्थाएँ व कालेज जैसी शासकीय संस्थाएँ मिलकर सर्वसम्मत आन्दोलन खड़ा कर सकती हैं।

'ब्राह्मणी नदी का मालिक कोई व्यक्ति या कम्पनी हो सकता है'– यह यहाँ के समाज ने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन यह सत्य है। दाजिंग की एक सभा में आज यह जानकर उनकी चिंता बढ़ गई। सभा में उपस्थित सभी ने कहा कि इस नदी पर किसी ने कब्जा किया, तो हम जान की बाजी लगा देंगे और फिर दाजिंग स्कूल के शिक्षक एवं छात्रों सहित पूरे क्षेत्र से आई जनता ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि किसी भी कीमत पर अपनी नदी को बिकने नहीं देंगे। हम आज से ही अपनी नदी पर पूरा ध्यान रखेंगे। इस गाँव में विनोबा जी 1962 में गये थे। यहाँ अभी भी एक सर्वोदय कार्यकर्ता रहता है। उनकी चेतना यहाँ के समाज में भी कुछ दिखाई दी।

दाजिंग की एक सभा में उपस्थित सभी ने कहा कि इस नदी पर किसी ने कब्जा किया, तो हम जान की बाजी लगा देंगे

दूसरे राज्यों की अपेक्षा उड़ीसा में नदियों के निजीकरण की अधिक सम्भावनाएँ हैं, क्योंकि यहाँ पानी के निजीकरण के पक्षधर हमारे समुदाय को बदनाम करने

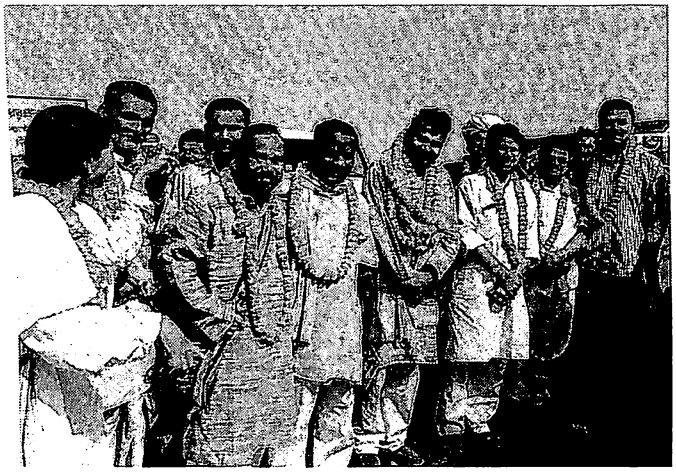

पर तुले हैं। अभी तक इस मसले पर नासमझी से समाज की संवेदनाएं खत्म हो रही थीं, पर जलयात्रा के दौरान यहाँ की संस्थाओं व जन संगठनों से दोबारा सक्रिय व संवेदनशील बनाने की कोशिश की गई।

उड़ीसा में नए सुखाड़ के क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हीराकुड बाँध से 40 कि.मी. बाद ही सुखाड़ और वीरान क्षेत्र का दृश्य दिखने लग जाता है। यहाँ पर बाढ़ और सुखाड़ का मिश्रित प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बरगढ़, देवगढ़ और सुन्दरगढ़ तीनों जिले नए बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बन रहे हैं। यहाँ पर जंगलों की आय के बारे में पूछने पर जानकारी मिली कि जंगली फल व तेन्दू पत्ता से प्राप्त आय लगातार नीचे जा रही है। गरमी में घास तो जल जाती है, परिणामस्वरूप बारिश में यहाँ मिट्टी का कटाव और जमाव बढ़ जाता है। इसे रोकने की चिंता तो यहाँ कुछ लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के मन में दिखाई दी, लेकिन उड़ीसा में तुरन्त जल-जंगल-जमीन के बचाव के लिए काम करने में कोई खास तेजी नजर नहीं आई।

जलयात्रा के रास्ते में पड़ने वाले स्कूलों-कालेजों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि पढ़ाई के साथ-साथ कार्ययोजना बनाकर विद्यार्थियों को अपने प्राकृतिक संसाधनों का चित्रण व संरक्षण तुरन्त शुरू करना चाहिए। इस विचार का सभी जगह स्वागत किया गया और इसे शिक्षा का नया आयाम मानकर इस दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता भी प्रकट की गई।

उड़ीसा के जन संगठनों व स्वैच्छिक संस्थाओं से एक खास आशा मेरे मन में जगी है कि उड़ीसा के भविष्य को सुखी, शान्तिपूर्ण और समृद्ध बनाने के लिए तत्काल एक संवाद शुरू करके निर्दलीय राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व दूरदृष्टि वाले नागरिकों को एक मंच पर लाया जाये। इनमें पानी की प्यास जगाकर, पानी सहेजने और इसके प्रबन्धन की नीति बनाने के लिए एक आन्दोलन खड़ा हो सकता है।

इस राज्य की जलनीति के घटक थे- डेल्टा की बाढ़ और कालाहांडी, बलांगीर, देवगढ़, सुन्दरगढ़ जैसे सुखाड़ क्षेत्र तथा पुरी जैसे समुद्र-तटीय क्षेत्रों की जैविक विविधता, भू-साँस्कृतिक उपलब्धता, पारिस्थितिकी, खेती एवं मानसूनी दबाव वाले क्षेत्र। स्थानीय विविधताओं का पूरा आदर करते हुए यहाँ की जलनीति बने। इसके लिए एक अभियान शुरू किया जाये। इस अभियान की सतत् सफलता तभी सम्भव है जबकि सुखाड़ वाले इलाकों में जन अभिक्रमों से जल बचाने का कार्य शुरू हो। इसमें आने वाली बाधाओं को रोकने के लिए सत्याग्रह और आन्दोलन चले। गरीबों के साझे जंगल, पानी और जमीन की मालिकी बनाए रखने के लिए जगह-जगह लोगों का मानस तैयार किया जाए, तभी उड़ीसा में प्रकृति का सिंहनाद गूंजेगा।

इस समय पूरे देश में निजीकरण का सबसे ज़्यादा खतरा यहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ की सरकार को निजीकरण पसन्द है।

इस समय पूरे देश में निजीकरण का सबसे ज़्यादा खतरा यहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ की सरकार को निजीकरण पसन्द है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी यहाँ आने के लिये लालायित हैं। इन्हें रोकने वाले श्री आदित्य पटनायक, श्री लिंगराज, श्री अच्युतदास, श्री मुक्तकण्ठ, श्री जगदानन्द, श्री ए. बी. स्वामी, सुश्री नीता जैसी बहुत सी क्रान्तिकारी ताकतें मौजूद हैं। अब देखना है, कौन सी ताकत जीतेगी? हमारे देश में नैतिक ताकतें जीतती रही हैं, इस बार भी यहाँ की नैतिक ताकत... उड़ीसा जल बिरादरी ही जीतेगी।

नज़र लागी बेईमान की

झारखंड

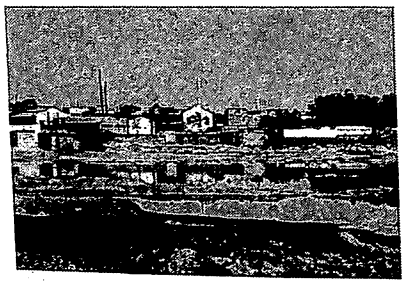

झारखंड प्रांत बिहार से अलग होकर देश का 28वां नया राज्य बना है। भौगोलिक रूप से यह राज्य पहाड़ों और वनों से घिरा भू-भाग है। देश का लगभग 45 प्रतिशत खनिज इस राज्य के हिस्से में आता है। लौह, तांबा, अभ्रक, कोयला और ऊर्जा के क्षेत्र में काम आने वाला यूरेनियम भी इस राज्य में पाया जाता है।

औद्योगिक विकास की दिशा में इस राज्य का देश में अग्रणी स्थान है। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, टाटा मोटर्स और टाटा समूह के कई अन्य उद्योग तथा एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक इकाई क्षेत्र इसी झारखंड में है। यह भी कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा सारंडा जंगल भी इसी प्रदेश के हिस्से में आता है। एक तरफ स्वर्ण रेखा नदी में आज भी सोना चुनने का काम होता है, तो दूसरी तरफ देश की अति प्रदूषित नदियों में शुमार दामोदर नदी भी यहीं है। औद्योगिक विकास के पूर्व नदियों के जल से ही झारखंड के मूलवासियों का जीवन यापन होता था, परन्तु औद्योगिक विकास के कारण झारखंड की लगभग सारी नदियाँ प्रदूषित हो चुकी हैं। टाटा स्टील कम्पनी के माध्यम से जमशेदपुर में जल प्रबन्धन की दिशा में कार्य करने के लिए फ्रांस की 'विवेन्डी वाटर' कम्पनी आयी थी, परन्तु उसे वापस जाना पड़ा। झारखंड में बड़ी-बड़ी औद्योगिक परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं। झारखंड की खनिज सम्पदा पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की गिद्धदृष्टि आज भी है तथा औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन कर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की शर्तों के तहत हमारे देश की सरकार उन्हें सौंप देना भी चाहती है। झारखंड की सड़कों के दोनों ओर नये औद्योगिक क्षेत्रों के बोर्ड स्पष्ट दिखाई दिए। सरकार भी किसानों की जमीन कब्जा कर उन्हें मनमाफिक हाथों को सौंपने की जल्दी में दिखी। अगले विधानसभा चुनाव तक संभवत: विस्थापन न हो, पर अन्तत: तो होगा ही।

एक तरफ स्वर्ण रेखा नदी में आज भी सोना चुनने का काम होता है, तो दूसरी तरफ देश की अति प्रदूषित नदियों में शुमार दामोदर नदी भी यहीं है।

इस साल झारखंड की सरकार ने पूरे प्रदेश को सूखा क्षेत्र घोषित किया है। दिलचस्प बात है कि झारखंड के एक बड़े भू-भाग में धान की फसल होती है। वह भी पूरी तौर पर बरसात के पानी पर निर्भर है। अगर वर्षा नहीं होती, तो गांव का गांव रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन करता है। यह अजीब बात है कि अधिक पानी की फसल तो बोते हैं, पर अधिक पानी का संग्रहण नहीं करते।

झारखंड में बेकारी एवं बेरोजगारी की समस्या ने उग्रवादी गतिविधियों के लिए जमीन तैयार की है। झारखंड के अधिकांश जिले उग्रवाद से प्रभावित हैं। झारखंड में शराबखोरी की समस्या भी प्रमुख है। शराबखोरी के कारण मजदूर वर्ग संगठित नहीं हो पाता और न अपने हालात पर सोचना चाहता है। झारखंड के कई जिले आदिवासी बहुल जिले हैं। यहां पर कुल 31 आदिवासी समूह के लोग रहते हैं, जिसमें सात आदिम जनजाति समूह हैं । झारखंड राज्य बनने के बाद सरकारी एवं प्रशासनिक लूट बढ़ी है तथा गांव स्तर पर दलालों की संख्या भी बढ़ी है।

ये सभी कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं, जिनके चलते लोगों के मानस में पैठे बगैर जलयात्रा के उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं दिखती। श्री ओमप्रकाश जैसे साथियों ने पानी का काम करने की चिंता जरूर दिखाई। तय हुआ कि जलबिरादरी शीघ्र ही राज्य के बुद्धिजीवियों, बुनियादी समझवाले राजनेताओं, छात्रों तथा उद्योगपतियों के बीच जल संसाधन के महत्व को रखेगी। उन्हें बतायेगी कि पानी बचेगा, तभी उद्योग व शेष समृद्धि बची रह सकेगी। रांची-जमशेदपुर की बहुमंजिला आर्थिकी के बीच मैंने बोतलबंद पानी नहीं पीने का संकल्प दोहराया। कहा कि जो उद्योग प्रदूषण फैला रहे हैं, उन्हें कचरा समेटना ही होगा, वरना कोई बड़ी बात नहीं कि बिरसा मुंडा के इस प्रदेश की समृद्धि फिर कभी न बचे। फिलहाल प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के खिलाफ कुछ बीज बोने में हम सफल रहे।

जो उद्योग प्रदूषण फैला रहे हैं, उन्हें कचरा समेटना ही होगा, वरना कोई बड़ी बात नहीं कि बिरसा मुंडा के इस प्रदेश की समृद्धि फिर कभी न बचे।

पानी का भोग भी, सूखा भी

महाराष्ट्र

बापू की कुटिया सेवाग्राम के राष्ट्रीय जल-सम्मेलन में जल बिरादरी के हम सब साथी इकट्ठे हुए। हमने दो दिन के जल-सम्मेलन में जलनीति-2002 को बदलवाने की घोषणा की। यहीं पर नगर निगम की अध्यक्षा के हाथों से जलनीति-2002 की होली जलाई। इस अवसर पर पूरी जल-बिरादरी और शहर के लोगों ने भाग लिया और सभी ने जलनीति को जलाया।

"जल कोई व्यापार की वस्तु नहीं, जीवन का आधार माना जाये। इस पर सबका समान हक कायम रहे। इसका निजीकरण नहीं किया जाये। नदियों पर समाज का मालिकाना बना रहे। नदी किसी को भी नहीं दें। नदियों को जोड़ने का विरोध करें। जल संरक्षण का कार्य सब जगह राज और समाज मिलकर करें।" उक्त निर्णयों को देश भर में लागू कराने हेतु समाज की तैयारी जल साक्षरता द्वारा होगी। यह निर्णय हुआ।

जल साक्षरता आन्दोलन में महाराष्ट्र अगुवाई करने को उत्सुक दिखा। इसे लेकर नौजवान श्री अमोल, सुश्री अपर्णा, डा. नन्दा आदि बहुत उत्साहित हैं।

सुश्री विभा गुप्ता जी और सुश्री अमला जी के सान्निध्य से ही यह जलयात्रा इस प्रदेश में चली। यहाँ के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी जितनी रुचि ले रहे थे, इनसे ज़्यादा यहाँ के किसानों में रुचि दिखाई दी। इस राज्य के मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों ने इस यात्रा में उत्साह दिखाया।

श्री आर. आर. पाटिल जी यात्रियों को अपने मूल घर लेकर गये। उन्होंने अपने काम भी दिखाये। यहाँ के मंत्री भी हमारे काम देखने अलवर आये। यात्रा के दौरान क्या कर्मचारी, क्या इन्जीनियर सभी ने राजस्थान के काम देखकर, अपने प्रदेश में भी इसी तरह के काम करने का निर्णय जताया। इस राज्य में एक तरफ विकसित खेती के नाम पर ज़्यादा पानी से पैदा होने वाली फसलों पर जोर है, तो दूसरी तरफ सजीव खेती के जरिए पानी बचत का भी जोर दिखाई दिया।

म्हसवाड़ तहसील के सभी गाँव टैंकर पर ही निर्भर हैं। ... बैंक गाँव-गाँव में टैंकर का पानी इकट्ठा करने बाबत प्लास्टिक की बड़ी-बड़ी टंकियाँ कर्ज पर दिलवा रहे हैं।

यह प्रदेश संगठित होकर काम करने का अनुभवी प्रदेश है। इस अनुभव से अन्न बहुत मिला, लेकिन धरती को हानि हुई। धरती का पेट खाली हो गया। देश के 40 प्रतिशत बाँध बनाने वाला प्रदेश आज बेबस है। अजीब बात है कि एक ही जगह गन्ना भी दिखेगा व पीने के पानी के टैंकर भी।

इसका परिणाम यह है कि सूखे की मार से प्रदेश भर में आज भी लोग तरस रहे हैं। सतारा जिले की म्हसवाड़ तहसील के सभी गाँव टैंकर पर ही निर्भर हैं। शोलापुर, उस्मानाबाद सभी प्यासे हैं। प्लास्टिक बिक्री करने वालों के पौ-बारह हैं। बैंक गाँव-गाँव में टैंकर का पानी इकट्ठा करने बाबत प्लास्टिक की बड़ी-बड़ी टंकियाँ कर्ज पर दिलवा रहे हैं।

पानी के नाम पर पाइप, टैंकर व टंकी की बिक्री ही बढ़ रही है। यह प्रदेश पानी का सुन्दर बाजार जैसा लगता है, जहां साइकिल-रिक्शा, गधा-घोड़ा, ट्रेक्टर, टैंकर और मोटर साइकिल सभी पानी ढोते हुए दिखाई दिये।

इस राज्य में पानी की कमी के कारण बहुत से लोगों ने आत्महत्यायें की हैं। इनके परिवारों से मिले, पता चला कि पानी के लिए कर्ज करके कुएँ खोदे। पानी नहीं निकला, तो फिर कुएँ खोदे... फिर भी सूखा मिला। अन्त में हताश होकर अपनी जीवन-लीला को ही सुखा लिया। इस प्रदेश में किसानों में सनाई की परम्परा मौजूद है।

इस प्रदेश में मराठों से लेकर सिन्ध, कोहली सभी पानी के जानकार थे। जगह-जगह पानी बचाने का कार्य करते थे। इसी से जीवन चलाते थे। आज विकास की दौड़ में ये सब कुछ भूल गये हैं।

यहां गाड़गे सन्त सफाई वाले अद्‌भुत सन्त हुए। इसी प्रकार किसानों की खेती के रक्षक कहलाने वाले, मजदूरों के हितैषी, गरीबों के मसीहा और सब तरह के आध्यात्मिक पुरुष यहां हुए; लेकिन पानी के नए संकट को समझाना अभी भी बाकी है। अभी इस दिशा में अन्य कोशिशें भी हुईं, लेकिन वह अभी पूरे प्रदेश में नहीं फैल सकी है। इस प्रदेश की जलनीति भूजल भण्डारों की सुरक्षा का कोई पुख्ता इलाज नहीं सुझाती।

इस राज्य में विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र सभी जगह मैं गया, लेकिन ज्यादातर जगह पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई थी। कुछ अच्छे काम भी दिखे। ये काम हिवरे बाजार के सरपंच ने किये हैं। जैसे उनके गुरु श्री अन्ना हजारे ने किये हैं, लेकिन केवल ये सब अपने गाँव तक सिमट कर रह गये। पानी का व्यापार यहां बहुत बढ़ा है। जब तक यह रहेगा, तब तक समाज पानी बचाने में नहीं जुटेगा।

सरकारी-गैरसरकारी सहायता ने इसी जिले में अन्य संस्थाओं ने वाटर शेड के नाम पर कई काम किये, पर सभी कुछ सरकारी सहायता पर निर्भर है। समाज का जल-आन्दोलन यहाँ नहीं बन सका। इस प्रदेश में ऐसे कार्यों की बहुत अनुकूलता है। यहाँ राजनेता भी दूसरे राज्यों से कुछ अलग हैं। पानी जैसे काम में जुटना चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्रियों ने भी समय-समय पर काम किया, लेकिन ये काम खास

एक व्यक्ति के चारों तरफ सिमट गये। श्री शरद पवार जी ने बारामती में अच्छा जल संरक्षण कार्य किया था। अब इनका भतीजा श्री राजेन्द्र पवार भी इस दिशा में बहुत चिन्तित है। वह अपने किसानों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को पानी बचाने हेतु तैयार कर रहे हैं। श्री राजेन्द्र पवार जल बिरादरी में स्वयं रुचि लेकर इस काम में जुड़े हैं।

महाराष्ट्र जल बिरादरी प्रत्येक जिला स्तर पर गठित हुई है। प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ पानी का कुछ कार्य हो, ऐसी तैयारी जल बिरादरी ने की है। सुश्री अमला रुइया, डॉ. नन्दा शिवगुण्डे, श्री दीपक मेपानी, श्री दिलीप पटेल, श्री जाय मंगलानी ने संगठन को इस क्षेत्र में शुरू किया। सुश्री विभा गुप्ता, श्री ज्ञानेन्द्र जी और श्री लोहिया जी आदि ने मार्गदर्शन दिया। पंढरपुर के संतों और पुजारियों का भी योगदान इस काम में रहा। महाराष्ट्र की नगरपालिकाओं, जिला परिषदों और पंचायतों का काफी सहयोग मिला। अधिकारियों ने भी इस यात्रा में रुचि लेकर सहयोग दिया। बातें सुनीं। इस दिशा में काम करने का वायदा भी किया।

नासिक, जो कभी प्याज के लिए प्रसिद्ध हुआ, वह अब पानी की कमी से प्रसिद्ध हो गया है।

नासिक, जो कभी प्याज के लिए प्रसिद्ध हुआ, वह अब पानी की कमी से प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ के गाँव तो अब प्याज को छोड़ रहे हैं। कम पानी वाली फसलें ढूंढ रहे हैं। विकास के नाम पर नया करने की चाह रखने वाले यहाँ के लोग बहुत उत्साहित हैं।

यहाँ के इन्जीनियर, व्यापारी तथा उद्योगपतियों को नदी जोड़ कर दूसरों के पानी का उपयोग करना अच्छा लगता है। आज़ादी मिलते ही ये इस काम में जुट गये थे, लेकिन अब तो इन्होंने अपना और पराया सभी खत्म कर दिया है। बिन पानी सब सून बनता जा रहा है। गरीब तो बेपानी हो गया है, पर उद्योगपति पानी का व्यापारी बनकर पानी का पैसा कमा रहा है। यहाँ पानी की लूट रोकने का काम वास्तविक और जरूरी है। इसी में जल बिरादरी लगी है।

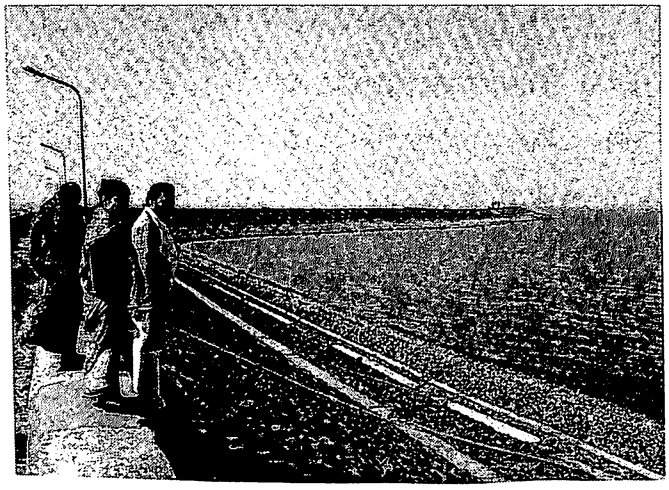

महाराष्ट्र की कोयना-कृष्णा नदियों के तट देखने में सुन्दर-मनोरम दिखाई देते हैं। यहाँ के बैल भी पैने सींगों वाले और चुस्त हैं। सुन्दर बैल अब ट्रेक्टर से लड़ रहे हैं। ट्रेक्टरों ने बैलों की लड़ाई में अभी अपनी जगह बना ली है, फिर भी सड़कों पर गन्ने की गाड़ी ढोते हुए केवल ये बैल ही दिखाई देते हैं। अकलूज-शोलापुर की सड़कें इन्हीं बैलों से भरी रहती हैं। दिन-रात चलने के बावजूद ये हर समय चुस्त दिखते हैं। फिर भी डीजल खर्च करने वाला ट्रैक्टर ही पनप रहा है। घास-फूस पर जिन्दा रहने वाला बैल मर रहा है। अब पानी की कमी से घास-फूस भी कम होती जा रही है। इसकी कमी गाय-भैंस-भेड़-बकरी को लील रही है।

पूरी मुम्बई को एक सौ वर्षों से बोरीवली का जंगल ही पानी पिला रहा है।

यहाँ के जंगलों में पुराने अच्छे जल स्रोत अभी भी देख सकते हैं। बोरीवली नेशनल पार्क में बौद्धकाल की जल संरक्षण परम्परा बची हुई है। अभी भी यहाँ रहने वाले इन्हीं भूमिगत कुओं से पानी पीते हैं। लेकिन यह पानी वहीं क्यों हैं, जहाँ जंगल है ? पूरी मुम्बई को एक सौ वर्षों से बोरीवली का जंगल ही पानी पिला रहा है। 'कान्हेरी केव' नामक जगह बौद्धकाल के जल गौरव को बढ़ाती है। यह गुफा आज भी खरी है। वर्षा जल बहकर एक पहाड़ी गुफा में इकट्ठा हो जाता है। जब मैं गया तो महिलायें इसी गुफा से अपने पीने के लिए पानी लेकर आ रही थीं। वे इसी से घर का पूरा काम करती हैं।

सुन्दर पहाड़ और समुद्र से घिरा राज्य होने के कारण महाराष्ट्र सांस्कृतिक समृद्धि वाला राज्य है। समाज एक-दूसरे का लिहाज करता है। यहाँ जातिगत भेदभाव नहीं है, पर राजनीतिक व दलगत भेदभाव भयानक है। दलों ने नई जातियाँ बनाई हैं। नई जातियों में किसी तरह का प्रेम यहाँ नहीं दिखता। सत्ता पाने की लड़ाई और टकराव स्पष्ट दिखती है। यह टकराव सत्ता के बँटवारे में भी मिलकर ही चलता है। जब अखाड़ा बदलना हो, तो यहाँ का समाज अखाड़ा बदल लेता है।

इस राज्य में सीमेन्ट कंक्रीट के जंगल, मोटरसाइकिलें व कारें बढ़ती जा रही हैं। समाज प्रकृति से दूर होकर तेजी से भौतिकवादी हुआ है, किन्तु अब कुछ समझदार लोग पीछे मुड़कर भी देखने लगे हैं। पुराने किसानों के सजीव खेती के प्रयोग यही बताते हैं कि जहाँ कहीं वर्षा के जल पर ही खेती करने का चलन बढ़ा, वहाँ किसानों की कर्ज में रुचि नहीं दिखती। वे किसान स्वतंत्र दिखते हैं। अभी तक सरकारों के कर्ज माफी अभियानों ने कर्ज लेकर घी पीने को बढ़ावा दिया है। अभी भी बैंक इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। रुपये वाले बैंक ने ही यहाँ का प्राकृतिक बैंक खाली कराया है। आज जहाँ धरती में पानी नहीं है, वहाँ के किसान अपनी जगह छोड़ कर शहरों में जाकर बेघर बनते जा रहे हैं। इस राज्य में पलायन का नया दौर चल पड़ा है।

रुपये वाले बैंक ने ही यहाँ का प्राकृतिक बैंक खाली कराया है। परिणामस्वरूप इस राज्य में पलायन का नया दौर चल पड़ा है।

अब विकास के इस तरीके से पलायन रुकने वाला नहीं लगता। लगता है कि प्रलय का दौर म्हसवाड़ (सतारा महाराष्ट्र) से शुरू होकर एक-तिहाई भू-भाग में फैल गया है। यह तो कुदरत ही रोक सकती है या फिर महाराष्ट्र का समाज खेती उद्योग में अनुशासित होकर बदलाव करे; जंगल को सबके भविष्य का साझा जीवन आधार मानकर इससे इतना ही ले, जितना अपनी मेहनत और पसीने से लौटा सके। यहाँ की राजनैतिक पार्टियां तो समाज को पहले कामचोर बनाकर, बाद में लुटेरा बनाने में मदद कर रही हैं।

राष्ट्रीय जल बिरादरी ने पूरे महाराष्ट्र में घूम-घूम कर कहा - ''मेहनत करके वर्षा की बूंदों को सहेजो, इसी से जीवन की जरूरत पूरी करो। प्रकृति प्रसन्न होकर तुम्हें सुखी, सन्तोषी और समृद्ध बनायेगी।'' इसी बात ने महाराष्ट्र में एक लहर पैदा कर दी है। यहाँ वर्षा जल सहेजना तेजी से शुरू हुआ। उन्होंने इस दिशा में तत्काल काम भी शुरू कर दिया। यात्रा में बहुत सी जगह काम शुरू कराकर मेरा उत्साह बढ़ता रहा। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पानी का सवाल महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर गया।

पर्यटन ही मारे, पर्यटन ही जिलाये

गोवा

11 अप्रैल, 2003 को जलयात्रा गोवा पहुँची। यहाँ बसन्त के बाद पेड़ों पर अच्छी हरी-भरी नई पत्तियाँ थीं, अच्छा मौसम और तापथा। हमारी जलयात्रा टीम में गोवा पर्यटन की चाह और उत्साह भी भरपूर था । मैंने इस राज्य की हरियाली और पानी को देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया । हमें लेने आये हमारे पुराने साथी श्री कलानन्द मणि यहाँ सबसे पहले मिले। इनसे भी मैं काफी समय बाद मिला था। इनके चेहरे की प्रसन्नता देखने लायक थी। बात-बात में हमारे एक अन्य मित्र श्री कलाड़ अलबारिश, इनका परिवार तथा गोवा के अन्य पानी, प्रकृति और पर्यावरण प्रेमियों का दल यहाँ इकट्ठा हो गया। बस! फिर सबके साथ एक बस और एक गाड़ी में बैठकर, जल यात्री यहाँ के पुराने तालाब देखने गये।

गोवा से राजस्थान तक की जल इन्जीनियरिंग तकनीक में मामूली अन्तर है; यूं पूरे भारत में जल दर्शन एक जैसा ही है।

पुराने तालाबों से केला, सुपारी, नारियल आदि की फसलें कैसे उगती हैं... देखी । तालाबों को बनाकर सिंचाई व्यवस्था व तालाबों की पाल पक्की बनाने की बाध्यता देखी। मौखी पत्थर काट कर कैसे सुन्दरता और कौशल से पाल बनती है, यह सब यहाँ के किसानों से समझा। कुछ श्री कलाड़ ने भी हमें समझाया, क्योंकि इन्होंने इस पर गहन अध्ययन किया था। कुछ श्री कलानन्द ने भी बताया। ये दोनों ही आजकल जल संरक्षण में बहुत रुचि रखते हैं।

गोवा में समाज के साझे कई तालाब देखे। तीन निजी तालाब भी देखे । इन्हें देखकर लगा कि गोवा से राजस्थान तक की जल इन्जीनियरिंग तकनीक में मामूली अन्तर है; यूं पूरे भारत में जल दर्शन एक जैसा ही है। भारतीय जल दर्शन... जल से खेती, उद्योग और जीवन चलाने के पीछे पानी का व्यापार करने की इजाजत नहीं देता। जल जीवन का प्रकृतिमय संसाधन है । इसे प्राकृतिक तरीके से ही सहेजकर उपयोग करने का भाव अभी भी जहाँ-तहाँ बरकरार है ।

जहाँ यह भाव नहीं, वहाँ बरबादी शुरू हो गई है ।

गोवा में ही मार्सेला पंचायत में हम गये। यहाँ का सारा पानी गोल्फ कोर्स बनाने वाली कम्पनी ने खरीद लिया है। उनके टैंकरों ने धरती से सारा पानी निकाल लिया है । मैंने स्वयं बिल्कुल सूखे चार कुएँ देखे।

हमारे साथ पंचायत अध्यक्ष, सरपंच और सदस्य आदि थे। इन सभी ने गोल्फ वालों के विरुद्ध पंचायत की तरफ से केस किया । ये जीत गये। फिर भी पानी की लूट बन्द नहीं हुई। सब यही बातें कर रहे थे। मैंने पूछा- ''पंचायत तो मालिक है। अब क्यों नहीं रोक पाते हैं आप?'' ये सब एक-दूसरे की तरफ देखने लगे। इन सबने माना कि ये भाई भी अपनी पंचायत के पानी को स्वयं सहेजने लगें, तभी मालिकाना बोध इनके मन में जगेगा। फिर गोल्फ को रोक सकेंगे।

पंचायतों को जल बचाने का रचनात्मक कार्य तथा जल के अधिकार सुरक्षित रखने हेतु संघर्ष करना चाहिए। संविधान का 73-74वाँ संशोधन आपको पानी के सारे हक देता है । यह जलनीति-2002 के विपरीत है। इसे बदलवाने हेतु सरकार पर दबाव बनायें; पंचायत के पक्ष में हुए फैसले को लागू करायें। इस पर सरपंच, पंच आदि सभी पक्षकारों ने मिलकर सोचा । पंचायतों ने जल बचाने के लिए लड़ने का संकल्प भी लिया । साली गाँव में पंचायत पार्षदों के साथ-साथ अन्य जिम्मेदार लोगों की सभा में भी ऐसी ही बातें हुईं; लेकिन यहाँ कुएँ सूखने का दुख और गुस्सा अधिक दिखाई दिया । सभी ने मिलकर गोल्फ को पानी बेचने का निर्णय बदलवाने का निर्णय लिया ।

इसके बाद हम गोवा रिसोर्स सेन्टर में पहुंचे । यहाँ श्री मार्टिन ने बहुत अच्छे से सभा संचालन किया । यहाँ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की लूट को रोकने का संकल्प लिया गया। इन्होंने समाज के अनुकूल जल नीति बनवाने का संकल्प भी लिया।

सोनसोहा पंचायत में जो गोवा का डम्प एरिया बना है, इससे तालाब पूरा दूषित हो गया है।

गोवा में तालाबों, कुण्डों, झीलों और झरनों के किनारे हमारे उत्सव आयोजित होते रहते हैं। तालाबों के किनारे कूड़ा भराव क्षेत्र में तब्दील हो रहे हैं। सोनसोहा पंचायत में जो गोवा का डम्प एरिया बना है, इससे तालाब पूरा दूषित हो गया है। इस दूषित क्षेत्र से दूर-दूर तक भूजल प्रदूषित हो गया है। आज यहाँ की नदियाँ गन्दी हो गई हैं।

यहाँ के सालमोला, सालिग और मारकेश जैसे सुन्दर प्राकृतिक झरने भी दूषित बन गये हैं। इनका प्रदूषण रोकने हेतु हमें मान्डवी नदी के किनारे के समाज को आन्दोलित करने की तैयारी करनी होगी। यहाँ का समाज आन्दोलनरत होकर झरनों को बचाने हेतु तैयार दिखता है।

गोवा छोटा राज्य है। इसलिए यहाँ पंचायतों के प्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री और सरकार को प्रभावित कर लेते हैं। सरकार पर दबाव बनाकर इन्होंने अपने कुएँ के जल की लूट रुकवा ली है, लेकिन विकसित राज्य होने के कारण जल के अनुशासित उपयोग करने हेतु ये तैयार नहीं दिखाई दिये। अब तो पाइप लाइन के जरिए पर्याप्त जल खर्च होने लगा है। हमने जल बचाने और कम उपयोग करने पर जोर दिया। कुछ लोग तैयार थे, पर अधिकतर चुप रहे। एक चिकित्सक ने अपना ऐसा घर बनाया है, जिससे उनकी जरूरत का पानी उन्हें वर्षा की बूंदों से ही मिल जाता है।

शिक्षा और विकास में गोवा के प्राकृतिक संसाधन उपयोग को बहुत महत्व दिया गया है। जब यह कम हो जाता है, तो लोग लड़ने लगते हैं।

शिक्षा और विकास में गोवा के प्राकृतिक संसाधन उपयोग को बहुत महत्व दिया गया है। जब यह कम हो जाता है, तो लोग लड़ने लगते हैं, लेकिन अपने जीवन में कम उपयोग करने की आदत अभी उन्होंने नहीं डाली है। प्रकृति के साथ जीने की आदत डालने की शुरुआत यहाँ के समाज को स्वयं करनी होगी, तभी गोवा बचेगा। गोवा में समाज और राज जैसे आज चल रहे हैं, इस रास्ते गोवा जल्दी ही अकाल के मुँह में चला जायेगा। गोवा बचाना है, तो गोवा का जल बचाना ज्यादा जरूरी है।

बहुत कुछ सीखने को है यहां

कर्नाटक

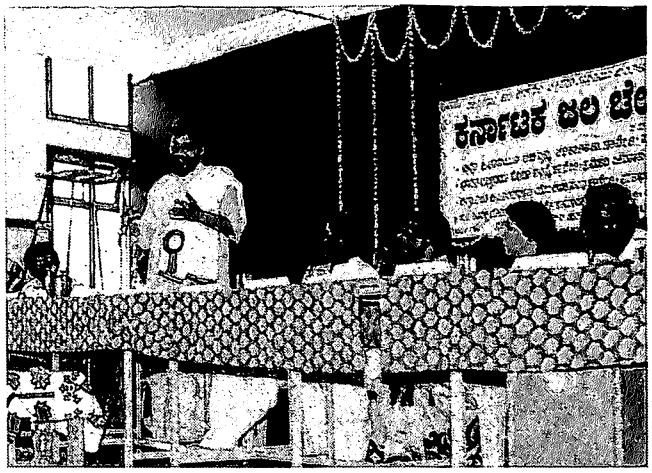

राष्ट्रीय जलयात्रा ने 13 अप्रैल, 2003 को कर्नाटक के धारवाड़ जिले में प्रवेश किया। इस राज्य में यात्रा को लेकर अत्यन्त उत्साह देखने को मिला। इस राज्य की जलबिरादरी के अध्यक्ष एक बहुत ही योग्य राजनेता श्री डी.आर. पाटिल हैं। इन्होंने बहुत ही उत्साह व समझ से इस प्रदेश में जलयात्रा का आयोजन किया। प्रत्येक दिन बहुत से कार्यक्रम आयोजित हुए । प्रत्येक कार्यक्रम में सभी पार्टियों के विधायक और पंचायत प्रतिनिधि जरूर आये। मन्त्रियों और अधिकारियों का पूरा सहयोग इस प्रदेश में रहा। 500 से लेकर 35,000 की संख्या वाली बैठकें इस राज्य में आयोजित हुईं। साधु, संन्यासी और जगद्गुरु सभी की भागीदारी बराबर बनी रही।

यहाँ कहीं-कहीं साँस्कृतिक-राजनीतिक समृद्धि दिखाई दी, तो गदग, धारवाड़, शपचर तक सूखा, उदासी के बीच धरती का सूनापन भी दिखाई देता है । पानी की कमी के कारण यहाँ किसानों का आन्दोलन भी चर्मोत्कर्ष पर था। आत्महत्यायें भी बहुत हो रही हैं। आत्महत्याओं को रोकने के लिए सरकारी-गैर सरकारी सभी प्रयास जारी हैं, लेकिन पीड़ित समाज इस कष्ट से कैसे बचे ? कर्ज, पानी की कमी और भूख सभी को सताते हैं। परिवार के परिवार जहर खाकर सदा के लिए सो रहे हैं। इन्हें जगाने का विश्वास पानी के काम से ही सम्भव है।

अब यहाँ की कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और इन्द्रावती सरीखी सदानीरा नदियों में

भी पानी कम होता जा रहा है। यहाँ चन्द्रप्रभा-घटप्रभा नदी में सिंचाई प्रबन्धन हेतु कुछ सामुदायिक प्रयास हुए हैं। बादलों पर भौतिक दबाव बनाकर, वर्षा कराने का प्रयास चल रहा है। यहाँ की सरकार ने पानी के लिए बड़े-बड़े प्रयास किये हैं।

इस यात्रा के पहले दिन ही गदग जिले में असूण्डी और होलकोटी गाँव में श्रमदान से जल सहेजने का कार्य शुरू करा सके। पूरे गाँवों ने सर्वसम्मति से कार्य शुरू किया। यहाँ पर लेखा-जोखा की पारदर्शिता सामने थी। कर्नाटक राज्य के पंचायत सचिव भी इस यात्रा में शामिल हुए। हजारों की उपस्थिति में सचिव ने स्वयं सब के सामने कार्यों की रपट प्रस्तुत की। कुछ कमी थी, इस पर सफाई पेश हुई। यह पारदर्शिता लोकतंत्र को मजबूत करने वाली है। जल बिरादरी अध्यक्ष श्री डी.आर. पाटिल जी के कारण ही यह सम्भव हुआ। असूण्डी-हर्टी के दोनों प्रयोग देशभर में फैलाने लायक हैं।

असूण्डी-हर्टी के दोनों प्रयोग देशभर में फैलाने लायक हैं।

इस राज्य के विश्वविद्यालय तथा मुख्य रूप से सिंचाई, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की ऊपरी तौर पर ही सही, दिलचस्पी इसलिए दिख रही थी, क्योंकि मंत्री और विधायक भी रुचि ले रहे थे। फिर भी उत्तर के राज्य अधिकारियों से ये बहुत अच्छे हैं। जिम्मेदारी निभाते हैं। उत्तर के सत्ता के गलियारों में सिर्फ बैठक होती है। यहाँ ऐसा नहीं देखा। इसीलिए यहाँ के राजनेता पानी जैसे सवाल पर हमारे साथ शामिल होकर, हमारी ही भूमिका निभा रहे थे।

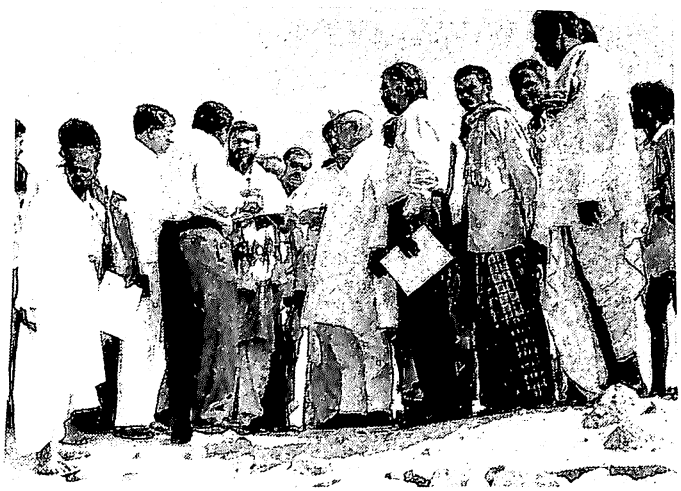

इस राज्य की स्वैच्छिक संस्थाएँ बहुत बड़ी हैं, लेकिन 'समूह' जैसी संस्थाएँ पानी पर बहुत सक्रिय नजर आयीं। यहाँ बहुत-सी संस्थाओं ने इकट्ठे होकर हजारों स्वयंसेवकों को बुलाया था। इससे संस्थाओं का पानी पर परियोजना आधारित जुड़ाव तो दिखा, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव कम ही नजर आया।

यहाँ के अलमट्टी बाँध के अतिथिगृह में हम ठहरे। अलमट्टी बड़ा बाँध है, लेकिन पानी की कमी के कारण खाली ही रहता है। इस पर राज्यों के विवाद भी चल रहे हैं। यहाँ एक सुन्दर पार्क भी है, जिस पर इस क्षेत्र की धर्म, संस्कृति और सभ्यता उकेरने का प्रयास किया गया है। यह कार्य वन विभाग कर रहा है।

दावण गैठ, श्री गर्रे जी जगद्गुरु का स्थान है। यहाँ जलयात्रियों को श्री जगद्गुरु की तरफ से बहुत स्वागत, सम्मान व सत्कार प्राप्त हुआ। इन्होंने जल बचाने का काम भी शुरू किया है। इनके भक्तों ने भी गुरु जी के 60 वर्ष पूरे होने पर 600 तालाब बनाने का निर्णय सुनाया। काम शुरू भी हुआ। श्री जगद्गुरु जी ने राजस्थान में अलवर पधार कर हमारे कार्य को भी आशीर्वाद दिया।

कर्नाटक राज्य के सिंचाई, खेती और जल से जुड़े तीन मंत्री तथा 10-12 विधायक हमारा कार्य देखने आये। इन्होंने वापस लौटकर वैसा किया है। मुझे केवल श्री डी. आर. पाटिल जी की जानकारी है। इन्होंने अपने क्षेत्र में एक हजार से अधिक तलाई बनाई हैं। अपने क्षेत्र में जल चेतना बढ़ाने का भी अद्भुत कार्य इन्होंने किया है। श्री पाटिल के काम से देश में राजनीतिक और सामाजिक गठजोड़ की पहल की जा सकती है। इन्होंने राजनीतिक सहायता उपलब्ध होने के बावजूद बिना पैसे सामाजिक सहायता व श्रमदान से काम किया। इस कार्य को बहुत फैलाया। श्री पाटिल केवल अपने विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं

श्री गर्रे जी जगद्गुरु के भक्तों ने भी गुरु जी के 60 वर्ष पूरे होने पर 600 तालाब बनाने का निर्णय सुनाया तथा श्री डी. आर. पाटिल जी ने अपने क्षेत्र में एक हजार से अधिक तलाई बनाई हैं।

रहे; यह काम पूरे कर्नाटक में विस्तार पा सके, इस हेतु इन्होंने पूरी निष्ठा से काम किया। इनके प्रयासों में इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई।

पिछले वर्षों में सूखे कर्नाटक और पानी वाले कर्नाटक का खेती में अन्तर कम हुआ। सभी क्षेत्रों में सिंचाई की खेती का चलन बढ़ा। इस चलन के कारण बाँध बहुत बने। इन बाँधों ने सिंचाई का पानी तो दिया, लेकिन इनकी क्षमता भी सीमित है। इस सीमा का उल्लंघन कर जब उद्योग, खेती और मानवीय जीवन की जरूरतें बढ़ गई, तो अब पानी की कमी सामने आ गयी है। अब गदग कपास नहीं उगा पा रहा है। हुबली, गदग, धारवाड़ पूरा क्षेत्र पहले कपास का केन्द्र था। बीच के दौर में यहाँ कपास की जगह ज्यादा पानी की फसलें आईं। इनमें धान, केला व गन्ना आया। इससे पानी की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ी। भूजल भण्डार खाली हुए। नतीजा सामने है कि अब पुरानी कपास की खेती भी सम्भव होती नहीं दिखती।

...इसी कारण यहाँ जंगल व जंगली जीवों को मारने वालों को पनाह मिल जाती है... वीरप्पन जैसा नायक बन जाता है।

इस राज्य में महाराष्ट्र से कम, लेकिन बहुत से नये बाँध बने हैं। लेकिन इनका लाभ इतना नहीं हुआ है। यहाँ की शक्तिशाली सरकारें भी पानी के विवाद में फँसी रही। इन्होंने राज्यों के पानी के सवालों को राजनैतिक सीमाओं पर उठाया, जबकि पानी किसी राजनीतिक सीमा को नहीं मानता; यह तो भौगोलिक सीमाओं को ही मानता है। भौगोलिक सीमाओं में रहने वाले किसान एक जैसी खेती, वेशभूषा, आहार-विहार, सब कुछ मानें तो जीवन भरा-पूरा आगे बढ़ सकता है। यहाँ के जंगलों में खदानें चल रही हैं; जंगल कट रहे हैं। जंगल काटने-कटवाने वाले ही अब यहाँ के नायक बन गये हैं। इस राज्य में जंगल और जंगल वालों में अपनेपन का आत्मीय रिश्ता नहीं दिखता। इसी कारण यहाँ जंगल व जंगली जीवों को मारने वालों को पनाह मिल जाती है... वीरप्पन जैसा नायक बन जाता है।

नागर होले से वनवासी विस्थापित हो गये। सरकार ने अच्छी तरह ही विस्थापित किए, लेकिन इससे जंगल और जंगली जीव बचने लगे हों, ऐसा हमें कहीं दिखाई नहीं दिया।

विजयदशमी के दिन सब गाड़ियां हरे केले के पेड़ों, फूलों से लदी हुई दिखाई देती हैं। उस दिन पूरे कर्नाटक... खास कर बंगलौर में ऐसा लगता है, जैसे पूरा समाज प्रकृतिमय हो गया है। ऐसा उत्सव सचमुच प्राकृतिक सौन्दर्य का प्रतीक है। यह प्राकृतिक सौन्दर्य-प्रेम हमारे जीवन को प्रकृतिमय बनाता है, लेकिन इस प्रदेश में पेड़, जंगल, बाग-उद्यान काट कर सीमेन्ट, कंकरीट के नये जंगल अधिक बन रहे हैं। घरों से लेकर उद्योगों तक का गन्दा जल नदियों में जाने से प्रदूषण बढ़ रहा है। बंगलौर की गिनती देश भर के सबसे अच्छे पेयजल वाले शहरों में है।

किसानों की भोग-लालसा से अब कहीं-कहीं हमारा देश भी नये सिरे से दूषित होने लगा है।

"पहले पानी दूषित करो, फिर शुद्ध करो। इसके लिए दुनिया के बड़े सेठों की मशीन खरीदो। भारत में जैसा गरीब देश सेठों का कर्जदार बनता जाये।" – यह प्रक्रिया कर्नाटक में ज़्यादा दिखाई दी। विकसित राज्य इसी प्रकार बनते हैं। इस मान्यता ने हमारा बहुत नुकसान किया है। अनुशासित जल प्रयोग का चलन यहां नहीं दिखता। संरक्षण और विकास के रिश्ते पूरे भारत में अब कहीं संतुलित नहीं दिखते। किसानों की भोग-लालसा से अब कहीं-कहीं हमारा देश भी नये सिरे से दूषित होने लगा है। यह प्रदूषण हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भयानक है।

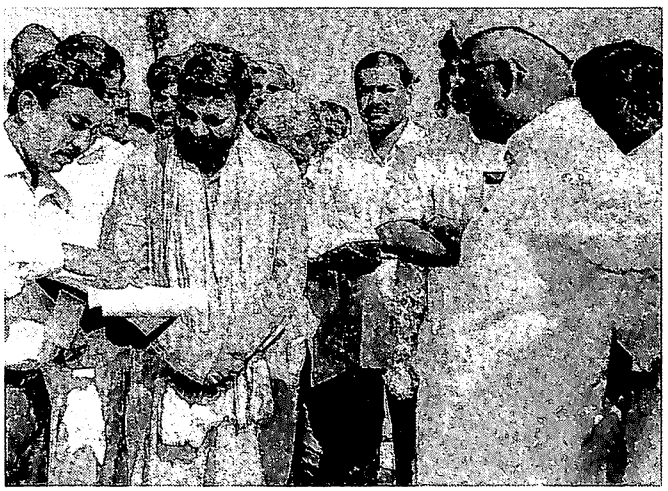

किसानों के जीवन में उभरते नये भय से मुक्ति हेतु इस प्रदेश में जगह-जगह मजबूत आन्दोलन दिखाई दे रहा है, परन्तु यह आंदोलन कुछ मांगने के लिए है। यह अपने अनुशासित प्राकृतिक रिश्तों को बनाने वाला नहीं दिखता। प्रकृति के साथ रहने, जीने का कौशल और प्रेमपूर्ण रिश्ता बनाने की चाह ज़्यादा नजर नहीं आई।

हाँ ! होलकोटी क्षेत्र में सजीव खेती की पहल अवश्य कुछ आशाजनक लगती है । इस प्रयोग से धरती से लेन-देन के रिश्ते भी समाज को समझ में आयेंगे। हमारा समाज जब तक धरती से लेन-देन के रिश्ते का ख्याल नहीं करेगा, तब तक धरती का स्वास्थ्य ठीक नहीं बना रह सकता। हमारी धरती का स्वरूप ठीक रहेगा, तो किसानों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ऐसी चेतना कर्नाटक से शुरू होगी । यह विकास और आध्यात्म दोनों के रिश्ते मजबूत करने वाला राज्य है । यह हम सब के लिए उदाहरण बन सकता है।

हाँ ! होलकोटी क्षेत्र में सजीव खेती की पहल अवश्य कुछ आशाजनक लगती है । इस प्रयोग से धरती से लेन-देन के रिश्ते भी समाज को समझ में आयेंगे ।

यहाँ की जलबिरादरी भी अलग है । यहाँ श्री डी. आर. पाटिल जैसे राजनेता, श्री साहूकार जैसा वैज्ञानिक, श्री जमादार जैसा शिक्षक, श्री रामप्पा जैसा क्रान्तिकारी इन्जीनियर मौजूद है । इसलिए मुझे इस जलबिरादरी से अधिक उम्मीद है । इस राज्य में जलयात्रा भी दूसरे राज्यों से अलग रही।

यहाँ की जलयात्रा में सबसे ज़्यादा लोग शामिल हुए । इस अकेले राज्य में ही 15 लाख से ज़्यादा लोगों से जल-संवाद हुआ। जल साक्षरता का आन्दोलन यहाँ सभी वर्गों को जोड़ सका। इस प्रदेश में हम छोटी-बड़ी ग्यारह नदियों के किनारे पाँच विश्वविद्यालयों, नौ कालेजों, बीस स्कूलों और चालीस जन संस्थाओं में जा सके । मेरी कर्नाटक यात्रा विरोधाभासी होकर भी उत्साहजनक रही। यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। दक्षिण दर्शन का पूरा लाभ कर्नाटक से मुझे प्राप्त हुआ। ऐसी यात्रा में पूरे दो वर्ष लगातार देश भर में जल-संवाद खड़ा करने का मेरा विचार और मजबूत बना। यहाँ के काम ने जल साक्षरता के प्रभाव का प्रत्यक्ष दर्शन भी कराया। इस प्रदेश को छोड़ते समय जलयात्रियों को उम्मीद बनी कि यहाँ प्रदेश भर में जल संरक्षण एवं अनुशासित जल उपयोग का संस्कार लगातार बढ़ेगा।

परजीवी राज खुद पर जीना सीखे

आंध्र प्रदेश

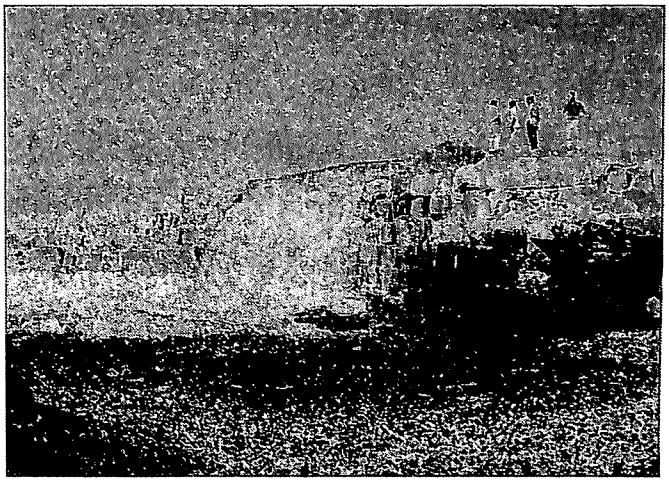

मुख्यमंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू के विधानसभा क्षेत्र कुप्पम में आज 22.04.03 को प्रवेश किया। कर्नाटक की बहादुर टीम ने जल संरक्षण व जल अधिकार के रक्षा संकल्प के साथ हमें आन्ध्र के लोगों को सौंपा। आन्ध्र में हमारा स्वागत आन्ध्र जलबिरादरी के युवाओं ने किया। यहाँ के परियोजना निदेशक भी हमारा स्वागत एवं अगुवाई कर रहे थे। सबसे पहले पंचायत प्रतिनिधियों, जिला अध्यक्ष व अधिकारियों ने कुप्पम विकास की वार्ता सुनाई; फिर टमाटर की खेती दिखाई। इस एक विधानसभा क्षेत्र पर मुख्यमंत्री जी ने सैकड़ों करोड़ खर्च किया है। इस खर्च से डीजल पम्प, बिजली पम्प, बैठक घर, गाड़ियाँ, कालेज भवन बहुत सुन्दर और बड़े-बड़े दिखाई देते हैं। बेस्वाद पानी से अभी इस राज्य की कुछ ऊपरी पैदावार बढ़ी दिखती है, लेकिन इस राज्य के आधे से अधिक भूजल के भण्डार खाली हैं। मूसी नदी नाला बनकर बह रही है। अब यह आस-पास बीमारी बढ़ाने का कार्य कर रही है। यहाँ पुराने जमाने की सभी जल संरचनाएँ नष्ट हो गई हैं। इस क्षेत्र में 300 से अधिक तालाब मूसी नदी को सदानीरा बनाए रखने का काम करते थे। एक तालाब भरने के बाद पानी फिर, नदी में चला जाता था और इसी नदी से फिर अगले तालाब में। इस तरह पानी का प्राकृतिक लेन-देन इस राज्य में था। नदियाँ और तालाब सब एक-दूसरे को जल देते रहते थे। कुछ अभी भी चल रहा है, लेकिन अब बदबूदार, सड़ा-गला, झागदार पानी ही इस नदी में रहता है। इसमें रासायनिक तथा अन्य सब प्रकार के प्रदूषण मौजूद हैं। नलकूपों से धरती का पेट फोड़कर सारा पानी निकाल लिया है।

मूसी नदी नाला बनकर बह रही है। अब यह आस-पास बीमारी बढ़ाने का कार्य कर रही है।

यहाँ पानी की कमी नहीं है; बस ! पानी की लूट है । बड़ों के पास पानी है ; गरीब बेपानी... बेजीवन है । इनका सारा जीवन बड़ों की सेवा में लगा रहा। अब भी ऐसा ही है। पानी का काम होता तो ग़रीब के नाम पर ही है, लेकिन सारा पैसा तो राजनेताओं के हाथ में ही जा रहा है । पहले जल संरक्षण के नाम पर लिया, अब इजराइली पद्धति से कम पानी का उपयोग करने के नाम पर लिया जा रहा है।

यहाँ पानी की कमी नहीं है; बस ! पानी की लूट है ।

कुप्प (काडा) परियोजना के अधिकारी श्री जी. एन. रेड्डी बराबर परियोजना के लाभ बताते रहे। लेकिन इस पर कितना खर्च हो रहा है, इसे रोकने की,... इसे वापस वसूलने की किसी ने भी कोई तैयारी नहीं दिखाई। कर्ज लेकर घी पीने का काम आन्ध्र में सबसे ज़्यादा दिखाई दिया। आन्ध्र में प्रत्येक दिन अलग-अलग समस्याएँ देखने को मिलती थीं । इन समस्याओं के समाधान हेतु जो प्रयास हो रहे हैं, वे अच्छा परिणाम लाने वाले नहीं हैं । आन्ध्र में जल समस्याओं के समाधान वास्ते 'नीरू-मीरू' नामक परियोजना बनी थी, लेकिन यहाँ की समस्याएँ तो बराबर बढ़ती ही जा रही हैं ।

'नीरू-मीरू' नामक परियोजना के बावजूद यहाँ पानी की समस्याएँ तो बराबर बढ़ती ही जा रही हैं।

गरीब का खेत और मेहनत बड़े के काम आए । इस समय हमारे राजनेता, अधिकारी और व्यापारी मिल कर ऐसी ही योजनाएँ बना रहे हैं । बिन पानी 'बूंद-बूंद सिंचाई कार्यक्रम' भी कैसे चलेगा? चले या न चले, लेकिन प्लास्टिक कम्पनी, राजनेता और अधिकारियों को लाभ तो मिल ही जायेगा।

पुगनूर भी समस्याग्रस्त है। यहाँ पानी की कमी के कारण पलायन हो चुका है। लोग गाँव छोड़कर शहरों में जा रहे हैं। घर-खेत सब खाली हैं। भूमिहीन कुछ करने की हालत में बिल्कुल नहीं हैं। जो कुछ पानी है, वह गरीब की पकड़ में नहीं आता। बड़े लोग बोर करके जमीन के नीचे से पानी निकाल लेते हैं।

यहाँ पानी पर बराबर अधिकार नहीं है । पैसे वाले पीने, खेती और उद्योग... सभी के लिए कैसे भी पानी ले आते हैं; बेपानी गरीब अपना घर छोड़कर बाहर भागने को मजबूर है। केवल भागने को मजबूर हों, इतना ही नहीं... कादरी गाँव में तो पानी की कमी के कारण आत्महत्यायें भी हुई हैं। रु. 15,000/- कर्ज पर लिये, इसका चार वर्ष में ब्याज जोड़कर रु. 64,000/- बन गया। इतना कैसे चुकाये ? यह किसान नारायण की सच्ची कहानी है । इतना ही नहीं, इस प्रदेश में इस वर्ष इन समस्याओं से ग्रस्त 500 से अधिक लोगों ने आत्महत्यायें कर ली हैं । इसी प्रकार अनन्तपुर जिले में कुआँ खोदने पर पानी नहीं मिला। फिर दूसरा कुआँ खोदा, इसमें भी पानी नहीं मिला, तो एक ने आत्महत्या कर ली । पानी की कमी के बड़े कारण तो आधुनिक बाजारू खेती, रासायनिक खाद, विदेशी बीज और प्रदूषित करने वाले जल आधारित उद्योग ही हैं।

इस प्रदेश में इस वर्ष इन समस्याओं से ग्रस्त 500 से अधिक लोगों ने आत्महत्यायें कर ली हैं।

उद्योग और बाजारू खेती केवल बड़ों को बड़ा बनाती है, गरीब को गरीबी के अधोतल में पहुँचाती है। इसका दृश्य टिम्पकटू में दिखा। टिम्पकटू गये, तो रास्ते में सड़क के दोनों तरफ अच्छे नये कपड़ों में कुछ महिलाओं को बैठे देखा। गाड़ी में बैठे साथी ने बताया कि यहाँ की महिलाएँ अब भूख-प्यास की मारी शरीर बेचती हैं। देह व्यापार का ऐसा चित्र देखकर मेरा मन कुंठित और दुखी हुआ। बताया गया कि ऐसा यहाँ केवल चार वर्ष पहले ही शुरू हुआ है ।

...देह व्यापार का ऐसा चित्र देखकर मेरा मन कुंठित और दुखी हुआ।

पानी की कमी से स्वावलम्बन, आत्मगौरव और सम्मान में कमी तो आयी ही, धर्म-जाति के नाम पर भी लड़ाई होती हैं। ये घटनायें महबूबनगर में ज़्यादा देखने-सुनने को मिलीं । जब कम पानी होता है, जिन्दा रहने के लिए सभी इसे पहले प्राप्त करने की चाह रखते हैं । पहले पाने की यह चाह ही लड़ाई को जन्म दे रही है । महबूबनगर और अनन्तपुर में ऐसी बहुत सी घटनाएं रिकार्ड में हैं।

पट्टल चैरू में मूसी नदी से जुड़े तालाब, इसके आस-पास के कुएँ व ट्यूबवेल सब कुछ प्रदूषित हो गये हैं। यहाँ इस प्रदूषण को रोकने का अच्छा आन्दोलन चल रहा है । टिम्पकटू में सरपंच और बबलू की संस्था ने अपने कुछ प्रयास प्रकृति संरक्षण में लगाए हैं। इनके प्रयासों के परिणाम भी दिखाई देते हैं ।

यहाँ अनेक क्रान्तिकारी... आन्दोलन करने वाले मौजूद हैं, फिर भी पानी की लूट का यह दृश्य वे कैसे देख रहे हैं?... समझ में नहीं आता।

खयम् में कोकाकोला की फैक्ट्री पानी खींच कर धरती का पेट खाली कर रही है। यहाँ अनेक क्रान्तिकारी... आन्दोलन करने वाले इस क्षेत्र में मौजूद हैं, फिर भी पानी की लूट का यह दृश्य वे कैसे देख रहे हैं?... समझ में नहीं आता। इस लूट को रोकने का प्रयास कैसे हो ? पंचायतें पानी के इस प्रकार होते शोषण को रोक सकती हैं। आन्ध्र पंचायत चुप क्यों है ? जबकि कोक के विरुद्ध केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में सभी स्तर पर पानी की लूट को रोकने की पहल हो रही है। आन्ध्र क्यों अन्धा होकर पानी की लूट देख रहा है ? शायद, विकास का दूसरा नाम लूट है। दूसरों के साधनों पर कब्जा करने वाला बड़ा माना जाता है। यह आन्ध्र में ज़्यादा प्रचलित है। आन्ध्र में प्रदूषण करने वालों को सजा नहीं मिल रही है; रोजगार देने वाला कहकर ईनाम दिया जा रहा है।

आन्ध्र को अन्धा होने से रोकने में श्री सुब्बाराव जी, सुश्री जसवीन जयरथ, श्री रामचन्द्रैया जी और सुश्री सोफिया जैसी बहिनों की खास भूमिका है। वैसे आन्ध्र में और भी कई स्तर पर कुछ अच्छे प्रयास चल रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों का प्रभाव प्रत्यक्ष हो, ऐसा जरूरी है।

राष्ट्रीय जलयात्रा में बोतलबन्द पानी खरीदकर नहीं पीने का हमारा संकल्प साकार रहा। कुछ सरकारी बैठकों में बोतलबन्द पानी प्रस्तुत होता था। जलयात्रियों में सहमति थी कि इसे वहीं रोका जाय, इससे इसका मुखर विरोध और जल अधिकार बचाने तक मुहिम खड़ा करना थोड़ा आसान होगा।

इस राज्य में लूट का अन्धापन बहुत है। आँखों के सामने लुटते देखकर किसी में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। यहाँ अच्छे पत्रकार हैं। कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता भी बातचीत में अच्छे लगते हैं; लेकिन लूट के साथ जीने का संस्कार बहुत ज़्यादा है। लूट देखकर वैसे भी देशभर में किसी को दर्द नहीं होता; आँखों में आँसू नहीं आते... अमीरी में करुणा और

तरस का बोध नहीं झलकता और गरीबों का भी अब अमीरों के प्रति दिल नहीं पसीजता। यह सब हमें यात्रा के दौरान भी अनुभव होता रहा।

आन्ध्र की सदानीरा नदियाँ सूख रही हैं। स्वर्णमुखी नदी इसी कारण सूखी। अमीरों ने जहाँ तक बस चला, कब्जा किया । गरीबों ने इसमें से रैली निकाल कर अपना पेट भरा। आसपास के कुएँ सूखने लगे। इस पर जब कुछ बड़े किसानों ने पानी रोकने की पहल की, तो गरीबों ने श्रमदान करने से मना कर दिया। काम शुरू नहीं हुआ। अन्त में गरीबों को तैयार किया, तब इस क्षेत्र में कुछ काम शुरू हुआ।

आन्ध्र की चेतना जगे, लूट रुके, तो सभी को पानी मिले; जो कि कठिन है, लेकिन असम्भव नहीं। कुछ जगह ऐसा चालू हुआ है । जहाँ-जहाँ ऐसा कुछ चालू है, वहाँ अच्छे परिणाम हम सबके सामने हैं। यह सब समता, सादगी और श्रम से ही सम्भव है । यहाँ की सरकार को भी यह सब समझना जरूरी है । राज और समाज अभी टूटा हुआ और अलग-अलग है । इसके जुड़ने की प्रक्रिया मुश्किल इसलिए है, क्योंकि राज अभी सभी कुछ दूसरों को दे रहा है। दूसरों से कर्ज लेकर ही विकास का रास्ता पकड़ रखा है।

अमीरों ने जहाँ तक बस चला, कब्जा किया। स्वर्णमुखी नदी इसी कारण सूखी।

राज को परजीवी बनकर दूसरों पर जीना छोड़ना पड़ेगा। जब यह छूटेंगे, तभी समाज भी श्रम करेगा। आज राज का भ्रष्टाचार देखकर समाज ने श्रमनिष्ठा से मुख मोड़ लिया है । राज भ्रष्टाचार छोड़े, लूट बन्द करे । आन्ध्र समाज की आँखें खुल जायेंगी। विकास, आधुनिकता और तकनीक आदि के नारे देने वाला आंध्र का राज सबसे नीचे जा रहा है । समाज की संवेदनहीनता सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन इसके प्रति राज ही जिम्मेदार है । वही पहल करे; समाज जुड़ जायेगा । बिगाड़ने वाला सुधारने की पहल करता है, तो परिणाम अच्छे रहते हैं।

एक सपना जगाने की जद्दोजहद

तमिलनाडु

आन्ध्र के विजयबाग में हुए कार्यक्रम के पश्चात् चेन्नई पहुँचे। समुद्र किनारे की लम्बी यात्रा के बाद तमिलनाडु में प्रवेश हुआ। गाँधी अध्ययन केन्द्र में श्री अन्नामलाई जी रहते हैं। श्री एन. कृष्णा स्वामी व चेन्नई के मित्रों ने इन्हें ही यात्रा की जिम्मेदारी दी थी। यहाँ पर सबसे पहले प्रेस वार्ता हुई। इसमें देशभर के जल संकट की जानकारी दी गई । काञ्चीपुरम में राष्ट्रीय जल सम्मेलन क्यों कर रहे हैं?... ये सब बताया। तमिलनाडु सरकार पानी प्रबन्धन के कार्यों में उदासीन क्यों है ? इसे तुरन्त जल संरक्षण करना चाहिए। इस पर विस्तार से कहा कि घर की छत से लेकर जमीन पर बरसने वाला सारा पानी बूँद-बूँद हमें सहेजना होगा, तभी यहाँ की जल समस्या से मुक्ति मिलेगी।

ईलिगों की पंचायत उत्तर की पंचायतों से बेहतर है । लोग मिलकर निर्णय करते हैं। अपने हक के लिए लड़ते भी हैं।

यहाँ के एक सरपंच जी ईलिगों रमा और सधिंता आये। इन्होंने तमिलनाडु में पंचायतराज व ग्रामीण विकास विभाग की पानी के प्रति बेरुखी का जिक्र किया। इनके साथ कुतम्बाकयन (त्रिवलूर) के लिये निकल पड़े। यहाँ ईलिगों की पंचायत में उनके कार्य देखे। पंचायत में बैठे। यहाँ की पंचायत उत्तर की पंचायतों से बेहतर है । लोग मिलकर निर्णय करते हैं। अपने हक के लिए लड़ते भी हैं। इन्होंने ग्राम स्वावलम्बन हेतु अपनी पंचायत में कुछ अच्छे प्रयास शुरू किये हैं... खासकर खाद्य प्रसंस्करण संबंधी कार्य । स्वयं पढ़े-लिखे हैं , इसलिए कम्प्यूटर चलाते हैं। गाँव का सरपंच कम्प्यूटर पर काम करता हुआ लोगों को अच्छा लगता है। ये गाँव में दुनिया भर की जानकारी से कुछ करने की बात करते हैं। चेन्नई की एक बहन जो पहले अमेरिका में रहकर पढ़ रही थीं; अब इनके कार्यों में मदद कर रही हैं । ये पूरे प्रदेश की जलयात्रा में भी साथ रही थीं।

विदेशों में इस प्रदेश के बहुत लोग गये । उन्होंने ही अब अपने प्रदेश हेतु कुछ अच्छा करने का तय कर लिया है । संहिता की तरह और कई अच्छे साथी इस

प्रदेश में अपनी धरती हेतु कुछ करने की चाह मन में लिए हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष रूप से अपनी इस यात्रा में कुछ अच्छा होता दिख नहीं पाया। यहाँ की मुख्यमंत्री ने जरूर चेन्नई जल सम्मेलन के तुरन्त बाद 'रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग' कराने का आदेश पारित कर दिया।

तमिलनाडु में कोक तथा पानी का व्यापार करने वाली बहुत सी कम्पनियाँ हैं। पूरे शिवलूर में धरती से जल खींच कर बेचने वाली नौ इकाइयां हैं, जो कि अच्छा पानी ढूँढ कर बिक्री करती हैं। इनके विरुद्ध कोई नहीं बोलता, क्योंकि इन्हें अम्मा का संरक्षरण प्राप्त है। अम्मा का स्वभाव तो महाराजाओं जैसा है । जब मन में आये, जो मन में आये, फैसला सुना दें। इसकी पालना होती है । जैसे 'रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग' के फैसले की तुरन्त पालना हुई। यह तो अच्छा था, लेकिन गलत फैसले भी इतनी ही तेजी से लागू किये जाते हैं। एक व्यक्ति द्वारा किये गये निर्णय कभी अच्छा परिणाम नहीं देते। अच्छे निर्णयों का लाभ भी केवल चहेते उठाते हैं-जैसे 'रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग' का लाभ कुछ ने ही उठाया। प्लास्टिक पाइप और सीमेंट की बिक्री बढ़ गई।

अम्मा का स्वभाव तो महाराजाओं जैसा है । जब मन में आये, जो मन में आये, फैसला सुना दें। इसकी पालना होती है, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा किये गये निर्णय कभी अच्छा परिणाम नहीं देते।

आज तमिलनाडु की बड़ी-बड़ी नदियाँ भी सूखी हैं। आदिकटूर गाँव में जाकर एक बहुत बड़ी नदी को सूखा देखकर आश्चर्य हुआ। यहाँ की महिलाओं का कष्ट नदी के सूखने से बहुत बढ़ गया है । पहले महिलाओं को 40-50 फुट पर पानी मिल जाता था। नदी गाँव की जड़ में बहती थी, इसलिए इसी में कपड़े धो लेती थीं । ज़्यादातर जरूरी काम नदी में हो जाते थे। अब नदी सूखने से पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है । पानी के लिए घन्टों खर्च होने लगा । अब पता लग रहा है कि अपने पानी की बात ही कुछ और होती है; दूसरों के यहाँ दूर पानी लेने जाने से सम्मान खोता है।

पानी का सम्मान तो जीवन में चमक और रौनक ही देता है। पानी जब जीवन में

नहीं रहता, तो जीवन से सब कुछ चला जाता है। जिन गाँवों की महिलाएँ अपने पानी पर जीवन चलाती हैं, वे अलग दिखती हैं; और जो दूसरों के पानी पर जीती हैं वे बिल्कुल अलग ही दिखती हैं। तमिलनाडु की महिलायें मजबूत और बहादुर हैं, लेकिन पानी की कमी ने इनके जीवन में भी गिरावट पैदा की है। फिर से पानी गाँव में आये, नदी बहने लगे... ऐसा सपना इस गाँव की महिलाओं ने देखा है या किसी ने बताया होगा कि हमने राजस्थान के अलवर में सूखी नदी में पानी कर दिया है; ऐसा यहाँ भी हो सकता है। कलक्टर भी हम से मिलने आया तो हम उसे नदी दिखाने ले गये थे। महिलाएँ मुझसे कहने लगीं, आप हमारे कलक्टर को रास्ता बता दो कि नदी में पानी कैसे आता है। यह कर देगा। यह नहीं करेगा, तो हम इसे त्रिवलूर में जाकर घेर लेंगे। मैंने कहा, इस नदी में जो बेहिसाब खदानें चल रही हैं, इसे रोकने हेतु तुरन्त कार्रवाई करें। खदानों के लिए ठीक जगह देखकर सीमांकन करना होगा। खदानें भूजल भण्डारों को प्रभावित करती हैं। आपका अधो भूजल भण्डार तो समाप्त ही हो गया है। नदी के जलग्रहण को ठीक से जीवित करना जरूरी है, जिससे कटाव-बहाव रुके। हरियाली के साथ-साथ नदी के निकट चैक डैम, जोहड़ आदि बनाये जायें, जिससे बहुत पानी रुके, धरती का पेट भरे। धरती का पेट भरेगा, तो नदी बहेगी।

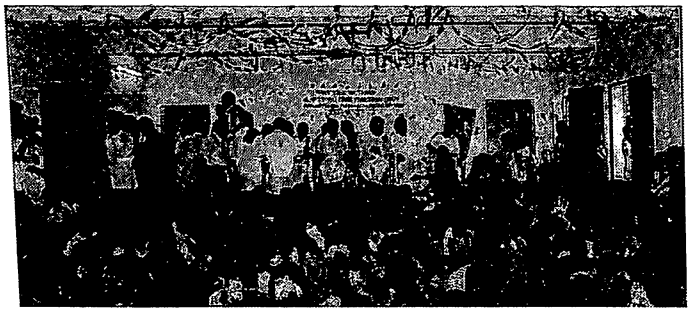

तमिलनाडु की महिलायें मजबूत और बहादुर हैं, लेकिन पानी की कमी ने इनके जीवन में भी गिरावट पैदा की है।

यह बात महिलाओं को बहुत अच्छे से समझ आई। मैंने धरती पर बैठकर अभ्यास कराया कि नदी क्यों सूखती है? कैसे इसे दुबारा बहने लायक बना सकते हैं? इस गाँव की महिलाओं का नदी के साथ जुड़ाव बता रहा था कि पानी और औरत का क्या रिश्ता है ? इन रिश्तों को हमारा भूतकाल जानता था, लेकिन वर्तमान भूल गया; इसीलिए भावी संकट ने मुँह खोल दिया है। आज हम जल संकट के मुँह में पहुँच गये हैं, बाहर निकलना हमें आता तो है, लेकिन हम बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।

हमारे समाज में जब अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का अहसास जग जाता है, तब इसे अपने काम पूरे करने का भी आभास होने लगता है। फिर वह स्वयं कार्यों में जुट जाता है । हमने यह बात त्रिवलूर के कलक्टर को समझाई । हमारे राजनेताओं और अफसरों ने अपने आपको दाता बना लिया है । सब कुछ वे स्वयं कर देंगे। समाज तो खाली लोटा है, जिसे केवल राजनेता और अफसर ही भरते हैं – ऐसी सोच हमारे राज का झूठा घमण्ड है। इस घमण्ड के अनुसार किये गये कार्यों ने हमारे समाज को भौंचक्का बना दिया है। कलक्टर सुनता रहा और उसने इस जिले में कुछ अच्छा काम करने की बात कहकर विदा ली, पर समाज के साथ मिलकर अच्छा काम करने का संकल्प लेने को वह तैयार नहीं था।

काम तो अच्छा है, पर पानी की माप पर इतना खर्च क्यों ? पानी की माप तो किसान का ट्यूबवैल या कुआँ भी बता देता है ।

तमिलनाडु की संस्थाओं ने कहा, यह ना भी करे तो कोई चिंता नहीं, हम समाज से मिलकर, समाज की जरूरत के अनुसार, समाज को ही काम करने हेतु तैयार करके इनके हित में कार्य करेंगे। इस चर्चा के साथ हम नागापटिनम के लिए निकल पड़े ।

नागापटिनम में गाँधी जी के विचार से प्रभावित कुछ लोग रहते हैं। इन्होंने महिलाओं को रोजगार देने के अच्छे कार्य किये हैं। यहाँ की संस्थाएँ भी जमीन के साथ जुड़कर महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने का प्रयास कर रही हैं। इस क्षेत्र में एकलखी महिला रैली आयोजित हुई। अच्छा लगा। पानी के सवाल पर महिलाओं का यह उत्साह देखने योग्य है । यहाँ से हमने अपने एक पुराने साथी श्री मनोहरन की संस्था में जाकर देखा। सरकारी भूजल बोर्ड के अधिकारियों के साथ जाकर पानी का उनका काम देखा। उन्होंने रिचार्ज का प्रयोग यहाँ शुरू किया है । इसमें बहुत-सा खर्च तो पानी की माप पर ही हो जाता है । काम तो अच्छा है, पर पानी की माप पर इतना जोर क्यों ? पानी की माप तो किसान का ट्यूबवैल या कुआँ भी बता देता है । कुछ अच्छा काम किसानों की जरूरत के अनुरूप

हो, तो इससे समाज में विश्वास बनेगा... समाज स्वयं काम करने लगेगा। अच्छी से अच्छी शोध तो फाइल में ही दबी रहती है पर इसे उभारना, बाहर लाना बहुत कठिन होता है। स्वार्थी ताकतें इसे उभरने नहीं देतीं। यह बात तमिलनाडु के भूजल वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार की। आजकल ये भी विदेशी बाजार से रूठे हुए हैं। विदेशी बाजार ने सबको लील लिया है। इससे मुक्ति हेतु ग्रामोदय गाँधीग्राम विश्वविद्यालय आदि सब लगे हैं। गाँधीग्राम में भी जल संरक्षण का अच्छा कार्य शुरू किया गया है। यहां सेहत, शिक्षा और खेती के स्वावलम्बन की दिशा में कार्य होते दिखे।

विदेशी बाजार ने सबको लील लिया है। इससे मुक्ति हेतु ग्रामोदय गाँधीग्राम विश्वविद्यालय आदि सब लगे हैं।

अभी हमारे नये मित्र श्री वासामलाई ने भी इस दिशा में 'ध्यान प्रतिष्ठान' बना कर कार्य शुरू किया है। इन्होंने तालाब को पुनःजीवित करने की अच्छी मुहिम चलाई है। इस प्रतिष्ठान के साथ जुड़कर नये सरपंच कई कार्य कर रहे हैं। नई जानकारी के साथ तालाब (टैंक) जैसी जीवन पद्धति को जगाना, ये अच्छा मानते हैं। इस दिशा में शोध भी कर रहे हैं। समाज के मन में स्वयं अपनी ताकत व श्रम से इस कार्य को कैसे पूरा कर सकते हैं? पुनर्जीवन कैसे हो सकता है ?... इसका आभास पैदा करना जरूरी काम है।

आज वासामलाई प्रतिष्ठान एवम् सर्वोदय विचारक-कार्यकर्ता सब मिलकर जल साक्षरता में जुटे हैं। अच्छा योजनाबद्ध काम कर रहे हैं। उन्होंने अच्छे कार्यक्रम आयोजित किये। मदुरई में तो सरकार, समाज और गाँधी संग्रहालय सब ही पानी का कार्य करने वाले हैं, ऐसा लगा। दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु में सबसे अधिक जोर जल संरक्षण पर ही दिखाई दिया, लेकिन अभी इसे धरती पर उतारना जरूरी है। यहाँ से हम वन्ताकुलम गये। पादरी, सन्त, मौलवी आदि से जल धर्म, मानव धर्म और सामुदायिक धर्म सम्बन्धों पर गहन चर्चा हुई। जल धर्म सबका एक है। इसे मिलकर निभाने के संकल्प से तमिलनाडु की जलयात्रा सम्पन्न हुई।

दर्शन तो है, पर व्यवहार नहीं

पॉण्डिचेरी

समुद्र किनारे का एक प्रदेश-पॉण्डिचेरी। राजस्थान से दस गुणा ज़्यादा वर्षा वाला यह क्षेत्र पुराने तालाबों की देख-रेख के बिना सूख गया है। यहाँ पानी की कमी का कारण महज कुप्रबन्धन ही है। इस प्रदेश की आबादी के पास वर्षा का पर्याप्त जल है।

पी.डब्ल्यू.डी. से मिलकर यहाँ के कुछ क्रान्तिकारी साथियों ने... खासकर बहनों ने इस प्रदेश में जलयात्रा का आयोजन किया था। इस यात्रा में हमने कई पुराने तालाब देखे। पॉण्डिचेरी सुन्दर पानी वाला प्रदेश दिखता है, फिर भी खेती और उद्योग में पानी की कमी की बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ।

पॉण्डिचेरी की सरकार ने पानी प्रबन्धन हेतु एक विदेशी संस्था को ठेका दिया है। 80 लाख रुपये में इस संस्था ने एक तालाब बनाया। बड़ी-बड़ी मशीनें लगी थीं, जो रिचार्ज नापती हैं। ज़्यादातर पैसा इसी तरह के काम में चला जाता है। वर्षा जल को ज्यादा से ज्यादा पकड़ना, इनकी प्राथमिकता नहीं है।

आज पानी के काम में विश्व बैंक व एशिया बैंक हमारी सरकारों को जो कर्ज दे रहे हैं, वे सब पानी पर नियंत्रण करने की नीति व कानून बनवाने में जुटे हैं।

राजस्थान और पॉण्डिचेरी में जल के नाम पर सौन्दर्यीकरण समान रूप से दिखता है। इसमें एक बात हम साफ देखते हैं कि आज पानी के काम में विश्व बैंक व एशिया बैंक हमारी सरकारों को जो कर्ज दे रहे हैं, वे सब पानी पर नियंत्रण करने की नीति व कानून बनवाने में जुटे हैं। पानी पर पैसा केवल नाममात्र के लिए है। पानी बचाने-बढ़ाने पर पैसा न तो जयपुर में खर्च हुआ और न ही पॉण्डिचेरी में। मामूली तालाब को खोदकर गहरा कर दिया। बस ! इतना ही... अधिकतर पैसा तालाब किनारे रोड बनाने या फव्वारे लगाने पर ही खर्च किया।

पॉण्डिचेरी और जयपुर के शहरी समाज का जल दर्शन भी एक जैसा ही है। दोनों जगह के ग्रामीण भी बिल्कुल एक जैसे ही हैं। दोनों जगह के किसान पानी

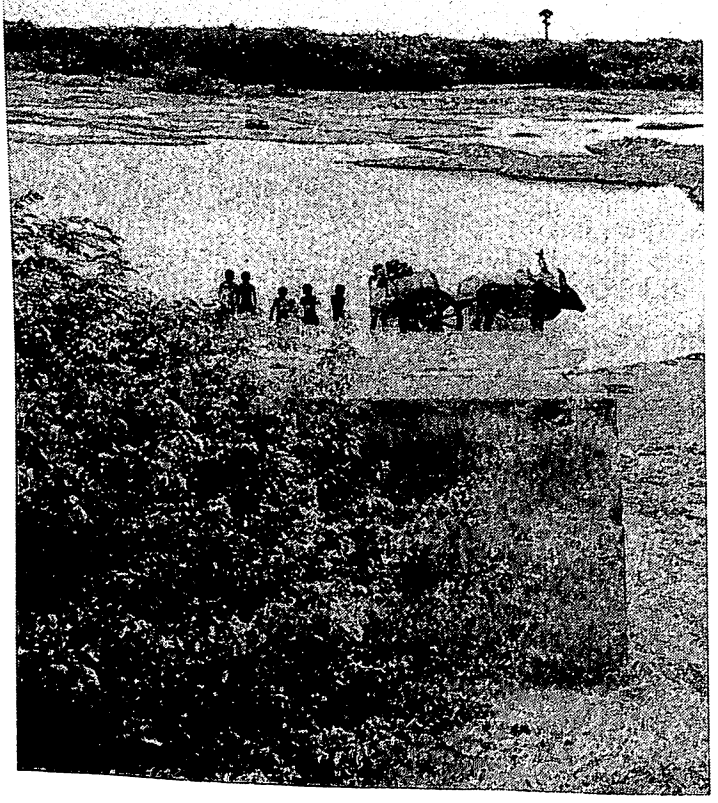

पॉण्डिचेरी और जयपुर के शहरी समाज का जल दर्शन भी एक जैसा ही है। दोनों जगह के ग्रामीण भी बिल्कुल एक जैसे ही हैं। दोनों जगह के किसान पानी बचाना चाहते हैं, लेकिन बाजारू खेती पानी बचाने नहीं देती।

बचाना चाहते हैं, लेकिन बाजारू खेती पानी बचाने नहीं देती। गाँव का पानी बाजार में अनाज, फल, सब्जियों के रूप में ही बहुत सस्ता बिक रहा है।

पॉण्डिचेरी के बाजार में अच्छी सब्जियाँ और फल दिखाई दिये। आध्यात्मिक प्रभाव यहां कुछ ज़्यादा ही है, परन्तु पानी का आध्यात्म कहीं नजर नहीं आया। कुछ युवाओं में बाजार से पानी खरीद कर पीना स्तरीय जीवन शैली का प्रतीक बन गया है।

कुछ स्कूल-कालेजों में पेप्सी-कोक के विरुद्ध वातावरण दिखाई दिया। तीन कालेजों के विद्यार्थियों ने पानी खरीद कर नहीं पीने का संकल्प लिया। एक बहन ने यहाँ जल सहेजने का सशक्त अभियान चलाने का संकल्प लिया। पॉण्डिचेरी में हम तीन दिन रहे। ज़्यादातर समय शहर में बीता। कुछ गाँवों में भी गये। गाँव भी कस्बे जैसे ही हैं। कस्बे होने के बावजूद यहाँ गाँव के संस्कार बचे हैं। इनमें जल संस्कार का भी मामूली दर्शन हुआ। जल संस्कार बचाना जरूरी है। जलदर्शन... जल संस्कार ही पॉण्डिचेरी को पानीदार बनायेगा।

उलट बहती ज्ञान गंगा

केरल

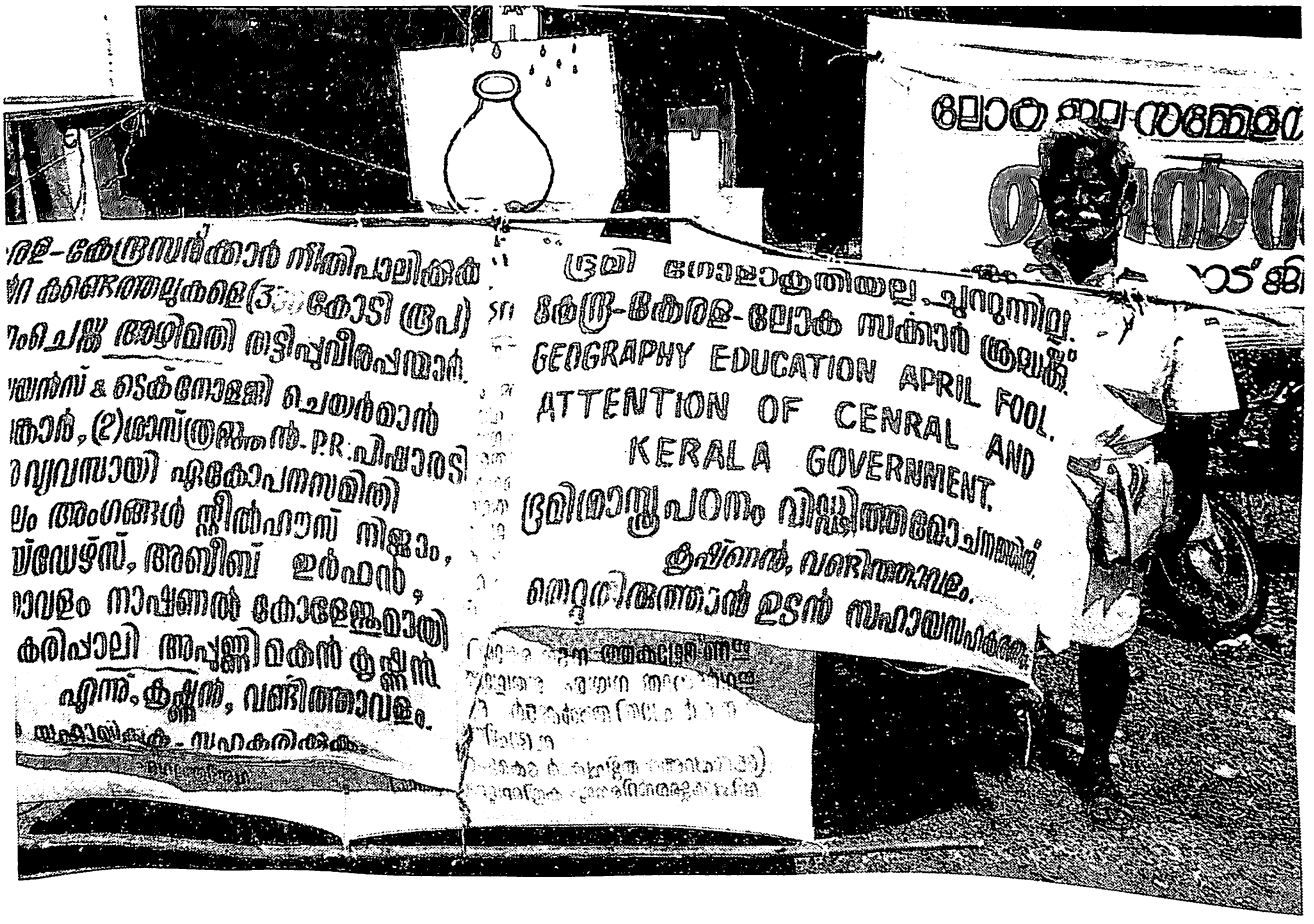

जलयात्रियों ने केरल को सबसे अधिक दिन दिए । हमारे कई दल अलग-अलग समय पर अलग-अलग जगह गये । केरल ऊपर से हरा-भरा, मधुर और मीठा प्रदेश लगता है । 44 नदियों के बीच यहाँ के पहाड़ों की हरियाली प्रसन्नता का अनुभव कराती है। कुछ छितरे जंगल, कुछ मगरमच्छ, जंगली मेंढे और बाघ-बकरियाँ आदि देखकर यहाँ मन आनन्द से भर उठता है। इस आनन्द को हम बाँट सकते हैं। यहाँ के लोग बाँटते भी हैं, लेकिन यहाँ मौखिक लड़ाई बहुत होती है । इसे कोई दूर से सुने, तो कड़वाहट नजर आती है । अच्छी तरह

केरल में बातें बहुत ज़्यादा हैं, काम भी खूब लेकिन यहाँ काम उल्टे रास्ते पर चल रहा है ।

समझने पर पता लगता है कि कड़वी बातें नहीं हैं; अच्छी... गहरी ज्ञान की बातें हो रही हैं।

केरल में बातें बहुत ज़्यादा हैं, काम भी खूब लेकिन यहाँ काम उल्टे रास्ते पर चल रहा है । पानी व प्लास्टिक का प्रदूषण यहाँ बहुत है । यहाँ सब लोग पढ़ना-लिखना और काम करना जानते हैं, इसीलिए यह राज्य शिक्षित माना जाता है । काम का परिणाम हमें कहाँ ले जायेगा; यह सोचते भी हैं।

केरल में लालच और भोग ज़्यादा दिखाई दिया। लेकिन सभी सुख और स्वाद की चाह करते हैं, जिससे इनका मन ललचाता है । मन का लालच छूटता नहीं है । वह सभी जगह छाया रहता है। स्व-स्तुति और स्वाभिमान का ध्यान बराबर रखा जाता है । शायद यह ही भौतिकता का सबसे बड़ा गुण है । भौतिकवाद नियंत्रण करने वालों को बड़ा मानता है । केरल के लोग भी अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। इस राज्य में नियन्ता और लोकतंत्र का अच्छा सम्बन्ध देख सकते हैं।

हमने देखा कि जलयात्रा की सभाओं में बहुत लोग आते थे। पंचायत अध्यक्षों को यहाँ बहुत सम्मान मिलता है । विधायक भी इन्हें बहुत आदर करते हैं। ऐसा उत्तर क्षेत्र के राज्यों में कहीं देखने को नहीं मिला। महिलाएँ स्वयं

अपना पद और कार्य सम्भालती हैं। ये अमरबेल जैसी परजीवी नहीं हैं; स्वयं करती व आगे बढ़ती हैं। पर्दा आदि नहीं होने के कारण इन्हें अवसर भी बहुत मिलते हैं; तरक्की भी खूब करती हैं, फिर भी केरल का समाज पुरुष प्रधान ही है।

पाँचीमडा में कोकाकोला और पुन्दसेरी में पेप्सी के विरुद्ध आन्दोलन सफलतापूर्वक खड़ा हुआ। ये दोनों आन्दोलन पानी की लूट को रोकने के उदाहरण बन सकते हैं।

केरल राज्य में स्कूलों का अनुशासन तथा शिक्षकों का कार्य बेहतर है । हमारे स्कूलों में तो शिक्षक सालों तक नहीं जाते; बिना स्कूल जाये वेतन लेते हैं। केरल में ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया। जलयात्रा के दौरान हम यहाँ के 100 से ज़्यादा स्कूलों में गये। बहुत से स्कूलों की भी जानकारी हासिल की। यहाँ कुछ सीमा तक काम की जिम्मेदारी निभाने का चलन है । यहाँ महिलाएँ ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन ये राजस्थानी महिलाओं जैसी कमरतोड़-पसीना बहाने वाली मेहनती नहीं हैं। यूँ तो राजस्थान में भी बहुत विविधता है । वहाँ एक वर्ग की महिलाएँ तो आज भी कुछ काम नहीं करतीं, पर इनके साथ तो दूसरी महिलाएँ भी सेवा में लगी रहती हैं। एक फर्क और है कि राजस्थान की महिलाओं में पानी की समझ है, केरल की महिलाओं में पानी का वैसा प्यार दिखाई नहीं दिया।

केरल में भी किला है -कासरकुड। किले का गणेश मन्दिर समुद्र तट पर है। सबरीमलाई दर्शन की यात्रा के लिये लाखों लोग इस फोर्ट के मन्दिर से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ फोर्ट वैसे तो खण्डहर जैसा है, लेकिन लोगों का जुड़ाव बहुत है । यहाँ से सबरीमलाई जाने वाले युवा 40 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत करते हैं। इन दिनों में मीट-मांस, शराब आदि का सेवन नहीं करते। सबरीमलाई यात्रा के दौरान सरकारी शराबबन्दी भी हो जाती है । यह अच्छा है। ऐसा उत्सव समाज को अपनी सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म और कर्म का बोध कराता है।

केरल की पंचायतों और समाज में अपने जल, जंगल, जमीन को लेकर थोड़ा-बहुत बोध तो है; तभी यहाँ पंचायतों ने कोकाकोला और पेप्सी के विरुद्ध अपना आन्दोलन ऊँचा कर दिया है । पाँचीमडा में कोकाकोला कम्पनी को बन्द कराने का कार्य शुरू हुआ है । पुन्दसेरी में पेप्सी के विरुद्ध आन्दोलन सफलतापूर्वक खड़ा हुआ। ये दोनों आन्दोलन पानी की लूट को रोकने के उदाहरण बन सकते

हैं। यहाँ की पंचायतें न्यायालय में गईं। इन्होंने जीत हासिल कर कंपनियों के विरुद्ध वातावरण भी तैयार कर दिया है। इससे देश की अन्य पंचायतें सीख सकती हैं।

केरल में मुख्यमंत्री सहित पूरी राज्य सरकार सब को समान रूप से पानी का हक देने पर सहमत है।

संविधान के 73-74वें संशोधन से मिला पानी का हक महत्वपूर्ण है । देशभर की पंचायतें जलनीति-2002 के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में जाकर इस संशोधन के माध्यम से जल के निजीकरण को रोक सकती हैं । गाँव या नगर के जल संसाधनों की बिक्री अथवा बढ़ते बहुराष्ट्रीय दखल पर रोक लगा सकते हैं। केरल और गोवा इस काम के अच्छे उदाहरण हैं। यहाँ की ग्राम पंचायतें न्यायालय में गईं और अपने जल हक का हवाला देकर जल के निजीकरण को रोकने में सफल रहीं।

केरल में मुख्यमंत्री सहित पूरी राज्य सरकार सब को समान रूप से पानी का हक देने पर सहमत है। जल संसाधन मंत्री श्री थॉमस व सांसद श्री रमेश चेनिथल्ला जैसे यहाँ के अन्य राजनेता इस विषय पर सहजता से बोलते हैं। यहाँ जनता दल के श्री वीरेन्द्र कुमार जी 'मातृभूमि' के सम्पादक भी रहे हैं। वह पाँचीमडा में कोकाकोला के विरुद्ध मैदान में आये। यह अच्छी बात है।

मुझे ऐसे बहुत सारे युवाओं ने पत्र लिखे हैं जिन्होंने जलयात्रा के बाद बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का पेय खरीद कर नहीं पीया है और आगे भी नहीं पीयेंगे।

यूँ तो कोकाकोला के विरुद्ध केरल की सभी पार्टियों के नेता मैदान में उतरे हुए दिखाई देते हैं । 22 जनवरी, 2004 के जल-सम्मेलन में सभी पार्टियों के नेता सम्मिलित हुए और सभी ने कोका-कोला के विरुद्ध अपना भाषण भी दिया; लेकिन किसी राजनेता ने कोकाकोला, पेप्सी व बोतलबन्द पानी खरीदकर पीना छोड़ा हो... ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है। हाँ ! बहुत से विद्यार्थियों, शिक्षकों और युवाओं ने पानी की लूट मचाने वाली कम्पनियों का पानी और कोक खरीदकर नहीं पीने का अवश्य संकल्प लिया है।

मुझे ऐसे बहुत सारे युवाओं ने पत्र लिखे हैं, जिन्होंने जलयात्रा के बाद बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का पेय खरीद कर नहीं पीया है और आगे भी नहीं पीयेंगे।

केरल धान प्रदेश है; पर अब यहां की सुन्दर वादियों में भी धान के खेत कम होते जा रहे हैं। धान वाली जमीन पर सीमेन्ट कंकरीट के जंगल बन रहे हैं।

किसानों का कहना है कि पेरियार नदी पर 70 साल पहले पांच करोड़ की लागत से जो बाँध बना था, इससे 80 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई का वादा किया गया था, लेकिन पानी की कमी के कारण कभी भी 50 हजार एकड़ से ज़्यादा सिंचाई नहीं हुई। पिछले 10 सालों से तो यह सिंचाई धीरे-धीरे और भी कम होकर 25 हजार एकड़ के आस-पास ही रह गई है।

किसानों ने यह भी कहा कि पानी की कमी के कारण अब अच्छी फसलें नहीं होतीं, इसलिए इस जमीन को बेचकर अपना जीवन चलाते हैं। शहरों के सेठ इस जमीन को खरीदकर बहुमंजिल भवन निर्माण में जुटे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री, राजस्व, उद्योग व जल संसाधन मंत्रियों के साथ बैठक में मैंने भूमि के दुरुपयोग को रोकने का कानून बनाने की सलाह दी। राजस्व मंत्री तत्काल बोले कि जमीन के इस तरह के उपयोग पर पाबन्दी लगने से हमारे राज्य में उद्योग नहीं आयेंगे और हमारे राज्य को उद्योगों की अधिक जरूरत है। मुख्यमंत्री जी के सामने ही इस तरह की बातचीत यह स्पष्ट करती है कि राज्य की विकास नीति में प्राकृतिक संसाधन प्राथमिकता पर नहीं हैं।

यह ठीक है कि केरल में उद्योगों ने बहुत पैसा कमाया है और खेती इतना अधिक नहीं कमा सकती; फिर भी क्या केरल को खेती और पानी की जरूरत नहीं है ?

यह ठीक है कि केरल में उद्योगों ने बहुत पैसा कमाया है और खेती इतना अधिक नहीं कमा सकती; फिर भी क्या केरल को खेती और पानी की जरूरत नहीं है ? इसकी साफ समझ व ठीक प्रबन्धन जरूरी है। ठीक प्रबन्धन वास्ते समाज और राज्य को मिलकर पहल करने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही। यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत सरल, सहज और ईमानदार कोशिश वाले व्यक्ति हैं, पर यह भी तंत्र को चलाने में सबकी बात सुनने और मानने को विवश दिखे।

केरल राज्य में श्रीकुमार पाडरे जैसे वैज्ञानिक... पत्रकार विकेन्द्रित जल प्रबन्धन के बड़े पक्षधर हैं। इन्होंने अपने राज्य के परम्परागत जल-प्रबन्धन के बहुत से तरीके हमारे यात्रा दल को दिखाये। यहाँ की सुरंगम पद्धति बहुत ही गहरी और वैज्ञानिक समझ के साथ आज भी खरी है। हमारे देखे तीन स्थानीय गाँव... सुरंगम पद्धति से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

पारंपरिक रूप में प्रत्येक मन्दिर के साथ यहाँ जरूर एक बड़ा तालाब हुआ करता था। यह तालाब पीने का पानी और खेती की जरूरत पूरी करता था। कासरकुड के पास एक बड़े तालाब पर हम गये, जो कभी 100 हैक्टर की सिंचाई करता था, लेकिन अब इस पर अतिक्रमण हो गया है और अब इससे सिंचाई नहीं होती। केरल के अधिकतर तालाबों का यही हाल है । बीच शहर के तालाब, तो अब पार्क में बदल गये हैं। यहाँ के कुछ बड़े किसानों ने अब जल प्रबन्धन का कार्य अपने हाथों से शुरू किया है । मैंने अलग-अलग जगह पर चार किसानों के ऐसे प्रयास देखे। यह देखकर आशा की एक किरण जगी है; लेकिन इस काम में सबसे बड़ी अड़चन विविध राजनेता हैं । वे अपने हाथों से खुद काम करने में विश्वास नहीं रखते। समाज को अपने पीछे बनाये रखने के लिये कुछ अलग-अलग तरह के सपने दिखाते रहते हैं, जिससे इस राज्य में जल प्रबन्धन का कार्य करने में सक्षम किसान भी सरकार की तरफ मुँह ताकते रहते हैं। सरकारों का मुँह ताकने का दौर जब तक जारी रहेगा, तब तक समाज पानी का स्वावलंबी काम नहीं कर पायेगा।

कासरकुड के पास एक बड़े तालाब पर हम गये, जो कभी 100 हैक्टर की सिंचाई करता था, लेकिन अब इस पर अतिक्रमण हो गया है और अब इससे सिंचाई नहीं होती।

केरल राज्य में भी कर्नाटक की तरह सन्तों की परम्परा है । यहाँ के कई सन्त ऐसे हैं जो कि सर्वधर्म में आस्था रखते हैं, लेकिन प्रकृति और पानी से आध्यात्मिक रिश्ते बनाने का मानस नहीं दिखता।

हमने सभी सभाओं में नदियों की पवित्रता और धरती व पहाड़ियों की हरियाली पर जोर दिया। प्लास्टिक को रोकने का संकल्प कई जगह दोहराया।

केरल राज्य में आधुनिक शिक्षा ने जो बदलाव पैदा किए हैं, वे प्रकृति से इंसान को दूर कर रहे हैं... प्रकृति और इंसानियत की दूरियाँ बढ़ रही हैं । केवल केरल में नहीं, पूरे देश में ऐसा है । यहाँ के चाय बागानों में रसायन, उर्वरक व कीटनाशक सतही और भूजल को प्रदूषित कर रहे हैं। यहाँ की खेती भी बाजारू दिशा में आगे बढ़ रही है । एक तरफ केरल सुन्दर, साफ-सुथरा और शिक्षित राज्य है, जहाँ का आधुनिक सदाचार ऊपरी तौर पर दिखता है; दूसरी तरफ प्रकृति

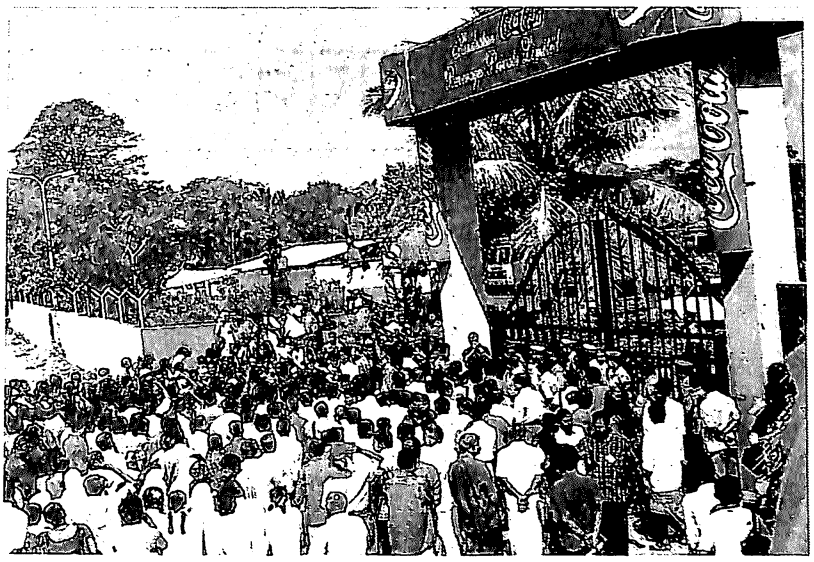

से दूरी, क्षणिक आनन्द के लिये स्थायी कष्टों का बढ़ना, जिन्दगी में निजीपन और आन्तरिक कलह इनकी बातचीत में स्पष्ट दिखता है। छोटी-छोटी बातों के लिये लम्बी-लम्बी लड़ाइयाँ यहाँ जोरदार हैं। इन लड़ाइयों को केवल बातचीत की लड़ाई नहीं, बल्कि मनभेद बनाने वाली लड़ाई कह सकते हैं। जिस मतभेद में मनभेद नहीं होता, वह अच्छा होता है लेकिन आज तो मतभेद से मनभेद बढ़ता ही जा रहा है। छोटे-छोटे मतभेद केरल में बड़े मनभेद को जन्म दे रहे हैं।

छोटी-छोटी बातों के लिये लम्बी-लम्बी लड़ाइयाँ यहाँ जोरदार हैं। इन लड़ाइयों को केवल बातचीत की लड़ाई नहीं, बल्कि मनभेद बनाने वाली लड़ाई कह सकते हैं।

केरल राज्य की जलयात्रा में सर्वोदय विचार के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेसी, भाजपाई और साम्यवादी सबसे मिलना हुआ। यहाँ के साम्यवादी दूसरे राज्यों से कुछ अलग हैं। ये जमीनी नजर आते हैं। संख्या कम है, परन्तु हर गाँव, कस्बे और शहर में कोई न कोई मिल ही जाता है, किंतु इन्होंने भी गरीबों के हक को धरती और प्रकृति के साथ जोड़कर कभी नहीं देखा। यदि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और कुछ बड़े घरानों से छोटी-मोटी लड़ाइयाँ लड़ीं भी तो, हक के लिये नहीं, बल्कि सुख-सुविधाओं के लिये ही। केरल की समृद्धि का सबसे सही रास्ता केवल स्वदेशीपन बढ़ाना और धरती से जुड़कर जीवन की जरूरत पूरी करने के लिये उत्पादन करना है। प्राकृतिक संसाधन... जल, जंगल व जमीन को बचाकर ही ऐसा होगा। यहाँ दूसरों की अपेक्षा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक खतरा है। केरल की कड़वाहट को रोक कर मधुर बनाने की जरूरत है। इसके बिना संरक्षण का साझापन संभव नहीं।

जल्द टूटेगा पंचनद का दंभ

पंजाब

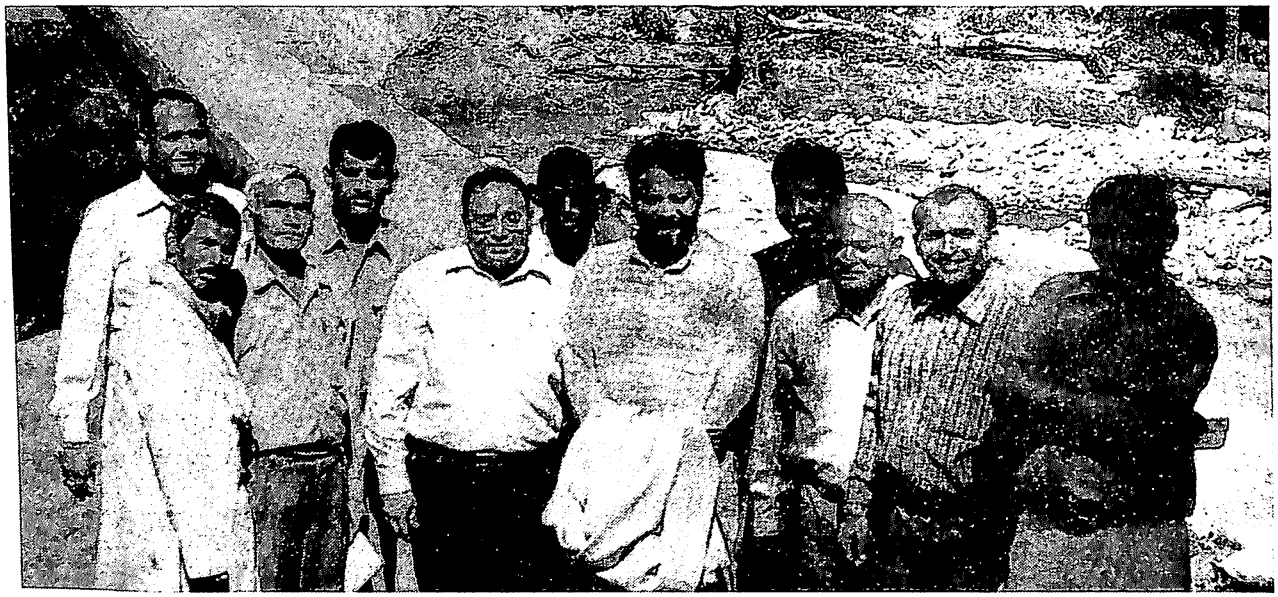

पंजाब पानी की पीड़ा से परेशान नहीं, बल्कि ज़्यादा पानी बहाने से परेशान है ।

पंजाब पाँच नदियों वाला प्रदेश है किन्तु, अब पंजाब में भी पानी की कमी हो रही है । यहाँ के भूजल भण्डार धीरे-धीरे खाली हो रहे हैं। गुरु नानक जी ने जिस नदी के किनारे तपस्या की थी, वह भी सूख रही है, लेकिन धान की फसल बोना कम नहीं हुआ; गन्ने की बुआई में भी कमी नहीं आई। लोग आज भी ज़्यादा पानी खर्च करने वालों को बड़ा मानते हैं। इसलिए वहाँ सिंचाई में पानी चलाया नहीं जाता, बल्कि बाढ़ की तरह बहा दिया जाता है । पंजाब पानी की पीड़ा से परेशान नहीं, बल्कि ज़्यादा बहाने से परेशान है । मक्खी-मच्छर सब इसी राज्य के गांव-गलियों में डेरा डाले हैं, ऐसा लगता है।

यहाँ धरती के भूजल भण्डार खाली हो रहे हैं। खेत भी सूख रहे हैं, लेकिन गाँवों के रास्तों में हमारी गाड़ी धंसी ही नहीं, बल्कि बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, भैंसा बुग्गी और ट्रेक्टर तक धंसे दिखे । यह देखकर ही पंजाब का चित्र समझ में आ गया। अपनी नदियों का पानी किसी दूसरे राज्य में नहीं जाये, पंजाब के राजनेता इसकी

दुहाई देते रहते हैं। खासकर जब चुनाव होते हैं, तब यहाँ यह बात चुनावी मुद्दा बनती ही है, लेकिन पंजाब की गलियों में पानी की जबरदस्त बरबादी होती है।

पंजाब में पानी की कई चर्चित कहानियाँ रही हैं, लेकिन आज समाज पर इन कहानियों का कोई प्रभाव नजर नहीं आता। आज तो यहाँ पानी की तस्वीर उलट गई है । अपनी प्यास की चिन्ता छोड़कर कभी गधों को पानी पिलाकर जिन्दा रखने वाला समाज, अब दूसरे इंसानों को पानी पिलाना तो दूर... दूसरों का भी पानी झपट रहा है । सतलज-यमुना लिंक इसका बड़ा प्रमाण है । बड़ा भाई पंजाब, छोटे भाई हरियाणा को पानी देने हेतु तैयार नहीं है।

अपनी प्यास की चिन्ता छोड़कर कभी गधों को पानी पिलाकर जिन्दा रखने वाला समाज, अब दूसरे इंसानों को पानी पिलाना तो दूर... दूसरों का भी पानी झपट रहा है । सतलज-यमुना लिंक इसका बड़ा प्रमाण है ।

पंजाब में जिस पार्टी की सरकार आती है , वह स्पष्ट तौर से पंजाब का पानी किसी को भी नहीं देने की घोषणा सबसे पहले करती है। वैसे इस राज्य का बहुत-सा जल खुद ही बहकर दूसरे देश व राज्यों में चला जाता है । अपनी जरूरत के अनुरूप यह राज्य पानी नहीं रोकता है । इस राज्य की जरूरत से ज़्यादा पानी यहाँ बरसता है । वर्षा-जल का उचित प्रबन्धन इस राज्य को ही करना पड़ेगा। यदि नहीं किया तो, यह राज्य पानी की कमी से तरसेगा। पंजाब विश्वविद्यालय ने कुछ स्थानों पर जल-जंगल-जमीन संवर्द्धन की अच्छी शुरुआत की है, लेकिन इससे सामाजिक जुड़ाव नहीं है । सामाजिक जुड़ाव न बन पाने से अच्छे अभिक्रम भी उपयोगी और टिकाऊ नहीं बनते।

राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों के सहयोग से पंजाब में जलयात्रा आयोजित हुई, इसीलिए विविध क्षेत्रों में विविध कार्यक्रमों में हम भागीदार बन सके। यहाँ के समाज में वर्षा जल को पकड़ने की ज़्यादा इच्छा-शक्ति दिखाई नहीं दी, इसलिए यहाँ जल सहेजना तथा इसका उपयोग करने का अनुशासन बनाना फिलहाल मुश्किल काम दिखता है।

बाढ़ भी, सुखाड़ भी

बिहार

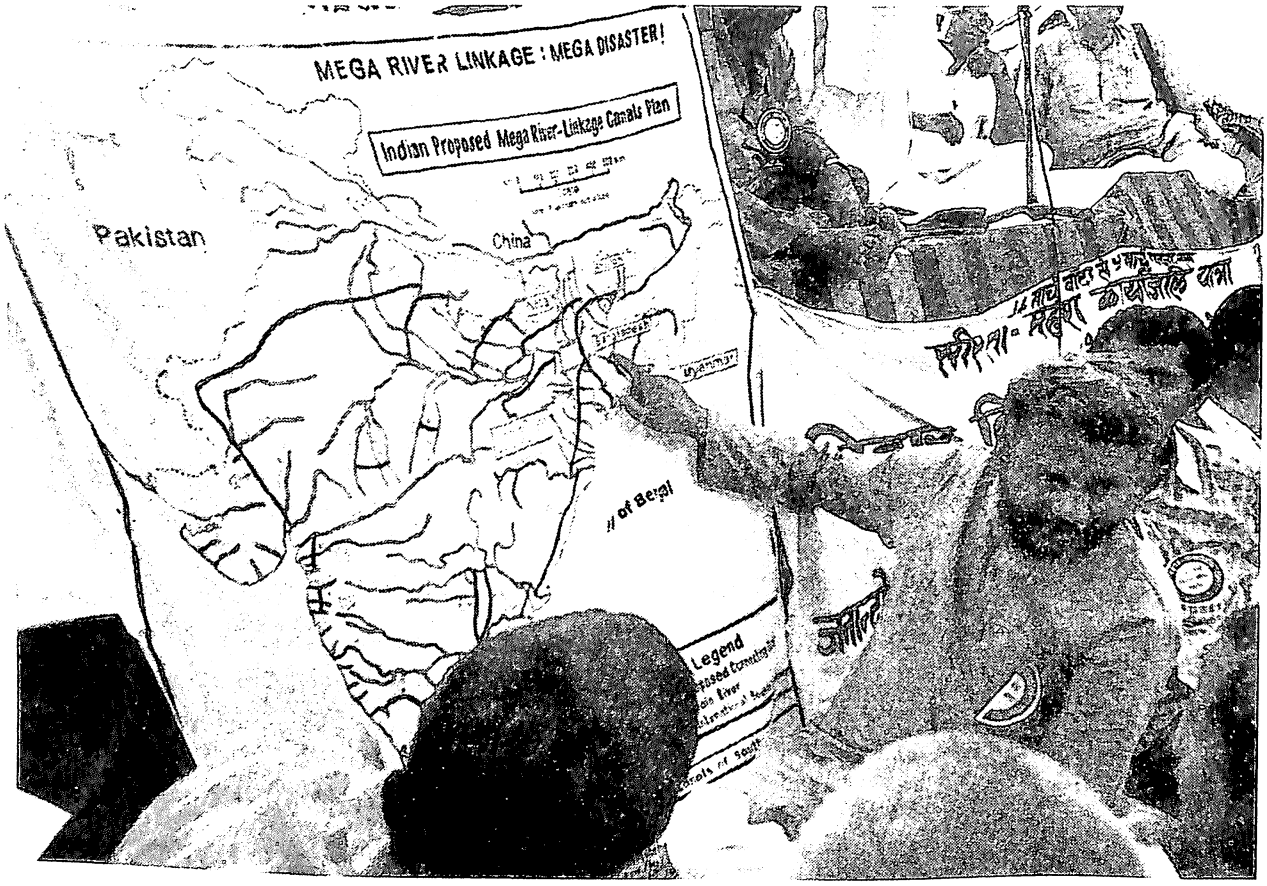

राष्ट्रीय जलयात्रा का एक चरण बिहार में ही सम्पन्न हुआ। बिहार बाढ़ का केन्द्र माना जाता है, लेकिन राष्ट्रीय जलयात्रा के दौरान बिहार में सुखाड़ और बाढ़ दोनों की मार का दृश्य देखने को मिला। जहाँ एक तरफ इस प्रदेश में शारदा, गंडक, कोशी और गंगा जैसी नदियों की बाढ़-विभीषिका से हर वर्ष गाँव और शहर उजड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ यही बाढ़ इस राज्य की गन्दगी को धोती हुई और नई मिट्टी से धरती को उपजाऊ बनाती हुई खेती को अच्छा बनाती है। नदियों

की दी हुई इस समृद्धि से ही कभी इस राज्य में बौद्ध व जैन धर्म पनपा था। अभी तो यहाँ मार-काट, लूट-खसोट और हुड़दंगपन ही ज़्यादा दिखाई देता है।

भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राजेन्द्र प्रसाद के कारण इस राज्य में उन्हीं के समय में बाढ़-मुक्ति के बहुत से उपाय शुरू हुए, जो बाद में भी चलते रहे। इन उपायों में से एक... नदियों के तटबन्ध सबसे अधिक प्रचलित माने जाते हैं। आज तो यह तटबन्ध ही बाढ़ को टिकाये रखने के साधन बन गये हैं। इन तटबन्धों से पहले यहाँ बाढ़ आती थी और दो-तीन दिन के बाद बहकर निकल जाती थी। अब नदी का तल तो ऊपर उठ गया और तटबन्ध के बाहर के हिस्से नीचे पड़ गये। अब इन तटबन्धों से पानी नदी में नहीं जाकर खेतों में ही रुका रहता है। आरम्भ में तो तटबन्ध बाढ़-मुक्ति के लिए एक सफल साधन माने जाते थे; अब ये ही बाढ़ को आमंत्रित करने वाले बन गये हैं।

इस यात्रा के दौरान इन तटबन्धों के बारे में समाज की बुलन्द आवाज सुनने को मिली। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालूप्रसाद यादव एवं वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी... दोनों से हम मिले। इन दोनों का मानना है कि बिहार की बाढ़ के मूल में ये तटबन्ध ही हैं। बिहार सरकार भी इन्हें तोड़ना चाहती है, लेकिन एक खास वर्ग है, जो इन तटबन्धों को बनाये रखना चाहता है। तटबन्धों के बनने से सिवाय नुकसान के कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में भी इस पर चर्चा कराई गई। कुछ लोग इन्हें

तुड़वाने के पक्ष में हैं और कुछ नये तटबन्ध बनाना चाहते हैं। ऐसे में हमने अभी तय किया है कि फिलहाल बाढ़ के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों को हम आर्थिक मदद दें। यह मदद एक पशु मरने पर कुल दो सौ रुपये और एक परिवार के लिए कुछ थोड़ा-सा अनाज मिलता है। इस मदद से किसका क्या भला होगा? यह समझ में नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि आपके राज्य की जलनीति में यदि जल के निजीकरण और नदियों को जोड़ने की योजना को रोका जा सके, तो अच्छा होगा। इस पर स्वयं लालूप्रसाद यादव जी और राज्य के दो मंत्रियों ने कहा कि हमारी सरकार पानी के निजीकरण की घोर विरोधी है। हम अपने प्रदेश में नदियों का जोड़ भी नहीं होने देंगे।

इन्हीं के बीच हमारे एक जलयोद्धा महेश और सरिता भी थे। ये दोनों ही पानी की लड़ाई में शहीद हो गये।

यहाँ पानी और नदियों के लिये लड़ने वाले कई पुराने साथी पहले से मौजूद हैं : श्री दिनेश मिश्रा, श्री पुष्पेन्द्र, श्री विजय कुमार, श्री प्रियदर्शी, श्री प्रभात और श्री अनिल प्रकाश। इन्हीं के बीच हमारे एक जलयोद्धा महेश और सरिता भी थे। ये दोनों ही पानी की लड़ाई में शहीद हो गये। इन्हें कार्याञ्जलि देने वाली यात्रा में जलयात्रियों ने भी शामिल होकर नदी जोड़ को रोकने के संकल्प को मजबूती दी।

तत्पश्चात् बिहार राज्य के मोनिया कस्बे के पास एक होटल में भोजन के लिए हमारी यात्रा रुकी। हमारे यात्रा दल में कुछ विदेशी महिलाएं भी थीं। ये बिहार के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती थीं। दुर्भाग्यवश वहां कुछ ऐसी घटना घटी कि यह स्थान उनके लिये सुरक्षित नहीं जंचा, अत: हम बिना भोजन किये वहां से निकल पड़े। आगे चलकर मोनिया के सरकारी होटल में ठहरे। वहाँ का माहौल भी कुछ बहुत अच्छा नहीं था। यहाँ की सड़कें भी बेहद खराब हैं। 150 किमी. की दूरी छह घंटे में तय हुई।

कोशी के इस बाढ़ क्षेत्र को पार करके हम खगड़िया पहुँचे। वहां मैंने कहा कि बिहार के पास अथाह जल है, लेकिन वह सब केवल बाढ़ की मार के रूप में दिखता है। क्या हम इस जल को बचाने के लिए और अपनी समृद्धि का प्रतीक बनाने के लिए जल के साथ जीने की परम्परागत कुशलता और क्षमता को पुनः जीवित कर सकते हैं? इस विषय में इस सभा में बैठे लोगों का बहुत समर्थन मिला। ध्यान रहे कि बिहार सम्पूर्ण क्रान्ति आन्दोलन का उद्गम स्थल रहा है और आज लोकतंत्र खतरे में है। इसके बचाव में बिहार के समाज को पहल करनी चाहिए। पानी के निजीकरण और नदियों के जोड़ने के काम को रोकना हमारा सबसे पहला और जरूरी काम बनना चाहिए। इसी से लोकनायक को श्रद्धांजलि मिलेगी। मैंने इस दिशा में काम करना स्वीकार करने वालों से हाथ उठाने को कहा, तो इस सभा में बैठे ज़्यादातर लोगों ने हाथ उठाकर तत्काल कुछ करने का संकल्प जताया।

पानी के निजीकरण और नदियों के जोड़ने के काम को रोकना हमारा सबसे पहला और जरूरी काम बनना चाहिए। इसी से लोकनायक को श्रद्धांजलि मिलेगी।

अगली सुबह होते ही वे हमें खगड़िया के आस-पास के गाँवों में ले गये। देखा कि कोशी नदी के तटबन्ध पर अभी भी बाढ़ से विस्थापित लोग घर बनाये बैठे हैं। कोशी नदी को नाव से पार कर हम मुसहर आदिवासियों के एक बड़े गाँव में पहुँचे। यह उजड़ा हुआ गाँव सरकार ने नये मकान बनाकर बसाया है, पर यहां अभी तक मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। दूसरे गाँव के रास्ते में औरतों ने हमें सरकारी आदमी समझ कर रोका और कहा – "जिस तरह पिछले गाँव के मकान बनवाये हैं, इसी तरह हमारे मकान भी बनवा दो।"

हमने पूछा कि अब से पचास साल पहले आप क्या करते थे और अब क्या करते हैं? उस समय और आज के हालात में क्या फर्क है? दो बूढ़ी महिलाएँ बोली – पहले अच्छा था। हम कहीं भी जाकर अपना पेट भर लेते थे। अब तो हम अपने घर से बाहर

मैंने जीवन में इतना व्यापक अन्तर और विरोधाभास बिहार की धरती पर ही देखा। एक तरफ अति आधुनिक खेती और दूसरी तरफ परम्परा के प्रमाण अभी भी बिहार में देखने को मिलते हैं।

निकलते हैं, तो जमींदार हमें रोक देता है, जमींदार के सामने हमारी हिम्मत ही नहीं होती कि हम कुछ बोल सकें।

वापस आते हुए दो तरह की फसलें देखीं; एक अति आधुनिक और दूसरी परम्परागत सजीव खेती। आधुनिक में मक्का टरमिनेटर की उन्नत फसलें थीं। दो साल पहले यह संकर बीज बहुत अधिक पैदावार वाला था। पिछले साल पेड़-पौधे तो बहुत स्वस्थ थे और देखने में बहुत अच्छी फसल दिखती थी, लेकिन भुट्टों में दाना नहीं पड़ा। किसानों के पूछने पर बीज बेचने वालों ने बताया कि मौसम की खराबी के कारण दाना नहीं पड़ा, इस बार हो जायेगा। अत्यन्त महंगे बीज खरीदकर फसल बोने पर भी घाटा ही है। दूसरी तरफ सजीव खेती पिछले साल भी अच्छी हुई और इस साल भी अच्छी होगी। मैंने जीवन में इतना व्यापक अन्तर और विरोधाभास बिहार की धरती पर ही देखा। एक तरफ अति आधुनिक खेती और दूसरी तरफ परम्परा के प्रमाण अभी भी बिहार में देखने को मिलते हैं।

दिन भर के भ्रमण से लौटने के बाद बिहार की स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होना था। इस संवाद से बाढ़ के साथ बिहार अपना सहजीवन कैसे सुखी और समृद्ध बना सकता है?... इस पर अभ्यास किया गया। बाढ़ के लाभ और हानियों के सूचीबद्ध विश्लेषण से इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि बाढ़ को प्राकृतिक रूप में स्वीकारना अच्छा है। बाढ़ मुक्ति के लिए जो उलट प्रयास हुए हैं, उनसे मुक्ति पाना जरूरी है।

यहाँ से हम पटना आये और पटना में हमारी जलबिरादरी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा स्व. सुश्री सरिता और जल बिरादरी के कार्यकर्ता स्व. श्री महेशकांत की श्रद्धांजलि सभा थी। इनके हत्यारों को पकड़ने के लिए आयोजित धरने में हम दिन भर व्यस्त रहे। सायं समय मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन दिया और उन्होंने हमारे सामने ही हत्यारों को तुरन्त पकड़ने का आदेश एस.पी. को दिया। जलबिरादरी के इन दोनों कार्यकर्ताओं ने तरुण भारत संघ से जल संरक्षण का कार्य सीखकर बिहार में बहुत अच्छे से काम किया था, लेकिन बिहार की राजनीतिक सत्ता को भी अच्छे काम मंजूर नहीं थे। उसी ने ही उनकी हत्या करा दी।

इन हत्याओं के विरोध में कई गाँव के लोगों ने अपने बाल मुंडवा दिये और पूरे प्रदेश में हत्याओं के विरुद्ध वातावरण बनाने का काम शुरू किया। इसीलिए 'सरिता-महेश कार्यांजलि यात्रा' का आयोजन हुआ। यह यात्रा बांदा से शुरू होकर दुधि, छपरा... खगड़िया पहुँची। मैं इस पूरी यात्रा में शामिल हुआ। मैंने कहा कि सरिता और महेश को सच्ची श्रद्धांजलि और कार्यांजलि उनके अधूरे कार्यों को पूरे करने से होगी।

बिहार में नेपाल से बाढ़ आती है। इस बाढ़ के कारण दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया में खेत डूब जाते हैं। बाढ़ से बचाने के नाम पर यहां अभी नया हाईडेम बनाने का काम शुरू हुआ है। वह भी उपयुक्त नहीं है। जिस तरह से तटबन्दी ने हालात बिगाड़े हैं, वैसे ही हाईडेम भी हालातों को खराब करेंगे। हमारा मानना है कि बिहार के लोगों को अपने बाढ़ और सुखाड़ से मुक्ति के रास्ते खुद ही खोजने चाहिए। पहले नेपाल से शुरुआत हो, फिर बिहार में भी जनोन्मुखी विकेन्द्रित जल प्रबन्धन को बढ़ावा दिया जाये। इससे ही बिहार राज्य में सुखाड़ से मुक्ति और बाढ़ के साथ जीने का कौशल आ सकता है। तभी बाढ़ क्षेत्र में कम पानी आयेगा। सुखाड़ में भी ज़्यादा दिन धरती के नीचे और धरती के ऊपर पानी रहेगा। तभी बिहार वास्तव में पानीदार बनेगा, पुनः समृद्ध होकर अपना पुराना गौरव हासिल करेगा।

मैली गंगा, सुप्त समाज

उत्तरांचल – उत्तर प्रदेश

गंगा के उद्गम से समुद्र में मिलने तक गंगा किनारे यात्रा करके गंगा दर्शन हुआ। 'गंगा बचाओ' का नारा लिए चली जलयात्रा ने गंगा का दुखी रूप देखा। अलकापुरी से पतले मजबूत धागे के रूप में चली आ रही अलकनंदा को टिहरी में कैद कर लिया गया है। देवप्रयाग में भगीरथी से मिलकर इसका नया नामकरण हुआ- गंगा। जब गंगा हर की पौड़ी हरिद्वार तक पहुँचती है, तो इसमें श्रद्धा से स्नान करने वाले लाखों लोग इस बात से बेखबर होते हैं कि गंगा अब हमारे हाथों से निकल कर दूसरे हाथों में चली गई है । इस पर अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने कब्जा कर लिया है । टिहरी बाँध सीधा दिल्ली पानी पहुँचायेगा।

ध्यान रहे कि गंगा जल जिन जलसूत्रों से सदा पवित्र बना रहता था, गोमुख से टिहरी के बीच वे पहाड़ों की राख जैसा पवित्र व शुद्ध होते थे। वही गंगाजल को दूषित नहीं बनने देते थे। अब वे तत्व टिहरी के ऊपर ही रुक गए, तो नीचे का जल दूषित होने लगा। देशभर के समाज को स्नान हेतु हर की पौड़ी पर अब वह पवित्रता नहीं मिल सकेगी। यह बात हमारे समाज की चिन्ता का विषय नहीं है हमारी चिन्ता का विषय है, पानी की लूट !

हर की पौड़ी पर अब वह पवित्रता नहीं मिल सकेगी। यह बात हमारे समाज की चिन्ता का विषय नहीं है, हमारी चिन्ता का विषय है, पानी की लूट !

हमारे गंगा के पानी को कम्पनियाँ अपना बनाकर बेच रही हैं। गंगा हमारे हाथों से जा रही है । केवल इतना ही नहीं है, बल्कि हम गुलाम बनने की भी तैयारी कर रहे हैं। इस विषय में सभी पार्टियों के राजनेता भी तैयार हैं। वे भी गुलाम बनाने के नये-नये रास्ते ढूँढ़ रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में नेताओं को अपनी सुरक्षा नहीं दिख रही है । गुलामी में इन्हें इनकी सुरक्षा मिल जायेगी । पीढ़ी-दर-पीढ़ी राज में हिस्सा मिलता रहेगा । इसलिए अब लोकतंत्र की जगह नया राजतंत्र बन रहा है । इस तन्त्र में जमीन-जल-जंगल-जीवन सब कुछ राज के हाथ में होगा। पहले मैनचेस्टर की लूट कपड़े जैसी मामूली चीजों में थी। अब तो जीवन देने वाले जल में ही लूट शुरू हो गयी । जीवन की यह लूट पहले भोटिया जनजाति के गाँव हरसिल बगोरी के जंगल से शुरू हुई थी। अब तो हरसिल से भी ऊपर गोमुख से ही गंगाजल की लूट शुरू हुई है । इसे रोकने के प्रयास भी तो हो रहे हैं, लेकिन उनमें कमजोरी है।

'गंगा बचाओ यात्रा' की सभाओं में लोगों में बहुत उत्साह दिखाई दिया । उत्तरकाशी की शहर सभा में मौजूद राजनेताओं ने गंगा को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों

को नहीं देने की बात कही। श्री सुन्दर लाल बहुगुणा जी ने भी अपने और गंगा के दर्द को बताया, लेकिन गंगा के दर्द ने किसी और को सताया नहीं। पता नहीं आज ऐसा क्यों होता जा रहा है, हमें हमारी साझी पीड़ा और दर्द का अहसास एवं आभास ही नहीं होता । जब तक समाज अपने दुःख-दर्द को समझ कर स्वयं कुछ करने को खड़ा नहीं होगा, तब तक हम लुटते-पिटते और गुलाम ही बनते रहेंगे ।

मवाना में पाण्डव-काल का बड़ा ताल आज भी देखने लायक बना हुआ है ; लेकिन गन्ने की खेती और अधिक पानी वाली फसलों का चक्र अब पुराने तालाबों से चलता नहीं दिखता ।

उक्त सब बातों को आज सुनकर कल भूलना हमारे नेताओं की आदत में है । इसका दर्शन हमारी 'गंगा बचाओ यात्रा' की हरिद्वार सभा में भी हुआ। हरिद्वार... हिमालय का प्रवेश द्वार है। इसे कभी भगवान से मिलने का रास्ता माना जाता था, आज यह उल्टे रास्ते दिखाने का केन्द्र बन गया है।

रुड़की जो हमारे देश की जल इन्जीनियरिंग का सबसे बड़ा केन्द्र माना जाता है । यहीं हमारे देश की जल कारीगरी विकसित हुई, पर अब यह केवल ठेकेदारी का केन्द्र बन गई है। यहाँ आज भी बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं; लेकिन सभी देश का पानी उतारने में लगे हैं। गरीब को पानी मिले, गरीब का पानी पर हक कायम रहे... इसकी चिन्ता यहाँ अधिक दिखाई नहीं दे रही ।

हस्तिनापुर आते-आते गंगा का रूप विकराल हो जाता है । यहां गंगा में भी बड़े-बड़े कटाव-जमाव दिखाई देते हैं। यहीं पर गंगा किनारे के गाँव मवाना में पाण्डव-काल का बड़ा ताल आज भी देखने लायक बना हुआ है ; लेकिन गन्ने की खेती और अधिक पानी वाली फसलों का चक्र अब पुराने तालाबों से चलता नहीं दिखता । यह दोआब का क्षेत्र कभी भूजल भण्डार हेतु प्रसिद्ध था, अब सूख रहा है । गंगा-यमुना के बीच मेरठ-बागपत का चोगाना भी पानी के संकट से जूझ रहा है । आधुनिक विकास की दौड़ में शामिल होने के कारण यहां ऐसा हुआ है ।

मेरठ से कानपुर आते-आते गंगा का रूप-रंग-चरित्र सब कुछ बदल जाता है । अब गंगा मैली ही नहीं, जहरीली भी बन गयी है। यहाँ गंगा जीवनदायिनी नहीं, मृत्यु-दायिनी है। यहाँ कुछ गंगा चिन्तक हैं, जो लम्बे समय से इसकी बात उठाते रहे हैं । यात्रा में भी बात उठाई, लेकिन कोई असर नहीं है । गंगा की पवित्रता बनाने वाला समाज आज सो गया है । जब समाज सो गया हो, तो फिर इसे जगाने के नाम पर भी लूटने वाले ही आते हैं । यदि हमारा समाज जगा होता, तो 'गंगा कार्ययोजना' के पैसे, समाज की चेतना तथा समझदारी से गंगा पवित्र बनने लगती; पर नहीं, समाज बेखबर बना रहा और ठेकेदार, इंजीनियर, नेता, व्यापारी, अधिकारी... सब गंगा पवित्र बनाने के नाम पर केवल लूटते रहे । गंगा मैली और मैली बनती गई। हम जहाँ भी गये, लूट का स्पष्ट दृश्य दिखाई दिया। कुछ जगह तो गन्दे नालों को रोकने के नाम पर सारे गन्दे नाले गंगा में मोड़ कर डाल दिये गये। 'गंगा कार्ययोजना' – गंगा को अधिक गन्दा बनाने वाला नंगा नाच है । मैं इसका सारा दोष केवल सरकारी व्यवस्था पर ही नहीं डाल रहा हूँ; समाज पर भी इसकी जिम्मेदारी है ।

जब समाज सो गया हो, तो फिर इसे जगाने के नाम पर भी लूटने वाले ही आते हैं । यदि हमारा समाज जगा होता, तो 'गंगा कार्ययोजना' के पैसे, समाज की चेतना तथा समझदारी से गंगा पवित्र बनने लगती।

यदि समाज ने गंगा की पवित्रता के विषय में विचार किया होता, तो गंगा से कटाव-जमाव रोकने के नाम पर बने सामाजिक कानूनों की पालना होती। आज वह नहीं हो रहा है । गंगा संहिता के अनुसार गंगा तट के 30 गज दूरी तक दोनों तरफ हल चलाकर कोई खेती नहीं करेगा। किसी प्रकार की कोई गन्दगी इसमें नहीं करेगा। इसके किनारे शौच आदि नहीं करेगा। शरीर पर उबटन आदि करके इसमें स्नान नहीं करेगा। कृत्रिम वस्तुओं के उपयोग पर रोक थी, पर गंगा आचार संहिता को व्यवहार में नहीं लिया गया। गंगा की पवित्रता बनाने वास्ते हमारे समाज को अपनी आचार संहिता बनाकर इसके किनारों को साफ रखना ही पड़ेगा। तभी गंगा साफ रहेगी।

इलाहाबाद जाते-जाते गंगा पुनः कुछ-कुछ फैली दिखाई देती है । संगम करोड़ों को बुलाता है । यहाँ कुम्भ का बुलावा हमें स्वीकार है, लेकिन इसे पवित्र बनाने का आह्वान हमें स्वीकार नहीं दिखता। इलाहाबाद में गंगा किनारे बुद्धिजीवियों की अच्छी सभा हुई। किसी ने गंगा को पवित्र बनाने का काम शुरू करने की पहल नहीं की। इस दिशा में काम करने वाला कोई आगे नहीं आया। भले ही यहाँ से आगे जाने वाले हमेशा आगे ही रहे। यह देश को चलाने वाले पूरे तीन प्रधानमंत्री देने वाला क्षेत्र है ।

केन-बेतवा नदी जोड़ का विरोध करने के लिए ही हमारे एक साथी श्री सुरेश रैकवार ने राजस्थान छोड़ वहाँ जाकर काम शुरू कर दिया है ।... मैं भी वहाँ जाने को प्रतिबद्ध हूँ।

खैर, हम इलाहाबाद से बान्दा के लिए निकले। यहाँ पर केन-बेतवा नदी के जोड़ का स्थान देखना था। पता लगा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा पर केन-बेतवा को जोड़ने हेतु 72 मीटर ऊँचा बाँध बनेगा। गाँव हालब से 231 कि.मी. लम्बी नहर ले जाकर झाँसी के बरूआ सागर में डाली जायेगी। इसके द्वारा पूरे बुन्देलखण्ड को पानी देने के सपने दिखाये जा रहे हैं। इन सपनों को देखकर नौजवान बहुत खुश हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग चिन्तित हैं। किसानों ने इसका बहुत विरोध किया है । समाजवादी किसान नेता भी इसके विरोध में हैं।

इस नदी जोड़ का विरोध करने के लिए ही हमारे एक साथी श्री सुरेश रैकवार ने राजस्थान छोड़ वहाँ जाकर काम शुरू कर दिया है । सुरेश ने पूरे बुन्देलखण्ड में वार्ता कर इसे रोकने हेतु जनमानस तैयार कर लिया है। मैं भी वहाँ जाने को प्रतिबद्ध हूँ।

बान्दा के लोगों से मिलना बहुत ही सार्थक रहा। बुन्देलखण्ड अब सचमुच बेपानी है । इसे पानीदार बनाने वास्ते मिलकर काम करने की जरूरत है । इसका यहाँ सबको अहसास भी हो गया है । बस, अब नदी जोड़ के विरुद्ध मौके पर ही सत्याग्रह की तैयारी के लिए श्री सुरेश रैकवार, श्री अभिमन्यु सिंह जी निकलने

वाले हैं। इन्होंने इस चुनावी दौर में पूरे क्षेत्र में नदी जोड़ के विरुद्ध वातावरण बनाना तय कर लिया है । ये इस दिशा में गम्भीरता से जुट भी गये हैं। हमें खुशी हुई । तत्पश्चात् हम कर्वी से बनारस पहुँचे।

बनारस में गंगा की सुन्दरता मन्दिरों से अद्भुत नजर आती है; लेकिन इतनी ही दूषित गन्ध हमें झकझोरती भी है । यहाँ श्री वीरभद्र मिश्र जी ने गंगा पवित्रता के जन प्रयास किये; लेकिन नेताओं ने उन्हें पछाड़ दिया। डॉ. श्री जी. डी. अग्रवाल जी ने भी गंगा की पवित्रता के भले प्रयास किये, लेकिन हमारे नेताओं के सामने उनकी भी नहीं चली ।

उत्तर प्रदेश जलबिरादरी कानपुर और घाटमपुर में गंगा को प्रदूषणमुक्त करने तथा मुरादनगर और मोदीनगर के बीच गंगा जल की बिक्री के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा करेगी

हमें संतोष है कि 'गंगा बचाओ यात्रा' उत्तर प्रदेश में बहुत ही सार्थक रही । इस यात्रा ने एक हलचल पैदा कर दी है । इस हलचल से समाज ने अपनी जिम्मेदारी को समझा। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जलबिरादरी कानपुर और घाटमपुर में गंगा को प्रदूषणमुक्त करने का बीड़ा उठायेगी। मुरादनगर और मोदीनगर के बीच गंगा जल की बिक्री के विरुद्ध कुछ आन्दोलन खड़ा करेगी तथा बान्दा में नदी जोड़ के काम को रोकेगी।

उत्तर प्रदेश जलबिरादरी ने जलयात्रा करके अच्छी शुरुआत की है । अब इस राज्य में जल संरक्षण, प्रबन्धन तथा पानी का हक बचाने की लड़ाई लड़नी है । इस राज्य को जनोन्मुखी व जल जरूरत पूरी करने वाली राज्य जलनीति बनाने तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस प्रदेश को अब 'गंगा बचाओ यात्रा' की अनुपालना का कार्यक्रम बनाकर पुनः लोगों के बीच जाना चाहिए ।

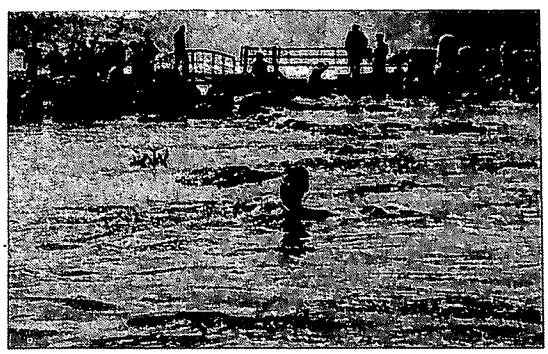

इस राज्य में श्री राम धीरज, श्री शेखर, श्री अरविन्द कुशवाहा और श्री ईश्वर चन्द्र जैसे जुझारू जलयोद्धा शामिल हैं । श्री अनिल राणा, श्री कुशलपाल और श्री वीरेन्द्र सिंह जैसे रचनात्मक काम करने वाले युवा हैं, इसलिए उम्मीद है कि यह राज्य गंगा बचाने के काम में अगुवाई करके दिखायेगा। सबने

अपनी जिम्मेदारी तय कर ली है। इस यात्रा के दौरान पाँच जगह जल बचाने का कार्य भी शुरू हुआ है । एक जगह बान्दा में नदी बचाने का संघर्ष शुरू हुआ । इस राज्य से 'गंगा बचाओ यात्रा' की विदाई पर बड़ा सम्मेलन हुआ।

उत्तर प्रदेश... देश को बनाने वाला प्रदेश है । इसमें बहुत क्षमताएँ और योग्यताएँ हैं, लेकिन इतनी ही बड़ी कमजोरी भी है । सारा समाज टूटा और बंटा हुआ है ।

उत्तर प्रदेश... देश को बनाने वाला प्रदेश है । इसमें बहुत क्षमताएँ और योग्यताएँ हैं, लेकिन इतनी ही बड़ी कमजोरी भी है । सारा समाज टूटा और बंटा हुआ है । आज इस प्रदेश में सामाजिक और साझी समृद्धि का कोई आन्दोलन दिखाई नहीं दे रहा। बिखराव ने साझे भविष्य को बनाने के सभी रास्ते बन्द कर दिये हैं । प्रकृति से लेन-देन का सन्तुलन बिगड़ गया। आज तो केवल लूट ही बची है । प्रकृति से लूटकर जीवन जीना ही यहाँ का एकमात्र उद्देश्य बन गया है । यहाँ भविष्य के साझे खतरे भी बहुत अधिक दिखाई दे रहे हैं।

खतरों से बचाव के उपाय हेतु इस प्रदेश की मरती संस्कृति व नदियों की सभ्यता को पुनः उभारना होगा। इस राज्य में जनसंख्या का दबाव जितना है, उतने संसाधन नहीं हैं । न तो साझा संसाधन ज्यादा हैं और न ही निजी । यहाँ मानसिक, शारीरिक ...सभी प्रकार का प्रदूषण बढ़ रहा है । समाज और नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं। इन दोनों के बीच बहुत दूरी बढ़ गई है । नदी और समाज के बीच की दूरी कम होवे, समाज नदी को अपनी माँ केवल कहे नहीं, बल्कि नदी के साथ माँ जैसा व्यवहार भी करे । नदी को जीवन आधार मानकर इन्हें कचरा ढोने वाली मालगाड़ी नहीं, बल्कि आपस में माँ और बेटा... दोनों एक स्वरूप होकर जीवन जीयेंगे; तभी हमारी निर्मल माँ गंगा सदानीरा बनकर हमारे समाज को समृद्ध बनाकर रखेगी।

'गंगा बचाओ यात्रा' इस प्रदेश में सम्पन्न होते समय नदी जोड़ के षड्यंत्र को रोकने का संकल्प बान्दा में समाज को हिला सका । जलयात्रा के दो वर्षों का राष्ट्रव्यापी चक्र भी 18-19 मई के राष्ट्रीय सम्मेलन में यहीं से अपनी आगे की यात्रा शुरू करेगा, यह तय हुआ।

अब बचेगी ब्रह्मपुत्र

उत्तर-पूर्व

उत्तर-पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ की चर्चा सदैव सुनते रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र का राज और समाज जल कैसे बचाता था?... इसकी बात कभी नहीं सुनी थी। इस वर्ष मार्च-अप्रैल में ये सब देखने-समझने को मिला। सबसे पहले असम में गौरी सागर, शिव सागर और जयसागर नामक तीन कुण्ड ताल देखकर आश्चर्य हुआ। जयसागर एशिया का सबसे बड़ा ढका कुण्ड है । यहाँ के महाराज ने अपनी मां जयस्मिता के नाम पर इसे बनवाया था। जयस्मिता महारानी ने जीवन भर अपने पति का कष्ट सहन किया था। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इनके पुत्र ने महाराजा बनते ही समाज को पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु कुण्ड बनवाया। शिव सागर-गौरीसागर कुण्ड... ये दोनों ही कुण्ड... समाज की श्रमशक्ति और समर्पण से बने हैं। ये राजस्थान के बड़े से बड़े टांकों से भी बड़े हैं।

जयसागर एशिया का सबसे बड़ा ढका कुण्ड है । यहाँ के महाराज ने अपनी मां जयस्मिता के नाम पर इसे बनवाया था।

मैं राजस्थान में पानी का काम देखने आए लोगों से आज तक सुनता रहा कि राजस्थान जल संकट से ग्रस्त है, इसलिए यहाँ समाज जल बचाने में जुटता है; जहाँ बहुत पानी है, वहाँ समाज पानी बचाने में नहीं जुटता। यह बात गलत सिद्ध हुई। राष्ट्रीय जलयात्रा में साफ दिखा कि कश्मीर से कन्याकुमारी, गोवा से गुवाहाटी तक राज और समाज जल सहेजता था। सभी जगह पानी को तीर्थ की तरह देखा गया। इसलिए समाज ने बाढ़ के साथ भी जीना सीख लिया था। बाढ़ व सुखाड़ कष्ट रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि समाज इसे प्रकृति प्रदत्त सुख-दुख के रूप में देख अपने मन को समझाता था। अब सरकार बाढ़ व सुखाड़ को

आपदा में प्रस्तुत करती है, इसीलिए बाढ़ नियंत्रण की बात भी बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कही जा रही है। समझदार समाज इसका विरोध भी कर रहा है। हम जानते हैं कि ब्रह्मकुण्ड से शुरू होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत-चीन होते हुए असम की सीमा में प्रवेश करती है। मीलों चौड़े मासोली जैसे सैकड़ों गाँव वाले द्वीप बनाने वाली यह नदी स्त्रीलिंग नहीं, नद्य कहलाने वाला पुल्लिंग है। इसमें बहुत तेजी से जल बहता है, इसलिए यह बहुत से द्वीप बनाता और बिगाड़ता रहता है।

मीलों चौड़े मासोली जैसे सैकड़ों गाँव वाले द्वीप बनाने वाली यह नदी... ब्रह्मपुत्र स्त्रीलिंग नहीं, नद्य कहलाने वाला पुल्लिंग है।

नदी जोड़ परियोजना के तहत अब ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश– भूटान सीमा के बीच हमारे कम चौड़े रास्ते से पकड़ कर एक कृत्रिम नहर के जरिए उड़ीसा की महानदी से जोड़ने की तैयारी है। इसके विपरीत जब 23 दिसम्बर, 2002 को महात्मा गाँधी की समाधि राजघाट, नई दिल्ली से राष्ट्रीय जलयात्रा शुरू हुई थी, तब उत्तर-पूर्व के प्रतिनिधियों ने ब्रह्मपुत्र नदी को बचाने का संकल्प लिया था। इसी के अनुरूप ब्रह्मपुत्र नदी को समझना तथा इस पर छाये खतरों को रोकने हेतु जल चेतना जगाना... जलयात्रियों ने जरूरी समझा। अत: हमने 22 मार्च, 04 का विश्व जलदिवस गुवाहाटी में मनाया। इस मौके पर डॉ. जी. डी. अग्रवाल, असम के श्री हेम भाई, शान्ति साधना आश्रम के कार्यकर्ता, विश्वविद्यालय के शिक्षक-विद्यार्थी तथा असम गण परिषद के युवा नेता उपस्थित थे। सभी ने 'ब्रह्मपुत्र बचाओ आन्दोलन' खड़ा करने की योजना बनाई।

असम में गुवाहाटी से शुरू होकर यह यात्रा सबसे पहले गौरीसागर पहुँची। यहाँ

शहर में रैली निकाली, पर्चे बाँटे तथा कई सभाओं को संबोधित किया। सभा में शिक्षक तथा शहरी बुद्धिजीवी ही अधिक आये । इन्होंने ब्रह्मपुत्र को महानदी से जोड़ने का विरोध तो किया, लेकिन बाढ़ से बचाव के उपाय भी पूछे । इसके बाद नदी किनारे स्थित दिइको अरमस गाँव के हायर सैकेण्डरी स्कूल में सभा हुई। यहाँ बालक, बड़े-बूढ़े, महिला-पुरुष सभी मौजूद रहे । नामदेव मन्दिर का ग्राम भावना कार्यक्रम तो काफी मोहक था। यहाँ मैंने नदी जोड़ने के विषय पर बात शुरू की, तो यहाँ के युवाओं ने खड़े होकर नदी जोड़ योजना का कड़ा विरोध किया। कुछ वृद्ध विद्वानजन बोलने लगे कि बाढ़ हमें बहुत कुछ देती भी है। कुछ कष्ट जरूर बढ़ता है, लेकिन सिर्फ कुछ कष्ट से बचने के लिए हम अपनी नदी को बिकने नहीं देंगे। ब्रह्मपुत्र हमारी माँ-बाप है। इससे हमारा जीवन चलता-बनता है, इसे हम किसी के हाथ नहीं जाने देंगे । जान देंगे, पर नदी नहीं जाने देंगे । यह सुनकर हम भी चकित रह गये।

बाढ़ हमें बहुत कुछ देती भी है। कुछ कष्ट जरूर बढ़ता है, लेकिन सिर्फ कुछ कष्ट से बचने के लिए हम अपनी नदी को बिकने नहीं देंगे।

श्री हेम भाई को यहां सभी जानते हैं। पूरी यात्रा में इनके परिचितों का पूरा साथ व सहयोग मिला। हेम भाई ने नदी जल, ब्रह्मपुत्र जल, गंगाजल, नदी जल दर्शन तथा जल तीर्थ के मामले को बहुत ही जोरों से और भली प्रकार उठाया।

इस गाँव के उत्साह को देखकर सभा के बाद हमने यहां भी जलबिरादरी गठन का सुझाव रखा। कुछ जगह पर जल बिरादरी बनी भी। 'ब्रह्मपुत्र बचाओ' का संकल्प सीधे काम का सन्देश देने वाला है । यह कार्यक्रम असम में 20 मार्च से 29 मार्च तक चला और अन्त में विजयसागर जिले के शान्ति साधना आश्रम की सभा में निर्णय लिया कि चुनाव में जन प्रतिनिधि से नदी जोड़ का विरोध करें। जो नहीं माने, उसे वोट नहीं देने का निर्णय लिया। चुनाव के बाद जब ब्रह्मपुत्र-महानदी जोड़ पर प्रत्यक्ष काम शुरू होवे, तो इसे रोकने के लिए जनमानस को पूरी तरह सजग व तैयार रहने की आवश्यकता जताई।

असम सर्वोदय मण्डल, कस्तूरबा गान्धी ट्रस्ट व आसू आदि संगठनों ने सर्वसम्मति से इसके विरोध में सीधे उतरने की बात कही है । दूसरे संगठनों को तैयार करने में श्री हेम भाई जुट गये हैं। मैंने श्री रवीन्द्र उपाध्याय जी को पत्र लिखा

है, वह भी इस कार्य में जुटेंगे और चुनाव परिणाम आने से पूर्व ही नदी जोड़ को रोकने की तैयारी पूरी कर लेंगे। यह जरूरी है, क्योंकि यदि आज असम हरा-भरा, खाता-पीता प्रदेश है, तो यह सब सुख-समृद्धि ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ही है। इसका रूप बदलने से समाज का रूप भी बदल जायेगा। यह बात असम के समाज के मन में जहाँ-तहाँ आ गई है। बस, इसे जोड़ने और उभारने की जरूरत है। 'ब्रह्मपुत्र बचाओ' का सन्देश इसे उभारेगा-जोड़ेगा।

श्री हेम भाई आध्यात्मिक पुरुष हैं। यही जल आध्यात्म को उभारेंगे, तो पूरा असम बह्मपुत्र के साथ जुड़ कर बह्मपुत्र-महानदी जोड़ के खतरों से असम को बचा सकेगा।

असम आज सब तरह से तृप्त करने वाला प्रदेश है। असम का केला-चावल, सब्जियाँ सब अच्छे लगे। केले की छाल में चावल, दही, गुड़ खाकर तो मैं तृप्त हो गया। खानपान का यह आनन्द ही अनोखा है। इसके स्वाद का अनोखापन बचाने वास्ते भी ब्रह्मपुत्र का बचना जरूरी है। यहाँ की धर्म-संस्कृति-सभ्यता... सब कुछ, ब्रह्मपुत्र की देन है। हमें यकीन है कि नदी के लेन-देन के रिश्तों को कायम रखने हेतु असम का समाज अपने धर्म को समझेगा और निंभायेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु 'ब्रह्मपुत्र बचाओ' का नारा शुरू हुआ। श्री हेम भाई, स्वामी जी और शान्ति साधना आश्रम की बहनें सब मिलकर ब्रह्मपुत्र आन्दोलन शुरू कर दें, तो पूरे असम में यह कार्य जल्दी ही फैल जायेगा।

दरअसल जल की अधिकता ने अभी तक उत्तर-पूर्व राज्यों को पानी की कमी से बचाकर रखा है, लेकिन याद रहे कि जहाँ अधिक खजाना होता है, लुटेरे उसी को केन्द्र में रखकर लूट की रणनीति तैयार करते हैं। बह्मपुत्र में इस समय सबसे अधिक पानी है। लुटेरों का ध्यान भी इसी पर है। अतः उत्तर-पूर्व राज्यों को पानी की लूट रोकने हेतु स्वयं खड़ा होना ही होगा।

टूटे तटबंध, तो सूखेगा साम्य

पश्चिम बंगाल

23 दिसम्बर, 2002 को राष्ट्रीय जलयात्रा का पहला चरण बापू की समाधि, नई दिल्ली से शुरू हुआ था, जो देशभर में यात्रा करता हुआ चौथे चरण में पश्चिम बंगाल पहुँचा। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया भयंकर सूखे का क्षेत्र है। यहाँ अकाल की छाया अच्छी वर्षा के बावजूद बनी रहती है, जो अब ज्यादा ही दिखाई देने लगी है, क्योंकि अब अकाल की मार से बचाने वाले तालाब मिट्टी व गाद भरने से टूटते जा रहे हैं। इसलिये जो बारिश होती है, वह बहकर समुद्र में चली जाती है।

पश्चिम बंगाल का दूसरा नाम तालाब और पोखरों का राज्य हो सकता है। सुबह नींद खुलते ही यहाँ का समाज तालाब से अपनी जिन्दगी शुरू करता है।

पश्चिम बंगाल का दूसरा नाम तालाब और पोखरों का राज्य हो सकता है। सुबह नींद खुलते ही यहाँ का समाज तालाब से अपनी जिन्दगी शुरू करता है। दिनभर अपना घर... अपना शरीर – बर्तन धोने से लेकर बर्तनों में पकने वाले चावल, मछली और दिनभर चबाया जाने वाला पान सब कुछ तालाब के पानी पर ही निर्भर है। तालाबों की सभ्यता और संस्कृति वाला यह राज्य परम्परागत विकेन्द्रित जल प्रबन्धन का सफल नमूना कहा जा सकता है। यहाँ पर गांधीजी के ग्राम स्वराज्य के लक्षण अभी भी मौजूद हैं। गांव के घर-घर में तालाब और सिंचाई के लिए ढेकली सबके हाथों में रची-बसी है। यहाँ की पंचायतें और गाँव स्तर के संगठन काफी सक्रिय दिखाई देते हैं। मिदनापुर जिले का निन्तोड़ी गांव यहाँ से शुरू हुए आज़ादी के आन्दोलन की याद दिलाता है। इस क्षेत्र में अभी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध बहुत गहरी समझ दिखती है। इस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पुराने साथी श्री अहमद भाई नई आज़ादी के लिए कार्यरत हैं।

हावड़ा जिले के कस्बानुमा मोड़ी गाँव के हर तीसरे घर में आज भी तालाब जिंदा है। यहाँ की गांधी शान्ति प्रतिष्ठान इमारत के सामने भी एक छोटा-सा तालाब है। सुबह-सुबह मुँह धोने, कुल्ला करने, कपड़े धोने तथा बर्तनों आदि की सफाई से यह बहुत ही गंदला दिखाई देता है। मोड़ी गाँव से 40 किलोमीटर दूर कामनी गाँव में अब से तीन-चार साल पहले तक बंगाल जलबिरादरी के अध्यक्ष श्री चन्दन पाल ने दूषित पानी को उपयोगी बनाकर खेती के काम में लेना शुरू कराया और इसके साथ-साथ मदद देकर कुछ नये कुण्ड व तालाब भी बनवाये। इससे इस क्षेत्र में धान, चावल, पान और मछली पैदा करने का काम शुरू हुआ। फलस्वरूप अब यहाँ से उजड़े हुए नौजवानों को खेती में काम मिलने लगा है। पानी के छोटे से प्रयोग ने यहाँ की जिन्दगी को बदल दिया है।

यह राज्य पानी के निजीकरण के खिलाफ लड़ाई का शुरुआती केन्द्र भी बन सकता है, कारण कि इस राज्य की सरकार निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष करने में माहिर है।

बंगाल एक तरफ पानी के रचनात्मक काम का सफल परम्परागत नमूना तो है, पर यह पानी के निजीकरण को रोकने हेतु लड़ाई की शुरुआत का एक केन्द्र भी बन सकता है, कारण कि इस राज्य में वर्तमान सरकार निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष करने में माहिर है।

अधिक वर्षा का राज्य होने के बावजूद यहां पानी की कमी साफ दिखती है। यह गाँव, हावड़ा जिले का गाँव है। फिर भी यहाँ पानी की कमी है। अभी कुछ नये ताल बनाकर यहाँ नई रंगीन मछलियाँ बिक्री के लिए पाली जा रही हैं। इसके लिए ही धरती से पानी निकाल कर तालाब को भरा जाता है। इस तालाब में मछलियों का पालन नये पैसे की भूख से जन्मा है। एक तरफ इस गाँव के सूखते खेत और पेड़, दूसरी तरफ आधुनिक रंगीन मछली-पालन... पानी के बाजारू उपयोग का दर्शन करा रहा है।

बंगाल में प्रगतिशील विचार एवं परम्पराओं का अच्छा मिश्रण है। इस परम्परा

और प्रगति के मिश्रण को हम अब कैसे देखते हैं? एक तरफ परम्परागत जल प्रबन्धन वाले तालाबों को राज्य आश्रय प्राप्त है और दूसरी तरफ पैसे की मार और विकास की भूख भी है। यह राज्य बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा है। विरोधाभास यह है कि यहाँ पर आधुनिक विकास की चाह वाला साम्यवादी राज्य संचालक वर्ग खुद तो बिना शारीरिक श्रम के सभी प्रकार के सुख पाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ यही वर्ग गरीबी की मार और इससे बढ़ती हिंसा को समान हक पाने का संघर्ष कहकर मान्यता दे रहा है।

...अन्यथा बंगाल की निजीकरण विरोधी मानी जाने वाली सरकार भी पानी को धीरे-धीरे निजी हाथों में सौंप देगी।

पश्चिमी बंगाल को यदि अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो परम्परागत विकेन्द्रित स्वावलम्बी जीवन पद्धति को स्वयं बढ़ावा देना होगा। इस राज्य में जन की जल जरूरत केवल वर्षा से पूरी हो सकती है। इस प्रदेश में भूजल के भण्डार अब दूषित हो रहे हैं। अमृत समान सतही पानी बहकर समुद्र में मिल जाता है। यूं जहाँ-जहाँ वर्षा जल को सहेजने के परम्परागत साधन आज भी बचे हैं, वहाँ-वहाँ पर्याप्त जल और जीवन की जरूरत पूरी करने वाले साधन मौजूद हैं। हमें पश्चिम बंगाल को बचाने वास्ते परम्परागत पानी प्रबन्धन को पुनः जीवित करना होगा।

बंगाल में श्री नारायण भाई और श्री चन्दन पाल जैसे जल संरक्षक व रचनात्मक कार्यकर्ता हैं, पानी के हक को बचाने के लिए श्री अहमद भाई और सुश्री निरूपमा अधिकारी जैसे संघर्ष करने वाले साथी भी यहां मौजूद हैं। श्री नारायण व श्री चन्दन पाल जैसे साथी ही पानीदार बंगाल बनाने की पहल करें, तो श्री अहमद जैसे सैकड़ों युवा आगे आकर बंगाल के साझे भविष्य को सुरक्षित बना सकेंगे। अब बंगाल में आज़ादी को बचाने की शुरुआत करना जरूरी है, अन्यथा बंगाल की निजीकरण विरोधी मानी जाने वाली सरकार भी पानी को धीरे-धीरे निजी हाथों में सौंप देगी। बंगाल जलबिरादरी ने अपने राज्य की जलनीति में तालाब-पोखरों को सुरक्षित करने हेतु कानून कायदे बनवाये; बंगाल के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल के विकेन्द्रित जल प्रबन्धन को सुनिश्चित कराया। बंगाल का समाज पानीदार बन सके, इसलिए शहरी तालाबों को पार्कों में बदलने से रोकना, ग्रामीण तालाबों से सजीव खेती, मछली पालन और पान की खेती को बढ़ावा देने वाले कानून बनवाना जरूरी है। इस राज्य में जन जल आयोग यहाँ के जल संसाधन

पर श्वेत-पत्र जारी करेगा, तभी पता चलेगा कि आज़ादी के बाद यहाँ कितने तालाब नष्ट हुए? इनके नष्ट होने से पानी का कितना संकट बढ़ा है? इस जलयात्रा ने देखा कि बंगाल का बड़ा ग्रामीण क्षेत्र बेपानी होता जा रहा है। गंगा जी फरक्का बैराज के बाद फिर कैद हो जाती है... दो भागों में बंट जाती है। एक बांग्लादेश पहुँचती है, तो दूसरी गंगा सागर। फरक्का पहुँच कर गंगा पर मानव नियंत्रण हमारे मन में बहुत से सवाल पैदा करता है परन्तु इन सबका जवाब है... समाज और सरकारें मिलकर जगह-जगह जल जरूरत के अनुसार जल जुटायें। जल जुटेगा, तो हमारे बांग्लादेश-चीन सबके साथ पानी से रिश्ते जुड़ेंगे। पानी को लेकर देश-देश में युद्ध का जो वातावरण बन रहा है, इसे हमें आपसी प्रेम व साम्य भाव में बदलना है। हमें भगवान के दिये जल को अमृत मानकर इसे बचाना और इसके मर्यादित उपयोग का संस्कार डालना है।

फरक्का पहुँच कर गंगा पर मानव नियंत्रण हमारे मन में बहुत से सवाल पैदा करता है परन्तु इन सबका जवाब है... समाज और सरकारें मिलकर जगह-जगह जल जरूरत के अनुसार जल जुटायें। जल जुटेगा, तो हमारे बांग्लादेश-चीन सबके साथ पानी से रिश्ते जुटेंगे।

इस संस्कार और व्यवहार की सभी जगह जरूरत है। गंगासागर, पुरुलिया, मिदनापुर.... हावड़ा सभी जगह जल को जीवन का आधार मानकर प्रबन्धन किया जाये। फिर फरक्का बैराज की लड़ाई और सूखते तालाबों से गाँव का कष्ट सबको दूर किया जा सकता है। बंगाल की साम्यवादी सरकार समतावादी, साहसी और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली तभी साबित होगी, जब पानी का निजीकरण रोक कर विकेन्द्रित जल प्रबन्धन को बढ़ावा देगी, तभी सबको समान रूप से जल मिलेगा। बंगाल सरकार को जलापूर्ति अधिनियम बनाकर पानी से जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकार के इस कानून से सबका और सच्चा भला होगा। समाज और राज मिलकर पानी पर अपना समान हक कायम रख सकेंगे। सबको शुद्ध पेयजल मिलेगा। इस सन्देश के साथ हमने 'आमार सोनार बांग्ला देस' की सुनहरी कल्पना के सच होने की उम्मीद जतायी।

विशेषज्ञों की नज़र में

राष्ट्रीय जलयात्रा

डॉ. एम.एस. राठौड़ *(जयपुर)*, **श्री नित्या जैकब** *(दिल्ली)*, **सुश्री कल्पना** *(हरियाणा)* और
श्री पंकज कुमार - श्री बृजमोहन, *'सीडा' सलाहकार (उत्तरांचल)*

यूं तो यह यात्रा 23 दिसम्बर, 2002 को शुरू होकर 26 जून, 2004 को दिल्ली में सम्पन्न हो गई, लेकिन इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु आगे का कार्य अभी भी जारी है। इस यात्रा में करीब साढ़े तीन करोड़ लोगों से जल सहेजने और जल का अनुशासित उपयोग करने की बातें हुईं, ताकि वे समाज को पानीदार बनाने की मुहिम खड़ी कर सकें।

निजीकरण से जल संवर्द्धन के ऐसे कार्यों तथा जन संगठनों को गहरा खतरा हो सकता है, जिन्हें देश के विभिन्न स्थानीय समुदायों ने अपने खून-पसीने से बनाया व सींचा है।

उद्भव

एक अप्रैल, 2002 को भारत की राष्ट्रीय जलनीति की घोषणा की गयी। पानी पर काम करने वाले अधिकतर प्रबुद्धजनों की राय में यह नीति भारत में पानी के केन्द्रीकरण को और बल देगी तथा एक ऐसा माहौल तैयार करने में सहायता करेगी, जिससे पानी के नियोजन व रखरखाव में निजी क्षेत्र का वर्चस्व बढ़े।

जलनीति के साथ ही सरकार ने देश की 37 नदियों को जोड़ने की एक विशालकाय योजना की भी घोषणा कर दी। उद्देश्य यह है कि इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न नदी घाटियों के बीच पानी का स्थानांतरण होगा, जिससे बाढ़-अकाल दोनों से मुक्ति मिल जायेगी। वे सोचते हैं कि इस योजना से कृषि और औद्योगिक विकास जैसे कई राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल हो जायेंगे। वे नहीं जानते कि इससे कितनी बरबादी होगी; जबकि जमीनी काम करने वाले बौद्धिक समूह व संगठनों की आशंका है कि निजीकरण से जल संवर्द्धन के ऐसे कार्यों तथा जन

संगठनों को गहरा खतरा हो सकता है, जिन्हें देश के विभिन्न स्थानीय समुदायों ने अपने खून-पसीने से बनाया व सींचा है ।

जल संसाधन भूमि व वनों के रखरखाव के बारे में एक सर्वमान्य तथ्य यह है कि आज हमारे प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करने व उनके प्रबन्धन के सरकारी तौर-तरीकों के कारण आज हमारा समुदाय पानी के अधिकार से वंचित हो गया है। इस अधिकार के न होने की वजह से ही जल और इसलिये भूमि व वन संसाधनों के प्रबन्धन में भी आम जन की रुचि घट रही है। जलयोद्धाओं का मानना था कि नई नीति जन समुदाय को प्राकृतिक संसाधनों के सामूहिक प्रबन्धन से और विमुख करेगी। भविष्य में भारत को गंभीर आर्थिक व पारिस्थितिकीय खतरों का सामना करना पड़ सकता है। इन खतरों की सबसे अधिक मार समाज के सबसे पिछडे. वर्ग को ही झेलनी होगी।

भविष्य के खतरों को छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल व अन्य राज्यों में घटित होने वाली हाल की घटनाओं ने और भी उजागर किया है । कई राज्यों में 'बूट' या अन्य तरीकों से जल संसाधनों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन इलाकों में स्थानीय जनाधिकारों की खुलेआम अवहेलना की गई है, तभी ये अधिकार राज्य सरकारों द्वारा निजी क्षेत्रों को सौंपे जा सके।

इसी संदर्भ में राष्ट्रीय जलबिरादरी का जन्म हुआ। भारत में कार्यरत नागरिक समाज को 'राष्ट्रीय जलनीति' व 'नदी जोड़ो परियोजना' के खतरों से जागरूक करने की तीव्र जरूरत को जल बिरादरी ने बड़ी शिद्दत से महसूस किया; तभी जन-जन के विचारों को समझने तथा इन्हें जगाने के लिए एक राष्ट्रीय जलयात्रा का आयोजन किया गया।

उद्देश्य

- पानी का संयमित उपयोग, जल संसाधनों को पुनर्जीवित करना तथा पानी की गुणवत्ता व मात्रा बढ़ाने हेतु जन-जागृति पैदा करना।
- निजीकरण की सरकारी नीतियों व नदी जोड़ो परियोजना के खतरों के साथ-साथ जन-जन को आगाह करना कि पानी पर हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।
- पानी के संवर्द्धन व प्रबन्धन पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को आपस में जोड़ना।
- देश के अलग-अलग कोनों में कार्य करने वाले जल योद्धाओं को एक ताने में बुनना, ताकि निजीकरण पर एक समुचित प्रहार किया जा सके।
- राष्ट्रीय व राज्यों की जल नीतियों को अधिक जनोन्मुखी बनाने हेतु सामूहिक शक्ति तैयार करना।

19 महीने की अवधि में यह यात्रा भारत के 29 राज्यों के 300 जिलों में गई। इनमें 17 राज्य तो अकालग्रस्त हैं। पानी के मुद्दों पर कार्यरत असंख्य व्यक्तियों के साथ यह यात्रा 90 शहरों-कस्बों, तीन महानगरों तथा हजारों गांवों से गुजरी।

मुद्दे

(क) भूमिगत व सतही जल संसाधनों का देशभर में व्यापक ह्रास हो रहा है, जिससे पानी की अत्यधिक कमी हुई है। इससे उत्पन्न गंभीर परिणामों को सारा देश भुगत रहा है। प्रकृति अपने आपको पुनर्जीवित करने की शक्ति तेजी से खो रही है। मानव व प्रकृति हेतु पानी की उपलब्धता तेजी से घट रही है। बाढ़ व अकाल के चक्र अब कम अवधि में ज़्यादा विकराल होने लगे हैं। जमीन के ऊपर व नीचे जल के दोहन से भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है और डार्क जोन में आने वाले जिले तेजी से बढ़ रहे हैं।

(ख) पेय जल

साफ पीने लायक पानी की उपलब्धता बहुत तेजी से गिर रही है, जिससे देश के

कई हिस्सों में जल के शोषक बाजार उत्पन्न हो रहे हैं। योजना आयोग के अनुसार 1952 में भारत में 232 गांव पेयजल रहित थे; वर्ष 2002 में यह संख्या 90,000 पर पहुंच गयी।

जिन क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध है, वहां पेयजल जनित बीमारियां व मानव तथा पशु हेतु पेयजल इकट्ठा करने में ज्यादा मेहनत करती है, जिसका बोझ अधिकतर महिलाओं पर ही है ।

भूमिगत व सतही जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन तथा औद्योगिक व घरेलू जल प्रदूषण से पेयजल की गुणवत्ता भी तेजी से घट रही है। फ्लोराइड, आर्सेनिक, खारापन व इनसे जनित बीमारियाँ भी बहुत अधिक फैल रही हैं।

(ग) बड़े बांधों के अपूर्ण वायदे

जल प्रबन्धन के मध्यम व बड़े बांध और नहरों से सिंचाई जैसे आधुनिक तरीकों की तरफदारी करने वालों द्वारा देश को अकाल व बाढ़ से मुक्त कराने के वादे किए गए थे। ये वादे झूठे साबित हुए हैं। कई राज्यों में अब बड़े बांध ही अकाल व बाढ़ के कारण बन चुके हैं। बड़े बांधों के सामाजिक व पारिस्थितिकीय दुष्प्रभावों का निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है, इसके बावजूद नर्मदा व टिहरी जैसे बांधों को बनाया जा रहा है। उड़ीसा का हीराकुड सफल बांध माना जाता है, किन्तु इस बांध के बाद भी कटक बाढ़ ग्रस्त है। यात्रा के दौरान इसके आसपास भी सूखी फसलें व सूखे गांव देखने को मिले।

(घ) जल संबंधी विवाद

स्थानीय स्तर पर जलाधिकार में असमानता व उपभोग में कुप्रबंधन होने के कारण निम्न समूहों के बीच कई तरह के विवाद उपज रहे हैं :
शहरी व ग्रामीण क्षेत्र - कृषि, उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र, - समृद्ध तथा पिछड़े वर्ग - ऊंची तथा नीची जातियां, - नदी घाटी के ऊपरी तथा निचले भू-भाग वासी - विभिन्न राज्य-उद्योग व स्थानीय समुदाय।

(ङ) सिंचाई हेतु जल

सिंचाई हेतु जल संसाधनों का बहुत तेजी से ह्रास हो रहा है, जिससे खाद्यान्न सुरक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ज्यादा जल खपत की फसलों के कारण भी पानी का असंयमित उपयोग बढ़ा है। उदाहरण के तौर पर देश के 3700 बांधों में से 1600 महाराष्ट्र में ही बने हैं। वहां भारत के जल संसाधन विकास का 40 प्रतिशत धन खर्च हुआ है, इसके बावजूद राज्य के 45,000 में से 6,000 गाँवों में पेयजल का गंभीर संकट है। क्यों ? इन गाँवों में पानी टैंकरों द्वारा दिया जा रहा है, जिससे कई लोग काफी मुनाफा भी कमा रहे हैं। इन्हीं क्षेत्रों में दूसरी तरफ गन्ने जैसी अधिक पानी पीने वाली फसलें पानी की कमी का कारण बन रही हैं। कुछ क्षेत्रों में बिजली तथा नहर के पानी की वजह से पानी के असंयमित उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है। नहर की सिंचाई द्वारा कई क्षेत्रों में ऊसर जमीन की मात्रा बढ़ रही है।

पानी की बढ़ती कीमत से जैसे देश के अधिकांश हिस्सों में पानी दूध से भी महंगा हो गया है, इसी तरह कृषि तथा इससे जुड़े हुये उत्पादों की कीमत बढ़ रही है।

(च) वैश्वीकरण के दबावों से उत्पन्न दुष्प्रभाव

राष्ट्रीय जलनीति यह कहती है कि पेयजल तथा सिंचाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन वस्तुस्थिति में सिर्फ उद्योग तथा शहरों के लिए पेयजल को ही अधिक प्राथमिकता मिल रही है। पानी के क्षेत्र में निजी कम्पनियों के आगमन को म्युनिसिपलिटी तथा राज्यों द्वारा जल प्रबन्धन की असफलता के वैकल्पिक समाधान के रूप में दर्शाया जा रहा है और आशा की जा रही है कि अर्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में पानी के गहराते संकट दूर होंगे। इस तरह के निजीकरण से सबसे गरीब वर्ग पर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ सकते हैं, जिनके पास पानी का मूल्य चुकाने की क्षमता नहीं है, वे सब नष्ट होने लगे हैं या नष्ट हो जाएंगे।

सरकार द्वारा जल संसाधनों को 'बूट' इत्यादि योजनाओं के तहत निजी कम्पनियों को सौंपा जा रहा है। इसका मुख्य कारण राजनीतिज्ञों, नौकरशाही व उद्योगपतियों

के बीच का गठजोड़ है। इस तरह की नीति व प्रकृति से गरीब, आदिवासी व स्थानीय समुदायों के लिए पानी पराया हो जायेगा।

छत्तीसगढ़, उड़ीसा व केरल इत्यादि में देखा गया है कि निजी कम्पनियों के फायदे को बढ़ावा देने के लिये स्थानीय जन समुदायों के हितों को कैसे दरकिनार कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ की शिवनाथ नदी रेडियस को दे दी थी। राष्ट्रीय जल यात्रियों ने नदी के किनारे के लोगों में इसके विरुद्ध चेतना जगा कर इस सरकारी ठेके को रद्द कराया तथा नदी को वापस समाज के नियन्त्रण में दिला दिया।

कभी पानी का काम करने वाले इंजीनियरों वाली ओड नामक पानीदार जाति के नाम पर ही उड़ीसा का नामकरण हुआ था; आज यहां की महानदी व वैतरणी जैसी बड़ी नदियों को सरकार ने बड़ी कम्पनियों को देना तय कर लिया। जलयात्रा ने वहां 'आगामी उड़ीसा' का नारा देकर इन ठेकों को रुकवाया। विधानसभा में हंगामा हुआ। अन्त में ये नदियां फिलहाल निजी कम्पनियों के हाथों जाने से रुक गई हैं।

केरल 44 नदियों वाला राज्य है। यहां की नदियों और तालाबों पर निजी कम्पनियों का नियन्त्रण बहुत तेजी से बढ़ा है। कोका कोला ने पलाचीमडा तक के पानी को बेचकर किसानों के कुएँ सुखा दिये हैं। लोग बेघर हो रहे हैं। पेप्सी ने पुन्दसेरी पंचायत का पानी धरती से निकाल कर बेचा। वहां भी लोग बेघर हुए। तब पलाचीमडा और पुन्दसेरी ने इसे रोकने की लड़ाई लड़ी । पंचायत की जीत हुई। जलयात्रा ने इस निर्णय को देशभर के समाज को सुनाया तथा इस निर्णय के पक्ष में जन समर्थन जुटाया। देशभर में जल व्यापार और जल शोषण इसी प्रकार रुके, ऐसी कोशिश की। जहां-जहां भी पानी के व्यापार को बढ़ावा देने वाले उद्योग थे, वहीं उनके विरुद्ध सांकेतिक धरने, सत्याग्रह, सम्मेलन आयोजित किए गए।

आन्ध्र स्थित कोदायली के रायलसीमा, महबूब नगर, अनन्तपुर आदि जिलों में पानी के कारण हो रही आत्महत्याओं को रोकने का वातावरण बनाया। कर्नाटक

के गदग जिले को भी आत्महत्या से बचाने वास्ते सामुदायिक प्रयासों से पानी की व्यवस्था करवाई। जलयात्रा ने समाज को पानीदार बनाने हेतु लोगों को तैयार कर जल हित को संरक्षण प्रदान किया ।

(छ) नदियों को जोड़ना

नदियों को जोड़ने की योजना निश्चित रूप से असफल होगी, क्योंकि किसी भी नदी बेसिन में अतिरिक्त पानी नहीं है। कई साल पहले तीन लिंक नहरों का निर्माण शुरू हुआ था : सतलुज-यमुना, कावेरी-गोदावरी और गोदावरी-महानदी। काफी खर्च और समय के पश्चात् भी ये जोड़ सफल नहीं हो पाये, क्योंकि कोई भी राज्य यह मानने को तैयार नहीं है कि उसके पास जरूरत से अधिक पानी है। जनता के पैसों की बहुत बड़ी बर्बादी का दूसरा नाम नदी जोड़ योजना है । नदी जोड़ योजना की बात नेहरू जी ने शुरू की थी। तभी से के. ए. राव, कैप्टन दस्तूर जैसे बहुत से लोगों ने इसके नाम पर बहुत नाम, पद व पैसा कमाया, लेकिन समाज को नदियों से दूर कर दिया।

नदियों को जोड़ने की योजना निश्चित रूप से असफल होगी, क्योंकि किसी भी नदी बेसिन में अतिरिक्त पानी नहीं है। कई साल पहले तीन लिंक नहरों का निर्माण शुरू हुआ था ... काफी खर्च और समय के पश्चात् भी ये जोड़ सफल नहीं हो पाये।

यात्रा में हमने नदियों की पवित्रता और पहाड़ों की हरियाली हेतु कुम्भ-महाकुम्भ की परम्परा को पहले की तरह जीवित करने का सन्देश दिया; नदियों को जोड़ने के नाम पर बाढ़-सुखाड़ मुक्ति की बात से भ्रमित होने को रोका और नदियों के साथ समाज को जोड़ने की बात सबके सामने रखी। इसे कहीं-कहीं सरकार ने भी माना। नदी जोड़ संबंधी कार्य-बल के अध्यक्ष श्री सुरेश प्रभु ने दिल्ली में इस हेतु एक विभाग बनाकर जलयात्रा के नायक श्री राजेन्द्र सिंह को उसका अध्यक्ष बनने की पेशकश की। श्री राजेन्द्र सिंह ने इस सरकारी समूह का अध्यक्ष बनने से मना कर दिया; लेकिन नदियों के साथ समाज को जोड़ने का कार्य करते रहने की प्रतिज्ञा की । सरकार ने नदी जोड़ के जो स्थान तय किए हैं, उन सब स्थानों पर समाज को नदी जोड़ के प्रत्यक्ष दुष्प्रभावों से अवगत कराया। राजनैतिक दलों की खींचतान से बचते हुए नदी जोड़ को वहीं मौके पर जाकर रोकने हेतु बांदा में सत्याग्रह की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। उत्तर-पूर्व में भी 'ब्रह्मपुत्र नदी बचाओ' आन्दोलन की शुरुआत की है। गुवाहाटी में श्री हेमभाई इस कार्य को आगे बढ़ाने हेतु तैयार हैं ।

नदी जोड़ के दुष्परिणामों को समझने हेतु कपड़े पर 'नदी जोड़ योजना' का मानचित्र बनाकर सब जगह दिखाया और समझाया। इस अभ्यास ने बहुत से लोगों को नदी जोड़ के भ्रम को रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल की।

दरअसल नदी जोड़ को समझने-समझाने का काम तो कई कार्यशालाओं के जरिए राष्ट्रीय जलयात्रा के आरम्भ से ही शुरू हो गया था। गुजरात में नर्मदा-साबरमती जोड़ का भ्रम बड़ा है, उसे सत्य करने की कोशिश की। नर्मदा का पानी कई जगह से थोड़ा-थोड़ा लेकर अहमदाबाद में केवल नदी पुल के पास डाला गया है। जनता को सिर्फ भ्रमित करने बाबत जो कुछ गुजरात सरकार ने किया, समाज के बीच जाकर उसकी पोल खोली।

सतलुज-यमुना जोड़ तथा कावेरी-तेलगु-गंगा जोड़ की असफलता के विषय में जानकारी हरियाणा-पंजाब-दिल्ली में छपती रही। कर्नाटक-तमिलनाडु में भी इसे स्पष्ट करने की बहुत कोशिश की। यह कार्य दक्षिणी राज्यों में चर्चा का विषय रहा।

हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अरवरी, रूपारेल, भगाणी, सरसा और जहाजवाली जैसी नदियों के साथ समाज को जोड़ने के अनुभव सुनाये। इन अनुभवों से नदियों को सदानीरा, निर्मल व प्रदूषण मुक्त बनाने की प्रक्रिया को समझाया। इस बदलाव की प्रक्रिया ने पूरी यात्रा में पानी के रचनात्मक और संघर्ष पक्ष को उभारा है। इस तरह पानी का काम देशभर के किसी भी कोने में करके अकाल और बाढ़ से मुक्ति पाई जा सकती है। नदियों को जोड़ने से देश को बाढ़ व सुखाड़ से मुक्ति नहीं मिल सकती। देश को बाढ़ व सुखाड़ से मुक्ति दिलाने हेतु अलवर-जयपुर की तरह आवश्यकता आधारित व विकेन्द्रित जल संरक्षण व जल प्रबन्धन करना होगा। ऐसा करने से सूखी नदी सदानीरा बन जाती है; खेती में रोजगार बढ़.जाता है; सबको पानी और उसका समान हक.... दोनों मिल जाता है। इस तरह की व्यावहारिक बातचीत ने समाज द्वारा किए गए जल बचाने के काम को बढ़ावा देने, नदियों को सदानीरा बनाने तथा प्रकृति व पर्यावरण के विपरीत नदी जोड़ को रोकने के अनुकूल देशव्यापी वातावरण निर्माण किया है।

(ज) पारम्परिक जल स्रोतों की अवहेलना

भारत के हर कोने में पारम्परिक जल स्रोतों के भंडार हैं, जो कि भारत की पारिस्थितिकी, मौसम व भौगोलिक-सांस्कृतिक परिवेश की विविधता से उपजी है। भारतीय संस्कृति व विभिन्न धर्मों में जल को पूजनीय माना गया है और देश में अभी भी पानी के संयमित उपयोग का जल दर्शन काफी सशक्त है। इस सबके बावजूद देश के हर कोने में पारम्परिक जल स्रोतों की अत्यधिक अवहेलना हुई है। इन स्रोतों के रखरखाव हेतु जनसमुदाय अब सरकार पर निर्भर हो गया है। तरुण भारत संघ ने अवश्य राजस्थान में पारम्परिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया है। इस काम ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी राज्यों में जल संरक्षण की परम्परागत विधियों को पुनर्जीवित करने का वातावरण बनाया है। देश भर में किसानों के साथ 4500 सभाओं में बहुत अच्छे से इनका जिक्र करने से वातावरण बनाने में मदद मिली। सभी सभाओं में बताया कि भारतीय समाज को जलदर्शन की समझ थी और जलकर्म को साझा कर्म मानकर सब काम अपनी-अपनी जिम्मेदारी से होता रहता था। इससे समाज जुड़ता था। पानी की पवित्रता का खयाल रखा जाता था। कम पानी में भी समाज अपना काम चलाता रहता था।

देश भर में किसानों के साथ 4500 सभाओं में जल संरक्षण के परंपरागत कार्यों का बहुत अच्छे से जिक्र करने से वातावरण बनाने में मदद मिली।

भूतल का जल सहेजने हेतु ताल, कुण्ड, सरोवर, बांध, जोहड़, जोहड़ी, खडीन, व कैरू आदि बने थे। अधोभूजल के लिए कुइयाँ, कुएँ और सुरंगम आदि बनते थे। पहले हमने पाताल तोड़ कुएं बनाकर केवल धरती का पेट खाली करने का कार्य ही नहीं किया, बल्कि धरती का पेट भरा भी था। जितना धरती से पानी लिया, उतना धरती को दिया भी था। इसीलिए हमारे परम्परागत जलस्रोत जिंदा रहे। आज हमारा जलदर्शन बदल गया है, इसीलिए भूजल भण्डार खाली हो गये और सूखी धरती के ऊपर हम प्यासे हैं। उक्त बातें यात्रा में परम्परागत जल प्रबन्धन की अच्छाई को उभार सकीं। जिन राज्यों में जल यात्रा गई, सभी जगह और सभी से ये बातें सुनने को मिलीं।

(झ) अच्छे प्रयासों से सीख

सकारात्मक दृष्टि से देखा जाये, तो देश के हर कोने में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं, जहां जन समुदायों ने पानी के संरक्षण व प्रबन्धन का काम बखूबी किया है। इन प्रयासों से न सिर्फ जल की उपलब्धता बढ़ी है, बल्कि अकाल व बाढ़ के विरुद्ध सुरक्षा भी पक्की हुई है। पीने के पानी तथा सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त होने से कहीं पलायन पूरी तरह रुक गया है, तो कहीं कम हुआ है; कृषि व इससे जुड़े हुए उत्पादन से ग्रामवासियों की समृद्धि बढ़ी है। ऐसे उदाहरण राजस्थान में जयपुर के नीमी जैसे सैकड़ों गांवों से लेकर महाराष्ट्र के हिवरे बाजार जैसे कई गाँवों के सफल प्रयोगों में नजर आते हैं ।

इन अनुभवों से देश के हर हिस्से में जल के ऐसे विकेन्द्रित तरीकों व तकनीकों को बढ़ावा देने की जरूरत उभरती है जो कि स्थानीय सांस्कृतिक-भौगोलिक व मौसम की विविधता के अनुरूप हों।

यह तो स्पष्ट हुआ कि हम यदि ठीक दिशा में जनमानस को तैयार करके कुछ काम करते हैं, तो उसका प्रभाव सरकारी तन्त्र पर जरूर होता है।

उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, बंगाल, कर्नाटक व आन्ध्र आदि राज्यों में अच्छे कामों की सीख से कुछ नये काम शुरू हुए हैं। इस यात्रा के वातावरण निर्माण से दो सौ जगहों पर नये काम शुरू हुए हैं। ये कार्य जब अन्य प्रदेशों में नीचे से शुरू हुए, तो सरकार को भी सीखने की जरूरत महसूस हुई। केरल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों के मुख्यमंत्री इस यात्रा में शामिल हुए एवं जलयात्रियों से मिले तथा उनसे खूब चर्चा की। इन खास लोगों ने अपने राज्यों में जहां जरूरत पूरी करने वाली जलनीति बनाने को कहा, वहीं जल के निजीकरण के विरुद्ध भी कुछ बोले; किन्तु इनके खुलकर न बोलने में इनकी मजबूरी भी दिखाई दी। इससे यह तो स्पष्ट हुआ कि हम यदि ठीक दिशा में जनमानस को तैयार करके कुछ काम करते हैं, तो उसका प्रभाव सरकारी तन्त्र पर जरूर पड़ता है। यात्रा के दौरान तरुण भारत संघ के जल संरक्षण के काम को देशभर में सबने पूछा और सभी भाइयों ने अनुभव सुनाए। इस अनुभवी काम ने समाज के अन्दर के आत्मविश्वास को जगाया। समाज मिलकर पानी का काम कर सकता है। यह अहसास पैदा किया।

यह यात्रा अच्छे प्रयासों की सीख का अच्छा मौका पैदा कर सकी है।

विवेचना

- जल मानव का मूलभूत अधिकार है। जल-जीवन का आधार है। जल प्रकृति द्वारा मानव को दिया गया ऐसा वरदान है, जिसका प्रबन्ध हम खुद मानव व प्रकृति के हित के लिए कर सकते हैं ।

- पानी कभी भी शासन या किसी व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं हो सकता । पानी हमेशा प्राकृतिक संसाधन रहेगा। शासन सारे प्राकृतिक संसाधनों की ट्रस्टी है, न कि मालिक। ये प्राकृतिक संसाधन जनता के उपयोग व हित के लिए हैं। अतः इन संसाधनों की रक्षा करना शासक का संवैधानिक कर्तव्य है। सभी के हित के लिए इन संसाधनों को सरकार किसी की निजी सम्पत्ति में परिवर्तित नहीं कर सकती। अतः जल संसाधनों का निजीकरण मानवता के खिलाफ जुर्म है। इसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए ।

अगर गांधीजी जीवित होते, तो जल के निजीकरण के खिलाफ जबर्दस्त आन्दोलन छेड़ देते। तब गरीब व उपेक्षित वर्ग के उत्थान का प्रतीक चर्खे के स्थान पर तालाब बन जाता।

- जल के वर्तमान संकट का कारण जल प्रबन्धन की कमी है, न कि जल की कम उपलब्धता। इसका एक ही उपाय है कि जल संसाधनों को इस हद तक पुनर्जीवित किया जाय, ताकि पानी की सतत् उपलब्धता इसकी मांग से कहीं ज्यादा हो। वैश्वीकरण तथा निजीकरण से लड़ने का एकमात्र दूरगामी तरीका समता ही है ।

- अगर गांधीजी जीवित होते, तो जल के निजीकरण के खिलाफ जबर्दस्त आन्दोलन छेड़ देते। तब गरीब व उपेक्षित वर्ग के उत्थान का प्रतीक चर्खे के स्थान पर तालाब बन जाता। गांधीजी जल के संवर्द्धन व प्रबन्धन हेतु समुदाय के मूलभूत व उद्योग को न बेचे जा सकने वाले अधिकार के लिये लड़ते ।

- नदियों को नदियों से जोड़ने के बजाय लोगों को नदियों से जोड़ना चाहिए। इसके लिये स्थानीय समुदायों को अपने जल संसाधनों का नियोजन, संवर्धन तथा प्रबन्धन का काम व उपयोग का अधिकार स्थानीय स्तर से लेकर नदी घाटी, राज्य व राष्ट्रीय स्तर तक प्राप्त होना चाहिए ।

- जल के संयमित व आदरपूर्ण व्यवहार की परम्परा को शीघ्रता से पुनर्जीवित करने की व्यापक आवश्यकता है। हमारी राष्ट्रीय जलनीति भारत के दर्शन व साँस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए ।

- शहरों में पानी के मूल्यों को इस तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे पांचसितारा होटल, बड़े उद्योग तथा अमीर कॉलोनियाँ उचित शुल्क अदा करें। झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले गरीब व पिछड़े वर्गों को भी नियमित पानी मिले व उनसे उनकी आर्थिक क्षमताओं के अनुसार कम ही शुल्क लिया जाये ।

आगामी लक्ष्य

- हर राज्य में राज्य स्तरीय 'जन जल आयोग' बने जो कि राज्य की जल स्थिति पर श्वेत-पत्र तैयार करे। इसमें राज्यों की जलनीतियों में विसंगतियों को सुधारने तथा राष्ट्रीय व राज्यवार जल नीति को जनोन्मुखी कैसे बनाया जाये ? इस पर भी चर्चा हो ।

- जन जल आयोग में कम से कम पाँच सदस्य हों :- राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, प्रमुख जल वैज्ञानिक, जल इन्जीनियर या गजधर, सामाजिक कार्यकर्त्ता और पत्रकार / पर्यावरणविद् ।

- गांव के स्तर पर जल के स्थायी प्रबन्धन हेतु ग्राम कोष होना अति आवश्यक है, जो कि निम्न तरीके से बनाया जा सकता है :-
  - हर परिवार द्वारा महीने में एक दिन का श्रमदान
  - नौकरी करने वाले परिवारों द्वारा महीने में एक दिन का वेतन दान
  - हर गांव में अनाज बैंक

- 73वें व 74वें संशोधन के अनुसार पंचायतों व स्थानीय म्युनिसिपल संगठनों को संसाधनों के नियोजन, संवर्धन व प्रबन्धन के अधिकार दिये गये हैं। इन संगठनों को इन कार्यों हेतु उचित सहायता प्राप्त होनी चाहिए।
- नदी घाटी के स्तर पर संसाधनों का नियोजन, संवर्धन व प्रबन्धन करने के लिये नये जल सांसदों को बनाना व सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक है।

जलयात्रा का कार्यक्रम

चरण	समय	राज्य
चरण – 1	23 दिसम्बर, 2002 से 10 मार्च, 2003	1. दिल्ली 2. हरियाणा 3. राजस्थान 4. गुजरात 5. मध्य प्रदेश 6. छत्तीसगढ़ 7. उड़ीसा
चरण – 2	10 मार्च से 30 मई, 2003	8. उत्तरांचल 9. दिल्ली 10. मध्य प्रदेश 11. महाराष्ट्र 12. गोवा 13. कर्नाटक 14. आन्ध्र प्रदेश 15. तमिलनाडु 16. पांडिचेरी
चरण – 3	1 जून से 15 जुलाई, 2003	17. केरल 18. कर्नाटक 19. महाराष्ट्र 20. मध्य प्रदेश 21. उत्तर प्रदेश 22. दिल्ली 23. हरियाणा

चरण	समय	राज्य
		24. पंजाब
		25. जम्मू और कष्मीर
चरण – 4	जुलाई और अगस्त 2003	26. हिमाचल प्रदेश
		27. पंजाब
		28. हरियाणा
		29. उत्तर प्रदेश
		30. राजस्थान
चरण–5	सितम्बर से नवम्बर 2003,	31. पश्चिम बंगाल
	दिसम्बर 2003	32. बिहार
		33. झारखण्ड
चरण – 6	दिसम्बर 2003 और	फालो अप विजिट
	जनवरी 2004	34. महाराष्ट्र
		35. केरल
		36. उत्तरांचल
		37. उत्तर प्रदेश
चरण – 7	मार्च से मई 2004	38. अरुणाचल प्रदेश
		39. असम
		40. मणिपुर
		41. मेघालय
		42. मिजोरम
		43. नागालैण्ड
		44. सिक्किम
		45. त्रिपुरा

राष्ट्रीय जलयात्रा के संयोजन में विशेष सहयोग के लिए हम जिनके आभारी हैं

दिल्ली

सर्वश्री अनुपम मिश्र, अरुण कुमार त्रिपाठी, महंत तिवारी, बहन सविता गोखले, दुष्यंत और अरुण तिवारी।

हरियाणा

सर्वश्री इब्राहीम, सुंदरलाल, राजेन्द्र यादव, डॉ. रामनिवास यादव और सुरेश राठी।

राजस्थान

सर्वश्री प्रो. एम.एस. राठौर, गोपालसिंह, बृजेश विजयवर्गीय, किशोर संत, भंवरसिंह चंदाण, डॉ. तेज राजदान, चक्रवर्ती सिंह, पृथ्वीराज सिंह, गजसिंह, विमला कौशिक और भगवानदास माहेश्वरी, निरंजन सिंह, कर्नल एस.वी. सिंह, लक्ष्मण सिंह, किशनलाल देशमा, केदार श्रीमाल, दृगपाल सिंह, सतेन्द्र सिंह, चमन सिंह।

गुजरात

सुश्री नफीसा बांरोट, राजू दीप्ति, श्यामजी भाई अन्ताला, प्रेमजी भाई बापा, महादेव विद्रोही, हंसमुख पटेल, मनुभाई मेहता और लल्लू भाई।

मध्यप्रदेश

सर्वश्री नीलेश देसाई, सुरेश मिश्र, रहमत भाई, श्रीपाद धर्माधिकारी और जय नागडा, राकेश दिवान, माधुरी।

छत्तीसगढ़

सर्वश्री गौतम बंद्योपाध्याय, रवीन्द्र मानव, ललित सूरजन।

उड़ीसा

सर्वश्री आदित्य पटनायक, मुकुंद कंठ, सुरेश, ए.बी. स्वामी, अच्युतदास, जगदानन्द और बृजभाई।

कर्नाटक

सर्वश्री डी.आर. पाटिल, साहूकार, जे. के. जमादार, विनय कुलकर्णी, एच.के. पाटिल और रामप्पा

महाराष्ट्र

सर्वश्री अमोल, अपर्णा, अमला रुइया, विभा गुप्ता, ज्ञानेन्द्र, डॉ. नंदा, सुरेखा शाह, चंद्रमोहन शाह और सुनील जोशी।

गोवा

सर्वश्री कलानंद मणि, कलाड़ अलबारिश

आंध्रप्रदेश

सुश्री बहन जसवीन जयरथ, सुब्बाराव, रामचन्द्रैया और सोफिया

तमिलनाडु

सर्वश्री स्व. एन. कृष्णास्वामी, ई. मनोहरन, अन्नामलाई, इलिंगो, राम-रमा दम्पति, संगीता बासीमलाई और कांञ्चि काम कोटि पीठ शंकराचार्य

पॉण्डिचेरी

सुश्री ललिता

केरल

सर्वश्री कालियन सुकुमारन, के.जी. अल्फास, डॉ. चोटा और श्रीकुमार पाउरे।

पंजाब

सर्वश्री उमेंद्र दत्त

उत्तरांचल - उत्तरप्रदेश

सर्वश्री जी.डी. अग्रवाल, अरविंद कुशवाहा, चंद्रशेखर प्राण, नरेन्द्र मल्होत्रा, अशोक भाई, ईश्वर चंद, अशोक राणा, वीरेन्द्र राणा तथा कृष्णपाल सिंह, अनिल राणा।

असम

सर्वश्री हेमभाई

बंगाल

सर्वश्री नारायण भाई, अहमद भाई और चंदन पाल

बिहार

सर्वश्री पुष्पेन्द्र प्रियदर्शी, प्रभात, अनिल प्रकाश, दिनेश मिश्रा और पानी के लिए शहीद हुए स्व. महेशकांत व बहन स्व. सरिता, विजय।

सहयोग

''जलयात्रा''का यह दस्तावेज जिस रूप में अब आपके हाथों में है। इसमें यात्रा के दौरान जल संस्मरणों के तथ्यों को संकलित करने में **तरुण भारत संघ** के सभी साथियों का विशेष सहयोग रहा है।

अम्बुज किशोर – सम्पर्क-पत्राचार, दूरभाष, ई-मेल द्वारा जलयात्रा की तैयारी

राकेश कुमार – वाहन सम्पर्क जलयात्रा को पूर्ण सफल सहयोग

सईद मुफ्तावर हसनथ – फोटोग्रॉफी जलयात्रा के दौरान चित्र संकलन में सहयोग दिया।

भागीरथी राठौड़ – जलयात्रा की सम्पत्ति वितरण व्यवस्था।

छाजूराम – जल संरक्षण के लोक गीत से समाज को प्रेरित करने।

कजोड़ी देवी – जल संरक्षण एवं संवर्धन में महिलाओं की भूमिका एवं महिला जनजाग्रति करना।

अर्जुन गुर्जर – ग्राम सभा द्वारा किये गए जल संरक्षण के अनुभव से जनजाग्रति करना।

देवयानी कुलकर्णी – जलयात्रा के लेख-प्रलेखों को कम्प्यूटराइज्ड करना एवं दस्तावेज की साज-सज्जा करना।

अरुण तिवाड़ी – जलयात्रा के दस्तावेज का सम्पूर्ण सम्पादन एवं स्वरूप में पूर्ण सहयोग।

डॉ. मनोहर सिंह राठौड़ – जलयात्रा के अनुभवों का संकलन करने तथा प्रकाशित करने में पूर्ण सहयोग दिया। उनके साथ श्री नित्या जैकब (दिल्ली), सुश्री कल्पना (हरियाणा), श्री पंकज कुमार तथा श्री बृजमोहन (उत्तरांचल) ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER
CHENNAI, SATURDAY, MAY 3, 2003

'Nobody is bothered about water security'

The New Indian Express

'Mafia trying to gain control of water resources'

पाण्यासारखी राष्ट्रीय संपत्तीही आता राजकीय संकटात : राजेंद्रसिंग

राष्ट्रीय जल सम्मेलन
NATIONAL WATER CONVENTION

தினத் தந்தி
DAILY THANTHI

'पानीदार बनने के लिए प्रकृति के लेन-देन का गणित समझना होगा'

जल चेतना यात्रा का द्वितीय चरण आरंभ
यात्रा देश के छह राज्यों में घूमेगी

ಶಿರಿಗೆರೆ: ಆಧುನಿಕ 'ಭಗೀರಥ'ಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ

सोलापूर, दि. ... मंगला कोळे ... अध्यक्षपदी सत्ता ... जिल्हाध्यक्षा सुमन ... यावेळी जिजाऊ ब्रिगेड ... सत्कार करण्यात आला. ... मनिषा जगताप, सुरेखा काटमोरे, स्वाती बोराडे, प्रज्ञा बगाडे व पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते

'... जाण्याचा धोका'

लोकमत
सोलापूर विशेष
मंगळवार ८ एप्रिल २००३ पान - २

पाणी वाचविण्यासाठी तरूणांनी पुढे यावे : राजेंद्रसिंह राणा

सोलापूर, दि. ७ (प्रतिनिधी)- सध्याच्या काळात पाण्याला महत्व येत असून पाणी वाचविण्यासाठी संघटीत होवून प्रयत्न करण्याची गरज असून त्यासाठी तरूणांनी पुढे आले पाहिजे असे प्रतिपादन राष्ट्रीय जल बिरादरीचे प्रमुख राजेंद्रसिंह राणा यांनी केले.

राष्ट्रीय जलबिरादरीच्यावतीची जलयात्रा आज (सोमवारी) सोलापूर शहरात आली होती. त्यानिमित्त महापालिकेच्यावतीने हुतात्मा स्मृती मंदिरात कार्यक्रमाचे आयोजन ... बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महापौर नलिनी चंदेले होत्या.

यावेळी व्यासपीठावर लेखिका सुरेखा शहा, मुंबईच्या अमला रूईया, डॉ. नंदा शिवगुंडे, तसेच जलयात्रा पथकातील छोटी पूजल, कमोदी मीना, दीपक मेहसाणी आदी उपस्थित होते.

महापौर नलिनी चंदेले यांनी उपस्थित मान्यवरांचे पुष्पहार घालून व शाल, श्रीफळ देवून स्वागत केले.

प्रारंभी शैला मेहता, सुजाता ... गांधी यांच्या लहान मुलींचे जलनृत्य सादर करण्यात आले.

यावेळी बोलताना राणा म्हणाले की, देशात आज पाण्याचे महत्व समजू लागले आहे. पाणी मिळविण्यासाठी संघटीत होवून प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अन्यथा पाणी हातून निघून जाईल अशी भिती त्यांनी व्यक्त केली. आज पाण्यासाठी ज्या चळवळी चालू आहेत त्यात तरूणांची संख्या आहेच पण तरूणांनी मोठ्या प्रमाणात पुढे येवून या चळवळीची ...

WELCOME
हुतात्मा

राष्ट्रीय जलबिरादरीच्यावतीने शहरात जलयात्रेचा आगमन

NEWS TODAY
NATIONAL DAILY
FOUNDER EDITOR: T.R.R

Linking of rivers a waste, says Magsaysay winner

एक धगधगता जीवनसंघर्ष
पाण्यासाठी !

सांगली (अशोक घोरपडे) : महाराष्ट्राच्या चोवीसहून अधिक जिल्ह्यात यंदा भीषण दुष्काळ पडलेला आहे. या दुष्काळ निवारण ... आव्हान राज्य सरका... सरक... मदत ... मह... प्र... त ... गावचे आहे. ... काम ... गतिक ... आहे. ... झलही ... नवर

ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸುಲಭ ಸೂತ್ರಗಳು
ಸಿರಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿಂದು ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಳ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

నీటిపై హక్కు ప్రజలదే: రాజేంద్రసింగ్

हरियाणा

राष्ट्रीय जुल यात्रा

तरुण भारत संघ

तरुण जल विद्यापीठ

भीकमपुरा किशोरी वाया-थानागाजी
जिला-अलवर, राजस्थान